हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1982

खंड 1 अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 29 मार्च 1982

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)34
अतारांकित प्र ान एवं उत्तर	(12)47
वि ोशधिकार का प्र न	(12)63
नलकूपों का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों को सहायता की अदायगी न करने सम्बन्धी	(12)63
विभागों/निगमों/बोर्डों आदि की वार्शिक रिपोर्ट देर से पे ा करना	(12)65
वि ोशाधिकार का प्र न	(12)67
वाक–आउट	(12)68
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव	
मैडीकल कालेज तथा अस्पताल रोहतक की दिन–प्रति दिन बिगडती हुई हालत सम्बन्धी	(12)69

वक्तव्य	
स्वास्थय तथा पर्यटन मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(12)71
वर्श 1982—83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(12)77
वाक आउट	(12)124
वर्श 1982—83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)125
राज्यपाल से संदे ा	(12)134
वि ोशाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना	(12)134
वि ोशाधिकार का प्र न—वि ोश समिति की रिपोर्ट	(12)140
वि ोशाधिकार का प्र न—वि ोश समिति की रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(12)141
वर्श 1982—83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)144

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 29 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़, में. प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होगें।

तारांकित प्र न संख्या 2586

यह प्र न पूछा नहीं गया क्यांकि इस समय मानीय सदस्य, राव इन्द्रजीत सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Crop Insurance Scheme in the State

***2605. Chaudhri Sant Kanwar:**

Swami Aditya Vesh:- Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether the crops insurance scheme has been introduced in the State;-

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of districts in which the said scheme has been introduced?

कृशि मंत्री (श्री भाम ारे सिंह):

(क) जी हां।

(ख) सदन के पटल पर विवरण रखा जाता है।

(ग) खरीफ 1981 तथा रबी 1981–82 में जो जिले इसके अन्तर्गत लिये गये है वे निम्न प्रकार से है–

(1) खरीफ 1981			
	(i)	धान की फसल	हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला और जीन्द।
	(ii)	बाजरा की फसल	हिसार, रोहतक और जीन्द
(2) रबी 1981–82			
	(i)	गेहूं	राज्य के सभी जिले।
	(ii)	चना	हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और जीन्द
	(iii)	जौ	रोहतक, गुड़गांव,

			फरीदाबाद, तथा महेन्द्रगढ़।

विवरण

जनरल इन् ोरेन्स कारपोरे ान आफ इण्डिया द्वारा एक पायलेट फसल बीमा स्कीम जो भारत सरकार की सलाह से तैयार करके प्रयोजित की थी उसे राज्य में खरीफ 1981 से लागू किया गया था। यह स्कीम सामूहिक तथा स्वेच्छा के आधार पर है। इसके अन्तर्गत केवल ऋणी किसान ही आते है। यह एक ही प्रकार के क्षेत्र पर (तहसील) पर आधारित होगी। व्यक्तिगत आधार पर नहीं। इस स्कीम के अन्तर्गत एक लाख प्रति तहसील के हिसाब से कुल 17.00 लाख रूपये का 13 तहसीलों में धान तथा 4 तहसीलों में बाजरा पर बीमा व्यापार करने का लक्ष्य था। धान पर 543 किसानों के 475.7 हक्टेयर क्षेत्र 9.40 लाख रूपये का बीमा किया गया जिससे 44387.73 रूपये प्रीमियम इक्ट्ठा किया गया जब कि बाजरा पर 66 किसानों के 111.4 हैक्टैयर क्षेत्र का 1.08 लाख रूपये का बीमा व्यापार किया गया तथा 5454.50 रूपये प्रीमियम इकट्ठा किया गया।

अधिकतम बीमा राि ा सीमा प्रति हैक्टेयर/किसान धान पर 2250/– बाजरा पर 1700/– तथा 3000/– जहां धान व बाजरा इक्टठै बोये गये थे/बिमीत राि ा की प्रीमियम की दर 4.5 प्रति ात से 5.00 प्रति ात थी।

रबी 1981—82

रबी 1981—82 में यह स्कीम बढा कर गेहूं के लिये सारे राजय में चने के लिये 12 तहसीलों में और जौं के लिये 11 तहसीलों में लागू की गई। रबी 1981—82 में इस कार्य के लिये कुल निर्धारित राशि ा 40 लाख रूपये थी। चने के लिये 6.00 लाख तथा जौं के लिये 5.50 लाख तथा गेहूं के लिये 28.50 लाख रूपये है। अधिकतम बीमा राशि ा प्रति हैक्टेयर/किसान गेहूं के लिये 2250/— चने और जौं प्रत्येक के लिये 1300/— रूपये निशि चत किये गये है। प्रीमियम की दर बीमा राशि ा का 4.50 प्रतिशि ात से 5.00 प्रतिशि ात तक है।

यह स्कीम कमशः राज्य सरकार और जी.आई.सी. दोनों 25 प्रतिशि ात और 75 प्रतिशि ात के अनुपात में चलाई जा रही है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, कृशि मंत्री जी ने बताया है कि गेहूं का बीमा सारे जिलों में लागू कर दिया है। इन्होने 'बी' भाग मे ंयह बताया है कि गेहूं का जो बीमा है यह प्रति हैक्टैयर 2250 रूपये है यानि 900 रूपये प्रति कएड। जहां —2 पर इब ओले गिरे है वहां पर सरकार 400 रूपया प्रति एकड के हिसाब में मुआवजा दे रही है। इन्होने अपने जवाब में कहा है कि फसली बीमा योजना के अन्तर्गत 900 रूपये प्रति एकड के हिसाब

से देगें तो फिर ये 400 रूपये प्रति एकड के हिसाब से कम कैसे देने लग रहे थे?

श्री भाम ोर सिहं: मेरे साथी ने भाायद बीमा स्कीम को पूरी तरह से पढा नहीं है। मुख्य मंत्री ने 400 रूपये प्रति एकड के हिसाब से जो रिलीफ उनांउस किया है यह स्पे ाल रिलीफ है जो बीमा योजना से अलग है। सर, यह स्कीम व्यक्तिगत स्कीम नहीं है बल्कि यह ग्रुप स्कीम है। इस स्कीम के तहत सारी तहसील को एक चूनिट काउन्ट किया जाता है। इस सकीम के अन्तर्गत टोटल तहसील की फसल का एवरेज निकाल कर जो नुकसान होता है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत तहसील के सीाी किसानों को भाामिल किया जाता है। इस स्कीम का फायदा सभी किसानों को मिलेगा। यह एक पायलेट स्कीम है। जो भारत सरकार की सलाह से इन्ंोरेंस कार्पोरे ान आफ इन्डिया के साथ चलाई गई है।

श्री अध्यक्ष: जिस इलाके में ओले पडे है क्या इस स्कीम का फायदा स्पै ाल रिलीफ से अलग होगा क्या इसके अन्दर टोटल तहसील की ईल्ड को भाामिल किया जायेगा?

चौधरी संत कवंर: एक तो ये 400 रूपया प्रति एकड के हिसाब से सहायता उन किसानों को देरहे है जिन किसानों की फसल ओलावृश्टि से खराब हो गई है। दूसरे यह कह रहे है कि फसल बीमा योजना के अधीन भी उन्हे 900 रूपये प्रति एकड की

सहायता दी जायेगी। क्या यह सहायता उनको उस समय मिलेगी जिस समय ये नुक्सान का पूरा ब्योरा देगें। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को फसल बीमा के तहत भी सहायता मिलेगी?

श्री भाम ोर सिहंः यदि किसान की उसके लिये इन्टाईटलमैंट होगी तो उसको जरूर सहायता मिलेगी। यदि इन्टाईटलमैंट नही होगी तो उसको सहायता नहीं दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः आप औसत कैसे निकालते है?

श्री भाम ोर सिंहः पर हैक्टैयर के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है।

श्री अध्यक्षः यदि किसानों का पूना नुक्सान हो जाता है तो क्या उनको पूरी सहायता मिलेगी?

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इस स्कीम के तहत किसान को लाभ उसकी हानि के अनुपात से दिया जाता है। इसस्कीम कालाभ देते समय उस की टोटल फसल का लौस निकाल लिया जाता है। जितना लौस होता है, उस हिसाब से किसान को सहायता दी जाती है।

श्री हीरानन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गेंहूं की फसल के बीमा के लिये जो रेट

2250 रूपये फिक्स किया गया है, यह किस माप दण्ड पर निर्धारित करते है?

श्री भाम ोर सिंहः जितनी टोटल रकम का बीमा करवाया जाता है, उस रकम का 4½ से 5 प्रति ात तक प्रीमियम देने का मापदण्ड जी0आई0सी0 ने फिक्स किया है।

राव बंसी सिंहः जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर बाजरे की फसल ही अधिक मात्रा में पैदा होती हैं । उसको इस में भाामिल नहीं किया गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिले महेन्द्रगढ़ऋ को क्यो नहीं भाामिल किया गया है?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, गेहूं और जौ के लिये तो इस जिले को भी इस स्कीम के तहत भाामिल कर लिया गया है। जिला महेन्द्रगढ़ की बाजरे की फसल को भी इस स्कीम के तहत लेने के लिये जी0आई0सी0 से बातचीत हो रही है। हमारी यह को ा ा है कि इस स्कीम में जिला महेन्द्रगढ को भी इन्कलूड कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और बताना चाहताहूं कि वहां पर बाजरे की फसल इनडैम्नीफीइबएल लिमिट अधिक है इसलिये जी0आईसी. नहीं मान रही। लेनिक हम अपनी तरफ से पूरी –2 को ा ा कर रहे है।

चौधरी रिजक रामः इन्होने अभी बताया है कि इस स्कीम में टोटल तहसील को भाामिल किया गया है। नुकसान को ध्यान मे ंरखते हुये टोटल तहसील की एवरेज किसानों के लिये

फायदेमंद नहीं है। क्योकि कई बार इंडिविजुअल नुकसान हो जाता है। इंडिविजुअल नुकसान हो जाता है। इंडिविजुअल नुकसान होने की वजह से किानों को फायदा नही हो पाता क्योकि जैसा ये बता रहे है उस हिसाब से सारी तहसील के नुकसान को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक किसान की सहायता दी जायेगी। इस तरह सहायता देने से इंडिविजुअल किसान घाटै में रहता है। दूसरी बात मेरी यह है कि ऐसे एरिया को इस स्कीम के तहत अलग से लेना चाहिये। तीसरी बात मेरी यह है कि मैक्सिमम ईल्डकिस तरह मुकर्रर करते है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंडिविजुअल नुकसान को निकाले के लिये कोई पैमाना निर्धारित करेगें?

श्री भाम ोर सिंहः सर, यह वालैन्टरी स्कीम है। कम्पलसरी स्कीम नहीं हैं जो किसान इस स्कीम से फायदा लेना चाहता है उसको मिलेगा और जो फायदा लेना नहीं चाहता उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहेगा उसका बीमा हो जायेगा और वह अपना प्रीमियम खुद देगा। यह व्यक्तिगत फार्मर्ज का बीमा नहीं हैं यह एरिया के हिसाब से बीमा किया जाता है। एक बात इन्होने कही थी कि मैंक्स्मिम ईल्ड किस तरह से मुकर्रर करते है। इस संबधं में मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों की औसत पैदावार फसल को ध्यान में रखते हुये निकाली जाती है। सभी

जिलों का रिकार्ड मेरे पस है। यदि मैंबर साहेबान आंकडे पूछना चहेगें तो मैं बताने के लिये तैयार हूं।

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंबर्ज साहेबन ने जो भांका जाहिर की है वह ठीक है। मै। मानता हूं कि इस स्कीम में अभी काफी त्रुटियां है और इसमें अभी काफी सुधार की जरूरत हैं स्टेट गवर्नमेंट का ऐग्रीकल्चर डिपार्टैमेंट निरन्तर जी0ए0आई0सी0 के साथ इस संबंध में बात कर रहा है और उन पर दबाव डाल रहा है कि एसको इम्प्रूव किया जाये। उनका कहना है कि यह पायलेट स्कीम है। इसे लागू करने से ग्रेजुअली जैसे जैसे ऐक्सपीरियंस गेन होता जाएगा आसमें सुधार लाते जाएगें।

चौधरी हुक्म सिंह: क्या मंत्री जी बतायेगें कि कौप इं ोरैंस स्कीम भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्यों इंटरोडयूस नहीं की गई? साथ ही मंत्री महोदय यह भी बताने का कशट करें कि प्रति फसल प्रति हैक्टेयर किसान को कितना प्रीमियम ने करना पडता है?

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मैने बताया है कि गेहूं के लिये तमाम एरियाज भामिल है। जहां तक दूसरी फसलों का संबंध है, उसके बारे में जैसा मैने पहले बताया जी0आई0सी0 की एक इनडैम्नीफाइख्बल लिमिट है। उससे ज्यादा नुकसान को वे पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं उसकी रेज 10 परसैंट से 40 परसैन्ट तक है। वे हमारे केस में तीस परसै।ट तक माने थे

लेकिन हमने उनसे पांच परसैंट और मनवा लिया है। जहां लौस की इनडैम्नीफाइख्बल लिमिट इतनी हो, वहां वे कौप इं ाोरेन्स करते है। भिवानी, महेन्द्रगढ, हिसार और सिरसा की लौस की वेरेज ज्यादा ुाल करने की वजह से वे नहीं मानते। हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे है कि वे इस बात को ऐक्सैप्ट कर ले।

प्रीमियम` बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं कि जितनी राि ा का बीमा होगा उसका साढ़े चार परसैंट से पांच परसैंट तक प्रीमियम होगा।

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, एक बात तो यह है कि ये मिनी बै।क्स के थ्रू इं ाोरैंस करते है जबकि सब जगह मिनी बैक्स नहीं है। (विघन)

श्री अध्यक्षः मैं तो मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा। यह बहुत उलझा हुआ सवाल है। इन्होने इसकी बहुत स्टडी की है और बहुत अच्छे ढंग से माननीय सदस्यों के प्र नों के उत्तर दिये है। इन्होने कहा है कि यह पायलेट स्कीम है। इसमें अभी बहुत सी खामियां है जो आहिस्ता–2 दूर की जायेगी। जहां तक मैने जायजा लगाया है इसमें जी0आई0सी0 का मेन हिस्सा है। जी0आईसी0 आप जानते है कोमर्ि ायल कंसर्न है और वह अपने प्रोफिट का ध्यान अव य रखेगा। जहां उसे लोस नजर आयेगा वह इस काम को नहीं करेगा।

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। जो वयक्ति कोआप्रटिव सोसाइटी का मैंबर है, उसी का इं ाोरेंस ये करते है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दूसरे लोगों की फसलों कायेबीमा क्यो नही करवाते?

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर सहाब, इनकी बात ठीक है कि जिन लोगों ने कोआप्रेटिव बैंक्स से कर्जा लिया है, क्रौप लोन लिया है, उन्ही को इं ोंरेस ये करते हैं। लेकिन हमने प्रैस किया है कि जो लोग दूसरे बैंक्स से लोन्ज लेते है या अपने पल्ले से पैसा खर्च करते है उनकी फसलों का भी बीमा किया जाये। अभी जी0आई0सी0 इस बात के लिये नहीं मानी है। दूसरी स्टेट गवर्नमेंटस भी इस बात को प्रैस कर रही है लेकिन अाी वे इस बात के लिये माने नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मै अपकी मारफत मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह यह बात लाना चाहता हूं कि आज के इंडियन ऐक्सप्रैस में हरियाणा की कौप इं ाोरेंस स्कीम को फार्स बताया गया हैं उसमं यह भी कहा गया है। कि इस स्कीम को एक डिपार्टमेंट हैंडल नहीं कर रहा हैं ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इसमें ब्रायनामा है। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट का इसमें ज्यादा हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा है कि नि ााना तो 40 लाख रूपये का था लेकिन क्रौप इं ाोरेंस केवल 8 लाख रूपये की हुई है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि यह बात ठीक है? यदि ठीक है तो इसके इलाज के लिये इन्होने क्या कदम उठाये है।

श्री अध्यक्ष: इसके लिये सैपरेट नोटिस की आव यकता है।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मैनेवह अखबार पढ लिया है। उसमें कुछ बात तो ठीक है लेकिन आंकडे गलत हैं अगर आप हुक्म दे तो मैं आकंडे इनको बता देता हूं कि किस फसल में कितने रूपये की और कितने हैक्टेयर जमीन की इं ाोरेंस हुई है।

श्री अध्यक्ष: नही, उसके लिये बहुत समय लगेगा। क्वै चन लिसट पर और भी बहुत से जरूरी सवाल है। अब मैं इसको इससे ज्यादा समय नही दे सकता। पहले ही 15 मिनट हो चुके है। (विघन) अगला सवाल।

Accidents occurred on G.T. road from Delhi to Ambala

***2610. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the total number of accident of vehicles occurred on Delhi-Ambala portion of the G.T. road and the total number of details occurred as a result thereof from 1-10-1981 to date and especially within the municipal limits of Panipat; and

(b) whether it is a fact that the major cause of accidents is due to over-taking of vehicles; if so, whether the Government is proposing to check this over-taking of vehicles on G.T. road?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal):

(a) Information is given as under:

Area	**Number of Accidents**	**Number of deaths occurred**
Municipal limits of Panipat	15	5
Remaining area of G.T. road	129	39
Total	**144**	**44**

(b) Yes. Overtaking of vehicles is one of the major causes of accidents. The Traffic Enforcement Staff is being strengthened and they are being provided with modern scientific equipment for checking any violation of Traffic Rules.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पार्ट 'ए' के जवाब में कहा है कि पिछले 6 महीनों में पानीपत में 15 ऐक्सिडैन्टस हुये है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि वहां बाहर ट्रक स्टैंड के लिये जो जगह ईयरमार्क हुई है, उस पर ट्रक स्टैंड कब तक बन जाएगा?

श्री अध्यक्ष: ट्रक स्टैंड का तो इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, पार्ट 'बी' के जवाब में इन्होनें कहा है कि ट्रैफिक ऐनफोर्समेंअ स्टाफ को मोड्रम साइंटिकि इक्विपमेंट दिया जा रहा हैं। क्या यह इक्विपमेंअ वास्तव में दिया भी जा रहा है या पेपर पर ही स्कीम है?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः सर, यह इक्विपमेंअ बाकायदा इस्तेमाल हो रहा है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, एक्सीडेन्टस की वजह से या ट्रक उलट जाने से कई–2 घंटे तक जी0टी0 रोड ब्लाक रहती है।कया मंत्री महोदय उन्हें फौरन रोड से रिमूव कराने का प्रबन्ध करवायेगें ताकि ट्रैफिक न रूके?

श्री कन्हैयालाल पोसवालः स्पीकर साहब, दो–तीन महीने में 115 वीहकल्ज को रिमूव करवाया है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक्सीडेन्टस और डैथ का नम्बर दिया है। कुछ दिन पहले कई ऐसी जगहों पर जहां ट्रैफिक ज्यादा होने की वहज से एक्सीडैन्टस होते है, स्पीड ब्रेकरज लगाये है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानीपत,त्र जो कि आवेर'क्राउडिड प्लेस है और जी0टी0 रोड पर है, क्या वहां पर म्युनिसिपल लीमिट मूें इस स्कीम के स्पीड ब्रेकरज लगायेगें ताकि ओवर क्राउंडिग और तेज स्पीड के कारण एक्सीडेन्टस कम हो सकें?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः जी0टी0 रोउ पर स्पीड ब्रेकर लगाने से पहले काफी सोचना पडता है, इसलिये जहां ऐसे हालत है वहां हम रोड को वाइडन करते है।

चौधरी गया लालः स्पीकर साहब, रात के वक्त झोटाबुग्गी या ऊंट रेहड़ा रोउ से गुजरते है तो उनके पास रैड लाइट नहीं होती है। जब सामने से कोइ ट्रक या गाडी आती है उसकी तेज लाइट होने के कारण से वे दिखायी नहीं देती। क्या मंत्री महोदय इस झोटा बुग्गी या ऊंट रेहडा पर रैड लाइट लगाने के बारे में विचार करेगें?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः हमारा स्टाु इनको भी चैक करता है। हमने एक स्पै ाल डी0एस0पी0 तीन इन्सपैक्टर, 26 खेस0 आई0, 66 हैड–कान्टेबल ओर कुछ ड्राइवर्ज चैक करने के लिये रखे हुये है। 24 घन्टें में 9 बीट्स बना कर चैक करते है।

श्री अध्यक्षः मैंबर साहब यह पूछ रहे है कि क्या झोटा बुग्गी और ऊंट रेहडा पर लाल बत्ती होती है या नहीं?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः इनको भी हम चैक करेगें और जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक करेगें।

श्री अध्यक्षः सड़कों पर हम देखते है कि इनके पास लालबत्ती नहीं होती।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः इस बारे में ज्यादा से ज्यादा चैक करेगें।

श्री भले रमः स्पीकर साहब, जिस प्रकार से हिमाचल की बसों में सफर कते हूये किसी बस दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति मर जाताहै तो उसे 20 हजार रूपये दिये जाते है। इसी प्रकार यहां भी ट्रकों से या ट्रांसपोर्ट विभाग की बसों से जो लोग मर जाते है, क्या मिनिस्टर साहब यहां भी उसी तरह का मुआजवजा देने की कृपा करेगें?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः हम ऐसा नहीं कर सकते। वे कोर्ट के थ्रू क्लेम कर सकते है।

एक आवाजः हवाई जहाज से एक्सीडैंट होने पर भी मुआवजा दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः हवाई जहाज से इसका कोई संबनध नही ंहै। हवाई जहाज सरकारी चीज है। अगर हवाई जहाज से मर जाता है तो सरकार ाि जिम्मेदारी बनती है।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः स्पीकर सहब, जो कोई ाि सडक बनती हैं उसके साइड पर मिट्टी डाली जाती है। कई बार या तो मिट्टी कम डाली जाती है या बरसात के दिनों में मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जिसके कारण ट्रकों के या अन्य वीकल्ज के एक्सीडेंट ज्यादा होते है। अम्बाला से यमुनानगर जो सडक जाती है उस पर आये दिन इसलिये ज्यादा एक्सीडेन्ट होते है क्योकिं

वहां पर मिट्टी नीचे बैठ गई है। क्या मंत्री महोदय ऐसा इन्तजाम करेगें कि पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमेंट मिट्टी डालते समय पूरी मिट्टी डाले और सख्त भी डाले?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः हम गाहेबगाहे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को लिखते रहते है लेकिन इस सवाल का इससे कोई संबधं नहीं।

श्री फतेह चन्द विजः मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि चैंकिग स्टाफ को सांइटफिक सामान दे दिया है लेकिन जो लिखित जवाब दिया है उसमें लिखा है कि साधन जुटायें जा रहे है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कौन सी बात ठीक है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः हमारी बडी कम्प्रीहैन्सिव स्कीम है जिसमें काफी स्टाफ है। यह स्कीम पूरे हरियाणा मे लागू है। ट्रैफिक इनफोरसमैंट स्टाफ की नफरी में वृद्धि की जा रही है।

Mr. Speaker: Any way, I am sure that the Government is alive of the problem and is doing a lot. But at the same time I must convey to the Government the grave concern of the House and my own that 44 deaths have occurred in five months whjich means nine deaths per monthe. It is a very high figure. जहां तक मेरा अन्दाजा है ओवर क्राउडिंग और आवेर स्पीडिंग की वजह से ज्यादा एक्सीडैन्टस होते है। इनको रोकने के लिये सरकार की कोि ा ा होनी चाहिये।

Outstanding amount as Sales Tax

***2626. Chaudhri Ajit Singh:**Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there are firms/persons who have not paid Sales Tax so far in the State; if so, the district-wise names and addresses of the firms/ persons and details thereof;

(b) whether any steps have been taken so far in connection with therecovery of outstanding amount of sales tax, as referred to in part(a) above; if not, the manner in which the outstanding amount of sales tax is proposed to be recovered; and

(c) whether any persons have beenarrested in connection with therecovery of the outstanding amount of sales tax; if so, the names and addresses of such persons togetherwith the amount outstanding against each one of them?

आबकारी व कारधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) हां, जिलावार पंजीकृत फर्मों/व्यक्तियों, जिनसे 50000 रूपये था उससे अधिक बिक्री कर की राि ा देय है, के नाम व पतों की सूची सदन के पटल पर रखी जाती ह। उन व्यक्तियों के नाम, जिनसे देय बिक्री कर की राि ा 50000 रूपये से कम है, नहीं दिये जा रहे है क्योकि ऐा विवरण तेयार करने में जो समय ाऔर मेहनत लगेगी उसके मुकाबले में पर्यापत लाभ नहं होगा।

(ख) हां, हरियाणा सामान्य विकय कर अधिनियम, 1973 की धारा–34 के अन्तर्गत विकय करकी बकाया रा ि ा की भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जार रही है और वि ोश तौर पर क्षीण आर्थिक स्थिति के मामलों में बकायों की वसूली कि तों मे ंकी जा रही है।

(ग) हां, जिन चूक–कर्ता व्यक्तियों को बकायों की वसूली हेतू गिरुतार किया गया था उनके नाम व पतों, उनसे देय सेल्ज टैक्स की रा ि ा सहित, कीसूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची 1

उन उद्योगपति/व्यापारियों जिनके विरूद्ध 1–2–82 को सरकार को 50000 से अधिक बकाया रा ि ा की वसूली होनी है, के नामों तथा पतों को द ार्ाने वाली सूची।

कमांक	**उद्योगपति/व्यापारियों के नाम**	**बकाया रा ि ा**	
		हरियाणा सामान्य बिकी कर अधिनियम 1973 के अन्तर्गत	**केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत**

1	2	3	4
जिला अम्बाला			
1	मै0 एस0एस0 ओबराय एंड कम्पनी, हमे ापुर	71769	3447
2	मै0 लक्ष्मी फूड मैनुफैक्चरिंग एंड सप्लाई	628706	——
3	मै0 हरियाणा रोडवेज, अम्बाला	240543	——
4	मै0 मैं ईस्टर्न कर्मि ायल कारोरे ान पिन्जौर	45450	231605
5	मै0 ि ाव ट्रेंडिग कम्पनी, अम्बाला भाहर	119268	6074
6	मै0 सोलर रेडियोज, अम्बाला भाहर	50557	——
जिला भिवानी			
7	मै0 डी0डी0सी0.लि0 चरखी दादरी	3836829	1955337
8	मै0 अन्ती राम नन्द	270736	20093

	कि ारे, भिवानी		
9	मै0 रिण बैजीटेबल प्रोडक्टस, भिवानी	624412	....
जिला फरीदाबाद			
10	मै0 किलरेन इन्जीरियरिगं प्राव (लि0)	700	188488
11	मै0 हरियाणा स्टील लि0 मथुरा रोड, फरीदाबाद	86528	218903
12	मै0 इण्डिया स्टील कारपोरे ान, मथुरा रोड, फरीदाबाद	53263	109860
13	मै0 अतुल ग्लास इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	395846	924924
14	मै0 हरियाणा एजेन्सीज (प्रा0) लि0	2313630	570
15	मै0 हाडा स्टील प्रोडकअस लि0	227879	——
16	मै0स्टील पायनीरयरज,	125054	18716

	फरीदाबाद		
17	मै0 राजधानी पेन्टस ण्ंड कैमिकल्ज	71431	27155
18	मै0संजीवएन्टरप्राईजीज	104554	6502
19	मै0बरटन स्काट इन्टस्ट्रीज	26773	117841
20	मै0 उशा फोरजिंगज एण्ड स्टम्पिगज (प्रा0)	95460	108780
21	मै0 गंगा इन्जीनियरिंग वर्कस	29040	156988
22	मै0प्रैस्टोलाइट आफ इण्डिया	267148	3396668
23	मै0ग्लोब मोटर वर्कस	352172	106486
24	मै0 रैकमैन आटो वर्कस	396643	318964
25	मै0 रैकमैन को ाकिनज	110533	14731
26	मै0डी0जी0एल0 (प्रा0) लि0	11705	178772
27	मै0 फरीदाबाद मैन्यूफैंक्चरिगं इन्जीनियरिंग	21206	95570

28	मै0 बी0आर0 इन्जीनियरिंग	10511	113303
29	मै0 इन्डस्ट्रीयल एंड एलाइड प्रोडक्अस	––	52111
30	मै0 राजधानी इलैक्ट्रीकल्ज	75000	––
31	मै0 बुल रैकरज (प्रा0) लि0	7035	473526
32	मै0सैको इन्डस्ट्रीज	3139	123774
33	मै0टाप स्टाईल एपरलज	...	344587
34	मै0 हिन्दोस्तान इन्डस्ट्रीज	25794	56186
35	मै0 गने ा पैंकिग इन्डस्ट्रीज	92917	100040
36	मै0स्वदे ा रबड इन्डस्ट्रीज	45753	242941
37	मै0क्लच आटो लि0	...	633866
38	मै0 नैपको बावल गियर्ज आफ इण्डिया	13795	138902
39	मैं0 एच0एम0एम (प्रा0) लि0	85093	393191
40	मैं0 इन्सपी आटो इन्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0	59577	286214

41	मै0 हरियाणा फुटवियर	129830	215242
42	मै0 एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	1107691	......
43	मै0 इन्डियन गैस सिलेंडर	...	1070000
44	मै0 गोलडन पेालिएस्टर प्रा0लि0	30438	124868
45	मै0 फारमाचैंम लैबारेटरीज	62513	21745
46	मै0ग्लोब स्टील लिमिटड, बल्लभगढ़	1013202	938282
47	मै0 नार्दन इण्डियाआयरन एंड स्टील कम्पनी	537885	..
48	मै0 चन्द्रभान, एल02	303488	....
49	मै0 दिने ा वाईन भाप एल0 2	75775	.....
50	मै0 य ापाल एल0 2	308568	......
51	मै0बी0 आर0 गुप्ता एल0 2	163421	......
52	मै0जे0एन0 भार्मा एंड भान्ज	236870	284675
53	मै0एपलाईन्स मैन्युफैंक्चरिंग	166273	27797

	कम्पनी		
54	मै0ब्रंक लाइनिंग लि.	--	736770
55	मै0लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्कस	541031	712786
56	मै0फी व्हील इण्डिया	64423	--
57	मै0 ईस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स लि0	--	196996
58	मै0 इन्डियन हार्डवेयरज इन्डस्ट्रीज लि0	12171	55052
59	मै0 एसोसियेटिड स्टील इन्डस्ट्रीज (प्रा0)	190765	37317
60	मै0हिनदोस्तान ब्राउन बोवरी फरीदाबाद	--	1800096
61	मै0ओरिएन्ट इलैक्ट्रीकल्ज इनेले ान (प्रा0)	2433	95170
62	मै0 एक्सैक्लसियरज प्लान्ट (लि0)	15293	424586
63	मै0भारत कारपेटस लि0	--	642733

64	मै0 राणा ट्रेडिंग कम्पनी	157709	--
65	मै0लक्ष्मी ट्रेडिंग	558610	..
66	मै0 इलाईड ट्रेडिंग कम्पनी	939563	..
67	मै0परल साईकिल इन्डस्ट्रीज लि0	239341	1201630
68	मै0 यू0के0 बिल्डरज (प्रा0)लि0	7931	425861
69	मै0करूसिनल स्टील इन्डिया	18043	39785
70	मै0 सोभद्रा टैक्सटाईलज	64566	..
71	मै0 ब्रिस्टल पेन्टस	18	156612
72	मै0लिकर ट्रेडरज प्राईवेट लि0	112119	2782
73	मै0वैस्टैण्ड म ीनरी मार्ट	8300	56000
74	मै0 हरियाणा सेल्ज कारोपरे ान, पलवल	135306	..
75	मै0बनवारी लाल पर ोतम	30744	28574

	दास, फरीदाबाद		
76	मै0कृश्णा कैमिकल्ज प्राईवेट लि0	30974	26315
77	मै0 इन्डोजैम फारमौसयूटिकल्ज	3000	348838
78	मै0साहनी ब्रदर्ज, फरीदाबाद	98796	9361
79	मै0टैली साउण्ड इनिडया लि.	4794	442153
80	मै0करूसिबल स्टील इन्डिया	12645	47392
81	मै0गम ा पईप (प्रा0) लि0	74936	110582
82	मै0 बल्लभगढ कोआपरेटिव मार्किटिंग सोसायटी लि0 बल्लभगढ	68351	..
83	मै0 एस0पी0 ग्रामोफोनज एंड कं0	57000	..
जिला गुड़गांव			
84	मै0 बैगल एंड कार्टनजं	..	471616

85	मै0ईगो मैटल वर्कस	26647	151330
86	मै0गोल्ड फील्ड मैन्यू कं0	36403	61627
87	मै0 मारूति लि0	1959791	3506458
88	मै0 एन्ट्रा कैमिकलज प्रा0 लि0	58837	10
89	मै0निबरो लिमिटेड	15950	502823
90	मै0राही ट्रेडिं कारपेारे ान	306000	..
91	मै0विजय कुमार रोजेन्द्र प्रसाद	288377	238157
92	मै0मारूति हैवी व्हीकल्ज	595899	72005
93	मै0 मोहन लाल एल02 सोहना	73179	..
94	मै0ने ानल ड्रग्ज मैन्यू0 क0	18350	40963
95	मै0बजाज मैटल वर्कस	51000	29949
96	मै0दुर्गा रबड इन्डस्ट्रीज	34048	36165
97	मै0बी0टी0 रीफैक्ट्रीज	5681	81933

98	मै0हरियाणा रोडवेज, गुड़गावं	177373	..
जिला हिसार			
99	मै0 ि ाव दत्त राय फतेह चन्द, हिसार	..	70000
100	मै0रघुवीरचनद पत राम, हिसार	..	31000
101	मै0 नत्थूराम नेम चन्द, हिसार	52160	144416
102	मै0विजय कुमार मुनी ा कुमार, हिसार	67957	112835
103	मै0पदम कुमार संजय कुमार, हिसार	145231	151189
104	मै0करण पाल अनिल कुमार, हिसार	17544	72088
105	मै0हरियाणा कनकास्ट, हिसार	..	304277
106	मै0 कालू राम कि ाोरी	4442	49925

	लाल, हिसार		
107	मै0 मंगत राम राम अवतार, हिसार	54314	466452
108	मै0 सेठ का ी राम, कैमिकल्ज (इण्डिया) हिसार	173798	..
109	मै0 गोयल ब्रादर्स, हिसार	6668	485748
110	मै0 हरियाणा रोडवेज हिसार	123560	..
111	मै0 बिरला मिल्ज, जिनिंग प्रैसिंग फैक्टरी फतेहाबाद	388399	..
112	मै0देस राज सुखदेव, फतेहाबाद	..	75000
113	मै0गने ा ट्रेडिंग मम्पनी, बरवाला	..	53832
114	मै0बरवाला दाल मिल्ज, बरवाला	29203	44432
115	मै0जे0सी0 मिल्ज फैक्टरी, फतेहाबाद	284971	..

116	मै0गोपाल दास चन्द्र मोहन, आदमपुर	149420	4744
117	मै0सरदार सिंह जगत सिंह	74500	..
118	मै0भारत ट्रेडिंग कम्पनी, हिसार	..	63774
119	मै0 प्लांट प्रोजक ान इन्सपैक्टर, हिसार.	149729	..
जिला जीन्द			
120	मै0 भयाम दत्त एंड कं0 एल0–2 जीन्द	58075	..
जिला जगाधरी			
121	मै0 मैगो वाच कं0 यमुनानगर	84555	..
122	मै0 दोलत राम एण्ड सन्ज यमुनानगर	140000	..
123	मै0मुकन्द लाल भार्मा एंड कं. यमुनानगर	60000	..
124	मै0यू0सी0 ट्रेडरज,	83710	..

	यमुनानगर		
125	मै0 भगवान दास एंड कं0 जगारधरी	550859	34840
126	मै0आत्मा राम ज्ञान सिंह, जगाधरी	154492	..
127	मै0लक्ष्मी सिंह सोहन सिंह, जगारधरी	161951	128
128	मै0नेत्र सिंह दुर्गा सिंह, जगाधरी	86831	3344
129	मै0 पुनाईटिड टिम्बर इन्डस्टरीज जगाधरी	127813	..
130	मै0प्रेमदास पाहवा एंड कं0 जगाधरी	1151305	4877
131	मै0 श्रमिक मैटल प्रोडक ान कोपरेटिव इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि0 जगाधरी	56978	245
132	मै0किरण मैटल, इन्डस्ट्रीज	39429	23515

133	मै0 ांकर स्टील	60000	..
जिला करनाल			
134	मै0 गवर्नमेंट मैडिकल डिपों, करनाल	4130290	18296530
135	मै0गीताचावला एल0 2 करनाल	82834	..
136	मै0खोसला सैल्ज, जी0टी0 रोड करनाल	148731	..
137	मै0हरियाणा रोडवेज, करनाल	234941	..
138	मै0सोलेक ा आयल एंड फरटीलाईजर, जी0टी0 रोड करनाल	146050	..
139	मै011वैल्डवैल आर्क इलैक्ट्राडज करनाल	99164	44927
140	मै0नरे ा कुमार एंड कं0 एल–2 घरोंडा	89741	..
141	मै0कुन्दन लाल लाजीमल,	90000	..

	पानीपत		
142	मै0एस0के0 गांधी पानीपत	60335	60335
143	मै0नीलम बेकरी, पानीपत	60335	..
144	मै0करनाल डिस्टलरी, लिमिटिड, करनाल	117022	181040
145	जयकि ान जिन्दल, करनाल	107000	..
जिला कुरूक्षेत्र			
146	मै0हंस राज भगवान दास, कैथल	58303	..
147	मै0 हरियाणा रोडवेज, कैथल	113889	..
148	मै0 सन्त लाल टेकचन्द, कैथल	131455	..
149	मै0अवतार सिंह एंड कम्पनी	78822	..
150	मै0विनोद ऐ ाोसियेट लिमिटेड, कुरूक्षेत्र	87460	..

151	मै0 डिस्ट्रीक्ट फूड सप्लाई कन्ट्रोलर लाडवा	..	459244
152	मै0बलबीर सिंह जोगेनद्र सिंह एल02 लाईसैंसी पुन्डरी	58985	..
153	मै0 अजीत सिंह चीमा एंडकं0 एल–2	89605	..
154	मै0रजनी बोन मिल्ज, कैथल	446	51709
जिला नारनौल			
155	मै0 छोटे लाल चिरंजीाल, नारनौल	197622	..
156	मै0रामकि ान भयोचन्द, राय नारनौल	..	395245
157	मै0मर्चेंटस इण्डिया रिवाड़ी	163332	14107
158	मै0 महेन्द्र कूमार संजय कुमार रिवाड़ी	65486	..
159	मै0 त्रिखा राम राम	..	50000

	प्र ााद, रिवाडी		
160	मै0 सोनी इन्डस्ट्रीज रिवाड़ी	112186	95186
जिला रोहतक			
161	मै0मनोहर लाल सुरे ा चन्द महम	71866	54877
162	मै0रायल बोडी बिल्डर, रोहतक	305278	160649
163	मै0पाहवा बोटल सप्लाई कम्पनी, रोहतक	53784	122396
164	मै0एन0आर0 इन्डस्ट्रीज, बहादुरगढ	14004	274429
165	मै0टरोक्स फारमैंसी यूटीकल्ज,बहादुरगढ़	..	89300
जिला सोनीपत			
166	मै0 हरियाणा राईस ण्ड जनरल मिल्ज, गोहाना	104280	..
167	मै0डिपरी फूडज लिमिटिड	127517	1121739

	रायी		
168	मै0हरियाणा रबड इन्डस्ट्रीज सोनीपत	854951	1119861
169	मै0अ ाोक मोटर स्टोर, सोनीपत	483550	7644
170	मै0फन्डली इन्जनियंरिग (प्रा0लि0) कुन्डली	19930	127743
171	मै0देवासिया अबराहम एंडकम्पनी, कुन्डली	270956	60
172	मै0अबथ इन्डस्ट्रीज, सोनीपत	11383	73196
173	मै0कपूर रबड लिमिटिड सेनीपत	..	56937
174	मै0औरगनी कैमीकल इन्डस्ट्रीज, सोनीपत	11223	1142520
175	मै0 सूरज स्टील लिमिटिड, सोनीपत	1473659	85939
जिला सिरसा			

176	मै0 सिरसा इन्डस्ट्रीज सिरसा	297788	58780
177	मै0पदमावती राजे कोटन जिनिंग फैक्टरी सिरसा	231378	..
178	मै0भाखड़ा कोटन एंड जिनिंग फैक्टरी सिरसा	182249	..
179	मै0चौधरी कोटन जिनिंग प्रैसिंग फैक्टरी, डबवाली	155878	50086
180	मै0बैनी गोपाल महाबीरप्रसाद, सिरसा	128833	..
181	मै0गुप्ता एंड सन्ज, डबवाली	...	225391
182	मै0दुर्गा आयल एंड जनरल मिल्ज सिरसा	53194	..
183	मै0हरजी राम बलवन्त सिंह, सिरसा	164586	..
184	मै0गुप्ता काटन जिटिंग एंड प्रैसिंग फैक्टरी डबवाली	328283	..

185	मै0गोपी चन्द टैक्सटाईल मिल्ज, सिरसा	322067	2005597
186	मै0दीनानाथ सुभाश चन्द सिरसा.	119647	47981
187	मै0मित्तल एंड क0 सिरसा	..	101800
188	मै0हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी	..	92590
189	मै0रामनाथ मल्होत्रा, सिरसा	..	61552
190	मै0खेमजी विश्रामजी एंड सन्स, डबवाली	..	72748
191	मै0लक्ष्मण दास करतार सिंह, सिरसा	36965	87060
192	मै0मनोहर लाल राजकुमार, डबवाली	31148	23414
193	मै0सूरजा राम काटन जिलिंग प्रैसिंग फैक्टरी कलांवाली	288743	30293
194	मै0 योधन मल एंड कम्पनी, एलनाबाद	70000	..

195	मै0भारत कांटन कारपोरे ान, सिरसा	144138	61696

सूची II

गिरफ्तार किये गये व्यापारियों की सूची

कंसं0	फर्म / व्यक्ति का नाम तथापता	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का नाम	बकाया रा ि ।	
			हरियाणा सामान्य बिकी कर अधिनियम	केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम
1	**2**	**3**	**4**	**5**
जिला अम्बाला				
1	मै0 जवाहर लाल एल–2 पंचकुला	श्री जवाहर लाल	35000	..
2.	मै0 सोलर रेडियोज	श्री नरे । चन्द,	50557	..

	अम्बाला भाहर	हिस्सेदार		
जिला भिवानी				
—	—	—	—	—
जिला फरीदाबाद				
3	सुरे ा फाईन आर्टस फरीदाबाद	श्री विजय कुमार, हिस्सेदार गांव कुराल, बल्लभगढ़	3094	..
4	मैं0 नानक चन्द राम किशन, होडल	श्री रामकि ान पुत्र नाथीमल होडल, हिस्सेदार	19856	..
जिला गुड़गावं				
5	मै0 मोहन लाल एल–2	श्री मोहन लाल मलिक	73179	..

	सोहना			
जिला हिसार				
6	मैं0 करण पाल अनिल कुमार, हिसार	श्री करणपाल, हिस्सेदार	17544	72088
7	मैं0कालू रामकि ोरी लाल हिसार	श्री महावीर प्रसाद हिस्सेदार	4442	49925
8	मैं0मंगत राय राम अवतार हिसार	श्री पुनम चन्द हिस्सेदार	54314	466452
9	मैं0 बाला जी दाल मिल्ज हिसार	श्री गोपीराम हिस्सेदार	..	32367
10	मैं0हरियाणा साल्ट कम्पनी हिसार	श्री बनारसी दास मालिक हिसार	4635	..

11	मैं0 ांकर ट्रेडिंग कम्पनी		..	9724
12	मैं0राम लाल, भयाम सुन्दर, फतेहाबाद	श्री तेलू राम हिस्सेदार	26271	..
13	मैं0अग्रवाल एंड सन्ज हिसार	श्री बलबीर सिंह हिस्सेदार	16639	..
14	मैं0भारत ट्रेडिंग कं0 हिसार	श्री सती ा कुमार मालिक	..	63774
जिला जीन्द				
15	मैं0 तेलू राम निवास, उचाना	श्री सतपाल हिस्सेदार	39391	3058
16	मैं0रामचन्द्र रामे वरदास, जीन्द	श्री रामचन्द्र मालिक	30682	..

17	मैं0सु ील मैटल इन्स्ट्रीज जगाधरी	श्री ओमप्रका ा अग्रवाल, हिस्सेदार	3148	9136
18	मैं0 किरण मैटल इन्डस्टीज जगाधरी	श्री कृश्ण लाल, हिस्सेदार	229429	23512
19	मैं0बी0जी0 एंड क0 यमुनानगर	श्री बि ान स्वरूप हिस्सेदार	2384	..
20	मैं0हरियाणा बोटल स्टोर	श्री गुरदित्त सिंह, हिस्सेदार	46600	..
21	मैं0 महेन्द्र सिंह भाटिया	श्री महेनद्र सिंह मालिक	10857	771896
जिला करनाल				

22	मैं0 नरे ा कुमार एंड कं0 घरौंडा	श्री नरे ा कुमार, मालिक	89741	.'.
23	मैं0गीता चावला, एल–2 करनाल	श्री अजीत सिंह चीमा पार्टनर	82834	...
जिला कुरूक्षेत्र				
24	मैं0 बसेसर दयाल परवीन कुमार, कुरूक्षेत्र	श्री बसेसर दयाल पुत्र श्री छज्जू राम, थानेसर हिस्सेदार	9813	..
		श्री राधा कि ान पुत्र श्री दौलत राम, कुरूक्षेत्र हिस्सेदार		

जिला नारनौल				
–	–	–	–	–
जिला रोहतक				
25	मै0मोहन इन्डस्ट्रीज रेलवे रोड रोहतक	श्री ओम प्रका । मालिक मै0 मोहन इन्डस्ट्रीज रोहतक	36171	..
26	मै0सरन दयाल मेहता एल.2 रोहतक	श्री सरन दयाल मेहता हिस्सेदार	17200	..
27	मै0रायल बौडी बिल्डरज रोहतक	श्री श्रीयांज कुमार जैन हिस्सेदार	305278	160649
28	मै0माई धन सत नारायण	श्री माई धनुकर्ता	31260	..

	रोहतक			
जिला सिरसा				
–	–	–	–	–
जिला सोनीपत				
29.	मै0 जग्गा राम जय भगवान सोनीपत	री जय भगवान पुत्र श्री बिहारी लाल मालिक	47404	..

चौधरी अजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 195 आदमियों की और हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स बकाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ टोटल कितना रूपया बनता है। दूसरे जो आपने 195 में से 29 आदमी गिरफतार किये है। उनमें सीरियल नम्बर 134 पर मै0 गर्वनमैंट मैडिकल डिपो, करनाल की तरफ 41 लाख रूपया बकाया है, उसे गिरफतार नहीं किया लेकिन 29 आदमी जो गिरफतार किये है उनमें सीरियल नम्बर 17 पर मै0 सु ील मैटल इन्डस्ट्रीज जगाधरी जिसकी तरफ 12284 बनता है, उसे गिरफतार किया है। क्या कारण है कि जिसकी तरफ ज्यादा

रूपया बकाया था उसे गिरफतार नही किया और कम वाले को गिरफतार किया?

चौधरी मेहर सिंह राठी: यह करनाल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। दूसरे जो भी प्राइव्रेट लिमिटड कम्पनी होती है उनके भोयर होल्डर्ज होते है , उनकी लिमिटड लायबिलिटीज होती है। उन्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता। जिसका जितना भोयर होता है, उसके मुताबिक पेमैंट करते है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की फर्म है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः मंत्री महोदय बतायेगें कि 195 डिफालटर्ज मे से कितने आदमियों ने स्टे लिया हुआ है। जिन्होनें स्टे नहीं लियाहै क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और अगर की गई है तो वह क्या की गई है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: पांच करोड चालिस लाख के अमाउन्ट का लोगों ने स्टे लिया हुआ है। मेरे पास लिस्ट है। अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना देता हूं। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आपका कहना यह है कि आप बहुत जबरदस्त कार्यवाही कर रहे हो।

चौधरी मेहर सिंह राठी: बिल्कूल जी।

श्री अध्यक्ष: बजट में भी फाइनैंस मिनिस्टर महोदय ने यह बताया है कि रिकवरी अब पहले साल के मुकाबले में बहुत जयादा हो रही है। इसका मतलब यह है कि मंत्री महोदय बहुत जबरदस्त कार्यवाही कर रहे है। (ोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: हमें तो इनकी कार्यवाही बिल्कुल नजर नही आती।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह जबरदस्त कार्यवाही नहीं, जबरदस्ती कर रहे है।

श्री गुलजार सिंह: मंत्री महोदय का मन ा यह है कि छोटी–मोटी रकम, जिसमें 500 रूपये से लेकर 1000, 2000 या 10000 रूपये तक बकायाहै, के मामले बहुत ज्यादा है। मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों को तो अरैस्ट कर लिया जाता है लेकिन जिनकी तरफ लाखों रूपया बकाया पडा हुआ है, उनको कोर्टस के रस की वजह से गिरफतार नहीं किया जा सकता। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा रास्ता निकालेगें जिससे कि जिन आदमियों या कम्पनियों की तरफ लाखों रूपया बकाया पडा है, उनसे बकाया रा ि की रिकवरी जल्दी से जल्दी की जा सके? गरीबों से तो आप ही कर लेते है लेकिन अमीरों से नहीं करते।

चौधरी मेहर सिंह राठी: जैसे मैने बताया है कि जो बडी–2 रकम बकाया है, वह ज्यादातार ऐसी फर्मो की तरफ बकाया है जो प्राइवेट लिमिटड फर्में है। सैंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है

जिसके मुताबिक उनकी लायबिलिटी लिमिटड ही है। उसके मुताबिक ही हम उनसे वसूल कर सकते है। कोई अगर कोर्ट मे चला जाता है, तो हम क्या कर सकते है? यह कोई लट्ठमार हकूमत तो है नहीं कि गोली मार दो। अगर कोर्ट उनको स्टे दे दे तो हम क्या करे क्योंकि कोर्ट में हम इन्टरफीयर नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सवाल के पाट्र 'बी' के जवाब की आखिरी लाईन में कहा है–

"In hard cases instalments have also been allowed"

जिस इलाके में चार साल लगातार कहत पडता है, वहां पर तो यह सरकार किसान से रिकवरी करती हैचाहे वह तकावी कह हो, किसी लोन की हो या किसी दूसरे किस्म के ऋण हो। जिस इंडस्ट्रीयलिस्ट के खिलाफ इतना पैसा बकाया है, उसके बारे में आप यह कहते हो कि हार्ड केसजि में आप इनस्टालमेंट में भी उसको अलाउ कर देते हो। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस बात को तय करने के लिये कि यह वाकई हार्ड केस है। कौन सा पैमाना तय किया हुआ है जिसके तहत आप इन्स्टालमै।अस में अलाउ कर देते हो जबकि आप 500 रूपये की अमाउनट को भी एज एरिर्ज आफ लैंड रैवेन्यू वसूल करते हो, क्या इस बारे में मंत्री महोदय पोजी ान क्लैरिफाई करेगें?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिह जी तो यह चाहते है कि मुर्गी को खा लिया जाये। हम यह

कहते है कि पहले अण्डा खाओ। अण्डा खाओगें तो मुर्गी तो जिन्दा रहेगी और अण्डा फिर भी मिलता रहेगा। अगर मुर्गी ही मर गयी तो अण्डा कहां से मिलेगा। हमारा इन्सपैक्टर पहले जाता है , फिर ए0ई0टी0ओ0 जाता है, फिर ई0टी0ओ0 और फिर ई0टी0सी0 भी जाता है। अगर कहीं पर अडचन हो तो मै। खुद भी जाता हूं। हम वहां पर जाकर इस बात की कोि ा ा करते है कि हमारी रकम किसी न किसी तरह से निकल जाये। (व्यवधान एवं भाोर)

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो सूची इस सदन के पटल पर रखी है। उसमें इन्होने यह बताया है कि सेल्ज टैक्स की इतनी–2 रकम की चोरी इन–इन फर्मो ने की है। इसके अलावा कुछ लोगो को गिरफतार करने की बात भी कही गयी है। (व्यवधान एवं भाोर) वैसे तो चोरी ही है आप इसको बे ाक अपने भाब्दों में बकाया कह लो, यह आपकी अपनी मर्जी है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो बड़े–2 मगरमच्छ है , उनके खिलाफ इसलिये एक ान नही लिया जा रहा है क्योकिं वे सरकार को गाहे–बगाहे मदद करते रहते है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, यह चोरी का सवाल नहीं है, यह रूपया फर्मो की तरफ बकाया पडा हुआहै। हम तो जो पैसीबल कार्यावाही कर सकते है, कर रहे है। लेकिन कानून की इन्टरप्रैटे ान में या किसी दूसरी जगह पर हमारे अफसरों की भी गलती हो सकती है। वह जे0ई0टी0सी0 के पास

अपील करे, फिर ट्रिब्यूनल को अपील करे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाये, यह हर आदमी को डैमोक्रेसी में हम हासिल है। कोई भी आदमी किसी के फैसले को चैलेनज कर सकता हैं इनको छोडने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले हम गिरफतार नहीं करते थे तो जैन साहब यह कहते थे कि इनको गिरफतार क्यों नही करते। दो साल 6 दिन तक इनकी सरकार रही, इन्होने केवल 3 आदमी गिरफतार किये थे लेकिन हमने लगभग इतने ही अर्से में 17 आदमी गिरफतार किये है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, जो सूची मंत्री जी ने सदन के पटल पर रख है, उसमें सोनीपत की एक फर्म सूरज स्टील की तरु 1473659 रूपया हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का बकाया है यह एक बहुत बडी फर्मैं हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इनहोने यह उससे यह राि ा वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है। यह इतनी बडी फैक्टरी है। क्या इस फैक्टरी ने कोर्ट से कोई स्टे वगैरा तो नहीं ले रखा है या किसी दूसरी वजह से इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में थोडी सी पोजी ान क्लीयर करनाप चाहता हूं। यह सरकार हरियाणा में पहली सरकार है जिसने , जिस किसी भी उद्योगपति के खिलाफ बकाया राि ा खडी है, उसको एज एन्यिर्ज आफ लैंड रैवेन्यू वसूल करने का बाकायदा कानून बनाया है। (व्यवधान व भाोर) उसके तहत जैसे मंत्री महोदय ने बताया है,

हमने 17 आदमियों को जो बडे–बडे आदमी है, गिरफतार भी किया है और पूरी कार्यवाही कर भी रहे है। कुल बकाया रािा 12 करोड 82 लाख रूपये है जिससे से साढ़े आठ करोड रूपये के बारे में अदालतों से स्टे मिला हुआ है। (व्यवधान एवं भाोर) यह ठीक है कि साढे पांच करोड के बारे में अदालतो से स्टे मिला हुआ है। और 3 करोड रूपया बनता है जिसके बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरु से पूरी कार्यवाही की है। किसी के साथ भी किसी किस्म की रियायत करने को तो कोई सवाली ही पैदा नहीं होता। पहले यहां पर यह एतराज उठाया जाता था कि किसान, जिसकी तरु अगर 500 रूपये भी बकाया हो, तो उसे गिरफतार कर लिया जाता है लेकिन इन फैक्टरी वालों को गिरफतार क्यों नहीं किया जाता। हमने इस बारे में कार्यवाही की है। उनको अन्दर भी किया है। पहले जब तक उनकी लायबिलिटी बनती नही थी हम उनको पकडते नहीं थे। हमने इस बारे में कानून बनाया है। (व्यवधान एवं भाोर) आप सुनने की तो कृपा करे। हमने उसकी इम्पलीमैंटै ान भी की है। बाबू मूलचन्द जैन, सीनियर और पुराने मैंबर है। (व्यवधान एवं भाोर) आपके पास यह महकमा 2 साल 6 दिन तक रहा है और आप प्रानत के फाइनैंस मिनिस्टर भी रहे हो। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूलचन्द जैनः मैं तो 6 महीने ही रहा हूं। यह महकमा मेरे पास नहीं रहा है।

चौधरी भजन लालः चलो आपके पास नहीं रहा होगा। किसी दूसरे के पास रहा हेागा। मैं यह कहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसमें रिस्पौंसिबिलिजटी तो सब की सांझी होती है, जिम्मेदारी तो सब की इकटठी होती है। आपने जैसे मंत्री जी ने बताया आपने चौधरी देवी लाल जी की सरकार के दो साल 6 दिन के अर्से में केवल 3 आदमी गिरफतार किये। हमने सख्त से सख्त एक ान लिया है ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा वसूली हो सकती है। वह की जाये और इस बारे मे किसी से भी कोई रियायत नहीं बरती है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं । अगर कोई किसान अपने वक्त पर कर्जे की कि त न दे सके और उसकी मियाद पूरी हो जाये तो उससे सूद–दर–सूद चार्ज किया जाता है, क्या इसी तरह से इन फैक्टरी वालों से भी सूद–दर–सूद चार्ज किया जात है जिनकी तरु सेल्ज टक्स का रूपया बकाया है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः इनसे सूद तो हम 12 प्रति ात लेते है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, डालमिया सीमेंट फैक्टरी के खिलाफ हरियाणा जनललसेल्ज टैक्स का 38 लाख से जयादा रूपया बकाय पडा है। जब यह फैक्टरी बन्द हुई थी तो उसके मालिक ने सारा पैसा अपनी जेबों में डालकर इसको

दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था। आपको मालूम ही है कि इसके बाद इस फैक्टरी को सैंट्रल गवर्नमेंट ने टेक–ओवर करके फिर से चालू किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतनी बडी ध्नराि । को इस फैक्टरी की तरफ बकाया है वह किस प्रकार वसूल करेगें?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, हमने अपना क्लेम कमि नर आफ पेमेन्ट के पास दाखिल कर दियाहैं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकरसाहब, जो लिस्ट हाउस की टेबल पर रखी गई है उसमें अम्बाला रोडवेज और करनाल रोडवेज की तरफ टैक्स का पैसा बाकी दिखाया है और करनाल में ही गवर्नमेंट मैडीकल डिपों के अगेन्सट हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का 41 लाख 30 हजार और सैन्टर्ल सेल्ज टैक्स का 1 करोड़ 82 लाख रूपया बाकाया दिखायाहै। मतलब यह है कि अकेले मैडीकल डिपों के अगेन्स्ट दो करोड से भी जयादा रूपया सरकार का बकाया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि इन सरकारी एजेन्सियों के अगेन्स्ट टैक्स बकाया होने के कारण है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर सहाब, हमारी स्टेट की कारपोरें ांज के साथ बातचीत चल रही है और जो फर्म है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, इस स्टार्ड क्वै चन के साथ ही साथ इस बारे में मेरा एक अनस्टार्ड क्वै चन था। उस लिस्ट मे 132 आदमी ऐसे है जिनसे एक लाख से ज्यादा रूपया वसूल करता है और इनमें से केवल एक आदमी के खिलाफ ऐक्शन लियागया है, 131 आदमियो के खिलाफ ऐक ान नहीं लिया गया जबकि दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब ने लिखित जवाब में बताया है कि 29 आदमियों के खिलाफ ऐक ान लिया है। उनमें से 17 के खिलाफ गिरफतारी का ऐक ान लिया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि 131 आदमियों के खिलाफ ऐक ान न लेने का क्या कारण है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट में गये है। हर आदमी का अलग अलग केस है। ये मेरे कमरे में आ जाएं मै। इनको सारी बात समझा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पर मैने लिख कर हाफ एन आवर डिस्क्शन के लिये मांग की थी।

Mr. Speaker: I have not received it. When I receive it I will consider it. I will not be abe to give a reply just now. It it is in ordr, I will consider it. If not, I am sorry.

Electricity connections for tubewells

***2629. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any tubewell connections have been sanctioned recently in Rania Block of Distt. Sirsa; if so, their number;

(b) whether such connections were sanctioned after receiving due payment for the purpose;

(c) whether entries in respect thereof were duly made in teh official record; if not, the reasons therefor;

(d) whether the government has suffered any loss as a result of non-entry of the connections, referred to in part (a) above; and

(e) if so, the extent of loss suffered and the action; if any, taken or proposed to be taken against the officers/officials found responsible for such lapses?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) हां, सितम्बर, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान सिरसा जिला के रानिया ब्लाक के सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद 48 नं0 नलकूपों के कनैक ानों को स्वीकृति/जारी किया गया । निर्दिश्ट औपचारिकताओं कोपूर्ण किये बिना जारी किये गये । 158 नं0 कनैक ानों का सतर्कता कर्मचारियों द्वारा पता लगाया गया। बाद में इन को जुलाई तथा अगस्त 1981 के दौरान पूर्ण कराया गया तथा कनैक ानों का उचित हिसाब रखा गया।

(ख) हां, जुर्माने सहित देय राि ा वसूल की गई।

(ग) हां, सभी जारी किये गये कनैक ानों की प्रविशिटयां (एंटरीज) पहले ही कार्यालय अभिलेखा (रिकार्ड) में जा चुकी है।

(घ) नहीं, सभी दिये गये कनैक ानों को हिसाब (एकाउंट) में लाया जा चुका है तथा देय राि ा वसूल की जा चुकी है।

(ङ) यद्यपि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है फिर भी कनैक ान जारी करने से पहले औपचारिकताओं को पूरा न करने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, 210 कनैक ान ऐसे थे जो बिना इजाजत के चल रहे थे। मेरे कहने कामतलब यह है कि 210 कनैक ांज ऐसे थे जो नाजायज किस्म से चल रहे थे या चल रहे है और एच0एस0ई0बी0 का चीफ इंजीनियर वहां पर गया और उसने एक एस0डी0ओ0. को और एक ओवरसियर को मुअत्तिल किया लेकिन आगे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुर्ठ । स्पीकरसाहब, जो कनैक ांज नाजायज चल रहे थे उनकी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं की गई थी। रानियां बलाक में इस किस्म की बहुत हेराफेरी चल रही है। पांच लाख से लेकर पनद्रह लाख तक का घपला रानियां ब्लाक मे ंचल रहा है। इससे सरकार का भी नुकसान है और जमींदार का भी नुकसान है। क्या मंत्री

महोदय बताने की कृपा करेगें कि इस हेराफेरी को रोकन` के लिये वे कोई कार्यवाही करेगें?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैने अभी बताया है कि 158 केसिज इस किस्म क पकडे गये है जिनमें इररैगूलैरिटी थी। हमने एक एस0डी0ओ0 को सस्पैंड किया ओर एक जे0ई0 को चार्ज ीट किया हैं जैसे ही ये इररैगूलैरिटी हमारे नोटिस में आई हमने आफसरान को भेजा और वहां पर रेड किया। सारे इलाके में रेड किये गये और ये केसिज डिटैक्ट किये । हमने इन पर पैनेल्टी लगाई है। और पैनेल्टी इस ढंग से लगाई है कि जैसे टयूबवैल्ज के लिये सौलह रूपया पर–होर्स पावर हमारा फलैट रेट है। तो हमने उन पर पचास रूपया पर होर्स पावर पैनल्टी लगाई है। और यह उस दिन से लगाई है जिस दिन से टैस्ट रिपोर्ट दाखिल दफतर हुई है। और उस दिन तक जिस दिन तक यह कनैक ांज रैगूलर हुये। हमने इस तरह से सारे हरियाणा में रेड कराया है और तकरीबन एक करोड 75 लाख रूपया थ्रू पैनेल्टी के वसूल कियाहै। स्पीकर साहब, मैं हाउस को वि वास दिलाना ाहता हूं कि कोई भी आदमी या ओफिसर अगर कोई इररैगलैरिटी करेगा सरकार उसके खिलाफ ऐक ान लेगी।

Mr. Speaker: While I agree that the H.S.E.B. is doing a very difficult job and it is commendable के जो आदमी डिफाल्ट करते है उनके उपर आपने जुर्माना लगाया है और रूपया वसूल किया है। लेकिन 158 आदमियों को एच0एस0ई0बी0 ने

प्राईमा फैसाई बिजली की चोरी के जुर्म में गिलटी पाया है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैने पहले यही अर्ज कियाहै कि एस0डी0ओ0 को सस्पैंड किया है और जे0ई0 को चार्ज ीट किया है। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कवंरः स्पीकर साहब, जिस एस0डी0ओ0 को सस्पैंड किया गया था उसको तो बहाल कर दिया गया है। (ोर एवं व्यवधान)

सरदार तारा सिहः स्पीकर साहब, भागी राम जी कहते हैं कि एस0डी0ओ0 मेरा रि तेदार है, जो लोग पकडे गये है वे मेरे रि तेदार है। ऐसा ये पिछले सै ान में भी कहते थे। स्पीकर साहब, मेरा कोई रि तेदार नहीं है। मैं इन लोगो को जानता तक नहीं हूं। यह बिल्कुल गलत बात हजै, इसतमें कोई सच्चाई नही। मैं उन आदमियों को पहचानता तक नहीं हूं। जहां तक एक ान लेने की बात है, स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने 14 हजार 164 प्रिमिसिज पर रेड कराया और 1 करोड 97 लाख रूपया ऐज पैनेल्टी रिकवर किया। 1719 केसिल थेफट के पाये है और 263 डिपार्टमेंटल कर्मचारियों के खिलाफ एक ान लिया है। 158 केसिज इस किस्म के पकड़े है जिनमें इररैगुलैरिटी थी। स्पीकर साहब हम रात–दिन कोि ा ा कर रहे है कि कोई इररैगुलैरिटी न हो। हम किसानों को भी कहते है कि अगर आप

कम्रचारियों के साथ मिलते हो तो सरकार का और बोर्ड का नुकसान तो होता ही है लेकिन साथ में आपका भी नुकसान होता है। स्पीकर साहब, मैं सदन को वि वास दिलाता हूं कि बोर्ड किसी भी आदमी को प्रौटेक ान नहीं देगा।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस केस में जिस एस0डी0ओ0 को सस्पैंन्ड किया था क्या वह बहाल कर दियागयाहै या नही? दूसरा इस केस मे जो 10 और 15 लाख रूपये का घोटाला बताया जाता है क्या वह सही है?

सरदार तारा सिंहः पहली बात जो आनरेबल मेंबर ने कही कि 15 लाखरूपये का इस केस में घोटाला है। यह बिल्कुल बेसलैस बात कही गयी है। इनरैगलैरेटी सिर्फ इतनी हुई कि एक कंजूमर ने टैस्ट रिपोट्ट दी, ओर उसका नम्बर दो या ढाई महीने के बाद आना था लेकिन ए0डी0ओ0 ओर जे0ई0 ने मिल कर उस कंजूमर को पहले कनेक ान दे दिया। मैं इनकी यह बात मानता हूं कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी इनरैगलैरेटी करते वक्त जरूर कुछ न कुछ इल्लीगल ग्रेटीफिके ान लिया होगा लेकिन हमने उस आदमी के खिलाफ ऐक ान ले लिया है , उसे चार्ज ाीट कर दिय गयाहै और उसके खिलाफ केसजि भी बनाये गये हैं स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समय इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में लगभग 36 हजार के करीब स्टैट मे इम्पलाईज है और इतनी बडी एस्टैबलि ामेंट को कंट्रोल करना

कोई आसान बात नहीं है। चाहे कोई भी सरकार या आ जाये इस तरह के छोटे मोटे केसिज हो ही जाते है। कोइ भी आदमी दूध का धोया नहीं होगा, जब हमारे नोटिस में यह बात आई है। हमने फौरी एक ान लियाहै और आगे के लिये भी ऐसे कर्मचारियो/अधिकारियों पर तुरन्त ऐक ान लिया जायेगा, किसी को छोडा नहीं जाएगा। स्पीकर साहब, जहां तक एस0डी0ओ0 के सस्पेन् ान की बात है, सुबह मेरी सूचना के अनुसार, वह सस्पैंडिड है। उसे चार्ज ाीट कर दिया गया है और अाी तक उस का जवाब नहीं आया है।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनकी नालेज में यह बात है कि कुरूक्षेत्र और हरियाणा में दूसरी जगहों पर इसी तरह के केसिज हुये है ओर क्या उनके खिलाफ कोई ऐक ान लिया गया है या नहीं?

श्री अध्यक्षः इन सप्लीमैंटरी का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है, इसके लिये अलग से नोटिस चाहीये। यह प्रश्न तो केवल रानियां ब्लाक से संबंधित था।

कामरेड भाकंर लालः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगें कि क्या यह तथ्य है कि तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों को सस्पैंड किया गया है और उन पर फौजदारी मुकदमें बनायें गये है? क्या इन कर्मचारियों के इलावा कोंई और

उपर के अधिकारी भी भाामिल है, जिनको सस्पैंड किया गयाहो और उन पर फौजदारी मुकदमें बनाये गये हो?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साह,ब इसके लिये सेपरेट नोटिस देगें तो बता दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पश्ट कर देता हूं कि एस0डी0ओ0 और जे0ई0 दोनों सस्पैंडिड है। एक्सीअन के खिलाफ हम इंकवायरी करवा रहे है, उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसे केसिज में नर्मी नहीं बरती जायेगी और जिस किसी अधिकारी या कम्र्चारी का फाल्ट मिलेगा, उसको माफ नहीं किया जायेगा।

Construction of Bus-stand at Uklana Mandi

***2866. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the progress so far made in teh construction of Bus-=Stand at Uklana Mandi; and

(b) the number of bus queue shelters constructed in Barwala constituency so far, together with the location thereof?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जगह का चयन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रयत्न जारी है।

(ख) भाून्य।

श्री जयनारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैने अपने सवाल के पार्ट ''बी'' में यह पूछा था कि बरवाला निर्वाचन–क्षेत्र में अब तक कितने बस–क्यू भौल्टरों का निर्माण किया गया है तथा वे कहां–2 पर स्थित है तो मंत्री महोदय ने इसका जवाब दिया कि भाून्य। कहने का मतलब यह है कि कोई नहीं बनाया हैं इसलिये मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चहाता हूं कि सारी स्टेट के अन्दर कितने बस–क्यू भौल्टर बने है और इन के अपने हल्के में कितने बने और आदमपुर में कितने बनाये गये? दूसरा मेरा सप्लीमेंटरी मेरे सवाल के पार्ट ''ए'' से संबंधित है जिसक`उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उकलाना मंडी में बस–अड्डे के निर्माण हेतू जगह का चयन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रयत्न जारी है। ''प्रयत्न' भाब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मंत्री महोदय का कश्ट करेगें?

श्री जगरनाथ: स्पीकर साहब, वर्मा साहब ने अपनी सप्लीमैंटरी के पहले भाग में यह पूछा है कि सारी स्टेट में कितने बस–क्यू भौल्टर बनाये गये है। इस वक्त सारी स्टेट के आकंडे तो

मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वैसे स्पीकर साहब, ये विधायक अपने हल्के में तो रहते ही नहीं है। वम्र साहब तो हर वक्त हिार में ही घूमते रहते है। सुशमा जी दिल्ली रहती है। वर्मा साहब, जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त दो अढाई साल हमारे साथ रहे। उस वक्त भी यह विभाग मेरे पास था। अगर इनहें सचमुच अपने हल्के का ख्याल होता तो उस समय यह इन बातों का कभी न कभी जिक्र अव य करते। कभी मुझे कहते या चीफ मिनिस्टर साहब को कहते। लेकिन इन्होने कभी भी मुझे इस बारे में लिखित रूप में भी नहीं दिया। ये स्वयं तो ऐसे कामों को करवाने के हक में नहीं है, औ न ही थे। इन्होनें कभी यह नहीं हमे कहा कि मेरे हल्के में बस–क्यू भौल्टर्ज का निर्माण किया जाए। कभी ऐसी बात इन्होने कह ही नही। (ाोर एंव व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बडे दुख की बात है कि सरकार जवाब देने की बजाये यहां हाउस मे ंयह कहे कि मैबरसाहेबान उनको कीाी डिवैल्पमेंट के काम के बारे में उनके पास आकर नहीं कहते। यह उनका जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमैटरी का जवाब उनसे दिलवाया जाना चाहिये। मेरे प्र न का जवाब ही नहीं आया है। (ाोर एवं व्यवधान) मैने उनसे पूछा था कि उनके अपने हल्के में कितने बस–कू भौल्टर बने है, आदमपूरी के कितने बने है और मेरे हल्के में कितने बने है? ऐसा भेदभाव अपोजी ान के एम0एल0एज0 के हल्कों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या

वहां पर रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते है? क्यावे लोग इंसान नहीं है? बवानी खेडा के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार और बरवाला क्षेत्र के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः वर्मा साहब, आप सवाल पूछिये। (ोर व व्यवधान) मिनिस्टर साहब ने आपके सवाल के जवाब में कहा है कि इस वक्त सारी स्टेट के आंकडे उनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिये आप सैपरेट नोटिस दे। अगर आपको बवानीखेड़ा, बरवाला, आदमपुर वगैरह या दूसरी जगहों के बारे में सूचना चाहिये थी तो आपको पहले ही अपने सवाल में मैं ान कर देना चाहिये था।

श्री बीरेन्द्र सिंहः मिस्टर स्पीकर सर, सप्लीमैंटरी पूछने का मतलब ही यही है। अगर माननीय सदस्य पहले ही अपने सवाल में इन सारी बातों का जिक कर देते तो फिर सप्लीमेंटरी का मतलब ही क्या रह जाता है। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के पास, इनकी फाइल का सारीा जवाब है, वह फाइल पढ़कर जवाब नहीं देंना चहाते। अगर ये मुझे फाइल दे दे तो मैं पढ़कर बता सकता हूं। ये जवाब देना ही नहीं चाहते ।(ोर व व्यवधान)

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार किसी भी हल्‘के के सथ चाहे वे अपोजी ानके मैंबरों का हल्का हो, चाहे रूलिगं पार्टी के मैंबरों

का हल्का हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगी और सब के साथ यकसां सलूक यिका जा रहा हैं मैंबर साहब का यह कहना बिलकूल गलत है कि उनके हल्के के लोगों के साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। हमने यमुनानगर, हांसी , गोहाना ,पलवल जोकि अपोजी ान के हल्के है,में डिपोज बनाये है। सब के साथ यंकसा व्यवहार यिा है।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैंबर्ज, मैं मंत्री जी की बात को मानता हूं और वर्मा साहब को चयह चाहिये था कि वे सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखते कि उनके हल्के में डिवेल्पमेंअ का काम नहीं हो रहा है लेकिन वर्मा साहन ने मिनिस्टर साहब के कहने कू मूताबिक, सरकार को इसबारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया है। हरेक एम0एल0ए0 का यह फर्ज बनता है कि वे अपने–2 हल्कों की डिवैलपमेंट के बारे में सरकार को लिखे कि उनके हल्के में डिवैलपमेंट का काम बडा स्लो हो रहा हैं वर्मा साहब को भी इस बारे में मिनिस्टर साहब का लिखना चाहिये था।

श्री जयनारायण वर्माः स्पीकर साहब, हमने तो इसी संबध में प्रश्न पूछा है लेकिन हमारे सवाल का सही उत्तर नहीं दिया जाता।

श्री जगननाथः स्पीकरसाहब, मेने तो किसी भी हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता हैं गोहान, हांसी यमुनानगर जोकि अपोजी ान के हल्के है, वहां पर भी बस–स्टैंण्ड बनाये गये है।

पलवल में ीाी इस तरह के तरक्की के काम किये गये है। पूरी स्टेट के बारे में अगर ये पूछते तो हम बता देते। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Acquisition of land for allotment of residential plots to Harijans

***2894. Shri Ishwar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to acquire land for the allotment of residential plots to Harijans near the villages where the Village Panchayats have no land or have land far away from the villages in the State?

Revenue Minister (Chaudhri Sher Singh): Yes please.

Constructioin of Bridge over River Yamuna

***2616. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Public Workds (B & R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to construct a bridge in district Karnal over river Yamuna to link Haryana with Uttar Pradesh; and

(b) if so, the exact site where such bridge is proposed to be constructed , together with the time by which constrcution work in respect thereof is likely to be started.

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) जी हां।

(ख) इस पुल की साईट हरियाणा तथा उत्तर प्रदे । सरकार द्वारा आपसी सहमति से तय की जायेगी क्योंकि इस कार्य का खर्चा 50 : 50 अनुपात में उत्तर प्रदे । सरकार के साथ बांटे जाने का विचार है। उत्तर प्रदे । सरकार द्वारा पुल के खर्च की बांट की लिखित सहमति अभी आनी है। असके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा कर्ज दिये जाने की सहमति भी अभी अपेक्षित है। इन कारणों द्वारा इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पुल की साईट क्या होगी या निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा।

Construction of Roads in the State

***2713. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Public Workds (B & R) be pleased to state-

(a) the constituency- wise length of roads constructed since the date Shri Bhajan Lal took over as Chief Minister of the State; and

(b) the constituency-wise expenditure incurred thereon?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) व (ख) वांछित सूचना विवरणी में सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

Constituency-wise length of road constructed and expenditure incurred thereon since Shri Bhajan Lal took over as Chief Minister, Haryana i.e. from 28-6-1979 to 28-2-1982.

S.N.	Name of Constituency	Name of M.L.A.	Total and length (constructed i.e. metalled)KM	Total expenditure incurred on these roads (from 7/79 to 28-2-82) Rs. in lacs.
1	2	3	4	5

I. AMBALA DISTRICT				
1	Kalka	Sh. LachmanSingh	54.48	118.99
2	Naraingarh	Sh. Lal Singh	60.54	5931
3	Sadhaura	Sh. Bhag Mal	66.89	62.95
4	Chhachharauli	Sh. K.L. Poswal	51.21	58.21
5	Jagadhri	Sh. Brij Mohan	27.08	34.45
6	Yamuna Nagar	Smt. Kamla Verma	11.15	11.85
7	Mullana	Sh. Sher Singh	19.09	26.14
8	Ambala Cantt.	Smt. Sushma Swaraj	--	--
9	Ambala City	Sh. Shiv Parshad	3.87	7.86
10	Naggal	Sh. Sumer Chand	33.83	37-86
Total			**328.14**	**417.58**
II. KARNAL DISTRICT				

11	Indri	Sh. Des Raj	22.85	25.02
12	Nilokheri	Sh. Shiv Ram Verma	19.91	23.42
13	Karnal	Sh. Ram Lal Wadhwa	3.17	6.05
14	Jundla	Sh. Prem Singh	53.41	83.41
15	Gharaunda	Sh. Ram Pal Singh	67.54	113.31
16	Assandh	Sh. Jogi Ram	68.09	102.26
17	Panipat	Sh. fateh Chand	--	1.11
18	Samalkha	Sh. Mool Chand Jain	16.50	29.74
19	Naultha	Sh. Satbir Singh	35.09	43.61
Total			**286.56**	**427.93**
III. KURUKSHETRA DISTRICT				
20	Shahbad	Sh. Surinder Singh	18.17	23.26
21	Radaur	Sh. Lehari Singh	68.61	89.67

22	Thanesar	Sh. Devinder Singh	13.84	18.12
23	Pehowa	Sh. Tara Singh	30.69	35.59
24	Guhla	Sh. Ishwar Singh	40.06	67.39
25	Kaithal	Sh. Raghu Nath Goel	22.08	17.52
26	Pundri	Swami AgniVesh	33.87	44.82
27	Pai	Sh. Jagjit Singh Pohloo	12.09	12.28
Total			**248.41**	**308.65**
IV. ROHTK DISTRICT				
28	Hassangarh	Sh. Sant Kanwar	9.63	14.53
29	Kiloi	Sh. HariChand Hooda	3.70	4.80
30	Rohtak	Sh. MangalSein	--	--
31	Meham	Sh. HarSwarup	7.69	14.76

		Bura		
32	Kalanaur	Sh. jai Narain	12.87	22.44
33	Beri	Sh. Ajit Singh	17.84	22.81
34	Salhawas	Sh. Ram Narain	23.70	25.57
35	Jhajjar	Sh. Mange Ram	30.77	37.95
36	Badli	Sh. Udey Singh Dalal	22.68	28.74
37	Bahadurgarh	Sh. Mehar Singh Rathee	19.76	31.80
	Total		**148.64**	**203.40**
V. SONEPAT DISTRICT				
38	Baroda	Sh. Bhale Ram	10.15	9.71
39	Gohana	Sh. Ganga Ram	7.65	6.40
40	Kailana	Smt. Shanti Devi	18.08	22.47
41	Sonepat	Sh. Devi Dass	2.10	3.33
42	Rai	Sh. Rizaq Ram	13.09	17.45

43	Rohat	Sh. Om Parkash	8.63	12.43
	Total		**59.70**	**71.82**
VI. JIND DISTRICT				
44	Kalyat	Sh. Preet Singh	16.60	33.49
45	Narwana	Sh. Shamsher Singh	18.06	22.79
46	Uchanan Kalan	Sh. Birinder Singh	5.79	9.76
47	Rajound	Sh. Guljar Singh	7.10	8.83
48	Jind	Mange Ram	8.64	29.33
49	Julana	Sh. Zile Singh	16.93	19.07
50	Safidon	Sh. Ram Kishan	10.60	20.97
	Total		**83.72**	**144.24**
VII. FARIDABAD DISTRICT				
51	Faridabad	Sh. Deep Chand	-	--
52	Mewla	Sh. Gajraj	20.50	48.16

	Maharajpur	Bahadur Nagar		
53	Bllabgarh	Sh. Rajinder Singh	5.03	11.64
54	Palwal	Sh. Mool Chand Mangla	16.55	22.43
55	Hassanpur	Sh. Gaya Lal	21.99	27.05
56	Hathin	Swami AgniVesh	14.32	22.87
	Total		**78.39**	**132.15**
VIII. GURGAON DISTRICT				
57	Ferozepur Jhirka	Sh. Shakrullah Khan	17.00	27.57
58	Nuh	Sh. Sardar Khan	22.79	10.63
59	Taoru	Sh. Khurshid Ahmed	22.99	31.58
60	Sohna	Sh. Vijay Pal Singh	44.14	74.08
61	Gurgaon	Sh. Partap Singh	6.01	10.21

		Thakran		
62	Patuadi	Sh. Narain Singh	26.30	33.38
	Total		**139.23**	**187.45**
IX. BIWANI DISTRCIT				
63	Bhadra	Sh. Ran Singh Mann	10.59	9.30
64	Dadri	Sh. Hukam Singh	-	1.07
65	Mundhal Khurd	Sh. Tek Ram	5.55	7.30
66	Bhiwani	Sh. Bir Singh	1.88	2.07
67	Tosham	Sh. SurinderSing h	4.20	3.44
68	Loharu	Sh. Hira Nand Arya	5.84	7.29
69	Bawani Khera	Sh. Jagan Nath	29.44	44.40
	Total		**57.50**	**74.87**
X. HISSSAR DISTRICT				
70	Barwala	Sh. Jai	18.39	26.54

		Narain		
71	Narnaud	Sh. Virender Singh	11.81	12.07
72	Hansi	Sh. Baldev Tayal	7.82	11.67
73	Bhatu Kalan	Sh. Ran Singh	39.43	66.07
74	Hissar	Sh. Balwant Rai	0.82	1.38
75	Ghirai	Sh. Kanwal Singh	23.08	21.47
76	Tohana	Sh. Karam Singh	22.57	29.88
77	Ratia	Sh. Peer Chand	46.86	56.61
78	Fatehabad	Sh. Harphul Singh	50.62	90.83
79	Adampur	Sh. Bhajan Lal	93.77	157.44
	Total		**315.17**	**473.96**
XI. SIRSA DISTRICT				
80	Dabra Kalan	Sh. Jagdish	49.33	63.56

		Kumar		
81	Ellanabad	Sh. Bhagi Ram	76.26	111.45
82	Sirsa	Sh. Shankar Lal	23.79	32.35
83	Rori	Sh. Sukhdev Singh	41.79	56.86
84	Dabwali	Sh. Mani Ram	30.43	32.54
	Total		**221.60**	**296.76**
XII. MAHENDERGARH DISTRICT				
85	Bawal	Smt. Shkuntla Bhagwaria	28.50	30.62
86	Rewari	Sh. Ram Singh	17.81	26.36
87	Jatusana	Sh. Inderjit Singh	28.09	22.53
88	Mahendergarh	Sh. Dalip Singh	24.19	20.27
89	Ateli	Sh. BansiSingh	7.77	7.54
90	Narnaul	Sh. Phusa	3.44	2.65

		Ram		
	Total		109.80	109.97
	Grand Total		**2076.86**	**2848.78**

4th Afro-Asian Regional conference of I.C.I.D.

***2732. Shri Satvir singh Malik:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any Chief engineers of the Irrigation Department, Haryana submitted anypaper in the 4th Afro-Asian regional Conference of I.C.I.D.; if so, their number togetherwith the number of those whose papers were accepted; and

(b) the number of Chief Engineers who applied to the Government for attending the said Conderence together with teh names of those granted permission?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(ए) जी हां, श्री आर0के0 चौधरी, मुख्य इंजीनियर, एस0वाई0एल0 सिंचाई विभाग, हरियाणा तथा सर्व श्री जगमान सिंह और आर0एन0 पण्डित मुख्य इंजीनियरज, सिंचाई विभाग, हरियाणा जो हरियाणा राज्य लघु सिचाई एवं नलकूप निगम में बतौर प्रबन्ध निदे ाक तथा मुख्य इंजीनियर कंम ाः प्रतिनियुक्त पर था/है, ने अपने पत्र (4th Afro-Asian RegionalConference of ICID) को भेजे थे और कान्फैस ने उनहें स्वीकार कर लिया था।

(बी) उक्त (ए) में वर्णित अधिकारियों ने कान्फ्रैंस में जाने की आज्ञा मांगी थी। 2, सर्व श्री जगमान सिंह तथा आर0एन0 पण्डित को कान्फ्रैस में जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

Constituencywise roads Constructed during 1981-82

***2739 Rao Bansi Singh:** Will the Minister for Public workds (B & R) be pleased to state the distrcit-wise and constituency-wise kilometers of roads constructed during the year 81-82 (upto 28- 2-1082) in the State?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): वांछित सूचना विवरणी में सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

A- Districtwise length of roads constructed during 1981-82 (upto 28-2-1982)

S.N.	Name of District	Length in Kms. Constructed (metalled) during 1981-82 upto 28-2-1082
1	Ambala	35.84
2	Karnal	107.52
3	Kurukshetra	29.89

4	Rohtak	26.20
5	Sonepat	20.92
6	Jind	21.14
7	Faridabad	12.98
8	Gurgaon	8.85
9	Bhiwani	36.90
10	Hissar	106.93
11	Sirsa	37.55
12	Mahendergarh	17.65
	Total	**462.37**

B. Constituency-wise length of Roads constructed during 1981-82 (upto 28-2-1982)

S.N.	**Name of constituency**	**Nmae of M.L.A.**	**Road lengthj (in K.M.) completed during 1981-82 upto 28-2-1982**
1	Kalka	Sh. Lachhman Singh	7.55
2	Naraingarh	Sh. Lal Singh	4.63

3	Sadhaura	Sh. Bhag Mal	2.82
4	Chhachhrauli	Sh. Kanhiya Lal Poswal	7.63
5	Jagadhri	Sh. Brij Mohan Gupta	1.35
6	Yamunagar	Smt. Kamla Verma	--
7	Mullana	Sh. Sher Singh	4.29
8	Ambala Cantt	Smt. Sushma Swaraj	--
9	Ambala City	Sh. Shiv Prashad	--
10	Naggal	Sh. Sumer Chand Bhatt	6.57
11	Indri	Sh. Des Raj	4.70
12	Nilokheri	Sh.Shiv Ram Verma	4.08
13	Karnal	Sh. Ram Lal Wadhwa	1.50
14	Jundla	Sh. Prem, Singh	25.28

15	Gharauda	Sh. Ram Pal Singh	23.85
16	Assandh	Sh. Jogi Ram	33.69
17	Panipat	Sh. fateh Chand Vij	--
18	Smalkha	Sh. Mool Chand Jain	3.60
19	Naultha	Sh. Stavir Singh Malik	10.82
20	Shahbad	Sh. Surinder Singh Aujla	2.12
21	Radaru	Sh. Kehri Singh Mehra	2.50
22	Thanesar	Sh. Devender Sharma	3.00
23	Pehowa	Sh. Tara Singh	--
24	Gulha	Sh. Ishwar Singh	2.72
25	Kaithal	Sh. Raghu Nath Goel	3.00
26	Pundri	Sh. Agnivesh	12.98

27	Pai	Sh. Jagit Singh Pohloo	3.57
28	Hassangarh	Sh. Sant Kanwar	4.90
29	Kiloi	Sh. Hari Chanda Hooda	--
30	Rohtak	Sh. Mangala Sein	--
31	Meham	Sh. HarSwarup Bura	2.19
32	Kalanaur	Sh. jai Narain	3.79
33	Beri	Sh. Ajit Singh	1.70
34	Salhawas	Sh. Ram Narain	-
35	Jhajjar	Sh. Mange Ram	0.80
36	Bdli	Sh. Udey Singh Dalal	-
37	Bhadurgarh	Sh. Mehar Singh Rathee	12.82
38	Broda	Sh. Bhale Ram	4.50

39	Gohana	Sh. Ganga Ram	-
40	Kailana	Smt. Shanti Devi	7.67
41	Sonepat	Sh. Devi Dass	-
42	Rai	Sh. Rizaq Ram	6.03
43	Rohat	Sh. Om Parkash	2.72
44	Kalayat	Sh. Preet Singh	1.85
45	Narwana	Sh. Shamsher Singh	6.26
46	Uchana Kalan	Sh. Birinder Singh	-
47	Rajound	Sh. Gulzar Singh	1.33
48	Jind	Sh. Mange Ram	-
49	Julana	Sh. Zile Sigh	8.40
50	Safidon	S. ram Kishan	3.30
51	Faridabad	Sh. Deep Chand Bhatia	-

52	Mewla Maharajpur	Sh. Gajraj Bahadur Nagar	5.72
53	Ballabhgarh	Sh. Raninder Singh	1.93
54	Pawal	Sh. Mool Chand Mangla	0.36
55	Hassanpur	Sh. Gaya Lal	1.08
56	Hathin	Sh. Adiya Vesh	3.00
57	Ferozepur Jhirka	Sh. Shakrullah Khan	-
58	Nuh	Sh. Sardar Khan	3.50
59	Taoru	Sh. Khurshid Ahmed	-
60	Sohna	Sh. Vijay Pal Singh	2.95
61	Gurgaon	Sh. Partap Singh Thakran	-
62	Patuadi	Sh. Narain Singh	2.40

63	Bahdra	Sh. Ran Singh Mann	7.79
64	Dadri	Sh. Hukam Singh	-
65	Mundhal Khurd	Sh. Tek Ram	5.55
66	Bhiwani	Sh. Bir Singh	1.38
67	Tosham	Sh. SurinderSingh	-
68	Loharu	Sh. Hira Nand Arya	2.40
69	Bawani Khera	Sh. Jagan Nath	19.78
70	Barwala	Sh. Jai Narain	8.20
71	Narnaund	Sh. Virender Singh	2.02
72	Hansi	Sh. Baldev Tayal	3.32
73	Bhattu Kalan	Sh. Ran Singh	22.01
74	Hissar	Sh. Balwant Rai	--
75	Ghirai	Sh. Kanwal	8.50

		Singh	
76	Tohana	Sh. Karam Singh	-
77	Ratia	Sh. Peer Chand	10.10
78	Fatehabad	Sh. Harphul Singh	15.03
79	Adampur	Sh. Bhajan Lal	34.30
80	Dabra Kalan	Sh. Jagdish Kumar	6.70
81	Ellanabad	Sh. Bhagi Ram	11.44
82	Sirsa	Sh. Shankar Lal	5.89
83	Rori	Sh. Sukhdev Singh	10.63
84	Dabwali	Sh. Mani Ram	6.34
85	Bawal	Smt. Shkuntla Bhagwaria	6.10
86	Rewari	Sh. Ram Singh	4.80

87	Jatusana	Sh. Inderjit Singh	1.80
88	Mahendergarh	Sh. Dalip Singh	4.35
89	Ateli	Sh. BansiSingh	0.60
90	Narnaul	Sh. Phusa Ram	-
	Grand Total		**462.37**

Road from Kalanaur to Pilana in Distcit Rohtak

***2909. Chaudhri Jai Narain:** Will the Minister for Public works (B & R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Kalanaru to Pilana in Distrcit Rohtak; if so, the time within which it is likely to be constructed; and

(b) the names of roads in Kalanaur constituency on which earthwork has been done?

लोक निर्माण मंत्री (कवंर राम पाल सिंह):

(क) जी हां, किन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(ख)कलानौर विधान सभा क्षेत्र की उन सड़को के नाम जिन पर मिट्टी का काम पूरा हो गयाहै, विवरण में दिय है जो कि विधान सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

List of Roads of Kalnaur constituency on which earth wrk has been done:-

Sr. No.	Name of the road
1	Kalanaur to Nigana.
2	Garhi Ballabh to Patwapur,
3	Mokhra Khas to Kalanaur.
4	Basana to Meham
5	Bahu Akbarpur to Samargopalpur.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Foundation stones laid by the Chief Minister

650. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number and names of the projects whose foundation stones have been laid by teh present Chief Minister since he took over as such together with the dates on which teh said foundations stones were laid, separately;

(b) the names of projects as referred to in part (a) above, which have started functioning (to-date) togetherwith the dates these started functioning, separately; and

(c) whether there are any projects which have not yet started functioning; if so, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क), (ख) व (ग) अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे सभी सरकारी विभागों से एकत्रित करना होगा। लगभग तीन वर्श की अवधि के बारे में ऐसी ब्यौरवार सूचना एकत्रित करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम उससे प्राप्त हो सकने वाले किसी लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

Foundation stones for the construction of Middle and High Schools

651. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the distrcit-wise and year-wise total number of foundation stones laid for the construction of Middle and High Schools in the State during the period from Ist April, 1979 to-date togetherwith the fnames of such schools, separately;

(b) the dates on which the schools, as referred to in part (a) above, started functioning, separately; and

(c) the district-wise and year-wise names of Middle and High Schools which were proposed to be opened during

the period from Ist April, 1979 to-date, togetherwith the dates of their opening, separately?

शिक्षा मंत्री (चौधरी देस राज):

(क) दिनांक 1–4–1979 के आज तक किसी भी माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय के नये भवन निर्माण हेतू कोई आधार–शिला नहीं रखी गई।

(ख) उपर के भाग (क) के दृश्टिगत, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 1–4–79 के आज तक माध्यमिक तथा उच्च स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Foundation stones for the construction of Hospitals and Dispensaries

652. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the district-wise total number of foundation stones laid for construction of Hospitals and Ci9vil Dispensaries in the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to-date) togetherwith the names of such Hospitals and Civil Dispensaries, separately;

(b) the district-wise and year-wise total number and names of Hospitals and Civil Dispensaries which were proposed to be opened in the State during the period from Ist

April, 1979 to-date togetherwith the dates of their sanction and dates of start of construction thereof, separately, and

(c) whether the Hospitals and Dispensris, as referred to in part (a) above, have stated functioning; if so, the dates of their functioning commenced, separately?

स्वास्थय मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) जिलावार हस्पतालों तथा सिविल औशधालयों के ि ालान्यासों की संख्या निम्न प्रकार हैः–

1979—80

जिला	**संख्या**	**हस्पताल**	**सिविल औशधालय**
अम्बाला	1	सामान्य हस्पताल, अम्बाला	भाून्य
करनाल	1	रूरल रैफल हस्पताल, असंध	भाून्य
रोहतक	1	सामान्य हस्पताल, खरहर	भाून्य
सोनीपत	1	सामान्य हस्पताल, सोनीपत	भाून्य
फरीदाबाद	1	सामान्य हस्पताल, होडल	भाून्य
महेन्द्रगढ	1	रूरल हस्पताल, बावल	
सिरसा	1	सामान्य हस्पताल, सिरसा	भाून्य

हिसार	3	1. सामान्य हस्पताल, आदमपुर	भाून्य
		2. सामान्य हस्पताल, उकलाना	भाून्य
		3. सामान्य हस्पताल, फतेहाबाद	भाून्य
1980–81			
कुरूक्षेत्र	1	रूरल रैफरल हस्पताल, गुहला	भाून्य
1981–82			
फरीदाबाद	1	बी0के0 हस्पताल, फरीदाबाद	भाून्य

(ख) वांछित सूचना अनुबन्ध ''ए'' में दी गई है।

(ग) सामान्य हस्पताल आदमपुर दिनांक 14–5–81 से कार्यरत हो गया है।

अनुलग्नक–ए

क्र.स.	1–4–79 से अब तक खोले जाने वाले जिला संख्या वार	स्वीकृति की तारीख (निर्माण के लिये प्र ाासकीय स्वीकृति	निर्माण कार्य भारू करने की

	प्रस्तावित अस्पताल और औशधालय		की तिथि)	तिथि
1	2		3	4
	अम्बाला			
	सामान्य हस्पताल, अम्बाला		12–6–80	19–2–82
2	कुरूक्षेत्र			
	जिला क्षयरोग केन्द्र कुरूक्षेत्र (ाहरी ओशधालय		26–8–80	भाुरू नहीं हुआ है।
3	करनाल			
	(क)	सामान्य हस्पताल, करनाल	––	––
	(ख)	रूरल रैफल हस्पताल, नीलोखेड़ी	हस्पताल में 7–5–79 से प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र वर्तमान भवन में कार्य करना भाुरू कर दिया है।	

	(ग)	सामान्य हस्पताल उकलाना	26–8–80	9–5–81
	(घ)	रूरल रैफल हस्पताल, असंध	26–11–81	भारू नहीं हुआ है।
4.	रोहतक			
	(क)	सामान्य हस्पताल, खरहर	29–5–80	29–12–80
	(ख)	सामान्य हस्पताल, कलानौर	––	––
5	सोनीपत			
		सामान्य हस्पताल, सोनीपत	24–3–81	9–11–81
6	फरीदाबाद			

	(क)	बी0के0 हस्पताल	——	——
	(ख)	सामान्य हस्पताल, होडल	21—8—80	20—11—81
7.	महेन्द्रगढ़			
	रूरल रैफल हस्पताल, बावल		——	——
8	हिसार			
	(क)	सामान्य हस्पताल, आदमपुर	8—8—79	2—11—79
	(ख)	सामान्य हस्पताल, उकलाना	19—9—80	30—12—80
	(ग)	सामान्य हस्पताल, फतेहाबाद	6—12—79	23—1—80
9	सिरसा			
	(क)	सामान्य हस्पताल, सिरसा	23—8—79	30—11—79

	(ख)	जिला क्षयरोग केन्द्र, सिरसा (ाहरी ओशधालय)	5—6—80	कार्य अलाट कर दिया गा है। परन्तु भाुरू नहीं हुआ है
	(ग)	सामान्य हस्पताल, कलांवाली	*	—

*इन स्थानों पर सरकार की सैद्धातिंक स्वीकृति , भवन निर्माण की पहले ही जारी हो चुकी है।

Donations/Funds given by Minsiters out of their Discretionary Grants

653. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state:

(a) the names with addresses of institutions given donations funds by the Chief Minister, Cabinet Mini9sters, State Ministers Deputy Ministers, Chief Parliamentary Secretary, out of their descretionary grants together with the amount given in each case dueing the yearsw 1980-81 and 1981-82 (to-date) separately;

(b) whether the Chief Minister sactioned any mount, other than his descretionary grant to any institutions during the years, 1980-81 and 1981-82 (to-date); if so, amount thereof, separately;

(c) whehte the payments of the amount , as referred to in parts (a) and (b) above, have been madel if so, the dates thereof and, if not, the reasons therefor?

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह): इस प्र न का उत्तर तैयार करने में बहुत अधिक समय व श्रम लगेगा तथा वांछित सूचना के उत्तर से समय लाभ भी नहीं होगा।

Hotels, Motels, etc. run by the Tourism Department and Hospitality Organisation

691. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the details of the income and expenditure incurred by the various hotels and motels run by the Tourism department and the Haryana tousism Corporation in the State during the years 1978-79, 1979-80, 1980-81 and 1981-82 upto date;

(b) whether it is a fact that different Hotels and Motels, the State Guest House at Chandigarh, M.L.A.'s Hostel at Chandigarh and the Haryana Bhawan Canteen at Delhi are being run by the Hospitality Organisation; and

(c) if so, whether it is also a fact that the units, referred to in part (b) above, are running into loss but the losses thereof are not being shown and are being declared as service units?

Healthe Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) The Tourism Department in Haryana is not directly running and hotels or motels. The haryana Toursim Corporation is, however, managing the various tourist complexes in Haryana including the motels set up by the Tourism Department Year-wise details of income and expenditure incurred on the tourist complexes and the motels run by Haryana Tourism corporation are given below:-

(i) Details of income and expenditure incurred on tourist complexes as a whole including motels.

		(Unaudited figures in lakhs)
Year	Income	Expenditure
1978-79	215.77	201.92
1979-80	260.38	236.22
1980-81	346.95	301.12
1-4-1981 to 31-12-1981	336.76	296.11
(ii) Details of income and expenditure incurred on motels alone.		
		(Unaudited figures in lakhs)
Year	Income	Expenditure
1978-79	16.93	15.60

1979-80	20.20	19.14
1980-81	23.79	18.88
1-4-1981 to 31-12-1981	23.53	16.81

(b) It is a fact that State Guest House, M.L.A's Hostel Canteen at Chandigarh and Haryana Bhawan Canteen at New Delhi are being run by the Hospitality Department Haryana kwhile the different Hotels and Motels in teh State are run by Haryana Tourism Corporation.

(c) The Haryana Hospitality Organistation runs these units on no profit no loss basis. While fixing the prices of eatables, drinks etc. non-commercial factyors are taken into account. The price of the articles suppled in the canteens is equivalent to the actual cost of raw, material plus 5 percent. The other administrative charges/costs viz. on staff, utensils, building etc. are not included in the sale price, because these canteens are oprned primarily for providing board and lodging facilities to V.I.P's/M.P's/M.L.A's, State Guests, Govt. Officers/officials etc. on nominal rates. To earn profit is not the objective of these units. Hence, Government have declared these canteens as service units in July, 1980, while the State guest House is working as service unit from joint Punjab times. Hence, no profit/loss accounts are maintained. However, the prices of articles are revised after every three months on the basis of the prevailing rates in the Market.

Adverse Remarks in A.C.R. Files

692. Shri Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether adverse remarks in the A.C.R. files of the State Government employees regarding their doubtful integrity are required to be supported by facts; and

(b) if not, the reasons thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) व (ख) इस विशय पर हिदायतों के अनुसार रिपोर्टकर्ता अधिकारियों को रिपोर्ट किये गये अधिकारी की ईमानदारी की ख्याति बारे अपनी राय व्यक्त करनी होती है और ऐसा करते समय उन्हें स्पश्ट रूप से बताना होता है कि कया अधिकारी बारे भ्रश्टाचार का संदेह है अथवा उसे भ्रश्ट समझा जाता हैं यह राय आमतौर उन कारणों से समर्थित होनी चाहिये जो कि रिपोर्टकर्ता अधिकारियों के ज्ञान मे हों।

Allotments of Residential Plots to Harijans and Weaker Sections

693. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the numbner of residenttial plots so far allotted in each district to Harijans and other weaker sections of the Society in the State:

(b) whether possession of the said plots has been given to all the allottees; and

(c) the number of complaints received during 1979-80, 1980-81 and 1981-82 regarding (i) non-delivery of possession of the plots; (ii) allotment of plosts in low lying areas including ponds (iii) non-allotment of such plots?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) सूचना अनुबनध ''ए'' पर रखे विवरण में दी गई हैं।

(ख) नहीं। कुछ मामलों में प्लाटों के कब्जें अभी दिये जाने है।

(ग) सूचना अनुबन्ध ''बी'' पर रखे विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुबन्ध ''ए''

क्रमाक	जिला का नाम	उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्लाट अलाट किये जाचुके है।
1	2	3
1	अम्बाला	8793

2	कुरूक्षेत्र	118869
3	करनाल	41187
4	सोनीपत	19770
5	रोहतक	23673
6	हिसार	25187
7	सिरसा	12824
8	भिवानी	14424
9	गुड़गावां	21307
10	फरीदाबाद	14770
11	महेन्द्रगढ़	12916
12	जींद	19352
.	जोड	226089

अनुबन्ध ''बी''

ि ाकायतें जो राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई

		1979–80	1980–81	1981–82	जोड़

(i)	प्लाटों के कब्जें न देने	53	56	7	116
(ii)	तालाबों समेत निचले क्षेत्रों में प्लाटों की अलाटमेंट करने तथा	11	14	6	31
(iii)	ऐसे प्लाटों की अलाटमैंट न करने के बारे में	44	19	12	75
	जोड़	108	89	25	222

Arrears of Salex Tax/Central Sales Tax

694. Shri Mool chand Jain: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to refer to reply to Starred Question No. 1972 answered on 10th March, 1981 and state-

(a) whether the arrears of sales tax amounting tomore than Rs. 11 crores, outstanding on 31st March, 1980, have been realized; if not, the details of the action, if any, taken against the defalutersl and

(b) the total amount of arrears of sales tax on 31st March, 1981 and on 28th Februrary, 1982, togetherwith the names and addresses of the persons and parties against whom arrears of sales tax/central sales tax amounting to more than Rs. one lakh are outstanding?

आबकारी व कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) 31–3–1980 को 11.14 करोड रूपये के विक्रय कर के बकायों में से विभाग ने 28–2–82 तक 2.71 करोड रूपये वसूल कर लिये है। 8.43 करोड रूपये की भोश बकाया राि ा में से जिन चूक कर्ताओं की ओर से एक लाख रूपये से अधिक राि ा वसूल हेतू बकाया है, उनके मामले में 3.20 करोड रूपये की वसूली उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य अपील अधिकारियों के द्वारा अवरूद्ध है। 8.27 लाख रूपये किस्तों में वसूल किये जा रहे है। 1.75 करोड रूपये ऐसी फर्मों से वसूली हेतू बकाया है जो लीक्वीडेट हो गई है और जिनके बारे में सरकारी लीक्वीडेटग्ज के पास क्लेम दर्ज करा दिये गये है। 34.43 लाख रूपये की राि ा का क्लेम भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमि नर आफ पेमैंन्ट के पास रजिस्टर करवा दिया गया है। 41. 09 लाख रूपये ऐैसे चूककर्ताओं की और बकाया है। जो कि दूसरे राज्यों में चले गये है। और ऐसे केसों में उनसे सम्बन्धित जिला संग्रहकों को वसूली हेतू प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है। 86.68 लाख रूपये के बकाया के केसों में सम्बन्धित चूककर्ताओं की सम्पति कुर्क कर ली गई है। 8.52 लाख रूपये की राि ा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों से वसूली हेतू बकाया है जिसके बारे राजय सरकार सम्बन्धित विभागों की और से किये गये कर मुक्ति अनुरोध पर विचार कर रही है। 1.90 लाख रूपये की बकाया राि ा को बट्टे खातें में डालने बारे सरकार द्वारा विचार किया जा रहा हैं बकाया के भोश अन्य मामलों में वसूली हेतू सक्रियता

से कार्यवाही की जा रही है। इसप्रकार बकाया राि । की वसूली में कोई और कसर नहीं रखी जा रही हैं।

(ख) 31–3–81 तथा 28–2–82 को कम ाः 10.88 करोड रूपये तथा 13.59 करोड रूपये की विक्रय कर की राि । वसूली हेतू बकाया थी। ऐसे चूककर्ताओं जिनकी और हरियाणा सामान्य विक्रय कर केन्द्रीय विक्रय कर की एक लाख यपये या उससे अधिक की राि । वसूली हेतू बकाया है। के नाम तथा अन्य विवरण संलग्ति अनुलग्नक 'ए'' में उपलब्ध है।

अनुबन्ध –ए

उन व्यापारियों/व्यक्तियों जिनके विरूद्ध 28–2–82 को हरियाणा सामान्य बिकी कर अधिनियम/केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम , के अधिनियम , के अन्तर्गत एक लाख से अधिक बकाया राि । की वसूली होनी है, के नाम तथा पते द ार्ाने वाली सूची।

कमाकं	व्यापारी/व्यक्ति का नाम व पता	बकाया राि ।	
		हरियाणा सामान्य बिकी कर अधिनियम 1973 के	केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956 के अर्न्तगत

		अन्तर्गत	
1	2	3	4
जिला अम्बाला		(रूपयों में)	
1	मै0 लक्ष्मी फूड मैनूफैक्चरिंग एंड सप्लाई	628706	——
2	मै0 हरियाणा रोडवेज अम्बाला	240543	——
3	मै0इस्टर्न कामर् ियल कारपोरे ान पिंजौर	45450	231605
4	मै0ि ाव ट्रेडिंग कम्पनी अम्बाला भाहर	119268	6074
जिला भिवानी			
5	मै0 डालमिया दादरी सिमैंन्ट, लि0 चरखी	3836829	1955337

	दादरी		
6	मै0किरण वैजीटेबल	624412	——
7	मै0अन्ती राम नन्द कि ाोर	270736	20093
जिला फरीदाबाद			
8	मै0गलोब मोटर वर्कस	353172	106486
9	मै0परेस्टोलाईट आफ इंडिया	267148	3396668
10	मै0रकमैन आटो (प्राईवेट) लि0	396643	3118964
11	मै0रकमेन कोशाकीन	110533	14731
12	मै0डी0जी0एल0 प्राईवेट लि0	11705	178772
13	मै0फरीदाबाद मनुफैक्चरिंग	21206	95570

	इन्जीनियरिंग		
14	मै0 फोरजिंग (प्रा0) लि0	568000	––
15	मै0विकास प्रिंटिंग म ीन	7256	107823
16	मै0एच0एम0एम0 लि0	85093	393101
17	मै0इन्सपों आटो इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0	59577	286214
18	मै0हरियाणा फुट वीयर	129830	215242
19	मै0एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	1107691	––
20	मै0इण्डियन गैस सिलैण्डर्स	––	1070000
21	मै0 परिसीजन स्टील एंड इन्जीनियरिंग	169137	890

	वर्कस		
22	मै0बरत राम स्कोट इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	26773	117841
23	मै0साहनी ब्रदर्ज	98796	9361
24	मै0स्टील पाईनर्ज फरीदाबाद	125054	18716
25	मै0ऊशा फोरजिंग	95460	108780
26	मै0गंगा इन्जी. वर्कस फरीदाबाद	29040	156988
27	मै0संजीव इन्टरपराईसिज	104554	6502
28	मै0 रोक्स एंड मिनरलज	101346	——
29	मै0रामा ट्रेडिंग कम्पनी फरीदाबाद	157709	——

30	मै0लक्ष्मी ट्रेडिंग कमपनी	558610	––
31	मै0अलाईड ट्रेडिंग कम्पनी	939563	––
32	मै0 एक्सलजीयर प्लांट कारपोरे ान लि0	15293	424586
33	मै0भारत कारपेट लि0 फरीदाबाद	––	642733
34	मै0 टेलीसांउड इण्डिया लि0	4794	241153
35	मै0धम ाा पाईप प्रा0 लि0	74936	110582
36	मै0 परल साइकिल इन्डस्ट्रीज	239341	1201630
37	मै0यू0के0 ब्डिर्स प्राईवेट लि0	7931	425861

38	मै0 जे0एन भार्मा एंड सन्ज	236870	284675
39	मै0एपलाईन्स मैन्युफैंक्चरिंग कम्पनी	166273	27797
40	मै0ब्रंक लाइनिंग लि.	——	736770
41	मै0 ईस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स लि0	——	196996
42	मै0लक्ष्मी रतन इन्जी0 वर्कस	541031	712386
43	मै0 एसोसियेटिड स्टील इन्डस्ट्रीज	190765	37317
44	मै0हिनदोस्तान ब्राउन बोवरी	——	1800096
45	मैं0 अतुल ग्लास इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 फरीदाबाद	395846	924924

46	मै0 किलरने इन्जी. प्र0लि0	700	188488
47	मै0हरियाणा स्टील लि0	86528	218903
48	मै0इण्डिया स्टील कारपोरे ान फरीदाबाद	53263	109860
49	मै0हांडा स्टील प्रोडक्टस लि0	227879	——
50	मै0 वुलरैकर्स प्रा0लि0	7035	473526
51	मै0टोप स्टाईल अपीरल	——	344587
52	मै0स्वदे ा रबड इन्डस्टरी	45753	242941
53	मै0क्लच आटो लि0 फरीदाबाद	——	533866
54	मै0 नैपको बेवल गीयर आफ	13795	138902

	इण्डिया लि0 फरीदाबाद		
55	मै0चन्द्र भान एल–2 बल्लभगढ़	303468	––
56	मै0य ापाल एल–2 फरीदाबाद	308668	––
57	मै0बी0आर0 गुप्ता एल–2 फरीदाबाद	163421	––
58	मै0बी0आरी0 इन्जीनियरिंग फरीदाबाद	10511	113303
59	मै0 ााको इन्डस्ट्रीज	3191	126774
60	मै0गणे ा पैंकिग इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	12917	140000
61	मै0गोल्डन पोलिस्टर	30438	124868

	प्रा0लि0फरीदाबाद		
62	मै0ग्लोब स्टील लि0 बल्लभगढ़	1013202	938282
63	मै0नादर्न इण्डिया आयरन एंड स्टील क0 फरीदाबाद	537885	—
64	मै0 लीकर ट्रेडर्स प्रा0 लि0 फरीदाबाद	112119	2782
65	मै0बरास्टील पैन्टस फरीदाबाद	18	156612
66	मै0इन्डोगम फरमैस्टीकलज फरीदाबाद	3000	348838
67	मै0हरियाणा एजैन्सीज	2313530	570
68	मै0हरियाणा सैलज	135306	——

	कारपोरे ान		
जिला गुड़गांव			
69	मै0बैगज एण्ड कारटनस गुडंगाव	—	471616
70	मै0इगो मेटल वर्कस गुड़गांव	26647	151330
71	मै0मारूति लिमिटेड गुड़गांव	1959791	3506458
72	मै0निबरों लिमिटिड गुडंगाव	15950	487823
73	मै0राही ट्रेडिंग कारपोरे ान	306000	——
74	मै0विजय कुमार राजेन्द्र प्रसाद	288377	238157
75	मै0मारूति हैवी व्हीकल्ज	595899	72005

76	मै0 हरियाणा रोडवेज गुडगांव	177373	——
जिला हिसार			
77	मै0 बिरला काटन एंड जिनिंग मिल्ज फतेहाबाद	388339	——
78	मै0जे0सी0मिल्ज फतेहाबद	284971	——
79	मै0हरियाणा कन्कास्ट, हिसार	——	304277
80	मै0रघबीर चन्द पत राम हिसार	—’—	310000
81	मै0 नत्थू राम नेम चन्द हिसार	52160	144416
82	मै0 सेठ कांि ा राम कैमिकल्ज इण्डिया हिसार	173798	——
83	मै0गोयल ब्रादर्स	6668	485741

	हिसार		
84	मै0विजय कुमार मुनीश कुमार, हिसार	67957	112835
85	मै0पदम कुमार ंजीव कुमार हिसार	145231	151189
86	मै0मंगत राय अवतार हिसार	54314	466452
87	मै0प्लांट परोटैक ान इन्सपैक्टर हिसार	149729	––
88	मै0हरियाणा रोडवेज हिसार	123560	––
जिला जीन्द		––	––
जिला जगाधरी			
89	मै0दौलत राम एंड कम्पनी	135000	––

	यमुनानगर		
90	मै0किरण मैटल स्टोर	229429	——
91	मै0भगवान दास एंड कम्पनी जगाधरी	550859	34840
92	मै0लक्ष्मी सिंह सोहन सिंह यमुनानगर	161951	128
93	मै0 युनाईटिड डिम्बर इन्डस्ट्रीज यमुनानगर	127813	——
94	मै0प्रेम दास पाहवा एंड कम्पनी यमुनानगर	1151305	4877
जिला करनाल			
95	मै0गवर्नमेंट मैडिकल डिपों	4130290	18296530

	करनाल		
96	मै0फूड कारपोरे ान	8939947	146382
97	मै0खोसला सेल्ज जी0टी0 रोड करनाल	148731	——
98	मै0हरियाणा रोडवेज करनाल	234941	——
99	मै0सौल्कस आयल एंड फर्टलाइजर जी0टी0 रोड, करनाल	146050	——
100	मै0वैल्डवैल आर्क इनक्ट्रोडज करनाल	99164	44927
101	मै0एस0के0 गांधी, पानीपत	66335	60335
102	मै0करनाल	17022	181040

	डिस्टीलरी जि0 करनाल		
103	मै0जयकि ान जिन्दल करनाल	103000	–
जिला कुरूक्षेत्र			
104	मै0हरियाणा रोडवेज कुरूक्षेत्र	113889	––
105	मै0सन्त लाल टेकचन्द	131455	––
106	मै0डिस्ट्रिक्ट फुड एंड सप्लाई कन्ट्रोलर	–	459244
जिला नारनौल			
107	मै0छोटे लाल रिंजी लाल नारनौल	197622	––
108	मै0रामकि ान भयोचन्द राय	––	395245

	नारनौल		
109	मै0मर्चेन्टस इण्डिया रिवाड़ी	163332	14107
110	मै0सोनी इन्डस्ट्रीज रिवाडी	115186	95186
जिला रोहतक			
111	मै0रायल बोडी बिल्डरज रोहतक	305278	160649
112	मै0पाहवा बाटल सप्लाई कं0 रोहतक	53784	122396
113	मै0मनोहर लाल सुरे ा चन्द, महम	71866	54877
114	मै0एन0आर0 इन्डस्ट्रीज बहादुरगढ़	14004	274429
जिला सोनीपत			

115	मै0डिपरी फूड लि0 राई	127517	1121739
116	मै0हरियाणा रबड इन्डस्ट्रीज सोनीपत	354951	1319861
117	मै0अ ाोक मोटर स्टोर सोनीपत	483550	7644
118	मै0कुण्डली इन्जीनियरिंग वर्कस प्रा0 लि0 कुण्डली	19930	127743
119	मै0देवसिया अब्राहिम एंड कम्पनी कुण्डली	270956	60
120	मै0सूरज स्टील लि0 सोनीपत	147359	85949
121	मै0हरियाणा राईस एंड जनरल मिल्ज	104280	—

	गोहाना		
जिला सिरसा			
122	मै0सिरसा इन्डस्ट्रीज सिरसा	297778	58780
123	मै0पदमावती राजेकाटन गिनिंग प्रोसिंग फैक्टरी, सिरसा	231378	—
124	मै0भाखडा काटन गिनिंग एंड प्रोसिंग फैक्टरी	182249	—
125	मै0 चौधरी काटन गिनिंग एंड प्रौसिंग फैक्टरी डबवाली	155878	50086
126	मै0बनी गोपाल महावीर प्र ााद सिरसा	128833	—
127	मै0हरजी राम	164586	—

	बलवन्त सिंह सिरसा		
128	मै0गुप्ता जिलिंग प्रोसिंग फैक्टरी डबवाली	328283	–
129	मै0गोपी चन्द टैक्सटाइल मिल्ज सिरसा	322067	2005597
130	मै0 भारत काटन कारपोरे ान सिरसा	142138	60695
131	मै0सुरजाराम काटन जिनिंग प्रोसिंग फैक्टरी काल–वाली	288743	30293
132	मै0गुप्ता एंड सन्स डबवाली	––	225391

वि ोशाधिकार का प्र न

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैने एक प्रिविलेज मो ान दिया था..................

श्री अध्यक्षः उसका जवाब आपके पास पहुंच चुका है।

(12.00 बजे) डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने उसके जवाब में कोई कारण नहीं बताया कि वह मंजूर क्यों नहीं किया गया है।। कोई कारण तो बताना चाहिये था।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Dr. Mangal Sein, M.L.A. has given a notice of breach of privilege against the Chief Minister, Haryana alleging that he misled the House by making a wrong statement about the alignment of S.Y.L. Canal. The Chief Minister had already clarified his position in the House. Besides, on page 234 of the Book Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher it is provided that a breach of privilege can arise only when the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly. So I withhold my consent to the raising of this quesiton of breach of privilege.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह जानबूझ करछिपाया गयाहै और बिल्कुल छिपाया गया है। (ाोर) इन्होने गलत स्टेटमेंन्ट दिया था। (ाोर)

Mr. Speaker: You know in your hearts of heart.यह कहना कि गलत स्टेटमेंन्ट दिया है, ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री ने कोई फालस स्टेटमेंट नहीं दिया। इतना तो आप जानते है कि अगर कोई भाब्द गलती से निकल भी गयातो उसे विलफुली नहीं कहा जा सकता।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होने विलफुली किया है।

श्री मूलचन्द जैनः मैं डा0 साहब से अनुरोध करूंगाकि वे इसमामले को ड्राप कर दें। इस बारे में आपके चैंबर में भी बात हो गई थी, इसलिये वह कृपा करके इसमामले को ड्राप करें।

Mr. Speaker: Thank you very much. I am most grateful to the Leader of the Opposition for showing such a cooperative4 attitude in the interest of the State of Haryana.

नलकूपों का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों को सहायता की अदायगी न करने संबंधी चर्चा

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, आज खेती सेपूरी उपज लेने के लिये बहुत पैसा पहले ही खर्च करना पडता है। आपका भी खेती से काफी नजदीक का वास्ता रहता है इसलिय मेराआपसे निवेदन है कि वि ोशकर, जो ट्यूबवैल एरियाहै, जहां पानी 80 फुट तक गहरा होता है। वहां किसान को 10 हार्स पावर तक का इंजन लगा कर पानी निकालना पडता हैं इसवजह से उनको अधिक पैसा खर्च करना पडता है। ऐसे किसान बैकों से पैसा लेकर अपनी जरूरतो को पूरा करते है ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने बीस या तीस हजार रूपये तक का कर्जा न ले रखा हो। इसी साल जिन लोगों को कनैक न मिले है, उनकी पांच हजार रूपये की कि त बकाया खडी हैं मेरा कहना यह है कि जहां ओले गिरे है व भीत लहर से नुकसान हुआ है उन लोगों

कोतो मुआवजा दिा जायेगा तथा आबियाना माफ किया जायेगा। क्या इन लोगों को भी उनके बराबर ट्रीट किया जायेगा जिन्होने टयूबवैलों से सिंचाई की है? क्या उनके बिल भी माफ किये जायेगे?

श्री अध्यक्षः आप कोई सबसटाटिव मोशन लायें, यह सरकार तो जमीदारों के हित के लिये बहुत कार्यवाही कर रही है।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, इन्होने मुआवजा देने के लिये तीन तरह की कैटेगरीज बनाई है। जिसका नुकसान 25 से 50 प्रति ात तक होगा उसको दो सौ रूपये प्रति एकड जिसका नुकसान 50 से 75 प्रति ात तक होगा उसको 300 रूपये प्रति एकड ओर जिसका नुकसान 75 से 100 प्रति ात तक होगा उसको 400 रूपये प्रति एकड दिया जायेगा। लेकिन चूंकि टूयबवैल ओनर्ज कोबहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पडता है और वे नुकसान की वजह से कि त नहीं दे पायेगें तो क्या उनको और इलाको के मुकाबले अधिक रिलीफ दी जायेगी?

श्री अध्यक्षः वैसे तो यह बडी रीजनेबल बात है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महेादय, इस बारे में पहले भी कई बार चर्चा हुई है ओर बार–बार मैं उस सवाल का जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं इनको एक बार फिर बता देता हूं कि जहां ओले पडे है वहां हमनेदा सौ रूपये से लेकर चार सौ रूपये तक प्रति एकड के हिसााब से

मुआवजा देने की स्कीम बनाई है। वहां पर सबसे पहले गिरदावरी करवा रहे है और हमें कहीं से भी ऐसी ि ाकयात नही आई कि गिरदावरी नहीं हो रही है। हमने बाकायदा कमि नर तक की डयूटी लगाई है कि वह मौके पर जाकर देखे। जहां तक इनका प्वाांयट है, यह भी वैलिड है। जहां भीत लहर की वजह से याओलों की वजह से नहरी जमीनों का नुकसान हुआ है. वहां के किसान का हमने आबियाना और मालिया मा ु कर दिा लेकिन कुछ जगहें ऐसी है,त्र जहां टयूबवैल से पानी लेते है। हम चाहते है कि उसको भी रियायत मिलनी चाहिये। लेकिन आप जानते है कि इसका संबंध बिजली बोर्ड से है और बिजली बोर्ड एक अलग संस्था है। हमारी किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है इस बारे में भी हम विचार करेगे। मैं इस समय इसबात की ्घोशणा तो नहीं कर सकता कि उनको भी मुआवजा देगें लेकिन हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है, हम उस पर गौर करेगें। जितना भी हम कर सकते है, करेगें। उसके लिये हम कोई कसर बाकी नहीं छोडेगे।

Mr. Speaker: I think , the assurance given by the Chief Minister should be appreciated.

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं हाउस के सामने एक बडी जरूरी चीज रखने जा रहा हूं कि हरियाणा के अन्दर पोटाि ायम सायानाईट बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है। यह एक पौयजन है और इससे जगाधरी और यमुनानगर में कई नौजवान व्यक्ति मर गये है। कल भी दो बच्चों ने इससे सू–साइड

कर लिया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसके बेचने पर पूरी पाबन्दी लगाई जाये। पोटाि ायम सायानाईट इंडस्ट्रीज में टैम्पर देने के लिये बहुत काम आता है।

श्री अध्यक्षः आप मेरे को इस बारे में लिख कर दे दीजिये, मैं उसे गवर्नमेंट को फारवर्ड कर दूंगा।

विभागों/निगयों/बोर्डो आदि की वार्शिक रिपोर्ट देर से पे ा करना

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, मैने परसों यह सवाल उठाया था कि अभी इतने महकमों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस नहीं आई है। आज अलग–2 डिमांडज पर बहस भाुरू होगी लेकिन अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस हमारे पास नहीं पहुूंची है। स्पीकर साहब, खास तौर पर जो सरकारी कार्पोरेशंज की रिपोर्टस है, एक दो को छोडकर बाकी की रिपोर्टस 4–5 वर्श से नहीं आई है। इसके अलावा मैने दो काल अटैन् ान मो ांज का नोटिस दिया है। एक तो भाूगर केन की प्राइस के बारे में है। कोआप्रेटिव चीनी कारखानां को छोडकर आज भाूगर केन की कीमत 10–12 रूपये प्रति क्विंटल तक पहूंच गई है। उधर भाूगर मिलों में भी कर‍ ान भाुरू हो गई है। दूसरामेरा काल अटैन् ान मो ान फसलों के डैमेज के बारे में हैं ये गेंहूं की फसल की गिरदावरी तो करवा रहे है लेकिन सब्जियों , चने और सरसों की फसल की गिरदावरी नहीं करवा रहे। जैसे पानीपत के नजदीक जो लोग

सब्जी बोते है, उसके बारे में भी ये कोई गिरदावरी नहीं करवा रहे है।

श्री हीरानन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचन्द जैन जी ने अभी जो कहा है उसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि मैं भी कल आने हल्के में गया था। एक फसल तारेमीरे की होती है, ये उसके नुकसान की भी गिरदावरी नहीं करवा रहे है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कई गांवों में पटवारी और तहसीलदार धांधली कर रहे है। सरकार उनको हिदायत करे कि वे सावधानी से काम करें। स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बतायाकि महेन्द्रगढ़ भिवानी जिले के रेतीले इलाकें में जहां पर लोग टयूबवैल्ज से पानी लगाते है बारे में वे अभी मुख्यमंत्री जी ने बतायाहै कि हम सहानुभूति से विचार करेगें स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि रेतीले इलाकों में, जैसे भिवानी और महेन्द्रगढ जिले का एरिया है, उन इलाकों में जिन किसानो ने टयूबवैल के बिजली के कनैक्ंज पहले से लिये हुये है यदि वे किसान लोड एक्सटैंान कराना चाहें तो क्या सरकार उन्हें प्रायर्टी बेसिज पर एक्सटैन देने के लिये विचार करेगी? स्पीकर साहब, जैसे किसी किसान ने अपने टयूबवैल की मोटर एक हजार हार्स पावर की लगाई हूई है और फिर अब वह 5 हजार हार्स पावर की मोटर लगाना चाहता हो तो क्या सरकार उन्हे प्रायर्टी बेसिज पर एक्सटैानं देने का विचार करेगी?

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बडी एप्रि ाएबल बात कही है। श्री रण सिंह मान ने टयूबवैल्ज के बारे मं जो कुछ कहा था उकसे बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बाबू जी ने कहा कि चने, सरसों और तारेमीरे की गिरदावरी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बाबू जी को और सारे सदन को बताना चाहता हूं कि जिस इलाके से मैं बिलौंग करता हूं, उस इलाके में ज्यादातर चने, सरसों और तारेमीरे की फसल होती है। किसान की चाहे कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी की भी फसह ळै, यदि ओलों की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से पूरा मुआवजा दियाजायेगा। ओलों की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है। उसका मुआवजा देने के बारे में सरकार ने जो नीति बनाई है उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अभी हीरानन्द आर्य बोल रहे थे। ये कंफयुजड आदमी है। उस समय पता नहीं क्या बोल रहे थे?इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कहने जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के बिलों के भुगातन का सवाल है, इस बारे में अभी श्री रण मान ने कहा था कि नहरों का आबियानला माफ कर दिया लेकिन टयूबवैल्ज से जो ुसल पैदा होती है उसके बिजली केबिलों के एरियर के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसबारे में भी

सरकार पूरा विचार करेगी ओर सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकेगी, किसानो की सहायता करने के लिये सरकार पूरी पूरी चेश्टा करेगी।

श्री अध्यक्षः बाबू जी ने महकमों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस के बारे में पूछा था। आप उसका भी जवाब दे दे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक महकामें की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का ताल्लूक है उसके बारे में मैं आकंडों के हिसाब से बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1976–77 में जिस समय बाबू मूल चन्द जैन वित्त मंत्री थे, केवल तीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस आई थी, 1977–78 मे केवल 11 रिपोर्टस आई। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस सरकार के बनने के बाद 1978–79 में 22 की रिपोर्टस आई, 1979–80 में 34 रिपोर्टस आई और 1980–81 में 9 रिपोर्टस आ चुकी है, बाकी रिपोर्टस के लिये महकमों को कह दयिागया है कि सारी कार्यवाही पूरी करके रिपोर्टस जल्दी से जल्दी भेजें। अध्यक्ष महेादय, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस आपके सामने जल्दी से जल्दी आएगी। आज की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस पे ा करने के लिये पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम किया है और पूरी कार्यवाही की है।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, 1981–82 के बारे में तो मुख्य मंत्री जी ने बताया ही नहीं है।

चौधरी भजन लालः 1982 का साल तो अभी खत्म नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: I had held discussion with the Chief Secretary on this subject and I am convinced के जितना पुराना एरियर्ज बकाया था वह तकरीबन सारा मेक–अप हो गया है। मुझे चीफ सैक्रेटरी साहब ने बताया है, लेकिन इसे कन्फर्म नहीं किया। But whatever the Chief Secretary has told me, I take it to be a pospel truth and he has told me कि इस साल 76 एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस डिपार्टमेंटस से आई है।

डा0 मंगल सैनः लेकिन स्पीकर साहब, हमारे पास तो एक भी नहीं आई।

Mr. Speaker: They ahve come from the Departments.

Dr. Mangal Sein: Sir, they have nt been laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: They are under print.

श्री मूलचन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्क ान तो आज भाुरू होनी है।

श्री अध्यक्षः बाबू जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस डिमांडज पर डिस्क ान करने के लिये थोडी बहुत गाइड लाईन तो जरूर देती है लेकिन यदि रिपोर्टस आपके पास न हो, तो भी कोई खास अड़चन वाली बात नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस तो आपको तीन

साल पुरानी गाइड लाईन दे सकजती है। I am qujite convinced if they are right up to-date, ये बडे काम की हैं लेकिन पुराने एरियर्ज के बारे में मुझे अभी चीफ सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि हमने 76 रिपोर्टस तैयार कर दी हैं इससे मैं समझता हूं कि अगले साल से स्थिति अच्छी हो जायेगी।

वि ोशाधिकार का प्र न

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूरी निहायत ही मानविक समस्या है और मुख्य मंत्री ने इस बारे में जो जानकारी हाउ को दी उससे हाउस को गुमराह किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर आपके समक्ष एक प्रिविलेज मो ान का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी उसका जवाब मैनें आपके पास भिजवा दिया है। (ाोर)

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महेादय, जो जवाब आपने भिजवाया हे उसके अन्दर कोई कारण नहीं बताये गये कि यह क्यों रिजैक्ट किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने हाउस को मिसलीड किया है। मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर मिस–लीड किया है। (ाोर एवं विघन)

Mr. Speaker: Swami Agnivesh had given notice of a breach of privilege against the Chief Minsiter alleging that while replying to his call attention motion in the House on 28th March, 1981, the Chief Minsiter had made a wrong

statement in the House. According to clasue (ii) of Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the HaryanaLegislative Assembly, governing conditions of admissibility of question of privilege-

"the question shall be restricted to a sepecific matter of recent occurrence."

and it has been examined by me that there was no mala-fide intention on the part of the Chief Minister while giving any information which Swami Agnivesh has alleged to be wrong. Therefore, I with-hold my consent to the raising of this question of privilege.

वाक आउट

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय......................................
...(ाोर एवं विघन)

Mr. Speaker: Since the ruling has been given, it is not to be recorded.

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, ...
...(ाोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः अखबरा की कोई खबर रिकार्ड न की जाये। (ाोर एवं विघन)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुन लें। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने यह माना है कि हरियाणा में बंधुवा मजदूर है लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते है कि हरियाणा में बंधुवा मजदूर नहीं है। इन्होने हाउस में गलत बयानी की है और हाउस को मिसलीड किया है। उसके बारे में स्वामी अग्निवे ा ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मो ान का नोटिस दिया था आपने वह रिजैक्ट कर दिया इसलिये हम वाक आउट कर रहे है।(ाोर एवं विघन)

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, काफी दिनों से प्रिवलिज कमेटी की रिपोर्ट श्री संत कंवर और स्वामी आदित्यवे ा के संबंध में आप के पास आ चुकी हैं इसलिये मेरी आपसे गुजारि ा है कि उसे सदन में पे ा कर दिया जाये। (ाोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हैं आपको याद आ गया इसलिये आपने यह बात कह दी। (ाोर एवं विघन)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी बात है। कई रिपोर्टें आपके पास आ चुकी है। प्रिवलिज कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस पर चेयरमैन के और 8 सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके है और वह आपके आफिस में दे दी गई है। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि उसे पे ा करना

चाहिये। (ोर) मुझे यह तो पता नहीं कि उसमें क्या लिखा गयाहै?

श्री अध्यक्षः आप कमेटी के मैंबर है, आपको पता होनाचाहिये। (ोर एवं विघन)

चौधरी उदय सिंह दलालः वह बात तो अलग है। मैं किसी बात की लीकेज नहीं करना चाहता। आप चेयरमैन से भी पूछ लें उनके भी दस्तखत हो चुके है। (ोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः मैने 4–00 बजे का समय दिया हुआ है। इस संबंध में मैं चार बजें एनाउसंमैंट करूंगा। आप कब से इतने भोले हो गये है कि अखबारों पर लिखी गई सारी बातों पर यकीन कर लिया जाये। (हंसीं, ोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः मैनें कहा है कि उस पर चार बजे एनांउसमैंट कंरूगां।

ध्यानाकर्शण सूचना

मैडिकल कालेज तथा अस्पताल, रोहतक की दिन–प्रति –दिन बिगडती हुई हालत संबंधी–

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैंबर्ज, मुझे सर्वश्री अजीत सिंह, उदय सिंह दलाल और संत कवंर एम0एल0एज0 की तरफ से मैंडिकल कालेज होस्पीटल रोहतक में बिगडती हुई हालत के बारे में काल अटेंन ान मो ांज के नोटिसिज प्राप्त हुये है। मैं इन्हे

मंजूर करता हूं। श्री अजीत सिंह अपना नोटिस पढ दें और हैल्थ मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमेंट दे दें।

श्री अजीत सिंह तथा चौधरी उदय सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्याव यक लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैडिकल कालेज तथा अस्पताल, रोहतक भारतवर्श में क्षेत्रफल तथा रोगियों के रहने की व्यवस्था के हिसाब से प्रथम स्थान पर है परन्तु इससमय इसकी हालत मरणासन्न है। बिगाड़ तो लगभग 6 महीने पूर्व से चल रहा है परन्तु इस समय इसकी द ाा अति भाोचनीय एवं चिन्ताजनक है।

अस्पताल व कालेज की हालत दिन प्रति दिन बिगडती जा रही है। भारी अर्थसंकट के परिणास्वरूप ही सभी क्षेत्रों में परे ाानियां व्यापत है।

यहां पर आने वाले रोगियों की द ाा अति भाोचनीय होती है। रोगियों को दवाईयों नहीं मिलती। गरीब व्यक्तियों द्वाराबाजार से मंहगें भाव पर दवाईयां खरीदना बहुत कठिन है। हजारों रोगी प्रति वर्श दवाई न खरीद पाने के कारण मौत के करालगाल में समा जाते हैं रोगियों की खुराक का भी वहां नितान्त अभाव है। बिस्तरे व पट्टियों की भी हर समय कमी ही रहती है। मैले–कुचैले बिस्तरे, थूक, पे ााब , टट्टी के बर्तन न होने के कारण तथा भाौचालयों व स्नानागारों में सफाई न होने के कारण रोगी कारोग घटने की बजाये बढता चला जाता है। बिजली

की नंगी तारे सदैव मौत की तलवार के समान लटक रही है। वर्शा ऋतु में कितनी ही छतों से सीधा पानी रिसता हैं रेागी के साथ आने वाले सहायक रोगी को ठीक कराना तो दूर रहा स्वयं रोग मोल ले लेते हे। सहायकों के रहने की व्यवस्था ले ा मात्र भी नहीं है। घोशित धर्म ााला के निर्माण की भी अब तक कोई चर्चा नहीं है।

लगभग 500 डाक्टरों, तीन हजार कर्मचारियों व 350 नर्सों में आपसी सामंजस्य न होने का दुश्परिणाम भी रोगियो को ही भुगतना पडता है। डाक्टर रोगियों के इलाज की अपेक्षा प्राईवेट प्रैक्टिस पर जयादा ध्यान देते है।डाक्टरो, कर्मचारियों, नर्सो व छात्रों की हड़ताल का नजला भी रोगियोको भुगतना होता है।

कालेज में बहुत से महत्वपूर्ण पद रिक्त है जिसके कारण बहुत से कार्य विचारधीन हैं अच्छे डाक्टर विदे ाों में जा रहे है।

विभागाध्यक्षों के हाथों में छात्रों के अधिकार होने के कारण सामान्य वातावरण नहीं रहता। चिकित्सा श्रेणी मे छात्रों के प्रवे ा की अनियमिततायें भी प्रका ा में आ रही है। छात्रों के छात्रावासों में भी असुविधायें निरन्तर बढ रही है।

सरकार द्वारा नियत्रिंत मैडिकल कालेज व अस्पताल हेतू कमेटी भी निश्क्रिय है। समस्याएं सुलझने की बजाये उलझी है।

सरकार के सभीवायदे आज कोरे सिद्ध हो रहे है तथा सरकार इस विशय में कुछ भी करने में पूर्ण विफल रही है।

यह एक गंभीर तथा हाल ही का मामला है जिससे जनता में भारी अंसतोश व्याप्त है। यह मामला राज्य की अर्थव्यवस्था व सामान्य प्र ाासन से भी संबधित है।

अतः वे इस अत्याव यक लोक महतव के मामले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्शित करते है और संबंधित मंत्री से प्रस्ताव करते है कि वे इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य देकर स्थिति को सपश्ट करें और सदन को वि वास में लें।

चौधरी संत कवंर

श्री उद सिंह दलालः—हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के इस विशय की और दिलाना चाहते है कि हरियाणा के सबसे ब्रडे चिकित्सा केन्द्र मैडिकल कालेज, रोहतक में जो दवाईयों सरकार की तरफ से रोगियों के लिये भेजी जाती है उनको बाजार में बेच दिया जाता है। इस मामले को लेकर वहां की जतनतामें बडी ही रोश तथा तनाव है। इस मामले को लेकर जिला रोहतक के प्रमुख नागरिक उपायुक्त रोहतक से भी मिले लेकिन उन्होने अपनी असमर्थता प्रकट की। केवल यहीं नहीं बल्कि उक्त कालेज के बडे डाक्टर दवाईयों को अपने घर लेकर जाते है तथा वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते है और सरकारी दवाईयों को बेचते है। इसलिये सरकार का फर्ज

बनता है कि इस बुराई को रोकने के लिये तुरन्त जांच कराई जावे तथा इस बुराई को बन्द करने के लिये जो प्रयास सरकार केगी वे इस महान सदन को बताने की कृपा की जावे।

वक्तव्य

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Health & Tourism Mininster (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar): Sir, it is not a fact that the condition of Medical College & Hospital, Rohtak, has been deteriorating. It has always been the special endeavour of the Government to providemost satisfactory services and case to the patients. The medicines are suppled to all the infoor and outdoor patients, as prescribed in the hospital pharmacopaeia. On an average, Rs.3/- are spent on each patient attending out-doors and about Rs. 25/- on each indoor patient for medicines. This is considerably higher than other hospitals in the country like the Post Graduate Institute. Chandigarh and All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, there are always two lists of medicines. One is for outdoor patients while the other is for hospitalised patients. This practice is followed strictly in this institution as well. These medicines are suppled to all. In some specialised cases, some more costly and sparsely used medicines are required. To procure such medicines for poor patients, help from the Red Cross Society as well as the Hosptial Wlefare Soceity is sought and, as far as possible, medicines are procured for them from these sources. Nobody has ever been denied medicines which have been listed in the

hospital pharmacopaeia. In the case of eligible patients requiring surgery, necessary operaitons are donr without any charge. In such cases laboratory investigations are also done free of any charge. Diet is given free to all patients having income below Rs. 300/- per month and,on an average, diet is provided to about 700 to 800 patients every day. Ordinary diet costs about Rs. 5/- per diem in the hospital. There is provision for special diet also including eggs and milk in the needy cases. It is wrong to say that food is not availbale to the hospital patients.

There is not shortage of bandages and such facilities have been made availbale free to all the patients of general ward. The hospital bed strength is 1074. In addition to it, if the patient comes to the hospital with a serious illness, we provide him/her accomaodation by providing extra beds in the concerned ward, and such patient is never refused admission in the hospital. Sometime about 100 extra beds have to be provided. Due to increasing demand for hospital facilities. Govermnent is considering the question of increase in bed strength, but it will bepossibleonly when funds are avilable. there are no dirth beds and the condition of bed-sheets has been satisfactory. There is no shortage of pans for sputum, urine and stool, which are very minor items and are being supplied to all patients. However, some of the patients take them away creating temporary difficulites, but then substitutes are provided. Cleaning of bath rooms is always taken care of and recently all the hospital bath rooms have been provided withexhaust fans to drive out the foul air. Besides, deoderants like phenyle and nanthalene balls are freely used. Adequate number of sweepers have been provided.

however, due to unfamiliarity of some attendants of the patients, and the patients, and the patients themselves, with the use of these facilities some incleanliness occurs.

There is no live wire of electricity hanging any where. Some work of laying of 15 amp. heating lines in the boys and girls hostels is being undertaken in order to provide better facilities to the students during winter. As a duspute with the contractor is going on in the court of law, some lines have yet to be properly fixed. If is totally incorrect to say that there is leakage of water from teh roofsin the rainy season.

The Government have a scheme to build a Dharmsala for the comfort of attendants of the patients in the Medical College, Rohtak hospital. The project has been prepared, but the construction, however, could not be started due to lack of funds. The estimated cost of the project is about Rs. 55 lakhs.

There is no lack of coordination between the doctors, nurses and staff. There is no specific complaint about extortion of money from the patients by the doctors. Any specific complaint will be investigated and proper action will be taken.

In order to meet the requirements of the patients to get the treatment from teh doctors of their own choice, system of paying clinics is in vogue. Out of the fee charged from teh patients, share goes to the doctor also. The matter is under consideration of the government whether this system should be continued or abolished.

There has been no strike of any short whatsoever either by the doctors, employees or nurses during the last one year. Some minor student problems cannot be ruled out in an institution of this size.

All the posts of Associate Professors are filled up. Only five posts of Professors out of 28 posts are lying vacant. This is however, not posing anyproblem because all sanctioned units in the College/hospital are functioning. In an institution of this size, some movement of doctors from the college is inevitable for training and short-term assignments in other institutions in India and abroad. However, nobody is permitted to go out of the department where the staff strength is less than 70 percent.

The recruitment processes of the college have now been streamlined and advertisements are in the process of issue to fill up the posts that are lying vacant. Government hopes to recruit the doctors twice a year in view of the special requirements of the college. It is incorrect that the doctors are going away and no doctor is in regular service has resigned or left service in the last one year.

There is not a singly case of irrigularity in admissions in the last one year. No complaint whatsoever has been received in this regard by the Goverment or by the Director-Principal. In fact, the Government can take credit that both admission and recruitment processes have been totally above board.

No inconvenience to the student shas been specified in the Motion. Of-course, additional hostel accomodation is

required in view of the increase in intake from 115 to 160 students in MBBS course last year and introduction of the Dental course. Construction work for the hostel accommodation for 325 students (cubicles) has been taken in hand and work has been allotted to the contractors.

The College is now being run directly by the government. It was taken over from the Maharishi Dayanand University in 1979.The decision making processes are quickandsmooth and it will be no exeggeration to say that the atmosphere todayin the College is much better, totally peaceful and free from agitation. This is a matter of gratification. The Committee referred to in the Calling Attention Motion is only advisory and does not affect the day-to-day functioning of the College. There is no promise of the Government is aware of the increasing demand of the public for continuous expansion of health facilities in the college. The demand is a proof of the quality of service rendered, rather than the mis-management. The Government is keen to expand this facility, but it will have to be done within the resources available to the State. Because of other demands for development, particularly the projects like Satluj-Yamuna Link Project, we have tostagger the expansion plans for the college.

It is incorrect to say that medicines supplied to the College are unauthorisedly resold in the market. The store of medicines is directly under the charge of Deputy Mekdical Superintendent of the College. The medicines brought to the Store are stamped in the college so that they cannot be sold in the market as fresh medicines. Cartones of medicines are destroyed. Regular stock taking has been introduced. No

complaint about the sale of medicines has been made in writing or orally by any responsible person to either the Principal of the College or to the government. Some anonymous complaints were received about the replacement of genuine drugs by spurious drugs. They were got verified and found tobe false. random checking by the State Drugs Inspectior is also got done to see that the genuine medicines are not replaced by suprious ones. Such check have not indicated any such practice in the College. On case of theft was detected some years ago and shortages in the store were detected again in September, 1981. Disciplinary action was taken in the earlier case and one employee was dismissed and others involved were given various other punishments. In the shortages detected in September, 1981 disciplinary proceedings against the employees concerned have been started.

It will be observed that necessary system of checks and control over the medicines is in operation in the college and it is incorrect to say that the medicines are regularly sold by senior doctors in the interest of their private practice. Government is informed that recently when some citiznes of Rohtak met the Deputy Commissioner on this question, the Deputy Commissiner advised the complaints to give specific instances with supporting documents and affidavits. No such documents or affidavits with definite complaints have been received by the Deputy Commissioner so far. It is possible in such a big institution that occasionaly some employees may create some mischief, but the government is alert to the problem and will take necessary steps to proceed against any such person who is found to be indulging in this type of

mischief. Action in such cases has been taken in the past and will be taken in future also in case of a specific incident. Speaker Sir, you will agree with me that it is somewhat irresponsible to make allegations of mis-appropriation of medicines against senior doctore of the College.

(At this stage Mr. Deputy Spekaer occupied the Chair).

May I bring to thenotice ofthe Members of the House that the college was recently visited by the Public Accounts Committee of this House. Though the formal report of theCommittee has not yet come, the draft of the observations of the Committee indicate that they were satisfied with the arrangements in the college within the resources available, except for improvements in the kitchen. Stpes have been taken to rectify this. With the change ofthe cooking gas lines and providing additinal ventilation and exhaust fans which is likely to be done within a month, it will be brought to a satisfactory level. Any other recommendation of the Committee will also be fully acted upon.

In the end, I will like to assure the House that the problems of the College engage continuous attention of the Government. We are proud of this Institution and will continue to improve and expand it to the extent resources become available. There is no cause for anxiety.

चौधरी अजीत सिंहः उपाध्यक्ष महेादय, मैं मंत्री जी से दो तीन बातों का जवाब चाहूंगा। पिछले साल एम0बी0बी0एस0 में दाखिले हुये है, क्या उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट चली

हुंई है क्योकिं कुछ प्रभाव ााली आदमियों ने अपने लडकों को दाखिल करवा लिया था और योग्यता वाले लडके पीछे रह गये थे?

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने स्टेटमेंट में कहा है कि छत कहीं से भी नहीं टपकती। उपाध्यक्ष महोदय यह बात ठीक नहीं है। गेट से ऐन्टर होते ही वहां पर जो बरामदा है उसकी छत टपकती है। रोगियों के साथ जो आदमी आते है, वे उसी बरामदे में विश्राम करते है और इससे उन्हें बडी असुविधा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होनें स्टेटमेंट में यह भी कहा कि पांच रूपये के स्तर की डाईट रोगियों को देते है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि पांच रूपये के स्तर की डाईट रोगियों के लिये बैलेंस्ड डाईट है? अगर नहीं तो क्या इसके स्तर को उंचा करवायेगें?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे फाजिल दोस्त ने तीन चार बातें पूछी है। एक तो इनहोने कहा कि वहां छत टपकती है। यह सरासर गलत है। कहीं भी छत नहीं टपकती। (विघन)

चौधरी संत कवंरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने भीगे हुये कपडें इन्हें दिखा सकता हूं।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये अपने कपडों को नल में भिगों लें तो मैं इनहें कैसे रोक सकता हूं?(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी संत कवंर जी

मुझे रेहतक रैस्ट हाउस में दो बार मिले इन्होने यह बात कभी नहीं बतायी कि मैंडिकल कालेज का बरांडा टपक रहा है।

चौधरी संत कवंरः मैने रैस्ट हाउस में आपको यह बताया था कि किसानों को जबरदस्ती पकड कर बन्द कर रखा है, उन्हें छुडवाओं लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्षः यह बात यहां पर इररेलैवेन्ट है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दुबारा बिल्डिंग का मुआयना करने के लिये तैयार हूं। अपने फाजिल दोस्तों को न्यौता देता हूं , वे मेरे साथ चले। वहां पर हमारे डायरैक्टर है, वे मैडिकल कालेज के प्रिसिंपल है, उनके पास जाये वे भी दिखा देगें आप किसी भी समय जायेगें, आपको सहयोग देगें।

डिप्टी स्पीकरसाहब, एक बात इन्होने खुराक के बारे में कही है। मैने अपने जवाब में पढ़ा है कि पांच रूपये रैगूलर डाइट की एवरेज है। वैसे जैसा भी मरीज होता है वैसी ही डाइट दी जाती है। सपै ाल इन्तजाम अन्डे और दूध का भी है। ज्यादा खुराक की जरूरत होती है तो ज्यादा देते है लेकिन पांच रूपये एवरेज है।

यह भी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी जिसमें उनहोने कई इररैगुलरेटिज को चैलेन्ज किया था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, जितने भी दाखिले हुये है वे

बाकायदा मैरिट के हिसाब से हुये हैं। जहां तक डिस्कि ानरी कोटे सेएडमि ान का सवाल है उसमें भी पूरा ध्यान रखते हुये मैरिट बेसिज पर किया गया है। कोई ि ाकायत बकाया नहीं है।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहिब, हमने काल अटैन् ान मो ान यह दिया था कि दवाईयां बाजार में बिकती है। जो डाक्टर प्राईवेट तौर पर प्रैक्टिस करते है, वे फीस ले करसरकारी दवाई देते है। हम यहां हाउस में दो तीन एम0एल0एज0 रोहतक के बैठे है। हम इनके साथ रोहतक चलने के लिये तेयार है। मंत्री महोदय इस बारे मेँ जाचं करायें कि क्या यह बात सच है? रोहतक के नागरिक डिप्टी कमि नर से मिले लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप दो एम0एल0एज0 की या दो आफिसर्ज की एककमेटी बना कर भेजें। हम उन डाक्टर्ज की लिस्ट बना कर देगें जो ऐसे प्रैक्टिस करते है। हम आपके साथ उनके मकान पर चलेगें। वे डाक्टर्ज दो सौ दो सौ रूपये फीस मरीजों से लेते है और फिर उसका एक्सरे या दवाई मैडिकल हास्पिटल से देते है। कम सेकम 40 डाक्टर्ज ऐसे कर रहे है। इन डाक्टर्ज को सरकारी मकान दे रखे है। आप वहां पर जाकर छापामारी या इन्कवायरी करवाओं, तब आपको असल बात का पता लगेगा। दो–तीन डाक्टरों के साथ ऐसा हो जाये और उनहें सजा मिल जाये तो मैडिकल कालेज की हालत में सुधार हो सकता है और उसे बचाया जा सकता है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब अभी मेरे फाजिल दोस्त ने जो कहा, उस बारे मं मै सबसे पहले वाजह करना चाहता हूं । इसवक्त वहां पर 350 डाक्टर्ज काम कर रहे है जिनमें से केवल 18 डाक्टर्ज को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत है। बाकी सभी डाक्टर्ज को नान–प्रैक्टिसिंग अलाउन्स मिलता है। जिन 18 डाक्टर्ज को नान–प्रैक्टिसिंग अनाउन्स नहीं मिलाता है वे प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस कर सकते है। जहां तक डाक्टर्ज की फीस चार्ज करने का सवाल है वह सारी फीस उनकी जेब में नहीं जाती। पचास परसैंट डाक्टर कोमिलता है और पचास परसैंट सरकार को देना पडता है। बाकायदा उनकी क्लीनिक्स बनी हुई है, वहीं प्रैक्टिस करते है। घरों पर नहीं कर सकते।

चौधरी सतं कंवरः 18 डाक्टर्ज को आपने प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रखी है, वे फीस ले सकते है। आप हमारेसाथ सरकारी गाडी की बजाये प्राइवेट गाडी में चलें, आपको हम दिखायेंगें कि वहां पर कितने डाक्टर्ज प्राइवेट तौर पर अपने घरों में फीस लेते हैं जो लोग फीस नहीं देते है वे बेचारे चिल्लाते रहे है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्ही लोगों की और ध्यान दिया जाता है जो फीस देते है। आप हमारे साथ चलें, आपको दिखायेगें किस॒कार से वहां धांधली हो रही है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जहां तक इसबात का संबंध है कि कुछ डाक्टर्ज नान–प्रैक्टिसिंग अलाउन्स भी ले रहे हे ाओर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उनहें आप पकडवाइये।

हरियाणा में कही ं भी ऐसे डाक्टर्ज है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उनहें पूरी सजा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रोहतक में केवल 18 डाक्टर्ज को प्रैक्टिस करने की इजाजत दी हुई है। वही प्रैंक्टिस कर रहे है। वैसे आपको पता है कि मैडिकल एजुके ान सैपरेट डिपार्टमेंट है। मुख्य मंत्री महोदय के पास यह विभाग है। मुख्य मंत्री जी पूरी निगाह रखते है। कोई ि ाकायत आयी तो जरूर एक ान लेगें।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रोहतक में मरीजोंके लिये धर्म ााला बनायी जानी थी, उसकी अब क्या पेाजी ान हे, क्यां नही बनायी जा रही है? आनन्दझा वालों से अपने नक ाा बनवाया हैं नक ाा बनवाने के हजारों लाखें रूपये दिये है लेकिन आज तक वहां पर एक भी ट्रक ईटों का नहीं पडा है। यह धर्म ााला कब तक बना दी जायेगी?

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि मैडिकल कालेज में जो पुराने डाक्टर्ज है, बहुत ही सीनियर और तजबेंकार है, जैसे श्री मैनी है , वे तजुर्बेकार और ऊंचे स्तर के डाक्टर्ज वहां से जा रहे है क्योंकि उनहें दूसरी जगहों पर ज्यादा फैसिलिटिज आफर की जा रही हैं । क्या मंत्री जी इदस चीज को ध्यान में रखते हुये कि वे हरियाणा के मैडिकल कालेज से न जायें, उनहे कोई खास फैसिलिटिज देगें? जो भी डिपार्टमेंट के हैड है वेदो चार सालों में

रिटायर होने वाले है, ऐसे डाक्टर्ज को फैसिलिटिज न दी गई, तो वे हरियाणा सरकार की सर्विस में नहीं रहेगें?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः वैसे तो मैने तफसील मे जवाब दिया हैं इस साल वहां से कोई भी डाक्टर नहीं गया है। जैसे इनहोने डाक्टर मैने का जिक किया। हम ऐसे सीनियर और तजर्बेकार डाक्टरों को फैसिलिटिज देगे। वह मैने जवाब मे बता दिया है। दूसरे उनहोने धर्म ााला का जिक किया। यह बहुत ही जरूरी है। सरकार भी महसूस करती है कि वहां धर्म ााला बननी चाहिये।

श्री उपध्यक्षः दलाल साहब, वे कह रहे हे कि एक साल से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया।

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकरसाहब, अगर सरकार उन्हें कोई अन्य फैसिलिटिज नहीं देगी तो वेदूसरी जगह जा सकते है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डाक्टर्ज की एक एजुकेटिड कलास है। हम सभी जूनियर और सीनियर डाक्टर्ज का ख्याल रखते है। धर्म ााला के लिये 7–8 लाख रूपया महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी ने देना है, लेकिन वह अभी तक नहीं मिला। चौधरी देवी लाल के समय में भी यह बात आयी थी लेकिन न तो हैल्थ डिपार्टमेंट को और न ही मैडिकल कालेज को यूनिवर्सिटी ने यह पैसा दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने सारी स्कीम बना दी

है नक ो पास कर दिये हैं सब काम करदिया हैं इसके अलावा हमारे मूख्य मंत्री महोदय न यह निर्णय लिया है कि 55 लाख रूपये की लागत से यह धर्म ाला जरूर बनायेगें।

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होने यह कहा है कि यूनिवर्सिटी ने इनको कोई पैसा नहीं दिया हैं तो इनहोने हजारो–लाखों रूपया नक ों को बनाने का किस फण्ड से अदा कर दियाहैं यह जरा बताने की कृपा करेगें? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, यह पैसा उस वक्त के वाईस चांसलर हरद्वारी लाल जी ने पे किया है। हमारा इससे कोई ताल्लूक नहीं है।

वर्श 1982–83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्षः मैंबर साहेबान, अब वर्श 1982–83 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर विचार हेागा। पहली प्रैक्टिस के अनुसारऔर हाउस कासमय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गयी सभी डिमांडज फार ग्रांटस तथा चौध्शरी राम लाल वधवा द्वारा दी गयी कट मो ंज एक साथ पढी और पे ा की गयी समझी जायेगी। आनरेबल मैंबर्ज किसी भी डिंमाड पर डिस्क ान कर सकते है लेकिन बोलते समय कृपया डिमांड कानम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते है।

That a sum not exceeding Rs. 84320573 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 2-General Administration.*

That a sum not exceeding Rs. 279233064 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 3-Home.*

That a sum not exceeding Rs. 49055580 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 4- Revenue..*

That a sum not exceeding Rs. 28152650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 5- Excise and Taxation.*

That a sum not exceeding Rs. 585787790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 15-Irrigation.*

That a sum not exceeding Rs. 388844510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 17-Agriculture.*

That a sum not exceeding Rs. 42821300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 22- Co-operation.*

Demand No. 2 (General Administration)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 3 (Home)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 5 (Excise and Taxation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 15 (Irrigation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 17 (Agriculture)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 22 (Co-operation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

राव राम नारायण (साल्हावास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस के नोटिस में एक–दो बातें लाना चाहता हूं । पिछले 2–4 रोज हुये इस हाउस में इसकिस्म की चर्चा हुई थी.................. ....का हाथ था। यह बात सरासर गलत थी कयोकि सरदार भगत सिंह के और उसके साथियों की ट्रायल एक ट्रिब्यूनल के जरिये हुई थी जिसका प्रैजीडेंट एक अंग्रेज था। सर भाादी लाल हमारे हरियाणा के एक महान सपूत हूयें है जोकि रिवाडी से ताल्लुक रखते थे और एक अच्दे पार्लियामेंटेरियन थे। वे मिन्टो मारले रिफार्म्ज के अन्दर 5 साल तक सैंट्रल असैम्बजी के मैंबर भी रहे। फिरवे चीफ जसिटस सिलैक्ट हुये ओर भाायद आल इंडिया में वह पहले ही इंडियन चीफ जस्टिस थे। उन्होने चीफ जस्टिस कीकुर्सी को करीब 15 साल तक ऐडोरकिया। उनके द्वारा दी गयी रूलिंग्ज को आज भी फोलो किया जाता है। उनके बारे में किसी भीकिस्म के डैरोगेटरी रिमार्क्स हम टोलरेट करने के लिये तेयार नहीं है।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, वह भाब्द चौधरी राम लाल वधवा जी ने वापिस भी ले लिये थे। इसलिये उनको यहां पर दोहराना उचित नहीं हैं अगर उनहोने कोई ऐसे भाब्द कह दिये थे, तो वे वापिस भी तो ले लिये थे। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Deputy Speaker: I further requested the Hon'ble Member then tokindly verify whether the death warrants were signed by Sir Shadi Lal? It he has verified it and he is saying so, he is correct. (Noises & interruptions)

राव राम नारायणः इसलिये सर भाादी लाल का नाम वहां के होस्पीटल से जोडना निहायत ही अच्छा कार्य है। सरकार ने यह एक बहुत ही अच्छा कार्य कियाहै और यह जरूर कायम रहना चाहिये क्योकि सर भाादी लाल एक अच्दे पार्लियामेंटैरियन थे। यही नहीं, वह एक अच्छे जज भी थे और हिन्दुस्तान के एक माने हुये कानूनदान थे। एक दूसरे प्वायंट के बारे में भी मैं हाउस मे कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, एक्स–सर्विस मैन जो सिवविल एम्पलायमेंट लेते है, उनके साथ काफी ज्यादती हो रही है। उनको रूल्ज के अन्दर मिलिट्री सर्विस का बैनिफिट टूवार्डज इन्क्रीमैंट और सीनियारटी मिलना चाहिये। यह बैनिफिट हमारी सरकार अकसर उनको देने में झिझकती रहती है। कुछ रूल्ज में इसतरह से परिवर्तन किया जारहा है कि करीब–2 हरेक एक्स–सर्विसमैन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोढ में जाना पडता है। तब उनहें कहीं जाकर इन्साफ हासिल होता है। पहले जोरूल्ज थे, वह ठीक रूल्ज थे लेकिन उनसे कुछ सरकारी अफसर जो पहले से ही सर्विस में थे, उनकी सर्विस–सीनियारिटी में अफैक्ट पडता था, इसलिये उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। रूल्ज को थोडा सा डिस्टार्ट किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिसने भी एक्स–सर्विसमैन वहां पर गये , उनके

हक में फैसला किया। मैने इस बार`में दो नोट लिखकर चीफ मिनिस्टर साहब को दिये थे लेकिन मुझे आज तक पता नहीं है कि उनका क्या बना है। न ही मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला हैं इसलिये मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि एक्स–सर्विसमैनों को जो हमारे इस मुल्क की और इस वतन की खिदमत दिलोजान से करते है, फ्रंट पर लडते हैं। 1971 की लडाई में उन्होने बहुत अच्दी तरह से काम किया और बाद में अगर वह आकर सिविल सर्विस हासिल करते है तो उनके साथ इन्साफ होना चाहिये जोकि नहीं हो रहा हैं तीसरी बात मैं हाउस के समने एक और रखनाचाहता हूं। लैंड एक्वीजी ान के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले भी यह बात हाउस में रखी थी और मैने अपनी पार्टी मीटिंग में भी इस बात को कहा था। लैंड एक्वीजी न के मसल`का हरियाणा में कोई न कोई इलाज होना चाहिये। 10–10 साल से लैंड एक्वायर हुई है लेकिन उनको मुआवजा अभी तक भी नहीं मिला है ऐसे कई आदमी अब भी है। मेरा कहना यह है कि हरके आदमी को टाईम पर मुआवजा लि जाना चाहिये। एक आदमी जिसको सौ रूपया मुआवजा मिलना होताह` , उस बेचारे का दो सौ या तीन सौ रूपया तो वैसे आने–जाने में खर्च हो जाता है। कभी लैंड एक्वीजी न आफिसर के पास जाता है तो कभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाद्दर पर जाता हैं मेरा कहना यह है कि इस सिस्टम को डीसैंट्रेलाइज किया जाना चाहिये। हरेक एस0डी0एम0 को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह लैंड एक्वायर करसके। अगर किसी हल्के में कोई बडा प्रोजैक्ट टेक–अप होना है, उसके

लिये एडी ानल स्टाफ दिया जा सकताहै। इस काम के लिये वहां पर एक एडी ानल तहसीलदार जो एस0डी0एम0 के तहत हो, दियाजा सकता है। जब तक आप इन पावर्ज को डीसैट्रेंलाईज नहीं करोगे, यह प्रौब्लम ज्यों की त्यों खडी की खडी रहेगी इस मामले में कई दफा तो इस हाउस मे विचार हो चुका है लेकिन इसका कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। सरकार ने कई बार हाउस में भी कहा है कि हम लैंड एक्वीजी ान आफिसर आपका अम्बाला में है और एक लैंड एक्वीजी ान आफिसर एचव0एस0ई0बी0 का भी वहां पर हैं मेरा कहना है कि आप पावर्ज को डीसैंट्रेलाईज कीजिये। एस0डी0एम0 को यह पावर्ज दे दी जाये। अगर कहीं पर कोइ बडा प्रोजेक्ट आ जाये तो बे ाक उसके लिये एडी ानल स्टाफ दे दें। जब तक आप इन पावर्ज को डीसैंट्रेलाईज नहीं करेगें तब तक इस प्रौब्लम का कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब भी कई ऐसे केसजि मौजूद है जिनमें 10—10 साल से मुआवजा नहीं मिला है। मैं अपने हल्के के बारे मे ंएक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । मई, 1979 में एक झाल गांव में जहां सारे गांव के खलिहान में गेहूं की फसल रखी गई थी वहां पर आग लग गयी थी। वह फायर एक्सीडेंटल फायर थी। उससे सारा गांव तबाह हो गया क्योकि सारे लोगों की ही फसल जल गयी। आज तक भी उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। उस केसज को एक भाटल कौक बनाया हुआ है। रैवेन्यू वाले एच0एस0ई0बी0. को भेज देते है और एच0एस0ई0बी0 वाले रैवेन्यू वालों को भेज देते है। कभी रैवेन्यू वाले यह कहते ळे कि यह

आग ट्रैक्टर से लगी है कभी कहते है कि भार्ट सरकिट की वजह से लगी है। मैं जब डिवैल्पमेंट मिनिस्टर था, मैने इसकी इन्कवायरी की थी । यह एक्सीडैंटल फायर थी ओर आज तक भी उसका मुआवजा दिया नहीं गया है। मैं यह कहताहूं कि इस बारे में मुआवजा मिलनाचाहिये और जो रूकावटें डाली जा रही है, उनको दूर किया जाना चाहिये क्योकिं यह एक सही केस है।

(13.00 बजे)

डिप्टी स्पीकर साहब, एक मामला मै ंरैवेन्यू डिपार्टमेंट और रैवेन्यू मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूं। मरे हल्के काएक पूरण नाम काआदमी है। उसने पार्टी ान का केस 1966 से फाईल कियाहुआहै लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। 1974 में उसकी फाईल गुम कर दी गई या डिस्ट्राय कर दी गई या चोरी हो गई। दूसरी फाईल चलाई गई। उस फाईल का भी पता नहीं चला फिर तीसरी फ ाईल चलाई गई। इसवक्त यह केस दो मिसलों मे ंचल रहा है। कमि नर तक इस केस का फैसला हो चुकाहै और पूरण के हम में फैसला हेा चुकाहे लेनिक आज तक उस भाई का जो पार्टी ान काकब्जा मिलना था वह नहीं मिला। मैने इस बारे मे एक सवाल भी पूछा था लेकिन उसका जवाब भी इनकुरैक्ट दिया गया। इस पर एक पैटि ान मैने रैवून्य मिनिस्टर को दी थी। इस आदमी के साथ सोली साल से खराबी हो रही है। मेरी दाखास्त है कि इसके साथ इन्साफ होना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैने पिछले सै ान में भी यह कहा था कि

मेरे हल्के में दस सडकें बननी बहुंत जरूरी है। मीटिंग्ज के अन्दर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तीन दफा वायदा भी कियाहै लेकिन वे बनने में नही आ रही है। आज सडकों के बारे में मेरा सवाल भी था। डिप्टी स्पीकरसाहब, आपदेखेगें कि साल्हावास के हल्के में 23 किलोमीटर सडकें बनी है जिन पर 25 लाख रूपया खर्च हुआ है। भजन लाल के हल्के में 93 किलोमीटर सडकें बनी है जिन पर 157 लाख रूपया खर्च हुआ हैं रामपाल के हल्के में 67 किलोमीटर सडकें बनी और 113 लाख रूपया खर्च हुआ है। मेरा कहना यह है कि इसतरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये और मेरे हल्के मैं जल्दी से जल्दी सडकें बननी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के बीच से जवाहर लाल नेहरू कैनाल गुजरती है और उसके साथ पुरानी कैनाल भी है।वहां पर वाटर लौगिंग है और एक–एक मील तक दोनों तरफ जमीन खराब हो गई है। इरीगे ान डिपार्टमेंट को कई दफा लिखा भी है लेकिन इरीगे ान डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोइ कदम नहीं उठाया है जिससे लोगों को रीलीफ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू कैनाल का सिस्टम फैलता जा रहा है, डिस्ट्रब्यूटरी फैल रही है लेकिन जहां गावं मिलते है वहां पर पुल नहीं बनाये जा रहे है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि लोगा खाल को तोड देते हैं इस तरह से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इसलिये साथ–2 पुल भी प्रोवाईड करनेचाहिये। डिपटी स्पीकर साहब, हमारे कुछ ग्राम सेवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिये गये थे। उनको काफी अर्सा गये हुये हो गया है और अब वे वापिस डिवैलपमेंट डिपार्टमेंट में आना

चाहते है। क्योकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनकी तरकी के कोई चांसिज नहीं है। मेरा सरकार को कहना है कि उनको वापिस आने देना चाहिये।

अब मैं कोसली के बारे में कहुंगा। वहां पर एक अस्पताल मंजूर हुआ था लेकिन वह बना नहीं है। वहां पर 1934 में एक मंडी मंजूर हई थी, वह भी आज तक नहीं बनी। वहां पर एक हाउंसिग कालोनी होनी चाहिये। वहां पर एक सैनिक स्कूल होना चाहिये क्योंकि वहां के बहुत से लोग फौल में है और आसपास के इलाकों से भी कम से कम हर घर से एक आदमी फौज मे हैं वहां पर एक टूरिस्ट कौम्पलैक्स भी होना चाहिये। सासरौली के लिये एक 33 के0वी0 कापावर स्टे ान मंजूर हो चुका है इसलिये उसका निर्माण होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मैं अपना भाशण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी संत कंवर।

(इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी हर स्वरूप बूरा पदासीन हुये)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमेन साहब मुझे भी बोलना है इसलिये मुझे समय दिया जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः आपको भीसमय मिलेगा। अब चौधरी संत कवंर को बोलने के लिये काल अपौन किया जा चुका हैं। आप बैठ जाइये। आपको बाद मैं समय मिल जायेगा।

चौधरी संत कवंर(हसनगढ़): चेयरमैन साहब, मै सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूं। यह सिंचाई की डिमांड है और सरकार हमसे इस डिमांड के लिये पैसा मंजूर कराना चाहती है। चेयरमैन साहब, आपको जानकारी है कि हमारे लोकदल के बाईस मैंबर है और सरकारने जैसा व्यवहारइन बाईस एम0एल0एज0 के हल्के के साथ किया है, उसकी मिसाल आपको इतिहास मे कहीं नहीं मिलेगी। आपको भी जानकारी होगी कि हामरा इलाका बाढ का इलाका है और बहुत ज्यादा बाढ हमारे यहां आती है। लोगों काबहुत ज्यादा नुकसान इस बाढ की वजह से होता हैं चेयरमैन साहब, काफी रूपयामेवात के इलाके , जहां के चौधरी खुर ीद अहमद है, पर खर्च किया जा रहा हैं । नौकरियों में भी ये लनोग अपने इलाके के लोगों की ही भर्ती कर रहे है। चेयरमैने साहब, हमारे यहां एक पाकसमा ड्रेन है और यहांपर पत्थर रखा हुआ है, लेकिन आज तक इसकी खुदाई नहीं हुई है। ठाकुर बरी सिंह हमारे यहां गिवैन्सिज कमेटी में आते रहते है और हमने बाकायदा यह मामला उठायाथा लेकिनआज तक म ीन भेजकर खुदाई नहीं हुई है। और हजारों एकड जमीन मेंपानी खडा है। चेयरमैन साहब, हमारे चहां एक कसरैटी गांव हैं सारे इलाके में यही एक गांव है जहां पर पीने कापानी नहीं हे औरतीन मील तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मीठा पानी हो। रोहतक जिले में सिर्फ यही एक गांव है जहां मीठा पीनेका पानी भी नहीं है। इस कसरैटी गांव मे कोई आउटलैट नहीं है जिसके कारण सारी जमीन बारानी है क्योकिं जो रजवाहा इस गांव

के पास से गुजरता है उसकी लाइनिंग करते समय एक्स0ई0एन0 ने दूसरे गांव वालों सेपैसा लेकर राजवाहे को उंचा उठा दिया जिससे इसगांव में पानी नहीं पहुंचता है और यह बात मैं कई बार मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाया हू। सारे गांव वाले एक्स0ई0एन0 और एस0इ0 से भी मिले ओरउनको बताया कि हमको इतनी तकलीफ है लेकिन अभी तक भी इस बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की गई।

अब मैं डिंमाड नम्बर तीन जो होम की है उस पर ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहताहूं। चेयरमैन साहब, आप जानते है कि हरियाणा के अन्दर और खासकर सोनीपत ओर रोहतक के अन्दर ला एंड आर्ड की क्या हालत हैं कांग्रेस एम0एल0एज0 ने भी पार्टी के अन्दर इस बात को उठाया था लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चेयरमैन साहब, सोनीपत और रोहतक के अन्दर जितने भी पूलिस के थाने है, वे आज रि वत के अडडे बने हुये है। मैं सदन को सोनी पत के एक केस के बारे मे बताना चाहता हूं। वहां पर एक बाल्मीकि लउके को सिकी लडाई झगडे के सिलसिल मे गिरफातार कर लियागया। कुछ समय बाद दोनों पार्टीज मे राजीनामा हो गया। उस लडके को लेकरदोनो पार्टीज थाने में जाने लगी। बाल्मीकि के लडके ने कहा कि मै ंथाने में नहीं जाउंगा क्योकि वह पूलिस क मार से बहुत अधिक डरा हुआ था लेकिन जब बिरादरी के लोगक उसको

जबरदस्ती थाने मे ले जाने लगे तो उसी समय स्टै न पर रेल आ गई और उस लडके ने थाने के डर से खुदकु ी करली।

चेयरमैन साहब, इसी तरह से हरिजनों की एक लडकी की मौत हुई हैं इस बारे में मैं आपको यह बतानाचाहता हूं कि रोहतक के अनदर एक आठवींऔर नौवी क्लास मंपढने वाली लडकी के साथ बडा भारी अतयाचार हुआ। चेयरमैन साहब, लडकियों सब की एक समान होती है। आपकी हो, मेरी हो या किसी और की हो, हम सब को बडे आदर के साथ उनसे सव्यवहार करना चाहिये। एक लउकी सुबह अपने स्कूल में गई और वहां से उसको कोई बुलाकर ले गया। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, यह बात जो संत कवंर जी बता रहे है, यह तो एक साल पुरानी बात है। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कवंरः अगर एक साल पुरानी बात है तो भी यह आपके सरकारी विभागों का..........................है। .... (ोर)

श्री सभापतिः यह निकम्मापन भाब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।

चौधरी संत कवंरः चेयरमैन साहब, मैंने कोई ऐसा बूरा लफज नहीं कहा है जोकि आप एक्सपनज करवा रहे है। चेयरमैन साहब, मैं भाई बीरेन्द्र सिह जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस

स्कूल में वह लडकी पढती थी, उस स्कूल का जो मालिक था, वह कांग्रेस यूथ का जनरल सैक्रेटरी था। (ाोर) वहां से उस लडकी को कोई बुलाकर ले गया, आधी छुट्टी के अन्दर लडकिया घर गई तो उनके घरव0ालों को किसी ने बताया कि आप की लडकी को कोइ स्कूल से बुलाकर लेगयाहै। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः संत कंवर जी, फिर आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की? क्या आपने पुलिस वगैरह में कोई रिपोर्ट दर्ज करवायी?

चौधरी संत कवंरः जब लडकी वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिये गये तो उनहोने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और टालमटौल कर दिया। ाम के वक्त तक लउकी की तला ा जारी रखी गयी। उस लडकी की ला ा रेाहतक मैडिकल कालेज के पास एक तालाब से मिली और डाक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक उस लडकी के साथ रेप किया गयाथा और बाद में मारा गया था। मैं डाक्टर मंगल सैन और चौधरी हरिचन्द हुड्डा, चार बाररोहतक में एस0एस0पी0 साहब को मिले डी0आई0जी0 गुड़गांव रेंज को भी मिले, आई0जी0 साहब को भी इस बारे में ि ाकायत की और फिर गृहमंत्री महोदय के दफतर में भी जाकर के यह सारी बात कही। फिर चेयरमेन साहब, आप ही बताये कि हम इसके इलावा क्या कर सकते थे? हम अपने वजीरों के नोअिस मे ंभी यह बात लाये लेकिन आज तक उस पर कोइ कार्यवाही नही की गयी।। हम जलसे–जलूसों में भी इन बातों का जिक करते रहे। इस कारण से

मेने पुलिस के लिये ....का भाब्द इस्तेमाल किया था। इसलिये मैं यह बातना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत और रोहतक दोनों जिलों में इस तरह की ला एंड आर्डर की स्थिति चल रही है कि किसानों के टयूबवैल्ज तक भी चोरी हो जाते है। जो सामान बाहरखेतों में उनकी जरूरत का रखा होता है, वह भी चोरी हो जात है जिससे बेचारे किसानों को काफी नुकसान उठाना पडता है। किसानों को खेतों के अन्दर कोई भी सामान महफूज नहीं है। बार–बार वहां पर चोरियां हुई है। सांपला के पास एक ट्रेन में डकैती हुई। लउकी काकत्ल किया गया लेकिन अभी तक इसमामले मे कोई गिरफतारी नहीं की गयी। क्योंकि इनके यूथ कांग्रेस के लोगों का वह स्कूल था जहां पर वह लडकी पढती थी। हमने डी0आई0जी0. साहब को कहा कि हम तीन चार आदमियों के नाम आपको बताते है, असव य ही उन से आप के कातिल कापता लग जायेगा। आप इन लोगों को गिरफतार करिये लेकिन कोई भी अफसर उनमैं से किसी को गिरफतार करनेके लिये तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब, आज अगर हम आपके सामने उन नामों को बतायेगें तो हमें वि वास है कि उन्ही में से आपको कातिल मिलेगें। लेकिन सरकार इस बात की इंक्वायरी करवाने के लिये तैयार नहीं होगी क्येाकिं इससे आपकी पार्टी की बदनामी होगी। इस तरह से आपकी पार्टी ऐसे लोगों को पनाह होती है या भाह देती है जिससे ऐसे लोगों को होसला बढ जाता है।

चेयरमैन साहब, इसी तरह से एक बदमा ा को पुलिस ने गिरफतार किया और जब पुलिस उस बदमा ा का मुंह काला करके बाजार में उसका जलूस निकालने के लिये तैयार हुई, वहां पर एक श्री बरा नाम के आदमी जोकि मुख्यमंत्री महोदय के काफी नजदीक माने जाते है, पुलिस स्टे ान में गये ओर एस0एच0ओ0 से बातचीत करके आये ओर उस बदमा ा का मुंह धुलवाया और उसको बाहर ले आये, हांलाकि उस बादमा ा काथाने में मुंह काला किया जा चुका था। उसको वापिस थाने के अन्दर ले जाया गया और उसका मुंह साफ किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कारनामें इनकी पार्टी के लोग करते है। मैं आपको बताता हूं कि चेयरमैन साहब, रोहतक, झज्जर, मेहम, सोनीपत , बहादुरगढ बगैरह मे जितने भी थाने है, वहां पर सब मेंरि वत खुले आम चलती है ओर इसकारण इन दो जिलो में डकैतियां बहुत हो रही है और मुलजिम पकडें भी नहीं जा रहे है।

चेयरमैन साहब, मैं आपको बताताहूं कि मोरखेडी के पास एक सरंपच जोकि बलियाना कारहने वाला था, ने ि ाकायत की कि एक चावलों का भरा हुआ ट्रक समगलिंग के लिये जाया जा रहा है। उसका जो मूलजिम था, वह मटिन्ड गांवका रहने वाला था। उस को पकड कर जब थाने के अन्दर लाया गया तो मैं अचानक वहां पर ही बैठा था औरवहां पर ही टेलीफोन पर थानेदार पर दबाव डाला गयाकि चुंकि यह आदमी किसी मंत्री महोदय के कुनबे से संबंधित है, इसलिये इसको छोड दिया जाये।

चेयरमैन साहब, कुछ दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री महोदय खरखौदा में गये तो इसी आदमी ने मुख्यमंत्री महोदय को हाथी के उपरचढाकरउनका जलूस निकाला। इससे, चेयरमैन साहब, आप अन्दाजा लगकासकते है कि डकैतियों में और चोरियों में पुलिस को अगर मजबूर कियाजाए तो फिर ला एंड आर्डर की हालत कैसे सुधर सकती है, इसी तरह से सहमदपुर के बार्डर पर चावलों का एक ट्रक नरेला की तरफ ले जाया जा रहा था और उस ट्रक में हमारी राज्य मं?ी श्रीमती भाान्ति राठी जी को बेटा बैठा था। जब उसे रोका गयातो उसने थानेदार को कहा कि मैं मंत्री काबेटा हू। इस मामले में भी थानेदार के उपर एस0एस0पी0 द्वारा दबाव डाला गया। चेयरमैन साहब, हमारे दोनों जिलो ंके अन्दर ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है। भगोलपूरी और सुलतानपुरी के अन्दर बडे–बडे चोरों के गैंगज है जो कि बाकायदा सोनीपत ओर रोहतक मे आते है और चारियें वे डाके डाल करके लोगों को लूट कर वापिस चले जाते है। लेकिन वे गैंगज पुलिस से मिले हुये है और रात को व दिन को किसानों के खेतों से उनकी मोटरें और दूसरा कीमती सामान, जोकि किसान की एक किस्म की सम्पति होती है जिसके बगैर किसान का कोई गूजारा नहीं है, उठाकर ले जाते है। इसतरह के कत्ल के कई केसिज है जिनमें सरकार ने जानबूझकर कर अपराधियों को गिरफतार नहीं किया है ओर न ही करनाचाहती है कायोकिं वे सभी इनके अपने ही पाले हुये आदमी है। दूसरी तरफ`हालत यह हो रही है कि लोग आजकल थानों में जाने से भी घबराते हैं लोग कहते हे कि पहले हरेक काम के लिय

फीस देनी पडती है। किसी की ि ाकायत करने जाना हो तो पहले सिपाही, फिर हवलदार और थानेदार को पहले रि वत देनी पडती है। अगररि वत न दी जाये तो किसी भी ि ाकायत पर कार्यवाही नहीं होती। इसबारे में हमने आई0जी0 साहब ओर पोसवाल साहब को भी चिटठी लिखी कि आप कृपया इसतरफ ध्यान दे। गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, इस तरह की पुलिस की धांधलियों कोसमाप्त किया जाये लेकिन कोई मंत्री या कोई सरकारी अफसर इस तरफ ध्यान देने के को तैयार नहीं है। (घंटी)

चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर की डिमांड पर आता हूं। चेयरमैन साहब, मै। इस डिमांड नं0 17 पर बोलने के लिये आपके दो तीन मिनट लुंगा। आज किसानों की क्या हालत है? आज किसान की हालत बहुत बुरी है। एक तरफ तो ओले पडे है, दूसरी तरफ बरसात हो गयी और किसान बेचारा बुरी तरह से मारा गया। किसानों के खेतों में बहुत ज्यादा पानी खडा हो गया, गेहूं की फल बुरी तरह से बरबाद हो गयी और गेंहूं की दो से तीन मन यील्ड पर–बीघा कम हुई है। सरकार यह कहती है कि 400 रूपये पर–एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जायेगा लेकिन बहुत थोडा है। हमारे को इस बारे में कोई बात कहने ही नहीं दी जाती है ओर अगर कुछ कहते है तो मा ाल द्वारा बाहर निकलवा दिया जाताहै। आज हमें नंगा होकर यहां पर इसलिये बोलने पर विव ा होना पडा है क्योंकि आज किसानों के हितों को बुरी तरह से कुचला जा रहा है उसे उसकी जिन्स की सही

कीमत नहीं मिल रही है। जो फसलें ओले पडने के कारण या बरसात के कारण किसानों की बरबाद हो गयी है, उन का मुआवजा सरकार की तरफ से सही रूप में नही दिया जा रहा है, इसलिये हमें यहां पर आवाज उठाना पड रही है। गरीब किसान की आज यह हालत है कि उसकी एक छोटी बच्ची जोकि आठ–नो साल की है, अपने सिर पर तब तक रहताहै जब तक उसकी अर्थी नहीं निकल जाती। बेचारे गरीब लोग इस तरह से अपने परिवारों को गुजारा कर रहे हैतरफ से सही रूप नहीं दिया जा रहा है इसलिये हमें यहां पर आवाज उठानी पड रही है परन्तु सरकार बिल्कुल चुप है। उसे किसी गरीब के उपर किसी किस्म की कोई दया नही आ रही है। गरीब किसान की आज यह हालत है कि उसकी एक छोटी बच्ची जोकि आठ नौ साल की है अपने सिर के उपर गोबर की टोकरी उठाती है और उस गोबर की टोकरी का भार उसके सिर पर तब तक रहता है जब तक उसकी अर्थी नहीं निकल जाती। बेचारे गरीब लोग इस तरह से अपने परिवरों का गुजारा कर रहे है लेकिन सयह सरकार टस से मस नहीं हो रही हाअैर गरीब किसानों का खून चूस रही है।

चेयरमेन साहब, यहां पर किसान की फसल के बीमे की बात भीकही जाती है कि किसानों की फसलों के लिये सरकार बीमा करना चाहती है लेकिन इस बीमे की रकम केवल 28 लाख ही रखी है जोकि बहुत थोडी है। आप ही बताइये कि इतनी थेडी राशि से किसानों का भला नहीं होने वाला है। फिर इस पर भी

सरकार को सबर नहीं। सरकार यह कहती है कि इस पैसे को भी तब किया जाएगा जब फसलों की एवरेज निकाली जायेगी। चेयरमैन साहब आज अगर एक गांव में ओलने पडते है और आधा दूसरे गांव मे ओले नही पडते तो इस हालत में सरकार क्या करेगी। इसलिये सरकार को सारी बातों का ध्यान रखना चाहिये।

अब मैं डिमांड नम्बर 22 पर कुछ बोलना चाहता हूं जो कोआपरे ान विभाग से संबंध रखती है। इस विभाग मं लेागों की अप्वायंमैंटस के बारे में काफी गडबड हुई है। केवल एक ही कौम के 100 मे से 80–90 लडको को लिया गया है या फिर दूसरी तरफ मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से जो लिस्ट थी उसमें से लडकों को लिया गया है। मतलब कि ठाकुर बिरादरी ओर बि नोई बिरादरी के लोगों को ही नौकरिया दी गयी है। एक कौम का अछुत बना दिया, दुसरी को यह कह दिया कि आप तो चौधरी चरण सिंह जी के आदमी हो। जो जाट थानों में लगे हुये थे, उनको एक दू मुधबन में भेज दिया। चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो थानों में लगे हुये जाट बिरादरी के आदमी थरे उन सब को पूलिस लाइन में भिजवा दिया गया।

Mr. Chairman: It is neither in the interest of your community nor of these officers.

चेयरमैन साहब, अब मैं जनरल एडमिनिस्ट्रे न पर बोलना चाहता हूं। हमारे तमाम अफसरों को ये अपनी–2 मर्जी की जगह लगा रहे है। यही नहीं, बकायदा लिस्टें बनने लग रही है,

क्योकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हे इसलिये अपनी मर्जी के अफसर लगाने लग रहे है। (विघन) हम तो इसलिये नहीं घबराते कि हम तीन साल तक लडर्ते रहे अब तो सिर्फ 15 दिनों का मामला है। अगले महीने की 10 तारीख को मामला तय हो जाएगा। जनता हमारी सरकार बनवायेगी और हम उधर के बैचों पर होगें। (विघन) चेयरमैन साहब, एक तरफ तो सरकार कितना ख्,ार्च करने लग रही है। ये कहते है कि इस घाटे का हम पूरा करेगें। आप घाटे को पूरा करना चाहते हैलेनिक मै बताता हूं। आप किसी भी जिले में चले जाये।..

....

....ये जीपें तो अफसरों को इसलिये मिली हुई है ताकि वे गांवों में लेगों की तकलीफे सुनने के लिये जाये। केवल इतना ही नहीं है ये जीपें दिल्ली तक भी जाती है।..............

....

....

................................जिस ड्रादवर की डियूटी नहीं थी उसको घर से बुला कर ल गया और खुद जीप चलाने लगा रास्ते में जब जीप का एक्सीडेंट होने लगा तो ड्राइवर को साईड पर बिठा दि। उस एक्सीडंट में ड्राइवर मारा गया। बाद में कागजों की खाना पूरी कर दी कि ड्राइवर जीप चला रहा था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार पैसा बचाना चाहती है तो वह इस पर अकुं ा लगायें। कार्पोरे ांज पर जिस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, वह सबको मालूम है।...

....

.....

Finance Minister(Chaudhri Khurshed Ahmed): Sir, this general type of allegations cannot be allowed on the floor of the House against a section of employees of a Corporation.

Mr. Chariman: They are expunged.

श्रीमती डा0 कमला वर्मा (यमुनानगर): सभापति महोदय, मैं डिंमाड नं03 पर बोलना चाहती हूं जिसमें 27 करोड 92 लाख 33 हजार 64 रूपये मांगे गये है। पैसा तो इन्होने ले लिया। इसका मुझे दुख नहीं लेकिन इस वक्त हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसको अगर अच्छी तरह से देखा जाये तो सचमुच भार्म आतीळैं इस वक्त हरियाणा में बसों के अन्दर बैकों के अन्दर और बस–डिपुओं के अन्दर किस तरह से डकैतियां और चोयिा ं हो रही है? हरियाणा की पुलिस चाहे कितने ही नये पुलिस स्टे ान खोल ले लेकिन क्या वह हरियाणा की जनता को वि वास दिलायेगी कि वह लोगों के जान व माल की रक्ष करेगी? आज हरियाणा के अन्दर लडकिासें की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यमूना नगर में अक्तुबर मास में एक केस हुआ। एक गरीब आदमी जोकि दिहाडी पर काम करने वाला था वह रात को पेपर मिल में डियटी पर गया। बाद में उसकी घर वाली अपने घर में अकेली थी। वह लडकी बहुत दलेर उसका नाम चिन्ता है। लेकिन 24 अक्तूबर की रात को 11 बजे उसके घर के अन्दर कोई व्यक्ति

घुस गया। उस लडकी ने बडी हिम्मत की, जब उस व्यक्ति ने उसकी इज्जत लुटने का प्रयास किया तो बाहर उसके आंगन में एक कुल्हाडी पडी थी जिसे उसने उस आदमी की तरफ फैंक दिया। मैं मानती हूं कि उस कुल्हाडी को फैकने की वजह से उस आदमी को चोट आई होगी लेकिन मैं उस लडकी को बधाई देती हूं कि उसने अपनी इज्जत बचपाने के लिये इतनी बहादरी दिखाई। दूसरे दिन उस लडकी के पति को पूलिस पकड कर ले गई तो मेरे पास वह लडकी आई । मैने उस लडकी से कहा कि पहले आप मुहल्ले के आदमियों को बुला कर लाओ ।अैरअगर वे मुझ को वि वास दिलायेगें कि तुम रात को अकेली थी ओर घर में वह आदमी घुसा था तो मैं आपकी सहायता करूंगी। थोडी देर बाद उस मुहल्ले के कुछ आदमी और कुछ औरतें उसके साथ आ गये और उनहोने मुझे व्रि ववास दिलाया। मैं उनके साथ थानें के अन्दर गई। एस0एच0ओ0 ने मेरी बात सुनी और कहा कि हम देख लेगें। लेकिनइतने मकें ही वहां डी0एस0पी0 साहब आ गये मैने कहा चौधरी साहब अगर एक लडकी अपनी इज्जत बचाने के लिये ऐसा काम करती है तो क्या यह गलत हैं यह ठीक है कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है तो डी0एस0पी0 ओर पोसवाल साहब से इस बारे में ुोन पर बात की ओर बताया कि अगर सैल्फ डिफैंस में कोई लडकी ऐसा करती है तो क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे? उन्होनें कहा कि हम ऐसे केसिज में मदद करते है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। केस उसी आदमी का दर्ज किया उस के पति को नाजायज तंग किया गया फिर उस की पांच छः सौ

रूपये खर्च करके सै ान कोट्ढ से जमानत हुई ि कच्ची दिहाडी पर काम करने वाले ने कर्ज लेकर जमानत कराई।आज भी केस चल रहा है। क्या गरीब आदमी को यही न्याय मिलता हैं? ऐसी बातों को देखते हुये कौन सी लडकी अपनी इज्जत बचाने के लिये सैल्फ डिफैंस में आगे आयेगी। क्या गृह मंत्री जी मुझे इस बात का जवाब देगें कि ऐसी लडकियों की वे क्या सहायता कर रहे है? आज पुलिस ने हद ात का वातावरण पैदा किया हुआह ै इसी तरह से दो महीने पहले नारायणढ में एक घटना हुई। एक ि ामला के डी0आई जी0 ने अपना मकान बनाने के लिय ि ामला से लकडी लाने के लिये एक ट्रक हायर किया। वह नानक सिंह का ट्रक था जो नारायणगढ का रहने वाला था। जब वे वापिस नारायणगढ पहुचे तो रास्ते में नानक सिंह अपनी लकडी अतारना चाहता था जो वह उसी ट्रक में लाया था। उस ट्रक में लकडी लाने वाला डी0आई0जी0 का रीडर था उस रीडर के साथ ट्रक मालिक की कुछ तू–तू–मैं–मैं होगई । उसने पुलिस को टेलीफौन कियाओर नानक सिह व अन्य दो आदमी अरैस्ट करवा दिये। उन तीन आदमियों की थाने में पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद सारे भाहर के अन्दर दह ात फैलाने के लिये उनके मुह काले किये गये। तीनों के हाथ उंचे करके मजबूर किया गयाकि तुम बोलो कि हम डकैत है ओर चोरी करते है। इस प्रकार की दह ात अगर पुलिस ने सारी जनता के अन्दर फैलानी है तो गृह मंत्री जी को वि ोश ध्यान देने की आव यकता होगी। आज पुलिस के अन्दर अगर कोई रिपोर्टग लिखवाने जाता है तो उसकी

रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर किसी मारपीट के मामले में लिखी भी जाती है तो मरने वाले को भी पैसे देने पडते है और मार खाने वाले को ीाी पैसे देने पडते हैं हमारे यहा जेलें भी है जिनको सुधार घर बनाने की योजना थी। जनता राज में एक जेल रिफार्म कमि ान बना था। मैं जानना चाहती हूं कि उसने जो ीाी सिफारि ों की थी, वे लोगों के सामने और यहां पर हम विधायकों के सामने क्या `रखी गई है? हम जानना चाहते है कि जेलों के अन्दरक्या सुधाार किया गया है। मैने एक बात सुनी थी कि कैदियों को चीनी वाल चाय मिला करेगी लेकिन वह आज तक नहीं मिली। मैं जानना चाहती हूं कि कमि ान ने जो सिफारि ों की थी, उनको क्यों नहीं माना गया है? लगता है सरकार चाहती नहीं, इसलिये कोई काम होता नही। जेलो ं में क्या हो रहा है आप को सुनकर आ चर्य होगा एक आम आदमी के पास एक छटांक नही, बल्कि कुछ मिली ग्राम या कुछग्राम अफीम हो तो उसको जेल की हवा खानी पडती हैं गृह मंत्री जी बतायेगें कि क्या यह तथ्य है कि अम्बाला जेल के अन्दर वहां की डिप्टी सुपरिन्टेंडैट जेल के अन्दर ही अफीम बेचती रही। यह नवम्बर की बात है। मुझे पता है कि अम्बाला जेल के अन्दर अफीम बेची गई है। लेकिन आज तक कोई एक ान नहीं लिया गया। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अफसर होने के बाद उसको इतनी छूट है कि वह जेल के अन्दर अफीम छिपा कर भी बेच सकती है जबकि आम आदमी के पास कुछ ग्राम भी अफीम हो या उसको बेच दे तो वह जेल की हवा खायेगा। यह कैसी व्यवस्था है? क्याक नून का मापदंड माने

के लिय अलग अलग राज होगा? सभापति महोदय, जेल में कुछ अन्य भी ि ाकायते है काम करने वाले अुसरों को यदि स्टेटस और वेतन ठीक न मिले तो उनके अन्दर कुछ विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। जेल रिफार्म कमि ान ने जेल अधिकारियों को वेतन देने के लिये सरकार से कुछ सिफारि ों की थी लेकिन उनकी पे में कुछ एनोमलीज रहगई है। इस सरकार ने असिस्टेंट सुप्रिन्टैंडैट (जेल) की पोस्ट तक तो एनेामलीज दूर की दी लेकिन डिप्टी सुप्रिन्टैंडैट और सुप्रिन्टैंडैट (जेल) के वेतनमानों में जो फर्क बताया जाता था, उसके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस लिये जेल अधिकारयियों में फस्ट्रे न आना स्वाभाविकहै । इसी तरह से मैडिकल अफसर का स्केल 940–2000 का हो और सुप्रिन्टैंडैट का स्केल 9001700 का हो जबकि परिजन एक्ट के अनुसार मैडिकल अफसर सुप्रिन्टैंडैट के अंडर होता है लेकिन इस पे–सकेल का डिफरैंस होने के बाद यह अंडर कैसे रहेगा? सभापति महोदय, सुप्रिन्टैंडैट (जेल) यदि 900–1700 के स्केल में होना तो मैडिकल अफसर उसकी बात नहीं सुनेगा। एडमिनिस्ट्रे ान के अन्दर डिसीप्लिन कैसे रहेगा और कानून की व्यवस्था कैसे पूरी होगी? इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहती हूं कि इनके वेतनों मेक जो फर्क है उसको दूर करने के अव य कोि ा ा करे। इसके अलावा होम मिन्स्टिर साहब यह भी बतायें कि जिस जेल आफिसर ने जेल के अन्दर अफीम बेची है उसको क्या सजा दी गई है ओर अब वह अफसर कहां पर लगाहुआ है? सभापति महोदय, मुझे पता चला है कि उस

जेल आफिसर को जीद में डी0पी0ओ0 की पोस्ट पर लगाया हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने उसके खिलाफ क्या एक ान लिया है?

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 4 पर बोलना चाहती हूं। सरकार ने कहा है कि ओलावृश्टि और जयादा बारि ा के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गई है उनको मुआवजा दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं अम्बाला जिलें में जिन किसानों की फसलें खराब हुई है,त्र उनके बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हू। अम्बाला जिले मं कुछ ऐसे भी लोग खेती करने वाले है जिनकी गेहूं की फसल तो ठीक है लेकिन उस गेहूं की फसल के साथ वाले एक या दो एकड में चना, सरसों या तोरियां बोया हुंआ था और वह सारी फसल नश्ट हो गई हैंउनको मुआवजा दिया जायेगा। सभापति महोदय, बार–2 बारि ा होने के कारण हमें यह भी डर है कि गेहूं की फसल के अन्दर भी दाना पडेगा या नहीं क्यों कि लगातार बारि ा होने के कारण गेहूं की फसल पर जो बूर आता है वह नीचे गिर गया है और बूर नीचे गिर जाने से सिट्टी में दाना पूरा नहीं पडता। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि गेहं की फसल भी पूरी तरह से नहीं हो पायेगी। जिन किसानों की गेहू की फसल इस तरह से नश्ट हो गई है या कम पैदा होगी उनको भी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहियै। पटवारियों व तहसीलदारों को आदे ा मिलने चाहिये कि ऐसे किसानों की

सहायता के लिये भी पूरी जांच की जाये। सभापति महोदय, यह हसरकार बडे बडे दावे करनी है कि हमने हरिजनों औ भूमिहीनों को सरप्लस जमीन बांट दी है। लेकिन मैं यहकहना चाहती हूं कि मेरे हल्के मेंरेलवे कर्व ाप यमुनानगर के पास महरमपुर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ हरिजनों को सरप्लस की जमीन दी गई थी लेकिन इस सरकार ने उस गांव के 8 हरिजनों को बेदखल कर दिया जो बेरोजगारी की वजह से मारे–2 फिर रहे है। वे कहां से अपनी रोटी कमायेगें? इसी तरह से सभापति महोदय, मरे हल्के मेंएक खजुरी गांव हैं उस गांव में 1966 में रूप सिंह जमीदार की 64 एकड सरप्लस जमीन थी जो हरिजनों मे और भुमिहीनों में बांटी गई थी लेकिन रूप सिंह ने कोर्ट में जाकर अपने रि तोदारों के नाम जोकि यू0पी0 या राजस्थान में रहते है अनाट करवा जी है ओर उन भूमिहीन गरीब किसान जिनके नाम मंगत सिंह और चांद सिंह वगैरह है उनसे वह सरप्लस की जमीन आज 6–7 वर्श के बाद वापिस ले ली है। इसलिये सभापति महोदय, इस सरकार से मैरी प्रार्थना है कि जो सरप्लस की जमीन भूमिहीनों और हरिजनों को दी गई है उसे उनके पास ही रहने देना चाहिये। उसे मंत्री अपने रि तेदरों या मिलों को ही न बांटे। यह एक तथ्य है कि मंत्रियों ने अपनी मनोपली बना रखी है। जितनी सरप्लस की जमीन है या कास्टोडियन की जमीन है या पंचायत की भाामलात जमीन है वह अपने भाई भतीजों में ही बांट रहे है। इसलिये मैं कहती हूं कि सरकार को इतने बडे बडे दावे नहीं

करने चाहिये कि हमने हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन बांटी ळै। यह सब थोथे दावे गरीब लोगों को धोखा देने के लिये है।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर पांच के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं। हरियाणा के परिश्रमी व कु ाल लेाग हरियाणाा विकास के लिये बहुत काम कर रहे है और बहुत सी ओद्योगि वस्तुयें बन रही है जो बहर भेजी जाती है। इसलिये हरियाणा प्रान्त के लिये यह गौरव की बात हैं यहां पर चाहे साईस कासामान हो, चाहे हैंडलूम कपडों का काम हो, याहे जुते हों और चाहे जगाधरी के बर्तनों का या सोनीपत में साइकिलों का काम हो इन कामों में हरियाणा ने काफी प्रगति की है और काफी सामान बाहर भी भेजा जाता है। लेकिन इस सरकार ने फैक्टरीज के लिये ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत रा–मैटीरियल पर भी प्रचेज टैक्स लगा दिया और रा–मैटीरियल से कोइ चीज बन जाती हे तो उसके उपर भी प्रचेज टैक्स लगा दिया। सभापति महोदय, हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट की क्लाज 9 और 24 के अन्तर्गत सरकार ने यह आदे ा दिये है। इस सरकार को देखना चायिहे कि इस एक्ट के अन्दर सैकै ान 9 और 24 के अतिरिक्त एक सैक ान 12 भी है। जिसके अन्दर स्पश्ट लिखा हुआ है कि वह आइटम चाहे रा–मैटीरियल कीहो या चाहे रा–मैटीरियल से बना हुआ पक्का सामान हो अगर वह भारत से बाहर भेजा जायेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने केवल मात्र निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये व व्यापारियों को

काम बढाने के लिये इंडियन सेल्जत टैक्स एक्ट की सैक ान 286 के माध्यम सेकुछ सुविधायें भी दे रखी है। सभापति महोदय, भारत सरकार को विदे ी मुद्रा की आव यकता है क्योकि हमें तेल बाहर से खरीदना पडता है। यदि भारत तेल बाहर से खरेदेगा तो विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी। भारत सरकार एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को फ्रेट चार्जिज में वह सेल्ज टैक्स में रीबेट देती हे और व्यापार को बढावा देने के लिये सस्ते रेट पर ऋण भी देती है ताकि हमारा सामान बाहर जाये और बाहर से हमें विदे ी मुद्रा मिले। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस प्रकार का एक्ट बना कर व्यापारियों पर प्रचेज टैक्स लगा कर हरियाणा का जितना माल बाहर जाता हे उसके उपर एक प्रकार से प्रतिबधं लगा दिया है। सभापति महेादय, रा—मै ।टीरियल लेने वाला व्यक्ति भी इस प्रेचज टैकस से दुखी हे और उसके बाद जब वक कारखानें में सामान के रूप में माल तैयार हो जाता हे तो उसके उपर भी प्रचेज टैक्स लगता है। आज जगाधरी के अन्दर या फरीदाबाद के अन्दर जो उद्योगपति अपना माल बना बाहर भेजते है इस तरह से टैक्स लगा कर इस सरकार ने उनकी कमर तोड दी है। जिस प्रकार से कई वर्श पुराना उन पर प्रचेज टैक्स लगा कर पैनल्टी के रूप मं उनहें तंग किया जा रहा हैं। इससे व्यापरी निरा ा है। इसक`परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आएगी ओर हरियाणा की राजस्व आय में भी कमी आयेगी। इसी तरह से सभापति महोदय एक्साइज एंड टैक्ले ान के अन्दर भी अजीब ही नीति बनी हुई है। चाहे उससे हरियाणा का अहित ही हो। इस बारे में मैने पिछले सै ान में भी

कहा था कि यमुनानगर में लकडी का बहुत काम होता है वहां पर टिम्बर मार्किट है लेकिन इससरकार की गलत नीतियों के कारण वहां पर जितने फोरेस्ट लीज होल्डर है वे यह महसूस करते हे कि हरियाणा में 4 परसैंट टैकस टिम्बर पर लगता है। जबकि जम्मू क मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेशमें ले गये है। यमुनानगर की लकडी मंडी आज विरा सी पडी हैं टिमबर से चलने वाले आरा म ीन के व्यवसाई अलग दुखी है। लकडी की चिराई करके बक्से बनाने पर भी सरकार ने अलग 4 प्रति ात सेल्ज टैकस लगाया हुआ है। सरकार को अपनी टैकस नीति पर पुर्नविचार करना चाहिये। कम से कम अपने पडौसी प्रान्तों के साथ तो कुछ तालमेज रखना चाहिये ताकि व्यापारियों के मन में रोश न रहे और हरियाणा को भी घाटा न पडे।

सभापति महोदय, हरियाणा सरकार को अपने व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिये। आज उनकी सुविधायें नहीं मिल रही है इसलिये वे मजबर हो कर हरियाणा प्रान्त से बाहर अपने उद्योग लगाने की सोच रहे है। खासकर यमुनानगर और जगाधरी के व्यापारी प्रान्त से बहार अपने उद्योग लगाते जा रहे है। हरियाणा सरकार को इस बारे में गहराई से सोचना चाहिये। व्यापारियों पर सरकार द्वारा अपनी गलत नीतियों से दबाव नहीं डालना चाहियें। इससे उतपादन और रीाजस्व दोनों में कमी आयेगी। (घंटी) सभापति महोदय, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जो बातें अभी मैने हाउस में रखीहै उन पर

सरकार को व्यवहारिक रूप देनाचाहिये। इन भाबदों के साथ मैं आपका धन्वाद करते हुये आना स्थान लेती हूं।

मास्टर जोगी राम(असन्ध–अनुसुचित जाति): सभापति महोदय , आज सदन के अन्दर वर्श 1981–82 की अनुदान मांगो पर चर्चा हो रही है। मैं डिमांड नं02, 15, 5, 17 पर बोलना चाहूगां हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह वर्श उत्पादकता का वर्श घोशित कियाहै। देश का किसान, दे ा का मजदूर जो मेहनत करता है जो खेतों में काम करता है और फक्टरीज में काम करता है उनकी भावनाओं को देखते हुये उन का मान बढ़ाने के लिये देश कीप्रधान मंत्री इस बात को लेकर आगे चली है इसलिये इस देश के अन्दर एक परिवर्तन की संभावना है। कुछसमय पहले प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के सामने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा था। उस समय जो लोग गरीबों के विरोधी थे, जो लोग समाज में दलित वर्ग का उत्थान नहीं चाहते थे वे सब लोग इक्ट्ठे हो गये थे और इण्डस्ट्रीयलिस्टस यानि उद्योगपति और पंजीपति सीाी लोगों ने मिल कर उस वक्त कांग्रेस पार्टी को पराजय दी थी। अब फिर दुबारा मेहनतक ा लोगों के कारण ही श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हाथ मजबूत किये गये है। दलित वर्ग को आगे ले आने के लिये नया 20 सूत्री कार्यक्रम आगे आया है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह पदासीन हुये)

आज हमारे दे ा के अन्दर स्थिति ऐसी है कि किसान और मजदूर को उपर उठाना है। प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला सूत्र सिचांई से संबंधित है। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने हमारे हरियाणा को रावी–'ब्यास का पानी देकर हरियाणा के लिये सबसे बडा तोहफा दिया है। इस पानी के आने से किसान और मजदूर दोनों को फायदा होगा। इससे लोगों को खेतों में पानी मिलेगा। जब उन लोगों को खेतों मे काम करने को मिलेगा तो यहां पर एक नई रो ानी आयेगी। इससे प्रान्त के एक नई दि ाा मिलेगी। मैं अपने वित्त मंत्री जी ओर मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनहोने अपने परिश्रम से और श्रीमती इन्दिरा गांधी के आ ार्विाद से यह पानी लाने में सफलता प्राप्त की है।

मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सब कठिनाईयों के बावजूद हम सब लोगों नेमिलकर ही किसी काम ओ आगे बढाना है। इस दे ा के लोगों का भला करने के लिये हमारे उपर बहुत सारी जिम्मेवारियां है। इसलिये हम सब का यह कर्तवय है। कि हम सब लोगों के भले के लिय इस महान सदन के अन्दर रहकर उनके हितो की रक्षा करें। सबसे पहलेक तो मैं यही कहूगा कि जो इस प्रानत में श्रम करता है मेहनत करता है, उस इंसान को उस मजदूर को या उस खेतीहर मजदूर को इतना वेतन मिलना चाहिये जितने की कम से कम उस के परिवार की आव कतायें पूरी हो सकें जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पेाशण कर सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

हमारा प्रान्त देशके तमाम प्रान्तों में दूसरे नम्बर पर आता हैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को मैडिकल एड मिलना चाहिये और एजुके ान मिलनी चाहिये। इस प्रान्त के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने एक कार्यकम चलाया हुआ हैं यह काय्रकम है देहात के अन्दर उद्योगीकरण करना यह स्कीम इसलिये चलाई गई ताकि देहात के गरीब लोगों को और हमारे नौजवानों को काम मिल सके। कुछ मेरे विपक्ष के साथियों ने इस बात को लेकर के आलोचना की कि जो भी उद्योग या लघु उद्योग स्टेट के अन्दर लगाये गये है, वे लगभग मर से गये है। मैं मुख्यमंत्री जी के इस प्रयत्न की सराहना करता हूं कि उन्होने इस काम को अपने अढाई साल के अरसे में काफी आगे बढाया है। इनहोने अढाई वर्श की अवधि के अन्दर लगभग 8 हजार लघु उद्योग सारे हरियाणा के अन्दर लगाये है। इससे लगभग 30 हजार व्यक्तियों को काम मिला हैं इन 30 हजार में से 50 प्रति ात ऐसे लोगों को काम मिला है जिन्हे हम हरिजन कहते हैं आज हमारे ये विरोधी लोग हरिजनों के ठेकेदार बनते हे और कहते है कि हमने इन हरिजनों का उत्थान कियाथा। अब ये इन उद्योगों के पतन की बात करते हैं जब इनका समय था उस समय इन्होने क्या किया वह भी मैं अभी बताता हू। जिससमय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो उनहोने इस काम को चलाया था। लेकिन उनहेाने इसमें एक भार्त लगा दी कि एक हरिजन, एक बैकवर्ड, एक किसान का बेटा और एक व्यापारी होना चाहिये। मै पूछना चाहता हूं कि जब घर के चार सदस्यों का आपस में मेल नहीं है तो क्या बाहर के चार सदस्यों का अपस में

काम करना ठीक समझकेगी या उनके लिये ऐसा करना संभव हो सकेगा। उनहोने अपने दिमाग से इस काम को करने के लिये सोच तो लियालेकिनजिस ढंग से चालू किया गया वह गलत था। वे हरिजनों और गीरब लोगों का भला नहीं चाहते थे। इससरकार ने पावर में आने परयह सोचा कि जो कुछ पहली सरकार ने गरीब लोगों का भला करने के लिये सोचा था वह गलत था। तब हमारी मौजूदा चौधरी भजन लाल की सरकार ने इस बात को दौबारा देखा है और इस स्कीम को बदल कर किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को वह काम करने का हम दिया। इस स्कीम के बारे में मैं सरकार को एक सुझाव दूंगा। लघु उद्योगों के अन्दर जो माल बनता है, गांव में उसे खरीदने वाली आज कोई एजेन्सी नहीं है। मार्किट में जब वे लाग बेचने जाते है तो भाहर में बने हुये माल में और गांव में बने हुये माल के भाव में फर्क होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार ने जो कंज्यूमर स्टोर्ज खोले है वह इस माल को खरीदे तथा आगे लोगों को बेचे। इससे लघु उ?ोग ठीक चलेंगे।

चेयरमैन साहब, यहां अध्यापक की बात बडे जोर भाोर से आई। कहां गया कि वह राश्ट्र निर्माता है। वाकई ही वह राश्ट्र निर्माता है। भूखें रह कर भी वह राश्ट्र निर्माण करता हैं उसे वे सुविधायें नही मिलती जो दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलती है। देहात में वह उन सब बातों से अलग–थलग पडा रहता है जिन बातो ंका भाहर के लोगा फायदा उठाते है। कई बार मांग आई कि उनको मैडिकल भत्ता दे दिया जाये। उनको देहात में

हाउस रैन्ट दे दिया जाये। मैं कहता हूं कि हमारी बडी अच्छी सरकार हैं वित्त मंत्री जी बडे भले मानस है। मुझे उम्मीद है कि वे इा बात को मान जायेगें क्योकि इसमें थोडे से पैसे का सवाल हैं जो लोग देहात के अन्दर सर्विस कर रहे है उनहें वहां पडे–पडे सारी उमर हो जाती हैं चेयरमैन साहब, उनकी जिन्दगी वहीं बीत जातीहै। उन लोगों को कभी मैडिकल भत्ता नहीं मिलता जितनी उनकी तनख्वाह होती है। (विघन व भाोर) अन सब बातों के होते हुये भी सरकार पता नहीं इस मांग को मानने में क्यों असमर्थ है? हमारी बहिन भाान्ति जी जी अध्यापिका रही है मगर पता नहीं ये भी क्यों ऐसा नहीं कर पाई । इस सम्बनघ में मेरा सुझाव है कि फिलहाल जिस भी हैडमास्टर या बी0ई0औ0को डी0डी0ओ0 की पार्वज हो यानि उसे मैडिकल बिल पास करने की पावर दे दे, जिससे देहात में सर्विस करने वाले अध्यापक को कुछ राहत मिल सके।

श्री सभापति : आपका समय हो गया है। (विघन) इसके अलावा बात यह है कि आज ऐजूके ानकी डिमांड ऐजेन्डे पर नहीं हैं

मास्टर जोगी रामः चेयरमैन साहब, सामान्य प्र ाासन के अन्दर सभी कुछ आ जाता है।

श्री सभापतिः आप वाइन्ड अप कीजिये।

मास्टर जोगी रामः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि डी0डी0ओ0 की पावर्ज जिन अधिकारियों के पास है उन सबको मैडिकल बिल पास करने की पावर दे ही जाये। अब क्या होता है? आज उसे 10–15 रूपये का मैडिकल बिल भी काफी देर के बाद मिल पाता है क्योकि वह कई जगह घुमता रहता है। (विघन) चेयरमेन साहब, आप जानते है कि मुलाजिमों को तो पैन्ान मिलती है लेकिन हमारे जो दुसरे बुढें लोग होते है, जिनका इस अवस्था में पहुंचने के बाद उनके बच्चे कोई ख्याल नहीं करते, उनकी सरकार की तरफं से कोई इमदार नहीं की जाती। उनकी देखभाल की भी सरकार कोजिम्मेवारी लेनी चाहिये तथा उनहें भी पैन्ान मिलनी चाहिये।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि पढे लिखे बेरोजगारों को भी सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिये जिससे वे अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके।

चेयरमैन साहब, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं इसकी उपलब्धियां, बहुत प्रांसनीय है। इनहोंने बहुत से पेड लगाये है और काफी संख्या में नये स्कूलों खोले है और अपग्रेड किये हैं इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाजत से डिमांड नं0 2, 3, 4, 5, 15, 17 और 22 का

जिक करना चाहूंगा। (विघन) पन्द्रह दिन से चेयरमैन साहब सरकार यह ढिढौंरा पीट रही है कि हमने यह कर दिया है और वह कर दिया है लिखने वाले भी इस बात से छक गये हे और सुनने वाले भी छक लिये है। चेयरमैन साहब, हकीकत यह है कि आज रोजमर्रा के काम में भी कोई अफसर या कर्मचारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता और इन्साफ नहीं कर सकता। चपडासी से लेकर कमि नर तक और सिपाही से लेकर आई0जी0 तक हरके व्यक्ति के पास सरकार की इतनी दखल अन्दाजी है कि सरकार के टैलिफोन के बगैर कोइ कारोबार नहीं होता। यहां तक कि बस और रेल के टिकट भी तब तक नहीं मिलते जब तक किसी वजीर या एम0एल0ए0 का टेलिफोन न चला जाये। ऐसा रिवाज इस सरकार ने डाल दिा है। कचहरियों तक के काम काज में ये दखल देने लग गये है। मैं किसी का नाम नहीं लेंगा क्योकिं वह बात अच्छी नहीं लगती। इनके सैन्टर में एकबहुत सीनियर मिनिस्टर हैं उसने बहादुगढ के एक मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी। उस आदमी ने उस चिट्ठी को भरी कचहरी में सरे वकीलों के समने पकडा दिया। वकीलों ने बडा भाोर मचाया। (विघन) वह सरप्लस जमीन का केस था। राठी साहब के हल्के का केस था। इनको भी इस बात का पता है। इन हालात में एकअधिकारी की बडी बुरी हालत होती हैं अगर वह इनकी बात नहीं मानताा है तो नैकरी से जाता है और अगर मानता है तो इन्साफ का तकाजा पूरा नहीं होता।

चेयरमेन साहब, एक बात मैं आपको और बताउंगा । यह बात डिमांड नं0 15 की हैं। चेयरमैन साहब, इन्हेने जिलेदारों की भर्ती की है। जो कुछ मैं बताने लग रहा हूं। इससे आप अन्दाजा लगा लेना कि इस सरकार की क्या कारगुजारी है। जिलेदारों की 62 लगह थी जो सरकार की तरफ से एस0एस0एस0 बोर्ड कोखाली बताई गई थी। जब भर्ती का समय आया तो वेकेन्सीज 80 हो गई। लेकिन चेयरमेन साहब, इन्होने 205 जिलेदार भर्ती कर लिये। मन्जूरी तो 62 की थी लेकिन भर्ती 205 करलिये । उनहें ट्रेनिंग पर भेज दिया। (विघन) इन्होने सोचा कि इलैक ान के बाद देखा जायेगा जो बीतेगी सो सही। मूंझे पता नहीं कि कांह से ये उनको तनख्वाह`देगे? सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि जो जिलेदार भर्ती किये गये हे वे या तो मुख्य मंत्री ने जो लिस्ट भेजी थी उसमें से भर्ती हिकये गये या फिर पन्द्रह–5 और बीस–बीस हजार रूपये लेकर के सीटें नीलाम हुई । मेरे पास ऐसे लडको के नाम है और उनहें मैं आपके सामने पे ा भी कर सकता हूं जिन्होने पन्द्रह–2 बीस–2 हजार रूपये देकर के सिलैक ान लिस्ट में अपना नाम लिखवाया हैं अनका नाम सीरियल नम्बर 175 सेलेकर के 200 के बीच में हैं वे बेचारे आज बडे परेशान है क्योकिं ट्रेंनिग के बाद उनहें नौकरी नहीं मिलेगी और उनका पैसा यों ही जाया जायेंगा। (विघन) बोर्ड वालों ने लिंस्ट न छापते तो लोगों ने उनको घेर लेना था और वे अपने रूपये वापिस मागंते। इस तरह से यह सरकार नौकरी लगा रही है। इस प्रकार की इनकी कारकरदगी है। यह गलत हिसाब–किताब है।

बातें बडी–2 करते है कि हम यह करने जा रहे है। कहते है कि हम स्टैट को आसमान पर ले जा कर छोडेगें यानी जमीन पर नहीं रहने देगें।

(14.00 बजे)

अब मै। डिमांड नम्बर चार के बारे में अर्ज करूंगा। चेयरमैन साहब, आप भी किसान घराने से ताल्लूक रखते है। एक एक्ट सन 1800 में अंग्रेजों के समय में बनाया गया ाा कि अगर किसी किसान के खेत में आग लग जाये, घर में आग लग जाये तो उसे रिलीफ देगें यह कानून बना तो हुआ है लेकिन उस बेचारे गरीब को पूरा रिलीफ नहीं मिल पाता हैं एक्ट में खामी होना एक ऐसी अड़चन है जिसक`कारण रिलीफ नहीं मिलता। अगर किसी आदमी की फसल, मवे ी या घर जल जाये तो इनका एक्ट इजाजत नहीं देता है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि दस परैस्न्ट दे सकते हैं अगर कानून इजाजत दे तो और भी ज्यादा दे सकते हैं आप लोगों ने बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया उस वक्त यह भी सोचना चाहिये था कि गरीब किसान का नुकसान हो जाये तो उसे पचास परसैन्ट दे दिया जाये। किसान की मदद का सवाल आता हे एक्ट अड जाता है। अगर उस एक्ट को बदल देते तो आप लोगों का भी कुछ नाम हो जाता। चौधरी भोर सिहं जी इस एक्ट को बदलने के लिये यहां पर बिल क्यों नही रखते? यदि ये ऐसा बिल रखेगें तो सब भाई एक रय से उसे पास करेगें और उससे गरीब लोगों

का भला होगां लेकिन इनके पास एक्ट बदलवाने के लिये फुरसत नहीं हे और न ही इस बारे में ये सोचते है।

चेयरमैन साहब, आज दे ा को आजाद हुये 30–35 साल हो गये लेकिन ठीकरी पहरे का मसला आज भी बना हुआ है। पुलिस की भाहर में जरूरत पउे तो डियूटी लगा देते है। अगर भाहर में दुकान या किसी और चीज का खतरा है तो पुलिस की डियुंटी लगा दी जाती है लेकिन गांवों में किसानों की कटाई कासमय चल रहा होता है लामनी करके राम को घर पहुंचते है उधर से ठीकरी पहरा निकला हुआ मिलता है। पुलिस का थानेदार या तहसीलदार गांव में जाता है कि आज 10–20 गांव के लोग रेलवे लाईन का पहरा देगें। रेलवे लाईन की हिफाजत रेवले वाले करें या पुलिस वाले करे। गांवों के किासनों की डियूटी लगाने की क्या जरूरत है? यह ठीकरी पहरा बिल्कुल बेगार एक्ट है। अंग्रेजों के समय का एक्ट है। उस समय ठीक था लेकिन अब इस`खत्म किया जाना चाहिये। (ाोर एवं विघन) ये इन लोगों की कारकरदगी है। मैं न पहले वजीर था और न ही इससौदे के साथ वजीर हूं लेकिन इससल कोि ा ा करेगें कि हमें भी लाइसैंस मिल जाये। (ाोर एवं विघन) अगर इस एक्ट को बदल दे तो बडी ही अच्छी बात होगी और इस सरकार का नाम भी होगा। (इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्य चौधरी राजेन्द्र सिंह पदासीन हुये चेयरमैन साहब, सरदार तारा सिहं भले आदमी है। उनकी मैं क्या निन्दा करूं? लेकिन इन्होने फरीदाबाद, सोनीपत

और बहादुरगढ़ के कारखानों की पौने तीन करोड रूपये की बिजी की एक्साइज डियूटी माफ करदी। इन जगहों पर बडे बडे अमीर लोगों ने फैक्टरीज लगायी है। नन्दा जैसे अमीर लोग बैठे है उनकी एक्साईज डियूटी माफ कर दी और गरीब किसानों की हजामत कर दी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनकी एक्साइज डियुटी क्यों माफ की गई है। आप सुन करहैरान होगें मन्दि गुरूद्वारे आर्य समाज मन्दिर और धर्म ााला को कनैक ान कमर् ियल बेसिज पर देते है। इन पवित्र स्थानो से बिजली के चार्जिज दुकानदारो के रेटस पर लिये जाते है। धार्मिक स्थान बडी मुि कल से बनाये जाते हैं कम से कम उन सथ्ानों से धरों वाला चार्ज कर सकते है। अगर कोई भारीफ आदमी धर्म ााला बनवाये तो क्या उसने कोइ तिरारत कर ली है। उसने धर्म का काम किया है आम आदमी को सुसविधा दी है। अगर उस धर्म ााला मन्दिर, गुरूद्वारे के आगे दुकान बनी हुई है। उससे अलग से चार्ज कर सकते हो यानि उसका अलग से मीटर लगादे। लेकिन बडे दुख की बात है कि धर्म ााला से भी दुकान बाला ही बिल लिया जाता है। बडे बडे करोडपतियों की आपने एक्साइज डियूटी माफ कर दी है। यह इसलिये किया है कि चुनाव आ रहे है और उनसे पैसे लेने है या ले लिये है। अब भाायद और भी कोई कागज बना रहे है ताकि और जयादा पैसे मिल जाये। मैं आपके जरिये रदार तारास सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि मस्जिद, गुरूद्वारे आर्य समाज मन्दिर, सनातन धर्म मन्दिर ओर धर्म ााला से बिजी के चार्जिज कम से कम लिये जाये।

चेयरमैन साहब, मेरा और भाई राठी साहब का ताजा समझौता हुआ हैं अगर न मानूं तो भी मुि कल है और अगर मानता हूं तो अपनी सही बात नहीं कह सकता । लेकिन फिर भी उकने नोटिस मं लाना चाहता हूं कि बादली और बहादुरगढ के बार्डर से सैकडों ट्रक बिना चैंकिग कराये गुजरते है। सारे के सारे सैल्ज टैक्स की चोरी करते हैं आप इन्क्वायरी करवा लें। कितने ही ट्रक मिलेगें जो रोजना सैल्ज टैक्स की चोरी करते है। वहां जो स्टाफ लगा हुआ है वह भी उनके साथ मिला हुआ हैं जब वे दिल्ली की और जाते है तो उकने कागज रख लेते है वापिस आते वक्त ले लेते है। अगर कोई ट्रक आगे पकडा जाये तो कह दिया जाता है। कि हमारे कागजात बार्डर बैरियर पर चैकिंग के लिये रख लिये है। आज ही सुवबह एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने माना है कि छोटे–2 अमाउन्टस की चोरी करने वाले या न जमा कराने वालों को गिरफतार किया जाता है। और जो बडे –2 लोग है जिनकी तरफ चालिस–2 लाख रूपये बकाया है उन्हें गिरफतार नहीं किया जाता। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे जिन आदमियों की तरफ पैसा बकाया है। उनसे पैनल्टी लगा कर वसूल किया जाये। जो उनके पास पैसा है वह एक किस्म से लोन के रूप में है। जब एक व्यापारी ने कोई चीज बेच दी और सैल्ज टैक्स भी लेलिया फिर उसे तीन महीन की रियायत देने की क्या जरूरत है? तीन महीने वह बिना ब्याज के उस पैसे को रख सकता है। दुकानदार ने पार्टी से पैसा वसूल कर लियाफिर उसे रखरने का क्या अधिकार है? जिन दुकानदारों की

तरफ चालिस–2 लाख रूपया बकाया है वह पांच–पांच साल पे नहीं करते है। पे न करने पर उनसे केवल 12 परसैन्ट ब्याज लिया जाता है। जो आदमी स्टे लेता है उससे 30 परसैंट ब्याज लिया जाना चाहिये जब तक इतनी पैनल्टी नहीं होगी तबग तक वह पैसा जमा नहीं करायेगा इसलिये मैं अपने भाई से कहूंगा कि वक्त बदलता रहता है। क्या पता कि दो महीने बादक्या होनेवाला है? दो महीने में ही आप अपना नाम कमा लो। सेल्ज टैक्स जितनी भी सख्ती के साथ वसूल करेागें, स्टेट का उतना ही फायदा होगा और आपका नाम होगा। किसी को भी माफ न करो। एक बार तो हल्ला बोल दो। तैसे ताबें मैने बहुत कहनी थी लेकिन अब कसम खा रखी है इसलिये ज्यादा नहीं कहनाचाहता।

चेयरमेन साहब, पुलिस के बारे मे भी अर्ज करना चाहता हूं। डी0एस0पी0 के ग्रेडज के बारे में चौधरी देवली लाल ने और चौधरी भजन लाल ने वायदा कियाथा कि एस0डी0एम0 के बराबर के देगें। वे कागज इधर उधर ही घूमते रहेते है। वेबेचारे न झंडा लेकरखडे हो सकते है और न ही कोई हड़ताल आदि कर सकते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि उनके स्कूेल एस0डी0एम0 के बराबर करने का जो वायदा किया गया था वह पूरा किया जाये। इसके अलावा पुलिस में सिपाही, हवलदार या जितने भी छोटे रैंक के आदमी है उनके लिये क्वार्टर बनाये, उनके बच्चों को पढायें और उनकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की करवायें क्योकिं यह एक डिस्पिलिन्ड फोर्स है और बोल नहीं सकती। आप बडे–2 अफसरों

का बे ाक कुछ भी करो लेकिन इन गरीब आदमियों की तरफ जो जुल्म का ि ाकार होने लग रहे हैं, खास ध्यान दो ताकि यह अपना काम अच्छी तरह से करसकें। हर महकमा अपनी डिमांड रख सकता हैं हर महकमें के आदमी अपना झंडा उठा सकते है, नारे लगा सकते है और हडताल कर सकते है लेकिन यह तो बेचारे बेजुबार है, इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं चेयरमैन साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहूंगां। इस बारे में बहुत सी कहानियां हो चुकी है। मैं उनके चक्कर में न पडकर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कोआप्रे ान मिनिस्टर यहां पर नहीं बैठे है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर बैठै है। जितने भी आदमी कोआप्रे ान डिपार्टमेंट में लगाये जाये है, उनका सिलैक ान इन्साफ के तकाजे पर पूरा नहीं उतरता। उसमें भेदभव की बदबू आती है। इस तरह से भेदभाव बरतना लोगों की नजरों में कोई अच्छी बात नहीं है ओर उससे सरकार का इमेज अच्छा नहीं बन सकता। मैं सारे हरियाणा के बारे मे तो कुछ नहीं कहता। मैं रोहतक की बात बता सकता हूं ं जो वहां पर बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज में मैंबर्ज है, उनमें से 6–7 हमारे अपने मित्र है। हमने उनसे यह कहा कि भई, तुमने यह क्या किया। आपने नौकरी का यह क्या सिस्टम भाुरू किया है? उन्होने यह कहा कि आप बे ाक हमें मुख्य मंत्री के पास ले चलो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ले चलो। हमने तो बंटवारा कर लिया। छोटी छोटी नौकरियों पर हमने लगा लिये। बडे –2 ओहदों पर सरकार

लगा लेगी। तीन साल तक तो फैसला होता नहीं। हम तो इस फैसले पर कायम है। चेयरमेन सहाब, इसके अलावा एक बात करके तो इन्होने कोआप्रेटिव इन्स्टीच्यू ान्ज को चुनाव में चुने हुये आदमियों की मैजोरिटी भी होगी तो भी वे अपने आदमी को चेयरमैने नहीं चुन सके। सरकार अगर किसी आदमी को चेयरमैन बनने नहीं देना चाहती तो जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज में इनके आदमी होगें, यानि सरकारी अफसर होगें , वे अपने वोटों से उसको नहीं बनने देगें। क्योकि 6–7 राय सरकारी आदमियों की होगी, इसलिये ये अपनी मर्जी का चेयरमेन बनवायेगें। मान लीजिये 9 आदमी चुनकार आ गये अनमें से 7 जिनकी मैजोरिटी है, एक आदमी को चुनना चहाते है लेकिन दो आदमी उन को चुनना नहीं चाहते तो वह आदमी नहीं बन सकेगा क्योकि गवर्नमेंट अपने अफसरों को इस बारे में हिदायत दे सकती है। किसी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि यह गवर्नमेंट की बात को टाल सके। मैं यह चाहता हूं कि अगर सरकार इन इंस्टीच्यु ांज में नौमीने ान करना ही चाहती है तो बे ाक करे लेकिन वह किस बात के लिये हो, यह बात पहले तय हो जानी चाहिये। उसका प्रयोग अगर बोर्ड कोई गलत काम करता है या कोई गलत पालिसी डिसीजन लेता है, वहां पर करना चाहिये। यह नही ंहोना चाहिये कि चेयरमैन का चुनाव हो ाऔर उसमें उनका दखल हो। मेरा कहना यह है कि कम से कम पब्लिक के चुने हुये नुमायंदो को अपनी रय से अपने मतलब का चेयरमैन बनाने का तो हम होना चाहिये। वरना तो डैमोक्रेसी या प्रजातन्त्र इस मुल्क में कायम रखने से कोई फायदा

नहीं होगा। अगर मंत्री जी जो महकमें का इन्चार्ज होगा, वह टेलीफोन कर देगा, तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं हो सकती कि उसकी बात को टाल सके और अपनी राय इधर उधर दे। इसके लिये मैने जैसे सुझाव दिया हे या तो वैसे कर लियोजाये वरना नौमिनेशन ही खत्म कर दिया जाये। (घंटी) चेयरमेन साहब, मुझे थोडा सा टाईम और दे दे मैने अभी एक दो बों और कहनी है।

श्री सभापतिः आपका समय समाप्त हो गया है, आप अब बैठिये।

चौधरी उदय सिंह दलालः चेयरमैन साहब, आपके और हमारे तो घरेलू ताल्लुकात भी है। मुझे कम से कम अपनी आखिरी बात तो कह लेने दें। मैं खेती बाडी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आप एक बात से अन्दाजा लगा ले। एक बात के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बडे जोरो से कह दिया और सरदार लछमन सिंह जी ने कह दिया। सब कहते है कि अनाज की मूवमैंट पर कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाबन्दी है। यह सरकार बे ाक हां करे या ना। सारे हरियाणा सरकार के आदमियों को यह पता है कि एक तरफ तो यह कहते है कि हम किसानों की तरक्की करवायेगे, किसानो को उनकी पैदावार का उंचा मुल्य दिलवायेगे। यह इस बात का ढिढोरां भी पीटते है कि हम किसान के लिये मर मिटेगें लेकिन यह करते कुछ है नही। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी

गांव में किसी दुकानदार के पोता हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। बोला भई मेरे पोता हुआ है। गांव वालों ने पूछा तो क्या करोगे। वह बोला कि भई कुछ धर्म पुणय करूंगा। गांव वाले कहने लगे कि तू हमें भैसों के लिये बिनौले ही पूरे तोल दियाकरो, इतना ही काफी है। ययदि कोइ किसान अपनी फसल को कुछ मंहगा बेच सकता है तो उसको मंहगा बेच लेने दे। लेकिन इनकी पालिसी तो उल्ट है यहां पर कुछ कहते है, अफसरों को कुछ और कहते हैं मै ंयह बात मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करके पुलिस और किसान के बीच टकराव न पैदा करो। या तो कानून ही ऐसा बना दो कि दिल्ली में गेहूं जाने ही नहीं देगें अगर ऐसा कहते हो कि कोई पाबन्दी नहीं है फिर सबको ले जाने दो। अब आपकी पुलिस तो यह कहती है कि जाने नही देगें ओर आप कहते हो कि कोई पाबन्दी नहीं है। ऐसा करके आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। छोटा मोटा भाई तो सब्र कर लेगा लेकिन अगर कोई भाई आपको खब्खी खान टकरा गयातो किसी को आप मुकाबले में मार दोगे और यह कहोगे कि वह तो पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया किसी को आप सेल्ज टैक्स की चोरी में पकडोगे। इसलिये अगर कानून ऐसा बनाते हो कि गेहूं की मूवमैंअ पर कोई पाबन्दी नहीं है, तो उस पर अमल भी करो। यह नहीं कि कहो, कुछ और करो कुछ। ऐसा करके आप किसान और पुलिस के बीच में टकराव पैदा कर रहे हो। मैने तो यह सोचा था कि नजफगढ यानरेला में कुछ गेहूं ले जाउं। राठी साहब मेरे मित्र है। इनको दिखा दूं। लेकिन फिर

सेाचा कि अगरमैं ले भी गया तो इससे दूसरे किसानों को फायदा नहीं होगा क्योकि वे बेचारे तो ले जा नही सकेगें। इसलिय मैं यह कहता हूं कि यह किानों को केवल दुख न दे तो इनकी बडी मेहरबानी । अगरकोई भला कर दे तो इनकी और भी जयादा मेहरबानी। न करे तो इनकी मेहरबानी। चेयरमैन साहब, आखिर में मै एक बात ओर कहूंगा।(घंटी) चेयरमैन साहब, यह कहते है कि हम गरीब हरिजनों का भला करेगें। अब इस भले की बात सुन लो। दिल्ली में और उसके आस पास तेा अमीर आदमी रहते है। वहां पर एक आदमी को 900 ग्राम चीनी कोटा से मिलती है। आप ही देखे कितनी गरीबो की भलाई होने लग रही है। वह दिल्ली जहां पर कि हिनदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी रहते है वहां पर 900 ग्राम चीनी मिलने लग रही है। चण्डीगढ जो इस गरीबी में सैकिण्ड नम्बर पर आता है, यहां पर 500 गग्रम चीनी मिलने लग रही है। और हरियाणा में केवल 300 ग्राम। मेरे मांडौठी या बादली में 300 गग्रम चीनी और दिल्ली और चण्डीगढ में 900 और 500 ग्राम चीनी। यह आप अन्दाजा खुद लगा ले कि कितना गरीबों का भला यह सरकार कररही है। अगर सरकार इसबारे मे कुछ महसूस करती है तो क्यों नही यह भारत सरकार से इस बारे में लिखा पढी करते कि सब जगह पर एक सी चीनी की डिस्ट्रिब्यू ान होनी चाहिये। इससे भेदभाव की बू आती है। इससे यह पता लगता है कि गांवों के लोगो की कोइ सुनवाई नहीं है। (घंटी) (ाोर एवं वयवधान) आखिर में मैं डिमांड नं0 2,3,4,5,15,17 और 22 का

विरोध करता हूं और यह दरखास्त करता हूं कि इनको पास न किया जाये।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर, अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं डिमांड नं0 15, 17, 22 , 2 व 3 पर बोलूगां आपको पता ही है और सारादे ा जानता है कि हमारी लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दे ा को एक नारा दिया है कि हिन्दुस्तान में गरीबों के उत्थन के लिये यह वर्श उत्पादकता का वर्श मनाया जायें। उनहोने श्रम कानारा दिया है। चेयरमेन साहब, इस नारे के अनुसार इस दे ा में उसी आदमी कमो जीने का हक है जो मेहनत करता है। यह दे ा तभी तरक्की कर सकता है यदि हर आदमी अपने हाथ से मेहनत करके खाये और मेहनत करके इस दे ा का पालन पोशण करे। अब मै आपके सामने डिंमाड नम्बर 22 रखता हूं यह डिमांड कोआप्र ान डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते है कि गरीबों की भलाई के लिय अगर कोइ महकमा काम करता है तो वह यही महकमा है सब से ज्यादा योगदान हमारा सहकारी विभाग करता है । आज हमारे हरियाणा में जो भी पंच हजार की आबादी का गांव है, उसके बारे में सरकार ने फैसला किया है कि वहां पर कन्जूमर स्टोंर द्वारा सारी चीजें मुहैया करवाई जायेगी गांवों मे जोचीजें भेजी जायेगी वह ठीक रेट पर आम आदमी को दी जायेगी। चेयरमैन साहब, अगर सरकार गरीब आदमियो की भलाई का कोई काम करती है याकोइ ऐसा काम

करती है जिससे आम गरीब आदमी का फायदा हो तो अपोजी ानके भाइयों को महसूस होता है क्योकिं वे अपने समय में कुछ भी नहीं कर पाये। सरकार से मेरा निवेदन यह भी है कि जब सरकार ने इतना बोल्ड फैसला लिया है कि हर पांच हजार की आबादी वाले गांव में कंज्यूमर स्टोर खोला जायेगा जिसमें हर जरूरी चली की उपलब्धि होगी, वहां सरकार को यह भी करना चाहिये कि जहां पर सरकार स्टोर खोले वहां पर वे सारी चीजें जैसे मिट्टी कातेल, दाल चीनी तथा और चीजें जो रोजना काम में आती है।, उन स्टौर्ज में उपलब्ध कराई जाये। इन चीजों की वहां पर कोइ कमी नहीं होनी चहिये। सभापति महोदय, मै एक बात और कहना चाहता हूं कि कोआप्रे ान डिपार्टमे ।ट गरीब से गरीब आदमी को टयूबवैल लगाने के लिये और जमीन खरीदने के लिये और जमीन ठीक करने के लिय कर्जा देता है लेकिन रेट आफ इंट्रैस्ट बहुत ज्यादा है इसको कम करना चाहिये। जिसरेट पर डी0आर0डी0ए0 का लेन मिलता है। उससे सिर्फ एक या दो परसैंट ज्यादा लिया जा सकता हैं गरीब आदमी इतना ब्याज नहीं देसकता और वास्तव में जो गरीब आदमी होता है वह ब्याज ही पूरा कर पाता है उसका मूल यूं का यूं ही खडा रहता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस कर्जे पर आठ परसै ।ट से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, इस महकमे कमेबारे में मैं एक बात और कहना चहाता हूं। कि कल ही एक क्वैश्चन आया था और बताया गयाकि इस महकमे में 66 आदमियों को भर्ती किया गयाओर उनमें से केवल तीन हरिजन लिये गये। आज भी

बिजली विभाग के बारे में एक सवाल आया था ओर सरदार तारा सिंह जी ने बताया कि 324 आदिमी भर्ती किये गये उनमें आठ हरिजन स्पै ाल तोर पर भर्ती किये गये जो अस्सी आदमी भर्ती किये जाने थे वे नहीं किये गये। मेरा निवेदन है कि जब सरकार ने गरीबों का इतना ख्याल किया है उनकी तरख्वाह भी बढाई जा रही है, ज्यादा चीजें उनको मुहैया की जारही है। उनको कर्जा दिया जा रहा है और दूसरी तरह की सहूलियतें दी जा रही है तो फिर नौकरियों में भी उनको ख्याल रखा जाना चाहिये। रिजर्वे ान को सर्विसिज मेंपूरा किया जानाचाहिये मैं चौधरी भजन लाल को दाद देना चाहता हूं कि जहांपहले पुलिस मेंतीन चार और छः परसैंट की रिजर्वे न थी वहां इन्होने 16 परसैंट तक की रिजर्वे ान पुलिस में पूरी की हैं मेरी प्रार्थना है कि रिजर्वे ान काजहां इतना ख्याल दूसरे विभाग रखते है वहां पर बिजली विभाग और कोआप्रे ान विभाग को भी ख्याल रखना चाहिये ओर इन दोनो विभागों में जो रिजर्वे ान के कोटे में कमी रही है उसको पूरा किया जानाचाहिये। (व्यवधान)......................तो हरिजनों के बारे में चेयर के आदे ाानुसार रिकार्ड नहीं किया गया। बोलने भी नहीं देते थे। चेयरमेन साहब, मैं होम मिनिस्टर और मुख,य मंत्री क बहुत आभारी हूं कि उन्होने पुलिस विभाग मे ं हरिजनों की भर्ती में बढौतरी कराई है। (ाोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, आप जानते हे कि जाहं तक रिजर्वे ान का ताल्लूक है, ये हमारे अपोजी ानक `भाई जो हरिजनों का दम भरते हे ये बसबसे पहले उनके खिलाफ बोलते थे और हमें कहा जाता थाकि

तुम हरिजनों के ठेकेदार हो। उस समय चौधरी......................कहते थे कि क्या तुमने हरिजनों का ठेका ले रख है। (ाोर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, मैं कहना चहता हूं कि जब हम ट्रेजरी बैन्चिग पर बैठते थे तो हमें कहा जाता था.........................

चौधरी भले रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमेन साहब, ये कह रहे ह `कि जब मैं ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठता था तो ये हमारे साथ ही ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठते थे। ये भी बैठते थे और हम भी बैठते थे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहराः चेयरमैन साहब, यह कैंडिट तो चौधरी भजन लाल को जाता है जिन्होने चार और छः परसैंअ से सोलह परसैंट की भती्र पुलिस में हरिजनोंकी कराई है। पिछली सरकार को हम बार बार कहते थे कि हरिजनों के उत्थान के लिये, हरिजनों के फायदे के लिये निगम की कैपिटल बढाओं लेकिन उस सरकार ने कोइ ध्यान नही ंदिया। चौधरी भजन लाल ने निगम की कैपिटल दो करोड से पांच करोड की हैं

श्री भागी रामः आन ए प्वायंट आर्डर सर। चेयरमेन साहब, क्या ये बता सकते हे कि निगत की बैठकें कब कब हुई है। मेरी जानकी के अनुसार पिदले डेढ साल से इसकी कोई मीटिंग नही ंहुई हैं

श्री लहरी सिंह मेहराः आप तो हरिजनों को लोन नहीं देना चाहते थे।चेयरमैन साहब हर तीसरे महीने निगम की बैठक

होती है। अगर भगी राम उसमें न आये तो क्या कियाजा सकता हैं चेयरमैन साहब, चौधरी टेकराम यहां पर बैठे हुये पिछली बार......... ....ने इनको 17 कमेटीज का मैंबर बनाया था और ....को इक्कीस बाईस कमेटीज का मैंबर बनाया था। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्माः सभापति महोदय, जो आदमी सदन में नही हैं उनका नाम यहां सदन में नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिये लहरी सिंह ने जो नाम लिये हे वे ऐैकसपन्ज करा दिये जाये।

श्री सभापतिः जो आदमी सदन में आने आप को डिफैनड नहीं कर सकता उसका नाम यहां नही लिया जाना चहिोय। लहरी सिंह जी आप सिर्फ डिमांड पर ही बोले। जो नाम इनहोने बोले है उनको रिकार्ड न कियाजाये।

श्री लहरी सिंह मेहराः चेयरमैन साहब, मैने अपने ुलैट पर प्रैस कांफ्रैस बुलाई और मैने चार्ज लगाया था कि ....के दामाद और समधी है वे 21–22 कमेटीज के मैंबर है लेकिन बाद मे इनहोने इस बात को डिनाई किया। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्माः चेयरमैन साहब, जो आदमी हाउस मे अपने आपको डिफैन्ड न कर सकते हो, उनका नाम यहा हाउस में नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : चौधरी टेकराम जी तो हाउस के सदस्य है वे तो अपने आपको डिफेन्ड कर सकते है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहराः चेयरमैन साहब, ये बार–2 अब मेरे बारे में कह रहे है अगर मैने कोई बात कह दी तो इनको बुरी लगेगी। अब मैं अपनी अगली डिमांड पर आता हूं।

श्री सभापतिः चौधरी लहरी सिंह जी , आपका समय खत्म होने वाला हैं आप बोलेने से पहले यह बता दें आप कौनसी डिमांड पर बोलना चाहते है।

श्री लहरी सिंह मेहराः मैं अब डिमांड नं0 17 पर बोलना चाहता हूं जोकि एग्रीकल्चर से सबंधित है। चेयरमेन साहब, जहां तक एग्रीकल्चर विभाग का ताल्लुक है इसमें कोइ दो राय नहीं है कि इस विभाग ने पिछले दोसालों से काफी तरक्की की है। जहां तक बीज का ताल्लूक था सस्ते और अच्छे बीज किसनों को उपलब्ध हो रहे है। लेकिन वास्तवक में जितने बीत किसानों को दिये जाने थे वह नहीं दिये गये है। अब मैं सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि पहले तो ने ानल सीड कारपोरे ान के द्वारा बीज लिये जाते थे लेकिन अब तो हरियाणा स्टेट की अपनी ही हरियाणा सीड कारपोरे ान है, अब तो किसी प्रकार की सरकार को बीजों के मामलों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अब तो सरकार को और अच्छी किसम के बढिया बीज किसानों को सप्लाई

करने चाहिये। इस सारे काम के लिये एग्रीकल्चर विभाग के ईमानदार औरसमझदार अधिकारी भी प्रं ासां के पात्र है।

चेयरमैन सहाब, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर मार्किट कमेटियों के लिये मंडियों का निर्माण हो रहा हैं यह भी एक बडा सराहनीय काम है। इसके साथ–2 सरकार से निवेदन करूगां कि आज किसान को अपनी जिन्स मंडियों तक पहुचाने के लिये बडी मुि कल का सामना करना पड रहा है और उसे दूर का और गन्दार रास्ता , टूटा–फूटा रास्ता मंडियों तक आने के लिये तय करना पडता हैं मंडियों तक जाने के लिये डेढ डेढ दो–2 फर्लांग का जो रास्ता खराब है, उस रास्त`की सरकार को ठीक ककरवाने के लिये भीघ्र कदम उठाने चाहिये ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्त का सामना न करना पडे। मार्किट कमेटियों की तरफ से इन सडकों का निर्माण करने के लिये पैसा लगना चाहिये। सरकार को इस और अव य ध्यान देना चाहिये ताकि किसान ठीक समय पर और बिना तकलीफ के अपनी जिन्स मंडियों के अन्दरला सके। (घंटी) बस चेयरमैन साहब, मैं एक दो बाते ंओर कह कर आना स्थान लूगां।

चेयरमैन साहब, अब मै इरीगे ान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं इसके लिये मैं सरदार तारासिं हजी ओर श्री देवेन्द्र भार्मा जी को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि उनहोने वास्तव में बहुत अच्छा काम कर दिखाया है। जो बडे–2 नदियां,

नाले, लोगों के रास्ते में रूकावट थे उन पर पुल बना दिये है और इस तरह से 10–10, 20–20 और 30–30 गांव आपस के में एक दूसरे से कट आफ हुये पडे थे, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बार्डर की तरह दूर–2 थे, अब उन सबको आपस में मिला दिया गयाहैं यह एक बहुत ही अच्छा औरसराहनीय कदम हमारे इरीगे ान मिनिस्टर महोदय ने उठाया है। इससे लोगों को बउी सहूलियतें मिल गई है। इसी तरह से मैं यह कहुंगा कि जिस तरह से कि यू0पी0 वालें ने यमुना नही के उपर अपनी तरफ बांध बनायाहै उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी ताजेवाला से होडल तक युमना नदी पर बांध बनाने के लिये प्रयास करने चाहिये ताकि किसानों को इस से लाभ होसकें इन भाबदों के सथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने कासमय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डाक्टर बृज मोहन गुप्ता।

श्री वीरेन्द्र सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर हैकं पहली बात तो यह है कि आपके होते हूये भी हमें बोलने कासमय नहीं मिला। हम तो इसी इन्तजार में थे कि हमें बोलने का समय दिया जायेगा और इसी इन्तजार मे हमें खाना भी नहीं मिला।

स्वामी अग्निवे ाः चेयरमेन साहब, मैं भी बार–2 बोलने के लिये खडा हो रहा हूं मुझे भीा अपनी पार्टी की तरफ से बोलने

काटाईम मिलना चाहिये लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे है।

श्री सभापतिः ठीक है जी, स्वामी जी आपको भी समय दियाजायेगा। अब आप बैठिये।

डा0 बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नं022 पर अपने विचार रखूगां जोकि कोआपरे ान विभाग से सम्बन्धित है और 13 करोड रूपये के लगभग की हैं सभापति महोदय, ट्रिब्यून अखबर ने अपने आर्टीकल के हैंडिग में ये लिखा हैं ''कोआपरे ान और करप्‍ न मूवमैंट इन दि कंट्री''। मुझ भी यह आर्टीकल पढने का मौका मिला। भाायद सभापति जी, आपने भी यह पढा होगा। नहीं पढा तो पढ ले। यह जो मूवमैंट सरकारी पैटर्न पर चलाई गई थी इस मूवमैंट का इस अब असली मकसद छोड दिया गया हैं और अब इस इलैक ान और करप्‍ ान मूवमेंट में बदल दिया गयाह । मैं तो यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जितने भी मैडीकल स्टेरज है उन सबसमें घटा ही चल रहा हैंमैं आपको अम्बाला कैन्ट की एक मिसाल देता हूं। वहां पर एक सुपर बाजार हैं वहां पर दो अढाई साल पहले एक बडा भारी घपला हुआ था ओर सरकार की तरफ से वहां पर एक सीनियर आडीटर आडिट करने के लिये भेजा गया था उसका नाम रामगोपाल था। उसने अपने आडिट नोट मे ंयह लिखा है कि यहां पर बडा भारी घपला हुआ हैं वहां के जी0एम0 साहब ने उस

आडीटर को यह कहा कि या तो नोट को बदलो नहीं तो हम किसी न किसी केस मे आपको फंसायेगें उसने कहा कि आखिर मैं किसी लिये यहां पर आया हूं। अगर कोई खरबी हेागी तो मे। अव य प्वांयट आउट करूंगा। वह न माना तो फिर उसके उपर एक झूठा केस बनायागया और उसे सस्पैंड कर दिया गया आज उस आदमी को लगभग दो साल हो चुके है। वह सस्पैंड ही चला आ रहा हे जबकि कानूनों के मुताबकि सस्पैंन्डिड आदती को 6 महीने के अन्दर–2 रि–इंस्ट्रट करना होता हैं आज तक उस का कोई चालान भी पुलिस किसी आदालत में पे ा नहीं कर सकी। उससमें जो जूनियर आदमी थे, वे सारे के सारे परमोट हो चुके है। यह हालत तो इस सरकार के राज्य में एक ईमानदार आदमी की है। जी0एम0 साहेबान भी फंसे हुये है इस प्रकार से यह तो इनके कोआपरे ान विभाग का हाल है।

चेयरमैन सहाब, इसके साथ साथ में डिमांड नम्बर 5 पर जोकि एक्साइज विभाग वगैरह से सम्बन्धित है पर भी कुछ कहना चाहता हूं। वे मिनिस्टर बैठे नहीं हैं मै उनको बताता। आज सुबह भी इस मसले पर बात हो चुकी है कि एक दवाई पोटाि ायम सायानाईड है, जोकि बहुत ही खतरनाक है जिसके सेवन से आदमी क्षणों तक भी जिन्दा नहीं रह सकता, वह दवाई खुलेआम बिक रही है। उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। जगाधरी और यमुनानगर में परसों ही एकलडका और लडकी इसके खाने से मर गये है।

इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि जगाधरी आज हरियाणा के अन्दर ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्श के अन्दर बर्तनों की इंडस्ट्रीज के नाम से प्रसिद्ध है। सारे हिन्दुस्तान में वहां से बर्तन भेजे जाते है। और कुछ बाहरभी जाते है। चूंकि हरियाणा के अन्दर उसका रा–मैटीरियल नहीं हेाता इसलिये वह भी बाहर से आता हैं हमने एक मांग रखी थी कि वहां पर सैन्ट्रल सैल्ज टैकस 4 प्रति ात से घटा कर 1 प्रति ात कर दिया जाए। वह ट्रायल के आधार पर कुछ महीनों के लिये किया भी गया और उसके बाद उसको एक्सटेंड करना था उस वक्त गवर्नमेंट हमारी थी लेकिन जब ट्रायल का समय निकल गया तो बदकिस्मती यह रही कि गवर्नमेंट बदल गई। फिर उस पर विचार हुआ। मैं किसी पर इल्जाम लगाने वाली बात नहीं करूंगा कि किसी मंत्री ने किसी से चन्दा लिया या नहीं लिया लेकिन मैं मंत्री जी सेएक बात जरूर कहूंगा कि यह बहुत जरूरी मसला है। जगाधरी मं बर्तनों की काटेज इंडट्ररी है घर–2 में बर्तन बनते है अैर वहां पर चारों तरफ से मजदूर आकर अपना पेट भरते है। वहां पर मजदूरों का हीन नहीं बिल्कि बाकी सब का भी धंधा चलता है लेकिन यह सरकार इस इंडस्टरी को बिल्कुल तबाह करने पर तुली हुई है। मैने पहले भी बताया था कि कई स्टैप्स मे से होकर गुजरने के बाद ये बर्तन बनते है। पहले रा–मैटिरियल को ग्लाना फिर उसका पीतल बनाना फिर उसको रोल करना , काटना, दबानाऔर डाई पर लगाना इत्यादि। यानि इसके कई प्रोसैस है तब कहीं जाकर बर्तन बनते हैं कोइ आदमी कुछ प्रौसैस करता है और कोई कुछ करता हैं । आप

जानते है कि मजदूर लोग पढे लिखे नहीं होते। रा–मैंटिरियल काकुछ पोर ान जिस जगह उसकी इंडस्टरीज होती है वहां से इधर–उधर जाता है। इस मुवमैंट पर मिनिस्टर साहब ने वि वास दिलाया था कि किसी की भी चैकिग नहीं होगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि इनके अ योरेंन्स के बावजुद जगह जगह पर चैकिंग होती हैं। बेचारे गरीब लोगों का सामान पकड करले जाते है और उनको जुर्माना भी करते है। उनका सामान भी खा जाते है और जो जुर्माना होता है वह फिफ्टी– फिफ्टी हो जाता हैं मेरी मांग यह है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इसके बाद मैं डिमांड नं03 पर आता हूं। मेने पिछले साल भी हाउस में एक किस्सा सुनाया थां रोहतक जिले के पास एक छोटा सा गांव खोरडा है। वहां पर एक बेवा मां थी जिसका एक 6–7 साल काबच्चा था और कोई और सहारा नहीं था। उस बच्चे को पहले तो वहां से गायब किया गया और जाते–2 लिख गये कि दस हजार रूपये फलां जगह पर भेज दो या रख दो , आपका बच्चा मिल जाएगा। वह बेचारी मां कहां से दस हजार रूपये देती। महीने डेढ महीने के बाद उस बच्चे का पत्थर बांध कर एक कुयें में डाल दिया गया यह केसी साल्हावास पुलिस स्टे ान का हैं उसके बाद किसी ने बेचारी गरीब बेवा को पत्र लिखा कि आपका बच्चा फलां कुयें में पडा हैं वहबेचारी चिट्ठी लेकर पुलिस के पास गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब दोबारा पुलिस के पास गई तो तीन दिन बाद पुलिस आई और उस बच्चे को कुंये से निकाला गया। मुझे आज तक उस केस

का पता नहीं था कि क्या बना लेकिन अब मुझे पता चला है कि वह केस अम्बाला इन्वैस्टीगे ान सैंटर में दे दिया गयाहै।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैने मंत्री जी से मांग की थी कि जगाधरी एक इंडस्ट्रीयल टाउन होने के नाते और वहां जयादा आबादी होने के नाते हमने क्या कसूर कियसा हे कि अभी वहां पर एक छोटा सा थाना है वह भी अपग्रेड न हो। अगरवहां का थाना अपग्रेड होगा तो वहां पर एक इंस्पैक्टर पुलिस आ जायेगा।कुछ एस0आईज0 आ जायेगें और कुछ ए0एस0आई0 तथा कांस्टेबल आ जायेगें। एक बात यह है कि वहां पर सट्टा बडा कामन चलता है। उनकी बाकायदा मन्थली बंधी हुई है। यानि जो सट्टा चलाने वाले लोग होतेह`, वे महीना बांध देते है और अपना काम आराम से चलाते है।

इसके उपर और ज्यादा न कहते हुये मैं डिंमांड नं0 2 पर कहना चाहूंगा। मुझे बडे दुख के साथ कहना पडता है कि जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदे ा का रिआर्गेनाइजे ान हुआ था तो उस समय सर्विस रूल्ज बने थे। उन सर्विस रूल्ज को ऐ तरफ रखकर हरियाणा के अन्दर कुछ और अमैंडममेंटस कर दी गई ओर सारी पावर सैन्ट्रलाईज कर दी गई। चाहे उसमें इंजीनियर्स हो, चाहे डाक्टर्ज हो या और हो, इन सब की एनुअल कंफिडैनि ायल रिपोर्ट एक आदमी लिखेगा। वह आदमी उनके महकमें का सीनियर अफसर नहीं होगा बल्कि एग्जैक्टिव काहोगा। इसके बारे में मैने एक सवाल भी दिया हुआ है भाायद उसका

जवाब कल आएगा। आप ही बताये कि टैक्नोक्रैटस के बारे में दूसर `डिपाटैमेट का आदमी क्या जानसकता है। इस बारे में अभी तक कोई सोच विचार नही हुआ। मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि हरियाणा में दो आर्डिनेंस आये और उनके माध्यम से रीआर्गेनाइजे ान के बाद रूल चेंज किये गये। रीआर्गेनाइजे ान एक्ट मे यह बात थी कि जो फैसिलिटीज सरकारी मुलाजिमों को एक स्टैट देगी वही दूसरी स्टेटों को भी देनी पडेगी लेकिन हरियाणा में उस तरह से नहीं हुआ। एक आर्डिनेंस के द्वारा हरियाणा के अन्दर एवरेज रिपोर्ट जिसके साथ कोई रिमार्क्स न हो, उसको एडवर्स कहा गया है। बडे दुख की बात है कि एवरेज रिपोर्ट कनवे भी नहीं की जाती। दूसरा आर्डिनैंस यह इ ू किया गया कि जो आफिसर 50 साल की एज क्रास कर जाएगा और उसकी 10 में से 6 कन्फीडैंि ायल रिपोर्टस अगर खराब होगी तो उसको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो पावर सैन्ट्रलाइज कर रखी है, इसका मुद्‌दा केवल एक ही है और वह यह कि किसी तरीके से इलैक न जीत ले। मंत्री जी क्यों नही जवाब देते कि हम इनको डिसैन्ट्रलाइज करेगें। जो कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे मे ंबात की गई है इस पर पुनर्विचार करेगें। मैं चाहता हूं कि जो सहूलियतें पंजाब और हिमाचल प्रदे ा के कर्मचारियों को दी गई है वही हरियाणा के कर्मचारियों को दीजाये। इसके साथ–2 मैं अन्त में यह कहूंगा कि ये जो डिमांडज रखी गई है, मै इनका विरोध करता हूं। इनहें पास न किया जाये। धन्यवाद।

स्वामी अग्निवे ा (पून्डरी): सभापति महोदय, मैं आपका बडा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मुझे इस बात की भी बडी खु ाी है कि आपने मुझे पहली बार अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर बोलने का मौका दिया। मैं मांग संख्या 2, 3, 4, 5,, 15 और 17 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस सरकार ने पिछले बजट सै ान के दौरान बडे जोर– ाारे के साथ यह घोशणा की थी कि हरियाणा के अन्दर 31–3–81 तक तमाम हरिजनों को जितनी भी सरप्लस जमीन थी, वह अलाट कर दी गई है। और उनको 31 मार्च से पहले पहले पूरी तरह से कब्जा दिला दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं इस सरकार की सबसे बडी गलत बात आपके सामने बताना चाहता हूं । मैं चौधरी भजन लाल की सरकार पर यह आरोप भी लगाना चाहता हूं। कि इस सरकार ने इतनी बडी असत्य बात फैलाई है जिसका मुकाबला नहीं होसकता कि सरप्लस जमीन हरिजनों में बांट दी गई है, न केवल बांटी जा चुकी है बल्कि पूरी तरह से कब्जा भी दिलाया जा चुका हैं। सभापति महोदय , मैं दावे के ाथ यह कह सकता हूं कि यदि यह सरकार पूरे हरियाणा के अन्दर यह सिद्ध कर दें कि इनहोने तमाम हरिजनों को, जो हरियाणा प्रान्त के रहने वाले है, सरप्लस जमीन बांट दी है, तो मैं आज ही विधान सभा से अपना इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। सभापति महोदय, इस तरह की घोशणायें करके इस सरकार को हरिजनों के साथ मजाक नहीं करना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है पहले तो हरिजनों को जमीन दी ही नही

जाती ओर उनको कब्जा नहीं दिला सकती हैं सभापति महोदय, यह सरकार पूरी तरह से बडे–बडे जमीदारों का पक्ष लेती है। हरियाणा में ऐसे हजारों जमीदार है जिन्होने सरप्लस जमीन अपने कुत्ते बिल्लियों के बेनामी नामों से करवा कर रखी हुईं हैं अपने रि तेदारों के बेनामी नामों में रखी हुई हैं अपने लडके–लडकियों के नाम करवा रखी है और अपनी अपनी पत्नियों के नाम करवा रखी है। यही नहीं बल्कि अपनी पत्नियों सेतलाक लेकर जमीन अलग– अलग नाम पर रखी हुई हैं सभापति महोदय, तलाक होने के बाद आज भी उनके बच्चे पैदा हेा रहे है। इसलिये मैं इस सरकार पर बडी गम्भीरता के साथ यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार की हरिजनों को जमीन देने की बात सरासर गलत है और गरीब हरिजनों की आंखों में धूल झोंकने के समान हैं। इसके अलावा सभापति माहदेय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह बडी गम्भीर बात है। हरिजनों को खेती करने के लिये जमीन देने की बात तो दूर रही, उनको रिहाय ी प्लाटस भी नहीं मिले है। गरीब हरिजनों को रहने के लिये अपना सिर छुपाने के लिये उनको जगह चाहिये। यदि कही पर उनको प्लाअस दिये भी गये है तो वे भी जोहडों और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर लिये गये है जहां पर कोई भी आदमी नहीं रह सकता। ऐसी जगहोंपर उनको प्लाटस दिये गये है और उनका भी कब्जा नहीं मिला हैं सभापति महोदय, आप मेरी इन बातों की पूरी तरह से छानबीन कर ले यदि एक भी बात असतय हो तो मुझे आप जो मर्जी सजा दे। सभापति माहेदय, मुझे यह भी मालूम है कि ट्रेजरी बैंचिज पर

बैठे हुये लोगों में से भी कुछसदस्य ऐसे है जो ईमानदारी से यह महसूस करते है कि हरिजनों के साथ यह मजाक हो रहा है। जब वे लोग हमें अलग से मिलते है, तो कहते ळे कि स्वामी जी आपकी बात ठीक है। इसलिये मैं उन्हें यह कहता हूं कि वे यदि महसूस करते है तो किसी स्टेज पर खडे होकर उन्हें इस बारे में बोलना चाहिये तरना कल अगर वे हरिजनों से वोट मांगने के लिये उनके पास जायेगें तो हरिजन लोग उनको अपना वोट नहीं देगे। इसके अलावा सभापति महोदय, हरिजन बस्तियों मेंस्ट्रीट लाइट देने की बात भी आई है। इस बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहताहू। सभापति महोदय, जनतापार्टी के भाासन के दौरान हरिजन चोपालों की बात भाुरू की गई थी और उस समय इस बारे में बहुत से सदस्यों ने इधर से भी ओर उधर से भी यह कहा था कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभापति महोदय, हरिजनों के नाम पर चौपाल बना कर हरिजन बस्तियों मे ंबिजली लगे या कुछ और काम होने लगता है तो यह कहते है कि हरिजनों की भलाईं के लिये काम हो रहे है। लेकिन सरकार हरिजनों के नाम पर यदि अलग से चौपाल बनाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह चौपाल नहीं चोपाड बना रही हैं चौपाल जहां पर होगी वहां पर चारो ंवर्ण इकट्ठे बैठने चाहिये। ब्राहमण,गुजर अहीर, जाट और चूहडा सब के लिये एक चौपाल होनी चाहिये। जहां पर गांव के सभी जाति के लोग इकट्ठे बैंठै। लेकिन यदि गांवो मे हरिजनो क लिये अलग चौपाल होगी तेा उनके अन्दर भी यह भावना पैदा होगी कि कविदासियों की अलग

चौपाल होनी चाहिये और रविदासियों की अलग चौपाल होनी चाहिये। इस तरह से करक`इस सरकार ने गांवो को उजाडने की को‍ि ा ा की है, उनको बसाने की को‍ि ा ा नहीं की। सभापति महोदय, आप भी गुड़गावं जिले के दयालपुरा गांव के रहने वाले है। आप जानते है कि सारे हरियाणा के अन्दर किसी ीि गांव मे हरिजनों के लिये पीने के पानी के कुयें अलग मिलेगें। उनके मोहल्ले अलग मिलेगें सभापति महोदय, हम सब भारत माता की संतान हैं स्वतंत्र भारत के नागरिक है। सबके हक एक बराबर होने के बातजूदभी गांवों में हरिजनो के लिये कुयें अलग है, उनके मोहल्ले अलग है और उनकी चौपालें भी अलग है। सभापति महोदय, पीने के पानी को नहीं बांटना चाहिये । परमात्मा ने पीने का पानी सबके लिये बराबर दिया है। किसी को अलग बांटने के लिये नहीं दिया। इस तरह से करके यह सरकार हरियाणा में जातिवाद को बढावा दे रही है। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि सभी सदस्य ईमानदारी के सथ इस बात को महसूस करे कि हरियाणा में एक आन्दोलन भाुरू किया जाये कि गांवों में पीने के लिये पानी सब के लिय बराबर होगा। गांवों में सब मोहल्लों के लिय एक ही कुआं होना चाहिये। इस बारे में सभी सदस्यों को मिल कर एक आन्दोलन चलाना चाहिये। इसके अलावा हरिजनों के लिये अलग चौपालें भीनहीं बनानी चाहिये। सभापति महोदय, जब हमारी जनतापार्टी की सरकार थी उस समय मैने अपने हल्के के किसी भी गांव में जाकर चौपालों की नीवं नही रखी। इसलिये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि गांवो मे एक ही चौपाल होनी

चाहिये। गांवो में किसी जाति वि ोश कें नाम पर चौपाल नहीं बननी चाहिये।

सभापति महोदय, सामान्य प्र ाासन के अन्तर्गत मैं एक और बात आपके और सदन के ध्यान मे लाना चाहता हूं। कि हम विधायक जनता द्वारा डायरैक्ट चुने जाते है इसलिये हमें कोई भी सरकारी अफसर डी0सी0 या एस0डी0एम0 वगैरह बरखास्त नहीं कर सकते । डायरैक्ट जनता द्वारा चुने हुये सदस्यों का यह अधिकार है कि उनको बरखास्त नहीं किया जा सकता जो गांवों में सरपंच होते है वह भी जनता द्वारा बरखास्त नहीं किया जा सकता जो गांवों में सरपंच होते है वह भी जनता द्वारा डायरैक्ट चुने जाते है लेकिन उनको सरकारी अफसर सस्पैंड या डिसमिस कर देते है। जब एक आदमी गांवों मे पूरे मतों से जीत जाता है तो उसको भी वही प्रिविलेजिज होने चाहिये जो एक विधायक को प्राप्त हैं जो विधायक है वे भी जनता द्वारा डायरैक्ट चुने जाते है यदि उनको कोइ सरकारी अफसर डिसमिस या सस्पैंड नहीं कर सकता तो सरंपच को कैसे किया जा सकता है। क्या सरंपच की कोई गलती है, जिसके लिये सरकार इतनी बडी सजा देती हैं किसी को सस्पैंड कर देती है और किसी को डिसमिस कर देती हैं सभापति महोदय, सरंपच के हाथों में गांवों के अधिकार दिये हुये है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गांव के पूरे अधिकार संरपच के हाथ में होगें लेकिन यह सरकार सरपंचों के साथ ऐसा व्यवहार करके स्वर्गीय महात्मा गांधी के स्वप्न पर कुठाराघात कर रही है।

इसलिये में कहना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार सरकारी अफसरों को नहीं देने चाहिये कि वे सरपंचों को सस्पैंड या डिसमिस कर दे। सभापति महोदय, सामान्य प्र ।ासन पर कल भी मैने एक सवाल उठाया था। उस समय चेयर पर अध्यक्ष महोदय थे, वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। पता नहीं उनको मेरा सवाल समझ नही आया या मैं उनको समझा नहीं सका। मैने यह सवाल उठाया था कि हरियाणा बने हुये आज 15 साल से भी ज्यादा समय होने जा रहा है लेकिन हिनदी के नाम पर बने हुये हरियाणा के अन्दर इस समय भी सारे के सारे काम कानून या विधि के काम अंग्रेजी में होते है। इस सरकार के जो काले अग्रेंज आफिसर बैठे है, क्योकि भूरे अग्रेंज आफिसर तो हिन्दुस्तान छोड कर चले गये लेकिन जो काले अंग्रेज आफिसर बैठे हुये हैवे हरियाणा की छाती पर मूंग दल रहे है ओर कहते हे कि हम पहले अंग्रेजी मे काम करेगें और फिर उसका अनुवाद हिन्दी में करेगे। सभापति महोदय, हाउस की टेबल पर जितने भी कागज रखे जा रहे हे वे सारे अंग्रेजी भाशा में होते है और फिर उनका अनुवाद हिन्दी भाशा में किया जाता है। सभापति महोदय, हरियाणा में कुरूक्षेत्र की धरती पर रह हरे आज ये काले अंग्रेज आफिसर हिन्दी भाशा की बिना पर बने हुये हरियाणा प्रान्त में आज भी सारे के सारे काम अंग्रेजी भाशा में कर रहे है। सभापति महोदय, हर साल 15 अगस्त को यह अनाउन्स किया जाता है कि 26 जनवरी तक सारा काम हिनदी भाशा में करेगें लेकिन इन बातों कोसुनत`हुये हमें आज पूरे 12 साल हो चुके है। लेकिन इस तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं हैं

इस सरकार के काले अंग्रेज आफिसर 6–6 महीने की एक्सटैन्‍ ान ले ले करके हिन्दी भाशा को लागू नहीं होने दे रहे हैं कानून का सारा मूल कार्य अंग्रेजी भाशा में किया जारहा है। जो दूसरे हिन्दी भाशी प्रान्त है उन्होने अपना कानून का काम ओर दूसरे सारे काम भी हिनदी भाशा में करने भाूरू कर दिये है लेकिन हरियाणा मे ंअभी भी यह काम अंग्रेजी भाशा मे किया जा रहा है। सभापति महोदय, इस लानत को दूर करने के लिये हम सरकार से अनुरोध करते है कि वह भाीघ्राति ाीघ्र स्वयं कोई कदम उठाये । **(15.00 बजे)** यदि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो किसी वक्त हरियाणा के अन्दर इस बारे में आन्दोलन भाुरू किया जायेगा और सरकार के काले अंग्रेज आफिसरों का घेराव किया जायेगा। यह अंग्रेजी भाशा हरियाणा प्रान्त में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सभापति महोदय, मुझे बडे दुख के साथ कहना पडताहै कि जनता पार्टी के भाासन काल मे जब चौधरी भजन लाल जी मंत्री हुआ करते थे, उसक वक्त फरीदाबाद में गोली कांड हुआ था। 17 अक्तूबर 1979 को वहां पर वह अत्याचार हुआ जो नहीं होना चाहिये था। बेचारे मजदूरों पर गोलियां चली। वे लोग न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे थे। वहां पर धारा 144 नही लगनी चाहिये थी। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। चौधरी भजन लाल की सरकार ने वहां पर 12 मजदूरों कोभून डाला। जो लोग उस एजीटे ान में हिस्सा नहीं ले रहे थे उन को भी भून डाला गया। वहां पर बडा अंसतोश फैला हुआ था। उस समय मैं चौधरी देवी लाल जी की सरकार में ि ाक्षा बोर्ड का चेयरमैन था। जब

मैने इस बारे मे ंसी0एम0 साहब से बात की और जुडि ायल इन्कवायरी की बात की तो मुझे वहा से उस समय की सरकार ने निकाल कर बाहर कर दिया। मुझे स्वयं निकलने का कोई दुख नहीं है। सभापति महोदय, बडे दुख के साथ कहना पहात हे कि 17 अक्तूबर, 1979 से लेकर आज 29 मार्च, 1982 तक सरकार ने जुडि ायल इन्कवायरी तो क्या मैजिस्टीरियजल इन्कवायरी की रिपोर्ट भी नहीं पे ा की। जुडि ायल इनकवायरी की मांग की गई थी लेकिन उसके बदले मे ंमैजिस्टीरियल इन्कवायरी के आदे ा दिये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट आज तक क्यों पे ा नहीं की गई? उसको कयौं रोक कर रखा गया है?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): रिपोर्ट तो आ चुकी है?

स्वामी अग्निवे ा: सभापति महोदय, आज तक कोई रिपोर्ट नही आई हैं सभापति महोदय, आप जानते हे कि डबवाली में बहन भीला देवी के साथ क्या हुआ। उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उस बेचारी की हत्या कर दी गई। सरकार ने कुछ समय बाद जुडि ायल इन्कवायरी रिपोर्ट पे ा की। उस रिपोर्ट के अन्दर जो दोशी थे उनको गिरफतार नहीं किया गया। सरकार कहती हे कि हमने उनको गिरफतार कर लिया। जब इन्कवारी करने के लिय एक हाई कोर्ट के जज श्री एम0आ0 भार्मा वहां पर जाते है, तो उनको कुछ और ही मिलता है। इन्कवायरी के अन्दर एस0एच0ओ0 को लोकअप में दिखाते है। एस0एच0ओ0

लोक अपन में नही ंमिलता। वह अपने आपको अस्पताल के अन्दर दिखाता है। जब जज महोदय वहां पर जाते है तो एस0एच0ओ0 वहां पर भी नही मिलाता और बाजार में घूमता हुआ मिलता है। यह आज की सरकार का हाल है । सभपति महोदय, आप ही बतायें कि कहां तक इंसाफ की आ ाा इस सरकारसे रखी जा सकती है। उन दोशियों को सजा होनी चाहिये। उनहोने उस बहन से मुंह काला किया था लेकिन उनको कुछ सजा नही ंदी जा रही हैं सभापति महोदय, इसी तरह से दूसरी जगहों के अन्दर भी घटनायें घटी है। इसी प्राकर से एक और घटना परसों गुडगांव के अन्दर घटी है। उस बहन के साथ बलात्कार किया गया ओर बाद में उसे मार दिया गया। सारे हिन्दुस्तान भर में इस बात की चर्चा है। लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही हैं सरकार की जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि अभियुक्तों को गिरफतार कर सके। जो बूढा बाप कल तक अपनी लउकी को यह कहता था कि बेटी यदि रास्ते में कुछ हो जाये तो थाने में चले जाना आज वही बूढा बाप कहता है कि बेटी अगर तुझे मेले में कोई गुण्डा छेड दे तो थाने में मत जाना उसी से हाथ पंाव जोडकर अपनी इज्जत बचा लेना।,

''पा वां जब चोर हो तो कौन रखवाली करे।

उस चमन का हाल क्या जिसका माली मालीपना न करे।

ऐसा आज के समय में हो रहा हैं आज बेटियों की दिन दिहाडे इज्जत लूटी जा रही हैं (ोर) सभापति महोदय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के अन्दर एक हरिजन लडके श्री वेद प्रका ा नरे जो एल0एल0बी0 में पढता था एक ब्राह्राण की जीवन आ ा नाम की लडकी के साथ भाादी कर ली। लेकिन सभापति महोदय उसके बाद क्या हुआ वह भी मैं आपको बतानाचाहूंगां उस क्षेत्र के कुरूक्षेत्र के विधायक ने जो मिनिस्टर भी है लडकी वालों पर जबरदस्ती दबाव डाला। ओर उस हरिजन लडके को पिटवाया गया ओर उसे थाने में बंद करवाया। उस लडकी से झूठा ब्यान दिलवायागया। सभापति माहेदय, इस प्रकार की भाादियेां को तो बढावा देना चाहिये था। इनहोने बढावा देने के बजाये उल्टा काम किया। सरकार को उस लडके और लडकी को प्रोत्साहित करना चाहिये था ताकि ऐसी और भी भाादियां हो सकें।लेकिन बडे भार्म के साथ कहना पड रहा ळै कि आज ऐसे नौजवानो का`सताया जा रहा है(घंटी) सभापति महोदय, मैं एक बात डिमांड नं04 जो कि रैवून्यू से सम्बन्धित है कहना चाहता हूं। आज किसान अपना काम चलाने के लिये कुछ पैसा को–आप्रेटिव बैको से लोन लेते है। लेकिन धारा 67–ए के अधीन ऐसे कर्जदारों के साथ बडी बदसलूकी की जा रही है। यदि कोई किसान अपना काम चलाने के लिये 100 रूपये या 500 रूपया कोआप्रेटिव बैकों से कर्जा ले लेते है तो उनहें बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया गयाहै। यह धारा 67–ए अंग्रेजो ंके समय से चली आ रही है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस को बदला जाना

चाहिये। प्रातः प्र नलोतरकाल के दौरान ाीी यहां पर चर्चा हो रही थी। जो लोग लाखों करोड रूपया सरकार को टैक्स का नहीं देते , उनका कुछ नहीं किया जाता। न ही उनको पकडा जारहा है और न ही उन पर कोइ मुकदमा आदि चलाया जारहा हैं जो लोगा सेल्ज टैक्स की चोरी कर रहे है उनहे ये बढावा दे रहे है। उनकी तिजोरियों से अपनी जेबें और अपनी पार्टी की जेबें भर रहे है। इससे जयादा बडे भार्म की बात ओर क्या हो सकती है? आज इन लोगों ने एग्रीकल्चरल जमीन पर तो सीलिंग लगाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बडे बडे सरमायेदार है, उनको को नही पकडते। आज जनता काफी परे ाान है। उनको नाजायज तौर पर दबाया जा रहा ळैं आज ये कह रहे हे कि कोइ किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। 18 एकड़ कोई 3–4 लाख रूपये की ही जमीन होगी। उसको तो ये परे ाान कर रहे है लेकिन जो करोडो रूपया सेल्ज टैक्स आदि का नहीं दे रहे है उनको कुछ नही कह रहे । जो बडे–2 इन्डस्ट्रीलिस्टस है उनको ये बढावा दे रहे है। यह एक बहुत ही राश्ट्रव्यापी प्र न है। इस पर सोचसमझकर कदम उठाना होगा। आज इन्होने किसानों पर तो सीलिंग लगा रखी है लेकिन जो बडी–बडी इंडस्ट्रीज के मालिक बने बैठे है उन्हे कुछ नहीं कहा जा रहा। इस सम्बनध में मेरा सुझाव है कि बडे–2 इंडस्ट्रीलिस्टस को छोडा न जाये, उनपर भी सीलिंग लगनी चाहिये। (व्यवधान एवं भाोर) सभापति माहेदय, आप भी आर्यसमाजी है और आर्य समाज से बहुत गहरा सम्बन्ध रखते है। भाराब की बात कहते हुये और सुनते हुये भार्म आती है।

लेकिन चौधरी भजन लाल की सरकार भाराब को अधिक से अधिक बढावा दे रही हैं जब अब सआप स्वयं आर्य समाज की सभा के मचं से बोलते है तो उस समय भाराब की आलोचना करते है लेकिन जब चौधरी भजन लाल, आप की सरकार गांव गांव में ठेके खोल रही है। भाराब के कट्टे गांवों में बांटे जा रहे है। बोतलें भर–2 गांवों मे ंपहुंचायी जा रही है। सरकार नारा लगा रही है कि भाराब खूब पियोऔर और खूब जीयो। पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं करा रही लेकिन भाराब अव य उपलब्ध करवा रही है।(घंटी) सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात और कहना चाहता हूं। सरकार यहां पर कह रही है कि एस0वाई0एल0 की एलाइनमेंट की बात हो गई है। पंजाब के सदन के अन्दर वहां के मिनिस्टर री कां ी राम ने कहा है कि एलाइनमेंट अभी नहीं हुआ है। ये यहां पर कह रहे है इलाईमेंट हो चुकी है इस तरह से सदनको गुमराह कर रही है बडे भार्म की बात है। इस तरह की बातों को आगे आने वाले समय में कोई सहन नहीं करेगा। सभापति महोदय मैं अन्त मे ज्यादा न कहते हुये जो ये डिमांडज पे ा हुई है, उनका विरोध करते हुये अपना स्थान लेता हूं।

श्री मनी राम(डबवाली –अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं0 3, 4, 15, 17 और 22 पर बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। (विघन) चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर बहुत छोटे–2 किसान है जिनके पास चार–पांच एकड या

दस–पन्द्रह एकड जमीन है ऐसे बहुत कम किसान है। ये सब लोग कर्ज से दबे हुये है। हमारे हरियाणा की आबादी एक करोड उन्नतीस लाख है। किसानों के उपर सारी किस्म के कर्जे 50 करोड रूपये के है लेकिन वे कर्जे माफ नहीं किये जाते। दूसरी तरु हिन्दुस्तान के अन्दर 200 घर ऐसे है जिनके पास 10 अरब के करीब कर्जे है जो कि माफ हो जाते है। यह बात मुझे बडे अफसोस से कहनी पडती है। फिर चेयरमेन साहब, किसान अपने खेत में जो जिन्स पैदा करता है उसका उसे पूरा भाव नही मिलता बाहर से तो मंहगे भाव से गेहूं मंगवा लिया जाता है लेकिन अपने किसान को सरकार ठीक भाव नही देती। यह भी बडे दुख की बात है।

चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं इरीगे ान डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । हरियाणा कृशि प्रधान प्रदे ा है। खेती बाडी आप जानते है, सिचाई से होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास आज पूरा पानी नहीं है। हमारे हरियाणा का एक तिहाई हिस्सा सूखा पडा हुआ है। अगर इसे पानी मिल जये तो हमारा हरियाणा आधे भारवर्श को खाना खिला सकता है। इरीगे ान डिपार्टमेंट के अन्दर एम0आई0टी0सी0 आता है। वह खालों की लाईनिंग कर रहा है। हमने समझा था कि लाइनिंग करने से पानी की बढोतरी हेागी लेकिन इन्होने इस किस्म काडिजाईन बनाया हे जिससे पानी टेल के खेतों को नही पहुंच पाता। नहरों का लैवल इन्होने उंचा बना दिया है । इससे टेल पर

पानी नही पहुंच पाता। मैटीरियल भी सब स्टैनडर्ड लगाया हुआ है। परिणास्वरूप खालें टूट जाती है। इस बारे में मै। सरकार को एक सुझाव दूंगा। ये फ्री बोर्ड तीन ईंच का लगाते है। इसकी वजह से खालों का पानी ओवर फलों हो जाता है और खेत तक नहीं पहुंच पाता। फ्री बोर्ड 6 ईंच काहोना चाहिये। ताकि टेल के खेतों को भी पानी मिल सके।

अब मैं डिंमाड नं0 22 पर जो कि कोआप्रे ान डिपार्टमेंट के बारे में है। बोलना चहाता हूं। मेरे भाई भागी राम जी ने सवाल पूछा था । वह सवाल सिरसा के एक बैंक में हुई भर्ती के सम्बन्ध में था। वहां एम0कौम0 और बी0कौम0 सडकों को तो नजरअन्दाज कर दिया गयालेकिन कम क्वालिफिके ान्ज के लडके लगा लिये गये। रिजर्वे ान ऐसा कह कर पूरी नहीं की गई कि क्वालीफाईड लडके अवेलेबल नहीं थे। यह हरिजनों के साथ बहुत भारी ज्यादती है। यही हाल फूड एण्उ सप्लाईज डिपार्टमेंट का है यहां फूट इंस्पैक्टर्ज से 8ए0एफ0एस0ओज0 प्रमोट किये गये लेकिन उनमें भी एक भी हरिजन नहीं लिया गया । यह भी हरिजनों के साथ ज्यादती है।

सरकार यहां कहती है कि हरिजनों को बडी भारी जमीन दे दी है। मैं सिरसा की बात आपको बताता हूं। वहां हरिजनों को सरप्लस जमीन ऐसी जगहों पर दी गई है जहां तक जाने के लिये रास्ता नहीं होता। पिदली बार मैने इस बारे में सवाल भी पूछा था लेकिन बात इधर उार की बातें करके टाल दी

गई। मेरी सरकारसे यह प्रार्थना है कि रास्ते का प्रोविजन जरूर होना चाहिये। अगर ऐक्ट में तरमीम करनी पडे तो तरमीम भी की जानी चाहिये। आज जमीन मालिक की मर्जी के मुताबिक मिलती है। यह बात नहीं होनी चाहिये।

अब चेयरमैन साहब, मै एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। रोहिडावाली गांव में जमीदारों ने हरिजनों की खडी फसलो ंपर ट्रैक्टर फेर दिया लकिन उनको ठीक मुआवजा नहीं दिलवाया गया। इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे है।

इसके बाद चेयरमैन साहब मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारी सरकार कहती है कि प्रानत में सब कुछ अच्छा है। पिछले दिनों आपको पता है डबवाली में दिन दिहाडे बैंक में डकैती पडी थी। पुलिस को उसी वक्त इंफार्म कर दिया गया था। अगर पुलिस उसी वक्त आ जाती तो हो सकता है कि डकैती पडने से बच जाती लेकिन पुलिस वहां आधे घंटे के बाद आई।

इसी तरह का वहां का एक केस और है। पिछले साल की बात है कि तरसेम लाल नाम के व्यक्ति के लडके को यू0पी0 से आये हुये कुछ बमा । उठाकर यू0पी0 ले गये थे जिसे पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी।

चेयरमैन साहब, एक और बात मैं आपको बताता हूं। डबवाली हल्के में खुइयामलकाना एक गांव है। वहां एक कांग्रेसी आदमी ने, जिसका का नाम मैं लेना नहीं चाहता एक सांड मरवा दिया था। उसकी एप्रोच उपर तक होने की वजह से वह बात वहीं दब गई। इनसब बातों से पता लगात है कि ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा में अच्छी नहीं हैं हरियाणा में आज दिन दिहाडे बैंक लूटे जाते है, बसों में और रेलों में डकैतियां होती है।लोगों को जान और माल खतरे में है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार निकम्मी है और इस निकममी सरकार को हमें बदलना है। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का विरोध करता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): सभापति महोदय, मैं डिमांड नं0 4, 15, 17 और 22 पर अपने विचार रखने चाहूंगा। (विघन)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मुझे समय नहीं मिल रहा हूं। मैं कई बार लिखकर भी दे चुका हूं।

श्री सभपति : चौधरी साहब, आपको भी समय मिलेगा। अभी आप बैठिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, 1982–83 के लिये जो बजट सदन में पे ा कियागयाथा उसमें बजट का लगभग 78 प्रति ात सिंचाई बिजली व कृशि पर खर्च करने का सरकार का नि चय है जिससे यह बात जाहिर होती है कि हरियाणा की

सरकार हरियाणा के अन्दर किसान की और मजदूर की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये एक नि चय लिये हुये है। इतनी बडी धनरा‍ि ा जो सरकार कृशि पर खर्च करने जा रही है। वह इस बात की प्रतीक है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जो नया बीस सूत्री कार्यकम पे ा किया गया है, उस पर यह सरकार पूर्ण रूप से अमल कर रही है। सभापति महोदय 20 सूत्री कार्यकम में 9 सूत्र कृशि से या सिंचाई से सम्बन्धित है और 5 सूत्र गरीब हरिजनों , पिछडी जाजियों और आदिवासियों आदि से सम्बन्धित है। सभापति महोदय विरोधी पक्ष के भाइयों की ओर से भिन्न–2 मदों पर दिये गये पैसे के विशय में दलीलें दे कर किटिसिज्म किया गया है। मैं उनकी दलीलों का जवाब न दे कर कुछ सुझाव सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरे दिये हुये सुझावों पर सरकार विचार करे। आज हरियाणा खेती के मामले में अग्रणीय है। हमें सोचना है कि हरियाणा किसी प्रकार से आगे बढ सकता है। आज दन में प्र नोत्तर काल में फसलों के बीमें के विशय में काफी चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने जवाब देते हुये बताया कि किस प्रकार से पायलट स्कीम फसलों के बीमें के लिये इन्ट्रोडयुस की गई है? चेयरमैन साहब जिस प्रकार से यह स्कीम इन्ट्रोडयुस की गई है, उस प्रकार से किसानों का भला होने वाला नहीं हैं उन्होनें हाउस में बताया किसारी तहसील को एक यूनिट बनाकर ओर उसकी एवरेज निकाल करउसकी धन रा‍ि ा मिलेगी। अगर एवरेज कम निकली तो उसे बहुत कम मिलेगा। मेरा सुझाव है कि किान का व्यक्तिगत तोर पर बीमा कराये या न कराये। इतने

कम्पलीकेटिड प्रोसीजर से एवरेज निकालेगें तो बडी परे ाानी होगी। स्टैटीस्टिकल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एवरेज निकालने पर जी0आई0सी0 बीमा करेगी तो गलत बात होगी। एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड जिसकी सालाना आच 20 करोड के लगभग है, उसका सारा का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंडियों पर खर्च किया जाता है। यानि मंडी की हदूद में खर्च होता है। मैं आपके जरिये सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड एक्ट में तरमीम की जाये। वह तरमीम इस बात को ध्यान में रखते हूये की जाये कि जो पैसा हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड से आता है उसे कौमन पूल में डाल दिया जाये। अगर बीस करोड़ को हम कौमन पूल में डाल`दगें तो किसानों की कि त दी जा सकती है।। इसलिये मेरा सुझाव है कि किसानों के प्रीमीयम की कि त मार्किटिंग बोर्ड अदा करे। यदि मार्किटिंग बोर्ड 60 परसैंट किस्त अदा करता है तो 40 परसैंट किसान अदा करे ताकि किसान का भी इन्ट्रसट बना रहै। ऐसा करने से किसान पर भी ज्यादा भार भी न होगा और वह अपनी फसल बीमा करा सकेगा। पहले सभी फसलों का बीमा करने काप्रोगग्रम नहीं था लेकिन अब सरकार ने फैसला किया हे कि गेहूं की फसल का बीमा किया जाये। गेहूं की फसल तो बहुत ही ज्यादा होती है। ओलावृश्टि या प्राकृतिक प्रकोप न हो तो गेहूं की फसल 25–30 मन फी एकड के हिसाब से तो निकल ही आती है। लेकिन बाजरा, सरसों और खासकर चने की फसल तो ऐसी है जो किसानों के लिये जुये के समान हैं इन्‍ ोरेन्स भी जुआ ही है। अगर किसान

बीस एकड में गेहूं बोता है तो सारी विपदाओं के बाद भी दो सौ या तीन सौ मन पैदा कर लेता है। बीस एकड में चना बोता हे तो वह बीससेर भी नहीं ले सकता। चने की फसल का बीमा बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से आदमी कापता नहीं होता कि वह किस समय गुजर जाये। उसी प्रकार से चने की फसल का पता नहीं होता कि कब वह मर जाये। उसी आधार को रखते हुये पालिसी तय की जानी चाहिये। हरियाणा का किसान खलिहान से उठनके के बाद भी सोचता रहता है कि फसल घर आयेगी या नहीं। हरियाणा में पैडी और गेहूं की तो मेन क्रेप है लेकिन जो फसलें बिल्कुल उन कौमन है, उनके बारे में भी भयोरिटी किसान को मिलनी चाहिये कि अगर उसका नुकसान हो जायेगातो बीमें से कुछ मिल जायेगा। बीस सूत्री प्रोग्राम में भी तिलहन की फसल की बढौतरी का प्रेाग्राम रखा गया है।

तिलहन की फसल का ऐतबार नहीं है। बारि ा न होतो भी खतरा है और बारि ा अधिक हो गई तो भी खतरा है। इसके अलावा अगर दूसरी विपदा आ गई तो भी फसल बरबाद हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा इन फसलों का बीमा कराया जाये।

चेयरमैन साहब, कृशि भुमि को मैं तीन वर्गों में बांटता हूं। एक वर्ग है जिसमें बहुत ही उपजाउ भुमि आती है। इस में जिला करनाल, कुरूक्षेत्र व कुछ हिस्सा अम्बाला, हिसार और जीन्द का भी आता है जो बहुत ही उपजाउ है। हमारा ि ावालिक हिल्ज

का एक बहुत लम्बा एरिया ळै। कालका से भाुरू होकर हथनी कुंड तक जाता हैं आज अगर हम उनकी आर्थिक अवस्था को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनके पास कोई साधन नहीं हैं जिससे कि वे अपनी रोजी रेाटी चला सके। सरकार ने वहां पर कुछ स्कीमों के लिये पैसा दिया है। एग्रीकल्चर फोरेस्ट और इरीगे ान डिपार्टमेंट को वाटर टैक्स के लिये यानि पानी इक्ट्ठा करके सिंचाई के साधन जुटाने क`लिये पैसा दिया हैं सरकार ने मारकन्डा और टांगरी पर बांध बना का इरीगे ान करने का भी प्रोग्राम बनाया था लेकिन इस बजट में इस प्रोजेक्ट के लिये पैसा नहीं दिया गया हैं वाटर टैक्स बनाने का तीन डिपार्टमेंट काम करते है। इस तरह से डिपार्टमेंटस मे काम की इतनी डुपलीकेसी होती है कि कोई भी डिपार्टमेंट काम नही कर सकता है। फोरैस्ट को अलग पैसा दिया जाता है। इरीगे ान को अलग और एग्रीकल्चर को अलग पैसा दिया जाता हैं इसलिये मेरा सुझाव हैं वाटर टैकंस बनाने के काम को युद्धस्तर अपने हाथ मे ले और दूसरी बात यह कि यह काम एक ही महकमे का सौपना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि भिवानी, महेन्द्रगढ़ और हिसार का रेतीला इलाका है। वहां सिचांई के साधन तभी अवेलेबल हो सकते है जब हरियाणा में रावी—व्यास का पानी आयेगा, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस बात की रिसर्च को जाती है कि ड्राई फारमिंग कैसे की जाये? कैसे उपज बढायी जा सकती है, लेकिन किसानों को इस बारे मे कुछ नहीं बतलाया जाता वह ज्ञान

न तो उनको होता है न उनके पास पहुंचता है और न ही पहुचाने की कोि ा ा की जाती है। यदि उनको ड्राई फारमिंग का ज्ञान हो जाये तो किसान अपनी पैदावार बढा सकते है।

इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आपके इलाके में और खासतौर पर रोहतक और गुडगांव के इलाके में बंजर जमीन है। इसकी रीकलेमे ान का काम लैंड पर जो काम हुआ है उसमें काफी प्रगति हुई है लेकिन सलाइन लैंड एक इंच भी रीकलेम नहीं की है। आज इस जमीन को ठीक करने के लिये बहुत फन्ड की जरूरत है । लाखों एकड भूमि बेकार पडी है। इसक`लिये सरकार को कितने ही करोड का प्रबन्ध करना पडे जरूर करना चाहिये। कृशि के बारे में एक बात और कहना चाहता हू। हरियाणा के लोग दिल्ली को लूटें तो हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुधर सकती है। लूट से मेरा अभिप्राय सिर्फ इस बात से है कि दिल्ली की आबादी 60 लाख की है। उसके साढे तीन तरफ हरियाणा पडता हैं यानि दिल्ली आधी तरफ से तो यू0पी0 से धिराहुआ है लेकिन साढे तीन तरफ से हरियाणा से धिरा हुआ है। करोडो रूपये की सब्जी हर महीने दिल्ली की मंडियों मे जाती है। सभापति महोदय, कृशि विभाग की यह जिम्मेवारी हे कि वह हरियााा के किसानों को दिमागी तौर पर ऐसा बनायें कि वे अपना क्राप पैटर्न इस तरह से अपनायें कि दिल्ली के नजदीक जितने भी किसान है वे सब्जी से अपनी आर्थिक हालात को सुधारें। इसके लिये इस प्रकार का आर्थिक

ढांचा तैयार करें जिससे कि किसानों को सरकार हरप्रकार की सहायता दे और उन्हें हर किस्म का इन्सैटिव मिले। सभापति महोदय, इसके साथ–2 मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूमं कि हरियाणा के किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा है सब्जी प्रिजर्व करने के लिये डिब्बे भी मुहैया करवाने चाहिये। बे ाक इसके लिये कोआप्रेटिव सैक्टर में कारखानें लगायें जिससे कि किसान हरी सब्जी डिबें मे बन्द करके गल्फ कंट्रीज की ओर अरेबीयन कन्ट्रीज को भेज सके। अगर ऐसा हो जाये तो करोडो रूपये की सरकार को आमदनी हो सकती है और करोंडों रूपये की किसान को आमदनी हो सकती है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में भी खसस तौर पर सुधार हो सकता है। इसके साथ–2 एक बात मैं और कहना चाहता हूं (घटीं)... सभापति महोदय, मै। एक बात कहकर बैठ सजाउंगा। रैवेन्यू के महकमे के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर एलान किया है कि सरकार उस लोगों को जिनकी फसलें ओलावृश्टि से खराब हुई है, 400 रूपये, 300 रूपये और 200 यपये प्रति एकड के हिसाब से कम्पनसे ान देगी। सभापति महोदय, मैं ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता हूं जहां पर ज्यादा फसल चने की होती है। अब की बार जब मैं हल्के में गया तो लोगों ने मेरे सामने पूरे गट्ठे के गट्ठे चने की ुसल के लाकर रख दिये और कहन`लगे कि आप खुद देख लें, इन सारे पेडो के अन्दर एक भी टाट नहीं है। सभापति महोदय, यह हकीकत है। पता नहीं ऐसा क्लाईमैटिक चैंजिंज की वजह से हुआ है औलावृश्टि की वजह से हुआ है या

किसी दूसरे कारण से हुआ है। लोग तो यह कहते है कि भाययद जो 9 ग्रह इकट्ठे हुये है उस वजह से हुआ है। (व्यवधान) मंत्री महोदय की यह बात भी ठीक हो सकती है। कि फसल मं कोई बीमारी ऐसी लग गयी होगी जिस वजह से उस हरे पौधे को अब जानवर भी नहीं खाते। सरकार ने इसकें लिये ब्रे ाक गिरदावरी के आर्डर्ज इ ू कर दिये है। (व्यवधान व भाोर) लेकिन ऐसे केसिज में जरूर विचार किया जाना चाहिये। आप चाहे क्लाईमैटिक चैंजिज या कैमीकल रीएक ान की वजह से या किसी दूसरे भी कारण से ऐसा समझें लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि ऐसे केसिज में तकावी और आबियाना सरकार को माफ करपा चाहिये। सभापति महोदय, अगर भारत सरकार ऐसे किसानों को कोई पैसा नही देती तो हरियाणा सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि कृशि प्रधान प्रदेश होने के नाते ऐसे लोगों को भी कम्पनसे ान दे। इसके अलावा एक बात मैं और कहनाचाहूंगा। मेरे साथियों, बहन कमला वर्मा और संत कवंर जी ने वि ोश रूप से एक बात कही। उनहोने यह कहा कि हरियाणा में ला एंड आर्डर ठीक नहीं हैं पुलिस इसकम्पीटेंट हैं ला एंड आर्डर खराब है। मैं तो इस बारे मे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक दिन डाक्टर कमला वर्मा जी मेरे पास बैठी हुई यह कह रही थी कि भाइ हम यंहा पर हरियाणा में अच्छे हैं यू0पी0 में 7 बजे के बाद तो लेाग बहर नहीं चलने देते।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक रोगी या बीमार आदमी हास्पिटल में जाता है तो सरे वहां जाये। अगर वहां पर हालत इतनी अच्छी नहीं है तो हरियाणा में भी उतनी ही बिगडनी चाहियै। आज हरियाणा मे जो इतने कांड हो रहे है बलविन्द्र कौर कांड और संतोश कुमारी कांड वगैरह इनकी वजह से इनको चिन्ता होनी चाहिये। परसैंटेज का थोडा बहुत फर्क होसकता है लेकिन इनको इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं तो इतना कह सकता हूं कि जिस तुस्तैदी के साथि जिस नेक नीयती के साथ पुलिस के महकमें में काम होना चाहिये, उसके साथ नहीं हो रहा है।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः पानीपत में कल ही डाका पडा हैं उसमें 3 आदमी मर गये हैं (व्यवधान व भाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना जरूर कह सकता हूं कि हरियाणा के अन्दर जब भी कोई डाका, राहजनी या चौरी की घटना हुई या बसों को लूटा गया तो उसके मुलजमों को गिरफतार भी किया गया और उनसे सामान भी बरामद हुआ। एक बात मै। पु्लिस के रवैये के बारे में कहना चाहता हूं कि जो उसका इन्वैस्टीगे ान या इन्टैरोगेन ान का तरीका है वह 50 साल पुराना है जिसमे सिर्फ टौर्चर करके और

गलत तरीके इस्तेमाल करके गरीब आदमी को सताया जाता हैं वह तरीका इस युग में भाोभा नहीं देता। यह जरूरी है कि इस युग में पुलिस को मानव को मानव समझ कर एक इन्सान जैसा व्यवहार करना चाहिये ताकि आने वाले समय में पुलिस का रैपुटै ान बढे और उसका रूतबाबढ़े। उसमें लोगों का वि वास बढनाचाहिये न कि घटना चाहिये। इन भाब्दों के साथ मैं सभी डिमान्डज को स्पोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

श्री भले राम (बडोदा–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं.2 से लेकर डिमांड नं0 22 तक जो आज के एजेंडे पर है, बोलना चहाता हूं। डिमांड नं. 2 जनरल एडमिनिस्ट्रे न के बारे में है।

श्री सभापतिः क्या आप सारी डिमांडज पर इक्टठा ही बोलेंगे।

श्री भले रामः सभापति महोदय, मैं नाम ले दूंगा। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रे न का सवाल है हरियाणा के एडमिनिस्ट्रे न की तरह भाायद ही किसी दूसरी स्टेट का एडमिनिस्ट्रे न ढीला होगा। सै ान कु कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर छपी थी कि हरियाणा में सारे सैक्रेटेरियेट में कोई भी मंत्री नहीं बैठा हुआ था, सारा सैक्रेटेरियेट ही खाली पडाह ुआथा और फाईले सारी पैंडिग पडी हुई थी।

चौधरी खुर ीद अहमदः सभापति महादेय, अगर हम किसी ीी दिन सैकटेरियेट खाली छोड दे तो भले राम जी इतने भले नहीं है कि उसको बिना कब्जा किये छोड दे। दूसरे ही दिन वहां पर कब्जा कर लेगें। (व्यवधान व ाोर)

श्री भले रामः येचरमैन साहब , मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक ान नजदीक है इसलिये चीफ मिनिस्टर ओर जितने दूसरे वजीर है सारे टूर कर रहे ह। चीफ मिनिस्टर ओर दूसरे वजीर जगह–2 पत्थर लगाते जा रहे हैं मैं तो चौधरी भजन लाला को पत्थरों काराजा कहता हूं । एक पत्थर लगाते है और कहते है हे काली माई! हे देवी, मैं आपकी पूजा कर रहा हू। श्रीमती इन्दिरा गांधी आई है बीस सुत्री कार्यकम लाई है। मेरी इलैक ान में लाज रखना। मैं जीत गया तो मैं तुम्हें राजी कर दूगा(ाोर एवं व्यवधान)। चेयरमैन साहब, मैं दावे के साथ कहता कि आज ऐडमिनिस्ट्रे न की हालत बहुत खराब है। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हू। मेरे हल्के में एक मुडलाना ब्लौक हैं वहां का टेचन्द नाम का आदमी एक साल पहले रिटायर हो गया था लेकिन हैड औफिस से उसकी चिट्ठी जाती है कि तुम्हारा स्थानान्तरण हो गयाहैं एक साल रिटायर हुये हो गयाऔर साल के बाद ट्रांसफर आर्डर भेजा जा रहा है। इस तरह की हालत आज ऐडमिनिस्ट्रे न की है। चेयरमैन साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज कल जितने भी इंटरव्यु चल रहे है चाहे एस0एस0एस0 बोर्ड के चल रहे है या डिपार्टमेंटस इंटरव्यू चल रहे है, चाहे वे इंटरव्यू

हैडमास्टर्ज के हैया पटवारियों के है इनमें सिलैक ान गलत ंढंग से होगी, मैरिट पर कोई नहीं आयेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि सारे इंटरव्यू इलैक ान तक बन्द कर देने चाहिये क्योंकि रूलिंग पार्टी नाजायज ढंग से भर्ती करेगी ओर जो लोग मैरिट पर होगें उनको नही लिया जायेगा। आज हमारे जो एम्पलाईज हे उनके अन्दर बडी भारी रिजन्टमेंट हैं कहीं पर आज हडताल होरही है और कही पर डिमोस्ट्रे ान किया जा रहा है ंसरकार कहती है कि हमने एम्पलाईज के पे सकेल्ज में जो ऐनीमोलीज थी वेखत्म करदी है, ग्रेड रिवाइज कर दिये है और एम्पलाईज को सिलेक ान गेड दे दिया हैं लेकिन पिछले दिनों पी0डब्ल्यू0डी के एम्पलाइज धरने पर बैठे थे। सरकार ने उनकी डिंमाड को मानने की बजाये उनके लीडर्ज की जिनकी आठ-2 साल की सर्विस थी, सर्विसिज टर्मिनेट कर दी। एम्पलाईज कहते है कि मंहगाई बढ रही है और प्राईस इंडैक्स पिछले साल से बहुत उंचा चला गया हैं सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्पलाईज को चार डी0ए0 की कि तें रिलीज करे। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने दावा किया हे और गवर्नर ऐड्रेस में भी कहा गया है कि यह सरकार हरिजनों की रक्ष करेगी। आज हरियाणा में हालत यह है कि जगह-2 डाके पड रहे है और लूटमार हो रही है। हरिजन लोग जो गांवों में रहते है, वे कहते है कि हम किसी से तंग नहीं है हम तो केवल पुलिस से तंग हे। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में वाकई हरिजनों की रक्ष करने की इच्छा है तो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा हरिजन अफसर लगाओ। सरकार यह तो कर

नहीं सकती कि जो हरिजन अफसर है उनको सिर्फ तंग ही कर सकती है। एक हरिजन डी0आई0जी0 जो स्टेट से आठ साल तक बाहर रहा हे और जिसका नाम ....है उसको मधुबन में लगा दिया....................

Chaudhri Khurshid Ahmed: Mr. Chairman, I think, he should not nhame the official.

श्री सभापतिः चौधरी भले राम ने जिस डी0आई0जी0 कानाम लिया हे उसको रिकार्ड न किया जाये। चौधरी भले राम जी आप किसी का नाम न ले।

श्री भले रामः चेयरमैन साह,ब जो हरिजन डी0आई0जी0 है या दूसरे अफसर है उनको तंग कर रखा है। चौधरी मुख्तियार सिंह और चौधरी रिजक राम भी कहते रहते है कि यह सरकार जाटों के खिलाफ है। मैंभी यह कहता हूं कि यह सरकार जाट और हरिजन अफसरों के खिलाफ है। चेयरमैन साहब, इनको पता हे कि देहात के जाट ओरहरिजन अब नजदीक आ रहे हैं इनको यह भी पता है कि आगे आने वाले इलैक ानों में ये लोगा कांगेस को वोट नहीं देगें इसलिये जाट और हजिन आफसरों को बाहर भेजा जारहा हैं। चेयरमैन साहब, अब मैं कृशि के बारे में कहना चाहता हू। सरकार बडी–2 घोशणायें करती रहती है कि किसानां के लिये यह किया जा रहा है वह किया जा रहा है। किसानों को बढिया ओर सस्ती खाद दी जा रही हैं फील्ड स्टाफ प्रोवाइड किया जारहा है ताकि किसानों को टैक्नीकल नो हाउ मिल सके लेकिन

चेयरमैन साहब, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा हैं फील्ड में कोई आदमी नहीं जाता। सारे औफिसर्ज दफतर में ही बैठे रहते है। चेयरमेन साहब, जैसे अभी ओले पडे गये तो एग्रीकल्चर को गांवों में जानाच.ाहिये था और वहां जाकर किसानों को सुझाव देना चाहिये था कि इस वक्त यह फसल बीजों लेकिन हकीकत यह है कि सब लोग दफतरों में ही बैठे रहते हैं रेडियों से जो ुसलों के बारे में बताया जाता है उसी से किसान लोग जयादा फायदा उठाते है। चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहनाचाहता हूं। यह सरकार भेदभाव की नीति रखती है। जिससमय चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो उनहोने इलान किया था कि भाूगर मिल्ज वहां पर लगाई जायेगी जहांपर भ्ाुगरकेन यानि गन्ना ज्यादा पैदा होता हैं चेयरमेन साहब, हमारे गोहाना में बहुत अधिक गन्ना पैदा होता है लेकिन जो तीन भ्ाुगरमिले सरकार लगा रही है उसमें गोहाना का कही नाम भी नहीं हैं इरिगे ान का भी यही हाल हैं यह तो ठीक है कि इस साल भगवान की दया रही ओर जयादा पानी की जरूरत नहीं पडी लेकिन इन्होने यह किया कि जो लोकदल के एम0एल0एज0 काएरिया है या जहां पर लोकदल के विचारों के लोग डौमीनेट करते है, वहां की माइनर्ज को और डिस्ट्रीब्यूटरीज को तंग कर दिया। चेयरमेन साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक बुटाना डिस्टीब्युटरी है और बुटाना माइनर है उसको तंग कर दिया गया है। वहां की मिट्‌टी अपने आप कट गईलेकिन किसानों पर झूठे केस बनाये गये और कोर्ट में उनको ले गये। दो सो या

अढाई सौ के करीब केसिज इसतरह के कोर्ट में ले गये है जबकि वास्तविकता यह है कि वह मिट्टी अपने आप कटी थी। किसी ने भी कोई कट नहीं लगाया था। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह के झूठे केसिज को सरकार वापिस ले।

चेयरमैन साहब, सरपंचों के लिये यह किया गया था कि वे बसों में फ्री सफर करेगें और उनको तीन सौ रूपया अलाउन्स फिक्स मिलेगा। सरपंचों के आइडैटिटी कार्ड भेज दिये गये वे बी0डी0ओ0 के पास पडे हुये है उनको नहीं दिये गये है मुझे कई सरपंच मिले ओर उन्होने मुझे बताया है कि इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। एस0टी0सी0 और जनरल मैनेजर कहते है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक ान्ज नहीं हैं कई सरपचों से दस गुणा किराया वसूल किया गया है। अब मै कोआप्रेटिव डिपार्टमेंटस की डिमान्ड नम्बर 22 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । थोडी देर पहले आपने कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा कि वहां पर किस तरह से अपांयटमेंटस की गई। चेयरमेन साहब, आज तक कोआप्रेटिव बैंक्स के चेयरमैनज की इलैक ान नहीं हुई। चेयरमैन साहब, मै। एक बात ओर कहना चाहता हूं कि गोहाना के एरिया के कुछ गांवों में खेडी, सरसाना, घनोरकला, घनौरखुर्द और गोहाना में ओलेपडे थे और वहां पर काफी नुकसान हुआ था। मैं तो किसान के बारे में कहना चाहता हूं:

किसान की कठिनाई को किसान जानै सै।

औरों को क्या बेरा भगवान जाने सै।

चेयरमेन साहब, गोहाना में घनौर खुर्द गांव में भ सयैन्ट परसै।ट किसानों की फसले बरबाद हो गयी हैं मैं ने इस बारे में सरकार से कहा भी था ओर सुझाव भी दियाथा कि वहां पर फौरी तोर परफुड फार वर्क वाली नीति काएलान कर दिया जाये क्योंकि जो छोटै–2 किसान थे, हरिजन भाई थे, जिनके पास बहुत थोडी बहुत जमीन थी वे बिल्कुल बेघर हो गये है और उनकी फसलें सैनट परसैनट तबाह हो गयी हैं वे लोग बिल्कुल खाली बैठे हुये हैं फसलें खराब हो जाने के कारण उनके पास कोई काम नहीं है जिससे वे कमाई करके आने व अपने बालबच्चों का गजुजारा कर सके क्योकि वे खेतीबाडी पर ही निर्भर करते है ंइसलिये अब मेरी इस सरकार से फिर रिक्वैस्ट है कि वे इस तरह काएलान करे ताकि किसानों और हरिजनों को सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सके।

इससे आगे चेयरमेन सहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि एमरजैनी के दिनों मे फार्मर्ज को 1000/500 रूपये की सहायता दी गयी थी। सहायता देते समय यह कहा गया था कि यह रकम सहायता के तोर पर दी जा रही है वापिस नहीं ली जायेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोगें के सिर के उपर वह कर्जा दिखयाा गया है और वे जिन लोगों को वह ग्रान्ट दी गयी थी, आज जेलों में बैठे है क्योकि उनके पास देने को कुछ नहीं है। इसलिये मैं सरकार से पूरजोर दरखास्त करूंगा कि जिन लोगों

को एमरजैन्सी के वक्ल ग्रान्ट दी गयी, उन सब का यह पैसा माफ कद दिया जाना चाहिये अन्त में मैं इन सब डिमांडज का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापतिः चौधरी ई वर सिहं।

चौधरी ई वर सिंह(गुहला–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 3, 15, 17, और 22 पर बोलूगां।

वाक –आउट

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमेन साहब, आप वायदे के मुताबि मुझे समय नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य पहले ही बोल चुके है..................................(ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः पोहलू साहब, 16 मिनट आप गर्वनर एड्रैस पर बोल चुके है और 14 मिनट बजट पर बोल चुके है लेकिन इनको समय नहीं दिया गयाथा। आप बैठिये, आपको भी समय मिलेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मुझे बोलने का समय मिलना चाहिये था, आप जानबूझ कर नहीं दे रहे है, इसलिये मैं प्रोटैस्ट के तौर पर सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री सभापति : पोहलू साहब, आप बैठिये आपको बोलने के लिये समय जरूर दिया जायेगा। (ोर)

(इस समय चौधरी जगजीत सहिं पाहलू सदन से वाक आउट कर गये)

वर्श 1982–83 के बजट के अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी ई वर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि मैं डिमांड नम्बर 3, 15, 17, और 22 पर बोलूगां। डिमांड नम्बर 15 जो है, वह सिंचाई से सम्बन्धित है। चेयरमैन साहब, मैं इस बारे मे कुछ कहना ओर सुझाव देना चाहता हूं जहां तक इस बात का ताल्लूक है कि आज हमारी सरकार नेसिंचाई की बात को सिरे चढाया है उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। लेकिन इसी सिलसिले में बउी भारी समस्या हमारे सामनेखडी है कि हमारे हरियाणा का कुरूक्षेत्र जिले का इलाका पंजाब के साथ लगता हैं पंजाब की जो माईनर हरियाणा में आती है, उसकायह हाल है कि जब हमारे यहां किसानों को पानी की आव यकता होती है तब तो उस माईनर में पानी छोडा नहीं जाता है और जब हमारे किसानों को पानी की आव यकता नहीं होती है तब पानी का

बहाव इतना ज्यादा हो जाता है कि किसानों की फसलेकं भी तबाह हो जाती है। इस बारे में मैने आई0पी0एम0 साहब, को एक पत्र भी लिखा था। लेकिन भाायद इस बारे में अभी तक कोइ कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये मेरी सरकार से रिवैस्ट है कि वह पंजाब सरकार के साथ बैठकर इस मसले को हल करे। जिस प्रकार दूसरी नदियां जैसे घग्घर वगैरह, है वे भी पंजाब और हरियाणा की सीमा के साथ साथ गुजरती है,वहां पर पानी की रोकथाम के लिये पूरा प्रबन्ध है, उसी प्रकार से इस माईनर के बारे में भी हमारी सरकार पंजाब सरकार से बातचीत करे ताकि जो पानी हरियाणा में आकर बरबादी करता है उससे हमारे किसान बच सकें और किसानों को किसी प्रकार की क्षति का सामना न करना पडे। कई बार तो इस माईनर में इतना जयादा पानी आ जाता है कि वह बांध पार कर लेता हैं इसलिये मेरा कहना यह है कि वैसे तो हमारी सरकार किसानों के हकों में नहरो को पक्का करने में माइनर्ज बनाने में सब तरह से अग्रसर है लेकिन उसी तरह से सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद मैं सहकारिताके बारे में भी अपने विचार रखना चाहूंगा। इसमें गरीब आदमियों के उपर एक तरह से एक हदबन्दी कर दी गई है कि जो थोडी जमीन का मालिक है या छोटा किसान है, उसको 1000 रूपये से ज्यादा कर्जा नही ंदिया जायेगा। यह जोलिमिट है, वह बहुत कम है। यदि कोई आदमी अपने ही खेत के उपर गुजारा करता है और उसका कोई दूसरा

कमाई का साधन नहीं है वह छोटा किसान है यदि वह दुसरे की जमीन ले कर खेती करनाचाहता है तो भी यह वह चाहगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिले खाद मिले, बीज मिले पानी मिले। हर तरह के खेती के साधनों की हर आदमी को जरूरत है लेकिन इस छोटी सी मदद से किसानका भला होने वाला नहीं हैं इससे क्या होगा कि किसानकागुजारानहीं चलेगा ओर वह फिर दूसरे अदायरों से कर्जा लेना भाुरू कर देगा और उससे वह कर्जई बन जायेगा और उसे भारी इन्ट्रस्ट देना पडेगा। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि इस ओर सरकार ध्यान दे और किसानो ंको ओर ज्यादा कर्जा दिया जाना चाहियें इस थोडी सा इमदाद से किसान का भला नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं अपनी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह कि जो कर्ज किसानों को दिये जाते है, वे मिनि बैक्स के द्वारा दिये जाते है और वहां पर अधिकारी जो है वे फर्जी इन्टरियां करके किसानों के नाम पर कर्जा चढा देते है। किसान तो बेचारा अनपढ है। इससे होता क्या है कि उसको मिलता कुछ नहीं है और दो–दो बार वैसे ही उसके नाम पर कर्जा चढा दिया जाता है। इससे उसके लिये बडी मुि कल खडी हो जाती है ाऔरवह कर्जा उतरे का नाम ही नहीं लेता (घंटी) इसलिये चेयरमैन साहब, मै ंअपनकी सरकार से कहूंगा कि जो कोआप्रे ान में फ्राड है,इसकी तरु सरकार अव य ध्यान दे और कोई ऐसा तरीका

निकाला जाये जिससे किसानों के साथ किसी किस्म काकोई खिलावाड न किया जा सके।

इससे आगे मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सराकर ने छोटी इकाई के लोगों कोनीचे सेउपर उठाने में काफी कदम उठाये है। चौकीदार और स्वीपर, जो दूसरे लोागों को गन्दगी से निकाल कर खु ाबू में लाता है,वगैरह की तनख्वाह एकदम 50 रूपये बढा दी है। इसके सरकार बधाई की पात्र है। (इस समय री उपाध्यक्ष पदासीन हुये।) इसक `साथ–2 उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने यहां पर बोलते हुये कहाकि सरकार ने जो धर्म ालाओं का या चौपालों का बनाने का इन्तजाम किया है, उसका बहुत बुरा असर होगा , मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हू। भाायद स्वामी जी को इसका ज्ञान कम हैं वे गृहस्थी नहीं है जो उनको इन सारी तकमलीफो का एहसास हो सके। अतः में अपनी सरकार से यह कहूंगा कि जो चीफ मिनिस्टर साहबन ने यह अनाउंस यिका है कि जो जो चौपालें अधूरी पडी हूई है उनको बनाने के लिये सरकार की तरफ से हरके को 5000–5000 हजार रूपये की मैंचिग ग्रान्ट दी जायेगी यह इन–सफीि ायेंट है, यह राि ा तो कुछ भी नहीं है। कई–2 जगहों पर चौपालें ऐसी जगहों पर बन रही है जहां के लोग मैंचिंग ग्रान्ट के लिये 5000 रूपये की राि ा इकट्ठी करके नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं हैं ऐसी चौपालों के लिय 5000–5000 रूपये की राि ा भी सरकार से मेंचिग ग्रान्ट के रूप में लेना बहुत मुि कल

है। इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसे इलाकों में सरकार को 5000 से भी ज्यादा रूपये की ग्रान्ट देनी चाहिये ताकि वहां पर चौालें पूरी की जा सके।

इसके बाद मैं डिमांड नं0 17 के बारे में कहना चाहता हूं। हम **(16.00 बजे)** सुविधा तो बहुत देने जा रहे है लेकिन प्रैक्टिकली एक आध बात गलत हो जाती है जिस आदमी का नुकसान हो गया उसको तीन चार सौ रूपये के हिसाब से मिल जायेगा लेकिन जो सीरी सांझी है उनको बडा किसान पूरा हिसाब नहीं देता और अगर पूरा हिसाब देता है तो पैसा समय पर नहीं देता। मेरी गुजारि ा है कि पटवारी या तहसीलजदार जो सुविधा दें, वह मौके पर दें ताकि सांझी को भी उससे पूरी सुविधा मिल `सके। मैं डिमांड नं15 के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कई माइनर्ज जो पक्के होने लग रहे है उनके अन्दर, सीमेंट और रेत की रे ाों ठीक नहीं लगती। हम जो खालें पक्की कर रहे है वेइसलिये कर रहे है ताकि हमारा पानी बढे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दियाजाये। धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 2, 15 ओर 17 पर बोलना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी ीाी एकबात के लिये किसी एक सरकार को बलेम नहीं दिया जा सकता क्योकि सरकारे आती है और चली जाती हे। सरदार तारा सिंह मेरे दोसत है यदि खाल पक्का करने

के लिये सीमेंट पूरा नही लगता उसमें इनका कसूर नहीं है बल्कि ठेकेदारों का कसूर है। मै। अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि हरियाणा सब का है, किसी अकेले का नहीं है जो लोग ट्रेजरी बैंन्चिज पर बैठ जाते है वे समझते हे कि हमारा राज है इसलिये वे अपोजी ान वालों को कुछ नहीं समझते लेकिन हमारा सब का यह हक है कि हम सब इन्तजाम को दखे। हम यहां पर जो 90 के 90 मेंबर बैठे है, हम सब किसानहै। किसान का मतलब यह नहीं होता कि जो हल चलाये वही किसान है। जो खेती पर गुजारा करता है वह भी किसान हे और जो मेरे जैसा वकील है वह भी किसान है। क्योकि एक वकील भी किसान पर ही निर्भर करता है। अगर किसान की खेती खराब हो जाती है तो उसका असर ूदसरे लोागों पर भी पडता है। नहर और खेती के महकमे बहूत जयर महकमे है । जो नाले पक्के हो रहे है उनमें सीमेंट पूरा नहीं लग रहा है। इसके लिये कन्सर्ड वजीरसाहब को चाहिये कि वे जाकर छापे मारे और कसूरवार अफसरों और ठेकेदारों केखिलाफ कार्यवाही करे। जैसे सन 1967 में जब मैं वजीर था, उस समय हमने किसानों की भलाई के बहुत काम किए थे। हमने अपने टाईम में 9महीनों मे ंसारा टिप–टाप कर दियाथा। उस समय अगर चण्डीगढ़ का मसला न उठता या हम इन्दिरा जी की सालसी मान लेते तो हमारी सरकार पूरे पांच साल चलनी थी। हमने फैसला किया कि इंन्दिरा जी की सालसी नहीं माननी।। अगर हम इन्दिरा जी की सालसी मान लेते तो उन लोगों का क्या होता जिन्होने रिवाडी में गोलियां खाई थी। में अब भी सरकार से कहूंगा कि

बडे–2 ठेकेदारों की जायदाद जब्त करके किसानों की खु ाहाल बना दो। सभी किसानों के खाल पक्के कर दो और और सारा खर्च सरकार बर्दा त करे। अगर पानी बढेगा तो आपका आबियाना ीाी बढेगा । सरकारे तो आती जाती रहती है इसलिये मै। कहता हूं कि किसानों की भलाई का यह काम कर दो। यहां पर हाहाकार मची हुई है कि किसानों का भला होना चाहिये। लेकिन चौधरी भाम ोर सिंह ने एक इन् योरेंस की पालिसी रख दी जो न तो हमारी समझ में आई और न ही स्पीकर साहब की समझ में आई मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक कमेटी बना दी जाये। वह फैसला करे कि किसानों को किस तरीके से कम्पनसेट करना है इस स्कीम को तहसील बेस न रख कर इन्डीविजुयल बेस बनाया जाये।

मैं यह भी चाहता हूं कि जिन बडे–2 कारखानेदारों से करोडो रूपये सेल्ज टैकस का सरकार ने लेना है उसे जल्दीकरवर किया जाये और किसानों की कुर्की बन्द की जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, राठी साहब मेरे भाई मै। इनको अपने हल्के मे ले गयाथा। मेरे हल्के में एक कसान ड्रेन है वह ड्रेन जब वीरेन्द्र सिंह जी मिनिस्टर होते थे, उन के समय में निकाली थी। जब मैंने राठी साहब को बताया कि यह ड्रेन इधर से निकलनी चाहिये थी तो इन्होने मेरी बात को मानते हुये अफसरों को हुक्म दिया कि इसे ऐसेनिकाला जाये। लेकिन इनके हुक्म केबावजूद भी वह उधर से नहीं निकाली गई। उसकानतीजा यह हुआकि वहां का सारा इलाका

डूब गया। मैं चाहताहूं कि इसमें जिन–2 अफसरों और ठेकेदारों का कसूर है उनसे नूक्सान का सारा पैसा वसूल किया जाये। एकमेरे हल्के में छात्र माजरी रजवाहा है, उसकी एक्सटैन्‍ ान मन्जूर हो चूकी है। मैं चाहता हूं कि उसके लिये पैसे का लन्तजाम किया जाये।

इसके बाद होम का महकमा भी बहुत जरूरी महकमा हैं मै चाहता हूं कि पुलिस को बढायाजाये। इसके बाद जो चौधरी भजन लाल जी ने कन्ज्यूमर स्टोर खोल दिये हे और सारी मा ि‍ल कौम उन दुकानों पर लगा दी है यह बात ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के लडको कोअफसर बनाया जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की स्ट्रैन्थ दोगनी होनी चाहिये। पुलिस में देहाती लडकोे की भर्ती होनी चाहिये। दुकानें तो गांवों मेंवैसे ही बहुत ज्यादा है। इसलिये मै मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर मा ि‍ल कौम के नौजवान भर्ती करने चाहिये। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सहाब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बात दलाल साहब ने कह है वह ठीक है किपुलिस में जो देहात के लडके है उनकी बहुयें तो गांवों में रहती है और लडकों की डियूटी भाहरों में होती है इसलिये उनके लिये फैमिली क्वार्टर बनाने चाहिये ताकि उनके साथ उनकी बहुयें भी रहे सके। मैं होम मिनिस्टर साहब से यह भी प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के नौजवानों को जहां पर डियुटी होती हैं वहां पर उनके लिये फैमिली क्र्वार अव य बनने चाहिये। इसके अलावा मैं

एक बात और कहना चाहता हूं। थानेदारों को कई बार मजबूर किया जाता है कि वे झूठी रिपोर्टस दर्ज करे क्योकि एस0पी0 मंथल मीटिंग में थानेदार से रिपोट्र मागंते है कि आपन्न कितने केसिज दर्ज किये। केस दर्ज करने के लिये थानेदारों को कोटा मुकर्रर किया हुआ है कि इतने केस जरूर दर्ज किये जाये। इसलिये थानेदार को कोटा पूरा करने के लिये झूठे केस दर्ज करने पडते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केस दर्ज करने के लिये कोटा मुकर्रर नहीं होना चाहिये। अगर थानेदार पर एस0पी0 का दबाव नम्बर पूरा करवाने के लिये पउेगा तो वह उसे पूरा करने के लिये झूठे केस दर्ज करेगा और खास करके एक्साईज के केसिज दर्ज करेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले तफती ा करने के लिये खामखाह लोगों की पिटाई करते है। केसों की तफवी ा साइक्लोजिकतल तरीके से की जाये। इसके लिये पुलिस वालों को रीफरै ार कोर्स करवाया जाये ताकि लोगों कोखामखाह पीटना न पडे। डिप्टी स्पीकर साहब, आज राज्य सभा के मैंबर का इलैक ान भी हो चुका हैं और इस वजारत का भी आखिरी टाईम आ गया है मेवल दो महीने की मियाद बाकी रह गई है। इसलिये इस सरकार ने जो सी0आई0डी0 पुलिस एम0एल0एज0 के पीछे लगा कर एम0एल0एज0 का हाजमा खराबकर दियाहै। उसे हटाकर कही दूसरी जगह लगाया जाये। हर वक्त सी0आई0डी0 का आदमी हमें अपने सिर पर खडा मिलता है। इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहताहूं कि आपके सी0आई0डी0 वाले बहुत होि ायार

है इसलिये उनको बंगला देश के बोर्डर पर नहीं भेजनाचाहते तो इस होस्टल का नाम हरियाणा एम0एल0एज0 होस्टल चण्डीगढ की बजाय सी0आई0डी0 पुलिस लाईन हरियाणा चण्डीगढ रख दिया जाए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरियाणा बने हुये 16 साल हो गये हैं और 16 साल से हमारा हाई कोर्ट इकट्ठा चला आ रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरियाणा काहाई कोर्ट अलग होना चाहिये। जब हमारी पंजाब से सारी चीजें अलग हो चुकी है तो हाई कोर्ट भी अलग होना चाहिये। इसके अलावा चण्डीगढ को भी हरियाणा में भाामिल किया जाना चाहिये क्योकि पंजाब वालें यहां पर अपने गेस्ट हाउस और दूसरे मकान वगैरह बना रहे ळै। मै। सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में हमारा हरियाणा भवन बना हुआ है उसी तरह से यहां चण्डीगढ में भी हरियाण भवन बनाया जाना चाहिये। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, कैथल सब–डिवीजिन में एडी ानल सै ान जज की कोर्ट होनी चाहिये। एक बार सी0एम0 साहब ने यह वायदा भी यिकाथा कि कैथल को जिला बनाया जायेगा लेकिन वह अभी तक नहीं बनाया गया है कि कैथल को जिला तो जब मैं सी0एम0 बनुंगा उस समय बना दूंगा लेकिन मुख्य मंत्री जी वहां पर एक एडी ानल सै ान जज की कोर्ट जरूर बना दें। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने कासमय दिया।

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): स्पीकर साहब, जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पे ा किया हे उसको देखते हुये आज उस पर हमारे सामने डिमांडज आई है। मैं इन डिमांडज का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। लेकिन साथ–2 कुछ ऐसी बाते है। जिनका जिक बजट स्पीच में भी नहीं आया और गवर्नर एड्रेस में भी नहीं आया। मैं उन बातों की तरफ सरकार का ध्यान इन डिमांडज पर बोलते हुये दिलाना चाहता हू। स्पीकर साहब जिन बातों का इस हाउस मेंआये हुये मुद्दत हो गई है और उन पर बार–बार चर्चा होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से , उन बातों के बारे में सरकार की क्या पालिसी है, वह क्लीयर नहीं हुढ। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर अपनी पालिसी बताये। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं मौरल एजुके ान के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। स्रकार टीचर्ज को सिटी अलाउन्स देती हैं स्पीकर साहब, जो टीचर्ज सिटीज के करीब 15 या 20 किलोमीटर के रेडियस के अन्दर रहते हे। उनको सरकार की तरु से एक फालतू अलाउन्स दिया जाता है लेकिन जोटीचर्ज रूरल एरियाज में रहते है उनको वह आलउन्स नहीं दिया जाता है। इससे क्या होताहै कि जो टीचर्ज पोलिटिकल इनफल्युन्स रखते है वे अपनी पोलिटिकल पुल्ल की वजह से सिटीज एरिया को हमे ाा के लिये काबू कर जाते है और 15 या 20 साल तक सिटी मे या उसके आसपास रहते है और रूरल एरिया में नही जाते है। इसलिये स्पीकर साहब, मै। आपके माध्यम से सरकार से इस बात की कलैरीफिके ान लेना चाहता हूं कि जो सिटी अलाउनस टीचर्ज

को दिया जाता है, वह रूरल एरियाज के टीचर्ज को क्यों नही दियाजाता? यदि यह अलाउंस सब टीचर्ज के लिये यकंसा कर दिया जाये तो सरकार को टीचर्ज की ट्रांस्फर्ज की जो परे ाानियां रहती है वह भी नहीं होगी और टीचर्ज भी परे ाान नहीं होगें। इसलिये मैं सरकार सेकहना चाहता हूं कि रूरल एरियाज के टीचर्ज को भी यह अलाउंस मिलना चाहियें। जो टीचर्ज सिटीज के पास लगे हुये है, वे रूरल एरियाज के टीचर्ज से अच्छे नहीं है। सब टीचर्ज बराबर है। इसके साथ–2 स्पीकर सहाब, हमारे दे ा की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत हरिजनों को प्लाटस देने की बात भी आती है। हरिजनों को प्लाटस देने के लिये इससदन के अंदन भी जिक हुआ है। स्पीकर सहब, 1975–76 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरिजनों को प्लाटस बांटे थे। उसके बाद किसी भी सरकार ने हरिजनों को पलाटस नहीं बांटे। आज उन बातों को लगभग 6–7 साल हो गये है उसके बाद हरिजनों को कोई भी रिहाय ी प्लाटस नहीं दिये गये हैं इसलिये स्पीकर सहाब, मैं सरकार से इस बात की क्लैरीफिके ान चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत यह सरकार हरिजनों को रिहाय ी प्लाटस कब तक दे देगी? इसके अलावा स्पीकर साहब,मैं मंत्रियों के बारे में एक बात कहनाचाहताहूं। यदि कोई एम0एल0ए0 मंत्रियों से मिलने के लिये चण्डीगढ़ में आता है तो उसको मंत्री जी नहीं मिलते है चाहे वह एम0एल0ए0 चार पांच दिन लगाता यहां पर आता रहे फिर भी कोई भी मंत्री चण्डीगढ में नहीं मिलता है। इस

बारे में मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चहता हूं कि वे हफले में रहेगी क्योकि लोग मंत्रियों के मिलने के बाद लोगों को यह तसल्ली तो होजाती है कि उनकी बात सरकार के कान तक पहुंच गई है।

इसके अलावा स्पीकर साहब , मैं इरीगे ान के बारे में कुछ बातें आपके सामनेरखना चाहता हूं। आप जानते है कि जवाहर लाल नेहरू कैनाल जब से खुदी है, उस समय से ही लोगों को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड रहा हैं मैं यह मानता हूं कि सरकार ने लोगों की बातें सुनकार जो उस नहर पर पुल बनाने के नामर्ज थे, वेकुछ कम कर दिये है। लेकिन अब भी जो नामर्ज है उनके मूताबिक यदि किसी जरूरी जगह पर पुल बनना है तोवह नहीं बन पाता है । सरकार के पास हमारी तरफ से कुछ सुजै ांज भी गई थी और इस बारे में मैने इरीगे ान मिनिस्टर साहब से बात भी की थी लेकिन इस बारे में आज तक कोइ जिक नहीं आया। स्पीकर साहब, अगर कोई 10 किलोमीटर लम्बी कैनाल है और उस पर यह सरकार 10 पुल मंजूर करती है तो हर किलोमीटर के बाद एक पुल बनाया जाता है। इस बारे में मै एकसुझाव देना चाहता हूं। कि एक किलोमीटर के बाद एक पुल बनाने की बजाये सरकार यह अलाउ कर दे कि 10 किलोमीटर लम्बी कैनाल पर जहां पुल की जरूरत है वहां पर पुल बनाया जाये। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक किलोमीटर के बाद एक पुल बनाया जाये। जहां भी पुल की जरूरत हो, वहीं पर बना

दिया जाये। इस वक्त जो पुल बन रहे है वे जैसी मैने सजै ान दी है उसी हिसाब से बनाये जाये ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। स्पीकर साहब, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इस बारे में आज कोई न कोई जवाब अव य दे। स्पीकर साहब, नहरे बनाने के लिये जमीन एक्वायर की गइ हैं सदन के अन्दर कई बार यह आ वासन दिया गयाहै। कि जिन किसानों की जमीन ली गई है। उनको पूरा मुआवजा दिया जायेगा। स्पीकर साहब, आज यहां पर कई जगह ऐसी है जहां पर किसानों को 5—5, 7—7 साल से पैसे नहीं मिले है और न ही उनका उनहें इन्ट्रैस्ट मिला है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि जो पैसा दिया जाये उसके साथ किसानों को इन्ट्रैस्ट भी दिया जाये। समय पर पैसा न मिलने की वजह से कई व्श्यक्ति मर चुके है। और यह पैसा लेने के लिये उन लोगो की बेटियों को इधर उधर जाना पडता हैं इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जब जमीन सरकार लेती है तोपैसा भी सरकार को उन किसानों के घरों में यानि उन गांवों में जा कर देना चाहिये जहां की जमीन जी गई है ताकि जो हमारी बहन बेटियां है उनको इस से परे ाान न होना पडे।

इसके अलावा मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और को—आप्रे ान की डिमांडज पर बोलना चाहता हू। सपीकर साहब, सदन में रिक्रूटमेंट की काफी चर्चा हुई है। हमारे जो नामर्ज फिक्स होते है, उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं हेा रही है। एक एक्ट है जिसका नाम मैं आपको पढ कर सुना देता हूं The employement

Exchanges Compulsory Notification of Vacanices Act, 1959.' यह सैन्टर्ल सरकार का एक्ट है। इसके तहत अगर वैकेंसीज भरनी है या रिक्रूटमेट करनी है तो जो बोर्ड का चेयरमैन है या किसी विभाग का हैड है या और कोई आफिसर है उसको एम्पलायमेंट एक्सचंज द्वारा दी जानें वाली सर्विसिज को कम्पलसरी नोटीफाई करना पडता हैं कि हमारे यहां पर इतनी वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज को अदर सौर्स से भरने के लिये एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज से ''नो औन्जैक ान सर्टिफिकेट'' भी लेना होता है । इस एक्ट के अन्दर यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी बोर्ड का अधिकारी गलत काम करता है तो उसको पहली दफा 500 रूपये जुर्माना किया जा सकता हैं और यदि दोबारा गलती करता है तो उस पर 1000 रूपया जुर्माना किया जासकता है। इस एक्ट को ध्यान में रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे कितने अफिसरों हद तक रिक्रूटमेंट ठीक हो सकती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति है कि लोगों को एम्पलाएमेंट दी जाये। यदि लोगों को एम्पलाएमेंट ठीक ढंग से दी जाये तो इस बात पर किसी को कोढ़ एतराज नहीं है। सदन के अन्दर मंत्री जी ने भी मान है कि रिक्रुटमेंट में गडबडी हुई है। यदि हम 2–4 अफसरों को इस प्रकार की सजा दे देगें तो काफी हद तक इस मामले को सुलझाया जासकता हैं स्पीकरसाहब, इसी प्रकार सेबिजली बोर्ड के अन्दर गडबडी हुई है। वहां पर जो पिछले चार सालों के अन्दर लेाअर डिवीजिन कलर्क्स भर्ती किये गये है उनकी संख्या 324 है। इन पोस्टों की सिर्फ एक बार एडवर्टाइजमेंट की गई थी। इन में से भी सिर्फ 28 ि ाडयुल्ड

कास्ट कैन्डीडेटस लिये गये है। मेरे कहने का मकसद इतना ही है कि यदि रिक्रुटमेंट में गडबडी करने वाले आफिसरों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये और उनको सजा दी जाये तो जो हमारा 19 करोड रूपये का घाटाहै वह भी काफी हद तक कम हो सकता है। इसके साथ–2 मै यह भी बताना चाहता हूं। कि 1968 से ले कर आज तक बिजली बोर्ड के अन्दर 6773 आदमी भर्ती किये गये है। इसके साथ–2 मेरी एक और रिकवैस्ट है कि जितने भी बडे–2 इंडस्ट्रियलिस्टस है उनसे बिजली के बिलों का पैसा पूरा लिया जाना चाहिये। जितनी बिजली वे कनज्यूम करते है, उसका खर्चा उनेस लेना चाहिये। उनसे साल में या 6 महीने में हर बार लेने की बजाये वीकली खर्चा लिया जाये। उनके पास बिजली बोर्ड की तरफ से 6–6 महने बाद बिजली के बिल जाते है। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में इंडस्ट्रियलिस्टस की तरफ 4,28,43,483 रूपया बिजली बोर्ड का बकाया हैं पिछले साल का 39 लाख है उससे पिछले साल का 53 लाख है और उससे पिदले सालों का 3 करोड 35 लाख रूपया बकाया है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इतना पैसा उनकी तरफ छोडना नहीं चाहिये। जितने भी बडे–2 इंडस्ट्रियलिस्टस है, उनको कोई छूट नहीं होनी चाहिये। यदिवह पैसा समय पर जमा न करवायें तो उनके कुनैक ान काट दिये जाने चाहिये। एक कम्पनी का एक सप्ताह में 10–15 लाख रूपये बिजली का खर्च आता है। इस संबंध में मेरी सुजै ान है कि आप उनसे वीकली पेमैट लेलें । यदि वे एक सपताह के बाद पैसे न दे तो उनका बिजली का कुनैक ान काट

दिया जाये। पिदले 10 सालों का न जाने कितना पैसा इसी तरह का बकाया होगा।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से कन्ज्यूमर स्टोर के अन्दर रिक्रूटमेंट की गई है। हमारी कांग्रेस आई सरकार की नीति है जो कन्जूमर्ज स्टोर खोले जायेगें वे देहातों कमे अन्दर यानि गांवों में खोले जायेगें। इस संबंध में मेरी सुजै ान है कि कन्जूमर्स स्टोर्ज के लिये जो भी भर्ती की जाये वह उसी जिले से की जाये जहां पर स्टोर खोला जाना हो। मान लो रोहतक के अनदर कोई स्टेार खोला जाना है तोवहां पर जो रिक्रेूटमेंट की जाये, वह उसी जिले के लोगों की होनी चाहिये। इसे साथ'–2 मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस गांव में स्टोर खोलना हो वहां पर स्टाफ जहां तक संभव हो सके, वहीं का लगाना चाहिये। इसक दो फायदे होगें एक तो यह कि उस गांवों के बुजुर्गों का उस पर दबाव होगा और दूसरे जो गांव के नीचे के तबकके के लेाग है उनको आव यकतानुसार चीजें मिल सकेगी। यदि बाहर के लोगों को वहां पर लगाया जाता है तो वे लोग पावर फुल हो जाते है और आना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकेतै। किसी एक आदमी को पावरफुल नहीं बनाना चाहिये। यदि एक आदमी को पावरफूल बना दिया जात है तो उससे वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरी राय है कि इस काम में एक आदमी को पावरफुल नहीं बनने देना चाहिये यह हमारी भारत सरकार की नीति है कि इस काम में कोई गडबडी नहीं होनी चाहिये। (घंटी)

मेरी सरकार से दोबार रिकवैस्ट हैं कि इस नीति को अच्छी तरह से लागू करे। मैं और अधिक न बोलते हूये आपका धन्यवाद करते हुये अपना स्थान लेता हूं।

राज्यपाल से संदे ा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैबर्ज, मुझे गवर्नर साहब की तरफ से एक चिट्ठी आई है। उसे मैं आपके सामने पढ देता हूं। इसमे लिखा हैः–

'Dear Mr. Speaker, I write to acknowledge with thanks the receipt of your Demiofficail letter No. HVS-LA/8568, dated 23rd March, 1982, forwarding a copy of the Motion of thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 22nd March, 1982. Please convey my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the Motion." (Thumping)

वि ोशाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना

Mr. Speaker: Gentlemen, the Privileges Committee had submitted a Report for being presented to the House. This was the Report on Swami Aditya Vesh's case. Today, the Chairman of the Privileges Committee has requested that the Report may be returned to him as some fresh matters have com to light and without them the Reort will be imcomplete.

In view of this, I do not see any reason as to why the Report should not be returned to the Committee.

Accordingly, I have ruled that the Report should be returned to the Committee as requested by the Chairman.

Dr. Mangal Sein: Sir, I want so submit something. (Interruptions).

Mr. Speaker: Let me read out other annoucement--------------- (Interruptions).

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खडे हुये)

डा0 मंगल सैन: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब,...........

श्री अध्यक्ष: मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, एक–2 बात का फैसला कर लेते है क्येाकिं इससे आगे कोई नौबत नहीं आयेगी । (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, एक विशय सदन में आया और आपने तथा सदन ने उसे प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उस कमेटी ने बडी डिटेल में सब चीजों को स्टडी किया है। यहां तक कि पुलिस के जरिये गवाह बुलाने पडे। वे आने को तैयार नहीं थे। प्रविलेज कमेटी ने उन्हें यही पर पैसे दिलवाये ताकि कहीं ऐसा न हो कि उनहें बाद में पैसे ही न मिले। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब, इसका रूलिंग से क्या सम्बन्ध है? (ाोर)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, एक बार इन्होने पहले भी टाईम लिया था। दोबार फिर टाईम लिया। उनके बार–2 समय लेने का मतलब क्या है? ये इनके डिलेंइगं टैक्टिक्स है। ये कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में पे ा नहीं होने देना चाहते। (ोर) हमें भाक है कि रिपोर्ट कहीं इनके मैंब्र के खिलाफ न हो। इनकी इस बात से हमारा यह भाक और पुख्ता होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को वापस नहीं भेजा जाना चाहिये। आज तक यह कभी नहीं हुआ कि रिपोर्ट आपको सबमिट हो गई हो, चेयरमैन ने उसे साईन कर दिया हो ओर उसे दुबारा कंसिड्रे ान के लिये वापिस भेजा गया हो।

श्री अध्यक्षः मेरा यह फर्ज है कि जो चीज मुझे प्रेजेंट की जाये, उसे मैं हाउस में पे ा करूं। चेयरमैन, प्रिविलेज कमेटी ने मुझे रिपेार्ट दी लेनिक दो दिन के बाद वे कहते है कि इसमें क्ुछ खामियां रह गइ है इसलिये इसे उनहें वापस कर दिया जाये। आप मुझे बतायें कि मैं किस बिना पर उसे रोक सकता हूं। जबकि जिस चेयरमैन ने उसे मुझे दिया है वही इन राइटिंग मेरे से उसे वापस करने के लिये रिक्वैस्ट कर रहा है?

डा0 मंगल सैनः क्या चेयरमेन इस बात के लिये बार–2 कहेगा? (ोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिये। मैं इस कमेटी का मैंबर हू। आठ मैंबर्ज

और चेयरमेन ने इत्तेफाक राय से पूरी छानबीन करके, एक एकफिकरा पढ रक, चार–पांच ड्राफट देख कर यह रिपोर्ट दी हैं जब इत्तेफाक राय से रिपोर्ट पे ा हुई हो तो अकेले चेयरमेन को कोढ पावर नहीं है कि वह इस तरह की चिट्ठी आपको लिखे। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है। (ाेर) उन्होनें मुझे कहा है कि मैं तो जिन्दा ही मर गयाहूं। मुझे जीने का हक नहीं हैं मैं हाउस मं बैठने के लायक नहीं रहा हूं। (ाेर) अगर स्पीकरसाहब, यह ीबात होनी है तो मैं और कुछ न कहते हुये हाउस से सिर्फ यही कहूंगा कि आज के बाद अपोजी ान का कोइ मैंबर किसी कमेटी का मैबर न बने। (ाेर) इस तरह से तो कमेटीज बिल्कूल बेसलैस हैं । लाखों–करोडो रूपया कमेटीज के उपर जाया किया जा रहा है। और किसी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आने नहीं दी जातीे। (ाेर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूरा भाशण दे दिया। स्पीकर साहब, प्रिविलेज मिटी को वह मैंटर रैफर हुआ था जिसमें चौधरी संत कंवर ने स्वामी आदित्य वे ा के खिलाफ ओर स्वामी आदित्य वेश ने चौधरी संत कंवर के खिलाफ ऐलीगे ान्ज लगाये थे । (विघन) क्या यह बात ठीक है कि स्वामी आदित्यवे ा के बारे में तो रिपोर्ट आ जाए लेकिन दूसरे मैंबर के खिलाफ रिपोर्ट न आये? (विघन)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच औफ प्रिविलेज बनता है। मुख्य मंत्री जी कह रहे है कि एक मैंबर के खिलाफ तो रिपोट्र आ गई लेकिन दूसरे मैंबर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं आई। यह ब्रीच ओफ प्रिविलेज है। इन्हें कैसे पता लगा कि रिपोर्ट उनके खिलाफ है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर लाल, मैने यह कहा है कि क्या यह बात ठीक है कि एक आदमी के बारे में तो रिपोर्ट आ जाये लेकिन दूसरे के बारे में न आये? (विघन)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं रूल पढ देता हूं। रूल 273 मे लिखा है:–

"The Report of the Committee of Privileges, with minutes of Dissent, if any, shall be presented to the Assembly by the Chairman or in his absence by any Member of the Committee."

आप रूल 274 भी देख लीजिये । इसमें लिखा है:–

"(1) After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration , whereupon the Speaker may put the question to the Assembly."

स्पीकर साहब, मैं आपके गौर करने के लिये तीन बातें कहूगा। पहली बात तो यह है कि यह रिपोर्ट हाउस मे अव य आनी चापयिहे क्येाकि हाउस इसके बाद बैठने वाला नहीं हैं हाउस प्रोरोग हेने के बाद यह रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। (विघन) हम यह समझते है कि इस रिपोर्ट कोखत्म करने के लिये यह साजि ा हो रही है। (ाोर)

दूसरी बात, स्पीकर सहब,यह हे कि प्रविलेज कमेटी जोबनी हुई है उसके चेयरमैन मालिक नहीं है।

Mr. Speaker: I do not understand, what do you mean by Malik? Chairman is Chairman.

चौधरी राम लाल वधवाः यह ठीक है कि चेयरमैन, चेयरमैन है, लेकिन जो प्रोसीडिग्जं प्रिविलज कमेटी की फाइनेलाइज हो चुकी है, जिस रिपोर्ट को प्रिविलेज कमेटी युनानिमसली या मैजोरिटी के साथ दे चुकी है चेयरमैने अपने अपाप कैसे वापस मांग सकता है?

श्री अध्यक्षः वधवा साहब, आपका तो प्वायंट आफ आर्डर था लेकिन आपने पूरा भाशण दे दिया ।

चौधरी राम लाल वधवाः सर, मैने जो तीन प्वाटंस रेज किये है मैं उन्ही के बारे में बोल रहा हूं। कमेटी जो प्रोसीडिंगज लिखती है, उसमें चेयरमैन को सईन करने के लिये इजाजत देती

हैं चेयरमने ने उस पर साईन कर दिये और रिपोर्ट आपके पास आ गई।

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): सर, मैं इस प्वायंट पर आपकी रूलिंग चाहुंगा कि स्पीकर साहब की रूलिंग आने के बाद क्या उसी मामला पर डिसक ान हो सकती है? (विधन)

Mr. Speaker: There can be no discussion on Speaker's ruling.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: मै कह चुका हूं कि जो रिपोर्ट आती है वह मुझे हाउस में रखनी पडती है लेकिन जब रिपोर्ट अन्डर एग्जामीने ान हो............ (ोर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: अन्डर–एग्जामीने ान से आपका क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष: अडंर एग्जामीने ान का मतलब यह होता है कि पहले सैक्रेटरी देखता है फिरे मेरे पास आती है। चेयरमैन ने यह रिपोर्ट 29 या 30 तारीख को पे ा करनी थी लेकिन उससे पहले ही चेयरमैन की ओर से लिखित रूप से रिक्वेस्ट आ गई कि वह रिपोर्ट वापिस की जाये। जब लिखित में रिक्वैस्ट आ जाये तोमुझे इन् ायोर करना पडता है कि जस्टिस की मिस कैरेज न हो

जाये। मैने इस बात को माना। मुझे इस बात का भी पता लगा कि स्वामी जी ने भी रिकवैस्ट की है कि मैं फरदर एवीडैन्स प्रोडयूस करना चाहता हूं। जब एक रिकवैस्ट चेयरमैन की तरफ से आ जाये कि फरदर एवीडैन्स आनी हे तो मेरा फर्ज है कि चेयरमैन की रिक्वैस्ट को एक्सपैक्ट कंरू। इसी आधार पर रिकवैस्ट मानी है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आने जो रूलिंग दी है उस पर कमेटी के इन आठ मैंबरों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि स्वामी जी की और से और एवीडेंस देने के लिये दरखास्त नहीं आयी। अब ये ज्यादा से ज्यादा इन्टैरिम रिपोर्ट की मांग कर सकते है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, अभी लीडर आफ दि हाउस ने कहा कि अभी दूसरा मामला पैंडिग था और उस पर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन दूसरा मामला तो आपके हुक्त के कारण स्टे था। वह हमारे पास हीयरिंग के लिये नहीं आया। वह फाइल डिप्टी स्पीकर साहब के पास चली गई। सारे हिन्दुस्तान के रूल्ज रैगुले ंज हम एग्जामिन करते रहे है।

Shri Kanahiya Lal Poswal: You cannot discuss this point now, (Interruptions).

चौधरी भजन लालः अभी यह रिपोर्ट दोबारा आपके पास आनी है।

चौधरी उदय सिंह दलालः इन्साफ का तकाजा है कि यह रिपोर्ट पे ा होनी चाहिये। आज तक 30–35 साल में किसी भी कमेटी ने ऐसा नहीं किया। (ाोर एवं व्यवधान) हमारे आनरेबल मैंबर चौधरी हरस्वरूप बूरा ने उनहें पूरा–2 मौका दिया हैं उनहोने उस रिपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। जितने अच्छे ढंग से उन्होनें स्टडी किया हे और कोई कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी रिपोर्ट दी हैं (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर सहब, मै ंआपके प्रार्थना करने के लिये खडा हुआ हू। कृपया आप अपनी रूलिंग को री–कंसिडर करे। मैने रूल्ज भी सरसरी तौर पर पढें है। जहां तक मेरा ज्ञान है आज तक कभी भी चेयरमैन देताहै तो उसे कमेटी अथोरिटी देती है कि इसे वह हाउस में पेश करे। जब यह रिपेार्ट कमेटी के कहने पर चेयरमैने ने दे दी तो इस रूल्ज की किताब में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि चेयरमेन को उस रिपोर्ट को वापिस लेने का अधिकार हो। स्वामी आदित्यवे ा ने जो लिख कर दिया है उसके बारे में चेयरमेन को अकेले ही फैसला लेने का अधिकार नहीं हे क्योकिं यह मामला कमेटी से ताल्लूक रखता हैं केवल कमेटी की डायरैक न पर चेयरमने आगे की कार्यवाही का सकता है। लेकिन मैं बहुत ही अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि स्पीकर को कोई अधिकार नहं हैं कि वह रिपोर्ट वापिस करे। कमेटी एक मिनी–हाउस है। यह एक मिनी–हाउस की ही रिपोर्ट है। हाउस ही इसे रिजैक्ट या स्वीकार कर सकता है। लेकिन स्पीकर को कोई

अख्तियार नही है कि वह चेयरमैन `साहब के कहने पर उसे वापिस करदे।

श्री अध्यक्षः बाबू मूलचन्द जेन जी ने दुरूस्त कहा है। रूल्ज मं कोई प्रोवीजन नही है कि चेयरमैन के कहने पर रिपोर्ट वापिस की जा सके और न ही रूल्ज मे यह प्रोवीजन है कि चेयरमैन को रिपोर्ट वापिस नहीं की जा सकती। इस मामले में रूल्ज साइलैंट है। When the rules are silent, the Speaker has to use his discretion and using the siscretion.............(interruptions) Please do not interrupt when I am speaking.

श्री मूल चन्द जैनः अगर रूल्ज साइलेन्ट है तो फिर प्रेसीडेंट देखना होगा। (ोर)

श्री अध्यक्षः आप मेरी बात सुनिये। मैं आपको रूल्ज को तोड कर टाईम दे रहा हू। अभी पोसवाल साहब ने प्वायंट आफ आर्डर उठाया था कि क्या स्पीकर की रूलिंग आने के बाद डिस्क ान हो सकती है? रूल्ज में है कि डिस्कशन नहीं हो सकती लेकिन फिर भी मैं रूल्ज को तोड करआप लोगों को आईम दे रहा हू। अभी बाबू जी ने कहा कि रूल्ज साइलैंट हैं अगर रूलज साइलैंट है तो उस पर भी स्पीकर की ही डिस्क्रि ान कामकरती है। दूसरा प्वांयट बाबू जी ने प्रैसीडेट का उठाया। डैमोक्रेटिक प्रोसीजर एवोलू ानरी प्रौसैस है। I think, from what little I have studied. the democratic process is an evolutionary process. It must change with the times.

चौधरी कंवल सिं जी ने पिछले दिनों एक प्वायंट रेज किया था कि क्या कमेटी माइनोरिटी में रिपोर्ट दे सकती है? लोक सभा की रूलिंग है कि कमेटी माइनोरिटी में रिपोर्ट नहीं दे सकती। माइनोरिटी की ओपीनियन रिपोर्ट में नहीं आती लेकिन प्रोसीडिंग्ज में आती है but I have discussed this matter with hundreds of people and I have given a ruling that the Committee is at liberty to give a minority report. Had I gone by the precedents, then I thin at times injustice could be done. आप सोचिये कि क्या कोई हमारे यहां ऐसा रूल है कि माइनोरिटी रिपेार्ट न दे? अगर कोई कमेटी युनानिमसली रिपोर्ट न दे ओर माइनोरिटी देना चाहे तो क्या मै ंउसे रोक सकता हूं? इसलिये हालात के मुताबिक प्रेसीडैन्ट बने हैं जिस समय वे प्रैसीडेंट बने उन हालात में ओर आज के हालात में फर्क होसकता है। इसलिये प्रैसीडेंट बेरी करते रहते है। टोटली पहले के हालात पर ही डिपैंड नहीं करना चाहिये। जब उन्होनं लिखकर दियाहै तो वे स्वामी जी ` और ाीा एवीडेंस लेसकते हैं मैने यह इसलिये किया ताकि कोई मिस–कैरिज आफ जस्टिस न हो जाये ओर इस बारे में कोई जल्दी भी नहीं है। अगर चेयरमेन री–कंसीडर करना चाहता है तो कर ले। कोई चेयरमैन सुओ–मोटी तो उस रिपोर्ट को चेंज नही कर सकता। He has to put if before the Committee again and if there is a question of its being put before the Committee for reconsideration, I am not in such a hurry कि मैं उसे ओवर रूल कंरू। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को फांसी के तख्ते

पर अभी चढाया जाना है और मैं 24 घंटे की मोहलत नहीं देसकता।

श्री कंवल सिहंः स्पीकरसाहब, आपको याद होगाकि इसी सदन के अन्दर दोनो ंसदसयों की तरफ से चार्जिज और काउन्टर चार्जिज लगाये गये थे। ....(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः मैं उस समय चेयर पर नहीं था। उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब थे। I have read about it. I have also listened to the tape recorder.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, उस वक्त स्वामी जी ने स्पैसिफिक चार्जिज लगाये थे। उन्होनें चौधरी संत कंवर पर चेयरमैन एग्रो–इंडस्टरीज रहने के दोरान धांधलेबाजी के स्पैसिफिक चार्जिज लगाये थे। (व्यवधान व भाोर)स्पीकर साहब, जब उन्होनें स्पैसिफिक डैलीबे ान्ज की। स्वामी आदित्यवे ा जी से यहां तक पूछा गया कि इसके अलावा आपका कोई चाज्र हो तो बतायें जिस पर उनहोने कहा नहीं,। जहां तक मेरी इततलाह है उनको बार–2 मौका दिया गया कि उन्होनें जो चार्ज लगाया है , उसको प्रूव करे।

श्री अध्यक्षः क्या आप कमेटी के मैबर हो? (ाोर व व्यवधान)

श्री कवंल सिंहः जी नहीं, लेकिन हमारेदूसरे साथी है जो इस कमेटी के मैंबर्ज है, वे हमें बताते रहते है। (व्यवधान एवं भाोर)

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): He is revealing the proceedings of the Committee. This is a breach of privilege itself. (Interruptions).

Mr. Speaker: Kanwal Singh Ji, you cna please see me in my Chamber; जहां तक रिपोट्ट की बात है जह मुझे चेयरमैन आफ दी कमेटी लिखकर देते है तो मै ंरिपोर्ट को वापिस कर सकता हू। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, इस तरह से तो कोई भी मेंबर महफूज नहीं रहेगा। अपोजी ान की बात को दबाने का आप अवसर क्यों दे रहे हो? इससे हरियाणा की जनता के दिमाग में भाक–सुबह पैदा होगा.... (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दे तो मे ंएक सुझाव देना चाहता हूं। एक वाया मीडिया बतानाचाहता हू। (व्यवधान एवं भाोर)

वि ोशाधिकार का प्र न वि ोश समिति की रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members on 16th instant after discussing the matter concerning the presentation for Shri Baldev Tayal Enquiry Committee Report with the leaders of the various parties, I had observed that as regards the notice of

notice of question of the breach of previlege, I would appoint a Special Committee to determine the source of leakage and fixing responsibility thereof. The next day, I also observed that I would allot time for discussion of the Baldev Tayal Committee Report on receipt of the Report of the Special Committee.

Accordingly, I appointed a Committee headed by Rao Ram Narain M.L.A. and consisting of Ch. ram Lal Wadhwa. Ch. Birender Singh, Ch. Preet Singh Rathee and Ch. Rajinder Singh, M.L.A's to enquire into the circumstances about the Report of One Man Baldev Tayal Enquriy Committee to the press and to fix responsibility for the same. This Committee has submitted its Report to me. According to this Report, the Committee has stated that it cannot help expressing its inability to pin point the source of leakage of the Report and fix responsibility of leakage on any one.

As the Committee has not been abloe to pin point the responsibility for the leakage of the Report on anyone, no prima facie case of breach of privilege is made out against Shri Baldev Tayal, M.L.A. Accordingly, I withhold my consent to the raising of the question of breach of privilege against, Shri Baldev Tayal , M.L.A.

I have received notices for the discussion of Baldev Tayal Committee Report from S/Shri Ajit Singh, Jagdish Kumar Beniwal and Ran Singh Mann, M.L.As. As also from Ch. ram al Wadhwa and Dr. Mangal Sein, M.L.As.

I have convened a meeting of the Business Advisory Committee on 30th March, 1982 at 11.30 A.M. to fix the time for its discussion.

वि ोशाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना (पुनरारम्भ)

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के मामले को लेकर हाउस में बहुत गर्मी पैदा हो रही हैं उस दिन भी बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट कोलेकर हाउस में काफी गर्मी पैदा हो गयी थी। उस दिन भी सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट में नही आने देना चाहती थी।

श्री अध्यक्ष: सरकार कैसे किसी रिपोर्ट को हाउस में आने से रोक सकती है?

श्री मूलचन्द जैन: उस वक्त तो रोका था। यह जो बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट थी, यह उस दिन इसलिये हाउस में पे ा नहीं हो सकी थी क्योकि सरकार उसको हाउस में आने नहीं देना चाहती थी।

गृह मंत्री (श्री कन्हेया लाल पोसवाल): उस समय तो लीकेज का सवाल था।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, फिर इनको गुड सैंस प्रिवेल की। फिर उन्होनें यह कहा कि चलो, अगल`दिन आ जायेगी वरना तो यह सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को भी हाउस

में नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में फिर इन्होने यह माना कि अच्छा आ जायेगी।

Mr. Speaker: I am sorry that the decision was mine. वह मान लियागया है या नहीं मान यिला गया है यह एक अलग बात है। परन्तु I had taken a decision.

श्री मूलचन्द जैन: उस दिन भी आने मेरे सुझाव को माना था। बजाये इसके कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट हाउस में न आये, मैं यह कहता हूं कि कमेटी की यह रिपोर्ट हाउस में आ जये और उस पर डिस्क ान के बाद सरकार मैजोरिटी के बल पर उसे पास न होने दे और रिजैक्ट करवा दे। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इन्साफ का तकाजा कुछ और ही हैं एक तरफ तो उसने इन्साफ किया था लेकिन वह बेचारा भी अपनी टिकट की वजह से मजबूर है। स्पीकर साहब, आप ही देख लीजिये कभी बेचारा बाहर जाता है कभी अन्दर आता है....................(व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: आपरेशन से पहले तो मैं आपसे भी और इससे भी जयादा जोर से बोल सकता था लेकिन आपरे ान के बाद मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूलचन्द जैन: मेरा सुझाव यह है कि बजाये इसके कि हाउस में बदमजगी पैदा की जाये, गलत ट्रेडी ान कायम किये जये और कोई गलत काम किया जाये, उस रिपोर्ट को हाउस मे

आने दें। आप कृपा करके ठंडे दिल से सोचे। चेयरमैन ने कमेटी की रिपोर्ट वापिस लेते वक्त क्या कोई मीटिंग बुलाई थी? स्पीकर साहब, मेरी इत्तलाह के मुताबिक नहीं बुलाई । मैं यह समझता हूं कि जिस उंची कुर्सी पर आप बैठे है , आप उसकी ट्रैडी ानज कायम रखेागें। चेयरमेन चौधरी हर स्वरूप बूरा अगर कमेटी की मीटिंग बुलाये बगैर आपसे इंडीवीजूअल तोर पर एज हर स्वरूप बूरा कोई रिक्वैस्ट करते है कि इस रिपोर्ट में कोई कसर रह गयी है ंइसलिये आप कृपा करके वापिस कर दें, ऐसी बात बिल्कुल अलाउ नही की जानी चाहिये। मैं निहायत अदब और नम्रता के साथ एक प्रार्थना करूंगाकि यह चेयरमैन को बिल्कूल भी अखितयार नहीं है। ऐसा करने से एक गलत ट्रेडी ान कायम हो जायेगी। बजाये इस किस्म के गलत रिवायात डालने के और गलत तरीके की बातें करने के , जिस तरह से बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आयी है , उसी तरह से यह रिपोर्ट भी हाउस में आ जाये फिर मैजोरिटी की बिनां पर सरकार उसको रिजैक्ट कर दे। (व्यवधान एव भाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः गवर्नमेंट का तो इसमे कोइ हाथ है ही नही।

श्री मूलचन्द जेनः जिस गलत तरीके से आप प्रिविलेज कमेटी के अन्दर दोबारा उस बात कोलाना चाहते हो, यह कौन नहीं जानता कि यह आपके गलत टैक्टिकैस है। मैं आपको गलती करने से बचाना चाहता हूं ताकि गवर्नमेंट गलती न करे। आप न

माने तो वह अलग बात है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि गलत तरीके अख्तियार करने की बजाये गवर्नमेंट को इस प्रिविलिज कमेटी की रिपेार्ट को हाउस के अन्दर आने देना चाहिये। डिस्क्स करके उसको अपनी मैजोरिटी की बिनापर रिजैक्ट करा दे।

Mr. Speaker: I have called a meeting of the Business Advisory Committee at 11.30 A.M. tomorrow, the 30th March, 1982 and I am always open to discuss this matter in this meeting but at present my ruling already given in the matter stands.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह मामला ऐसा हे जो बडा गम्भीर है। आप कृपया इस पर पुनः विचार कर ले। ऐसा कर लीजिये। अगर तो सारी प्रिविलेज कमेटी आपको आकर यह कह दे कि साहब हम अपना पूरा माईड एप्लाई नहीं कर सके। कहीं ऐसा न हो कि ना—इन्साफ हो जाये, इसलिये आप हमें कमेटी की रिपोर्ट वापिस दे दे, फिर तो ठीक है वरना आप इसे हाउस में आने दे। स्पीकरसाहब, आपने बिल्कुल बजा फरमायाहै कि डैमोकसी इवोल्यू नरी स्टैज पर हैं (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: When the Chairman of a Committee gives me in writing should I ask him कि आप सारी कमेटी को बुला कर लाओ। (interruptions)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट तो इस हाउस में आ चुकी है इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ....(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. I have already said that I have connened a meeting of the Business advisory Committee at 11.30 A.M. tommorrow, the 30th March, 1982 and I am always open to discuss this matter in this meeting. we can discuss this matter further in this meeting but at present my ruling given already in the matter stands. कमेटी के चेयरमैन की तरफ से एक रिक्वैस्ट आई और When the Chairman of the calibre of Shri Har Swarup Bura whom I think is a very able Chairman of the Committee, writes something, it might have some sound reasons (Interruptions)

डा0 मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैंबर्ज भी कम काबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा मैने कभी नहीं कहा कि मैंबर्ज काबिल नहीं है ंचौधरी उदय सिंह दलाल बहुत ही समझदार और काबिल मैंबर है।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, तायल कमेटी की रिपोर्ट के उपर आपने एक कमेटी बनाई थी जिसका लीकेज को ढूंढने का काम था। अच्छा होगा कि अगर उसकमेटी की रिपोर्ट हाउस में आ जाए। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I have never re-opened my ruling but I am always open for doing justice.

डा0 मंगल सैन: अध्यक्ष महेादय, वह हाउस की प्रोपर्टी है। उसमें बडी रिविलिंग बाते हैं.............(व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय , आपने जो कमेटी बनाई उसने क्या कियाऔर क्यो किया, ये सारी बातें हाउस के नोटिस मे ंआनी चाहिये। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I do not think it is necessary. That Committee was appointed with a specific prupose to examine the question of leakage and to fix responsibility for the same. We can discuss about this is the Business Advisory Committee.

चोधरी उदय सिंह दलालः अब सुमेर चन्द भट्ठ बतायें कि कहां से उनको कापी मिली? अगर वह नहीं बतात तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मो ान और बन जायेगी(व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः यह तो सब को पता है कि क्या हुआ...........(व्यवधान व भाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी कंवल सिंह की बात को मद्देनजर रख्ते हुये आपने एक रूलिग दी । मैं उस बारे में एक बात सबमिट करना चाहूंगा कि लोक सभ में स्पीकर की जो डारेक ांज है, उनमें डायरैक ान नम्बर 107 और 108 है। उनमे ंयह दिया हुआ है कि जब हाउस की कोई कमेटी किसी स्पै ाल मैटर को लेकर मीट करती है तो वहां पर बहुमत का व्यु और माइनोरिटी व्यू रिकार्ड तो हो जायेगा लेकिन जब हाउस में रिपोर्ट पे ा होगी तो मैजोरिटी डिसीजन जायेगा। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Rules are based on logic.

Shri Surender Singh: Exactly true. I do agree.

Mr. Speaker: So without any logic I will not allow.

श्री सुरेन्द्र सिंहः लौजिक यह है कि आज तक इस सदन में जितनी भी रिपोर्टस आई, चाहे किसी भी सरकार के वक्त में और किसी भी लैजिस्लेचर में आई हो, उसमें आबजरवेशन आती रही है। अगर किसी कमेटी के नौ मैंबर है तो यह तो हो नहीं सकता कि वे सब एक ही विचार के हों कुछ ही फैसले होते है जो सब के विचारों में एक साथ यानि यूनानिमसली होते हैं जो बहुमत का फैसला होता है वही हाउस की टेबल पर आता हैं लोकसभा के स्पीकर को डायरैक ान्ज ओर कौल एंड भाकधर जिसको आप साइट करते है। उस में दी हुई बात को मद्देनजर रखते हुये, मैं गुजारि ा करूंगा कि उस रूलिंग को आप रिंकसीडर करे।

श्री अध्यक्षः अभी श्री वधवा ने प्रिविलिज कमेटी के बारे में रूलिंग से कनेक्टिड बात पढी थी। That clearly provides that dissenting note should be recorded.

चौधरी राम लाल वधवाः रूल 273 में है कि मिनटस आफ डिसैंन्ट साथ आयेगा। (ोर एवं व्यवधान)

Shri Surender Singh: I have read all the directions of the Lok Sabha and they are easily available.

Mr. Speaker: Any way, this not the point at issue at all. I mentioned it by the way.

Shri Kanwal Signh: Sir, it would be recorded in the minutes of the Committee but it would bot be a part of the report.

Mr. Speaker: Please taek your seat. let us resime discussion on Demands for Grants.

वर्श 1982–83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

कृशि मंत्री (श्री भाम ोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो डिमांड नं0 17 है, इस पर चौधरी राम लाल वधवा ने कट मो ान दी थी। This cut motin was on the slow pace of developement of Agriculture in the State. अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं संक्षेप से हाउस को बताना चाहताहूं कि कृशि के क्षेत्र में हरियाणा में बहुत ट्रिमनूडस प्रोग्रैस हुई हैं और जो बढोतरी हुई वह इ तरह से है: धान की पैदावार हरियाणा में छः गुणी बढी है। स्पीकरसाहब, आज से चौदह साल पहले जब हरियाणा बना था उस के मूकाबले में आज गेहू की पैदावार तीन गुनी बढी है। कपास की पैदावार दुगने से जयादा बढी है। स्पीकर साहब, 1982–'83 के लिये सरकार ने कृशि की पैदावार का जो लक्ष्य निर्धारित कियाय है वह 71 लाख टन का किया है जोकि आल टाईम रिकार्ड है। इसके साथ ही साथ छठी पांच सालायोजना के खात्में पर एक करोड टन कृशि पैदावार होने का हमारा नि ाना है। हम समझते है कि हरियाणा इस लक्ष्य को अजीच कर सकेगा। स्पीकर साहब, कृशि की पैदावार को बढाने के

लिये खेती बाडी के महकमे ने और सकरार ने जो साधन जुटाये है उनमें एग्रीक्कल्चर इनपुटस की सप्लाई काएक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं संक्षेप मे ंसदन को बताना चाहता हूं कि 1966–67 में 2 हजारा 902 क्विंटल धान का बीज किसानों को सप्लाई किया गया था और 1982–83 में पच्चसी हजार क्विंटल धान का बीज किसानों को बेचने कालक्ष्य है। इसी प्रकार` जहां गेहूं के क्षेत्र में 1966–67 में 35851 क्विंटल बीज किसानों की सप्लाई किया गया था वहां 1982–83 में 1 लाख 25 हजारा बढिया गेहूं काबीज बेचने कालक्ष्य रखा गयाहै। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, 1966–67 में 13 हजार टन खाद की खपत थी जो आज बढकर 35 हजार तीन सौ टन हो गई है।। 1966–67 में 19 लाख हैक्टेयर भूमि एग्रीकल्चर के नीचे कवर करते थे और आज 51 लाख हैक्टैयर भूमि कवर कर पाये है। इसी तरह से 1982–83 में सायल कंजरवे ान में 171 लाख रूपये की खाद इस्तेमाल की करने का लक्ष्य है। स्पीकर साहब,मेरे दो साथियों चौधरी बीरेन्द्र सिंह और चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने कुछ सुझाव सरकार को दिये। एक सुझाव यह दियागया कि मार्किटिंग बोर्ड के जो सरप्लस फण्डज है, उनको क्रोप इं ाारेंस स्कीम हिसार?, रोहतक, जीन्द में 1981 की खरीफ के समय लागू की गई थी और रबी 1982 में चने के लिये क्रोप इं ाोरेंस स्कीम हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और जींद में लागू की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव इनका यह था कि जो मार्किट बोर्ड का सरप्लस फण्ड है, उसको फसल बीमा योजना के लिये इस्तेमाल किया जाये। अध्यक्ष महोदय,

पहले भी यह बात एक बार हाउस के सामने आई थी, और तीन–चार साल पहले इस इ ू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया थां सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया कि मार्किट कमेटियां बोर्ड काकोई भी रूपया मार्किट यार्ड के बाहर सरकार या मार्किट बोर्ड खर्च नही ंकर सकती। इस फैसले के बाद सरकार के हाथ बिल्कूल बन्ध चुके थे कि यह फण्डज बीमा योजना या किसी और योजना के लिये जिसका डायरैक्ट इससे ताल्लूक न हो, खर्च नहीं किये जा सकते थे। लेकिन फिर भी आज की मोजूदा सरकार ने एक साल पहले एक कमेटी बनायी थी। उसक कमेटी ने बडी छानबनी की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के दायरे में रहते हुये, इस रूपये कोखर्च किया जाये? किसान और व्यापारी के भले में ही यह रूपया खर्च किया जाना चाहिये और जजमेंट की भी कोई वायले ान न हो। इस बात पर विचार इसलिये किया गया ताकि इस के लिये कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों की वायेले ान ने करते हुये, सरकार ने उस पैसे से एप्रोच रोडज, सवीरेज टायलेट इत्यादि ओर भी कई बहुत सारे काम किसानों के भले के लिये मार्किट कमेटियों में मार्किट बोर्ड द्वारा खर्च किये जा रहे है। इसके साथ ही पोहलू साहब ने यह भी कह दिया कि आज जो क्रपस बीमा योजना है वह बेकार है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं आपको यादा होगा लास्ट ईयर जब बजट सै ान था

उस वक्त भी मार्किटिंग बोर्ड के एक्ट को अमैंड करने की बात सदन मे ंचली थी। सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा यह आ वासन इस हाउस मे दिया गया था कि ऐक्ट में ऐसी तरमीम की जायेगी जिससे कि किसानों का भला हो सके। लेकिन इस ंऐक्ट में आज तक कोई तरमीम नहीं हुई है।

श्री भाम ारे सिंहः स्पीकर साहब, जो आ वासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, उसके बारे मे ंएक कमेटी पांच–छः सदस्यों की बनाई गई थी और वह कमेटी उस दायरे कमे अन्दर–2 रहते हुये ....(ोर एवं व्यवधान)

Chaudhri Birinder Singh: Sir, this is not the thing. Still they can spend in between that.

Mr. Speaker: How can they spend on approach road?

श्री भाम ोर सिहः अध्यक्ष महेादय, जो आ वासन मुख्य मंत्री महोदय न यहां पर दिया था, उस आ वासन को पूरा करने के लिये एक कमेटी, जिसमें पांच–छः मंत्रीगण भी भामिल थे, बनाई गई थी और उसमें एल0आर0 साहब को भी बुलाकर पूरी तरह से डिस्क्स किया गया था। उस कमेटी ने आठ–नौ महीने तक पूरी डैलीब्रे ांज करके, इस पर विस्तार पूर्वक विचारविम र्ा किया गयाकि आया मौजूदा एक्ट में तरमीम करके हम उस रूपये को दूसरे जो एग्रीकल्चर के परपज है उन पर खर्च कर सकते है? कानूनी और हर तरह से यह रय थी कि इस एक्ट में तरमीम करके

सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट ळै अगर उसकी वायले ान करेगें तो। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रीगल आउट कर जायेगें।

श्री मूलचन्द जेनः स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री महोदय के आ वासन देने के बाद जो इस किस्म की कमेटी बनाई गयी थी, उसमें इन्होनें अपोजी ान को बिल्कुल भी वि वास में नही लिया। इनहोने क्या किया? नये परचेंजिग सैन्टर डिक्लेयर कर दिये। लेकिन जो असल बात है वह यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो आ वासन इस हाउस में दिया था, वह अब तक पूरा नहीं किया गया है। हम यह जानना चाहते है कि फिर इस कमेटी को बनाने का क्या रिजल्ट सामने आया है?

Chaudhri Birinder Singh: They have not settled it, Sir. They have not changed the preamble of the Act. (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, हमने यह कहा था कि हम इसका रास्ता निकालेगें। ऐसा तो कोई आ वासन मुख्य मंत्री महोदय न नहीं दिया था कि अपोजी ान के मैंबरों को भी इस मेटी के अन्दर नौमीनेट किया जायेगा। इस तरह से जिस तरीके से दूसरी कमेटियां फंक ान करती है, उसी तरह से इस कमेटी ने भी फन्क ान किया है। मेरा बाबू मूलचन्द जैन जी से और चौधरी बीरेन्द्र सिह जी से निवेदन है कि वे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है केवल 50 पेज होगें, उसको भाायद उन्होने पढा नही। अगर वे उस जजमेंट को पढ लेगें तो यह बातें मानेंगे ंकि

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने का जो नैकसस है वह यह है कि जिस किसी से कोई फीस कुलेक्ट करें उसी के उपर आप को वह फीस का रूपया खर्च करना पडेगा जो मार्किट फीस 2 परसैंट या तीन परसैंट व्यापारियों से लेते है ते वह पैसा मार्किट कमेटियों के यार्ड के अन्दर–2 ही खर्च होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

अध्यक्ष महेादय, इन सारी बातों को पूरी तरह से एग्जामिन किया गया था। मैं जैन साहब के बारे में बताना चाहता हूं, अभी–2 मुझे मेरे विभाग की तरफ से लिखकर दिया गया है कि जैन साहब इस मीटिग में बुलाये गये थे। डिपार्टमेंट के सचिव ने मुझे यह लिख कर दिया है। मूलचन्द जैन जीयाद कर ले, अगर यह बात रिकार्ड के मुताबिक गलत होगी तो मैं अपने भाब्द वापिस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन जैसा बताया गया है, उसके अनुसार वे मीटिंग में बुलाये गये थे।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, बुलाया होगा, मैं भाामिल हुआ था या नही, यह मुझे याद नही है और न ही मुझे इसकी इतलाह मिली है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इस कमेटी की मीटिंग में हमने सभी पहलुओं को बउी सूझ–बूझ के साथ एग्जामिन किा हैं हम आखिर में इस नतीजे पर पहूंचे है कि हम इस मार्किट फीस से इक्टठे किये हुये रूपये को मार्किट कमेटियों के यार्ड के

लिये ही खर्च कर सकते हे और कहीं पर वह इक्ट्ठा किया हुआ रूपया खर्च नहीं कर सकते।

इसके आगे आज पोहलू साहब ने जो बीमा योजना की बात कही है, उसके बारे मे कूछ कहना चहता हूं पोहलू साहब ने यह कहा कि व्यक्तिगत रूप में बीमा योजना भ्ाुरू की जानी चाहिये और उसके हिसाब से जिस–2 किसान काजितना–2 खराबा हुआ है, उसको उसी के हिसाब से मुआवजा देना चाहिये क्योंकि कईयों का जयादा नुकसान हो जाता है `ओर कईयों का कम होता है। इसलिये मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि जी0आई0सी0 तहसील बेसड योजना पर राजी हुई है न कि व्यक्तिगत बेसड योजना पर। इसके आबवी असली कई कारण है। एक कार का या किसी एक फैक्टरी का बीमा इंडीविजुअल तौर पर करवाया जाता हैं और अगरकल को कार का एक्सीडेंट हो जायेक, चाहे माईनर एक्सीडेंट ही हुआ हो, लेकिन कलेकम उन लोगों को ज्यादा भी मिल जाता है। इसी तरह से अगर किसी फैक्टरी को खुद भी आग लगाकर नुकसान कर लियाजाये तो उसके बाद पूरा क्लेम भी कर लिया जाता है क्योकि इस तरह के नुकसान को सामने देख लिया जाता है कि यह–यह नुकसान हुआ है। लेकिन फसल के मामले में जो बीमा की बात है इस बारे में जी0आई0सी0 वालों का कहना हे कि चाहे वे खुद ही अपने प ाुओ को, डंगरो को खेतो मे भेजकर अपना नुकसान करवा ले, इस बात की सुपरवीजन नहीं हो सकेगी। इसलिये इन बातें कोदेखते हये जी0आई0सी0 इंडीविजुअल लैवल पर बीमा

योजना की स्कीम के बारे में नही मानी और तहसील बेसड योजना के लिये राजी हुई है लेकिन हम बार–2 उनको इस बात के लिये प्रैस करते है कि उस के स्कोप को वे वाइडन करे।

इससे आगे स्पीकरसाहब, यह बताना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों से यह हाउस चल रहा है मैं वधवा साहब के कट मो ान के बारे मे कहना चाहता हूं । एग्रीकल्चर विभाग के दो सवाल हमारेसामने यहां पर आये थे। एक का जवाब डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय ने मेरी गैर–हाजिरी में दे दिय था लेकिन फिर भी अपोजीशन वालों ने एग्रीकल्चर विभाग के बारे मे कोई ऐसा मो ान या पवायंट रेज नही यिका जोकि आबजैक ानेबल हो। इससे साफ जाहिर है कि अपोजी ान के मैंबर साहेबान एग्रीकल्चर विभाग की सारी की सारी कारगुजारी से बडी अच्छी तरह से सन्तुश्ट है, इसलिये मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इन डिमांडज को पास किया जाये।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, क्या मैं आपकी इजाजत से मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछ सकता हूं?

श्री अध्यक्षः हां पूछ सकते हो?

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जी0आई0सी0 क्राप इं ाोरेन्स के बारे में बडी रिलेकटेंट हें चूंकि स्पीकर साहब, यह सारे दे ा का मामला है ाऔर सैन्टर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इस से सम्बन्धित है इसलिये मैं आपके

द्वारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदउय से यह कहुंगा कि इस मसले को हल करने के लिये कया वे भारत सरकार को हाई लैवल पर कोई समिति गठन करने का सुझाव देगें? इस बारे में क्या हमारे में मंत्री महोदय बातचीत करेगें ताकि इस मासले का हल किया जा सके। क्या इस बारे में कोई मीटिंग भारत सरकार के साथ करेगें कि सारी क्रपस को इस स्कीम के तहत लिया जाये?

श्री भाम ोर सिहं: स्पीकर सहब, इस बात पर मैने भी सारी बात यूनियन एग्रीक्लचर मिनिस्टर महोदय के नोटिस मे ंलाई है और उन्होने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि और ज्यादा कापस को इस स्कीम के तहत भाामिल करने की कोि ा ा करेगें बाद में जौ का एरिया जो था, वह इनक्लूड किया गया । उससे पहले जी0आई0सी0 जो के लिये मान नहीं रही थी। उसके बाद हमारे अफसर जी0आई0सी0 हैड आफिस बम्बई गये। हम बडे सीरियसली इस बात के पीछे है।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, यह हाउस काफी दिनों सेचल रहा है। और कोआप्रे ान का मसला कई बार यहां पहले भी पैदा हुआ। मैं हाउस में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी इंडीविजुअल केबारे मे हो। स्पीकर साहब, कोआप्रे ान महकमें ने जितना काम चौधरी भजन लाल की सरकार आने के बाद यिकाहै उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज सारे दे ा में हरयिाणा का नाम हैं पहले जहां माहराश्ट्र, गुजरात और दूसरे प्रान्तों में कोआप्रे न मूवमेंट देखने के लिये दूसरे

प्रान्तों के लोग जाया करते थे लेकिन आज महाराश्ट्र, गुजरात ओर तमिलनाडु तक से हरियाणा प्रान्त में यह मूवमेंट देखने के लिये आत`है। भजन लाल सरकार ने आने के बादत यह देखा है कि इस कहकमे का, गरीब किसान जो देहात में रहते है, उनसे ताल्लूक है। जैसे आपको मालूम है, इस महकमे में पहले काफी कप ान थी। ये सरी बातें आपके कानों में आई होगी। हमारे मेंबर साहेबान ने काफी जोर– ोर से इस डिपार्टमेंट के बारे में बताने की कोि ा ा की लेकिन वे एक भी लफज डिपार्टमेंट की फंक ानिंग के बारे में नही बतासके।(विघन) आप सारे हाउस की प्रोसीडिगज उठा कर देख लीजिये। एक भी लफज इन्होने डिपाटैमेंट की फंक ानिंग के बारे में नहीं बताया कि कोअप्रे ान महकमे ने कही कोताही की है।

श्री मूलचन्द जैनः दस हजार लोग गिरफतार किये गये इससे ज्यादा कोआप्रे ान डिपार्टमेट की क्या निन्दा हो सकती है? (ोर)

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले कह कर चलाह ू कि मैं किसी भाई पर कोई आक्षेपं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फंक ानिग के बारे में बताउंगा। पहले मैं केडिट सिस्टम के बारे में बताता हूं। गरीब किसानो को भाोर्ट, टर्म, मीडियम टर्म ओर लोंग टर्म के लोन दिये जाते हैं हाउस में बार–2 यह बातें आई कि सैकेटीज ओर आफिस बियरर्ज कजा्र ले लेते है ओर लोनीज की नहीं देते। हमने इस सारे सिस्टम को चेंज किया ओर इतना

आसान बनाया है कि एक आदमी का पैसा जमा करवाने के वक्त तो तमलीफ हो सकती है लेकिन लोन लेने के लिये देर नहीं होतीं यह सिस्टम सारे हिन्दुस्तान में केवल हरियाणा में ही है। दूसरी बात यह है कि पहले जहां हजारों केसिज एम्बैजलमेंट के होते थे ओर बैंकों सेपैसा लेकर लोगों को नहीं दियार जाता था, वहां आज ऐसा एक भी इंस्टांस अगर कोइ मेंबर बता दे तो मै मान जाउंगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर सह,ब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ठाकुर साहब ने यह जो कहा है कि बैंको से कर्ज बिना देरी के मिलता है। मैं यह बताना चाहताहूं कि आप किसी भी जिले की दस फाइलें मंगा ले। चाहे वह किसी भी बैंक की हो। आपको कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने बगैर पैसे दिये कर्जा लिया हो। आप उनको एग्जामिन कर लो अगर एक भी आदमी कह दे कि बिना पैसा दिये कर्जा मिला है। (ाोर)

चोधरी राम लाल वधवाः ....
....
....
....

Mr. Speaker: this is not point of order. It is a matter of detail. I will not be recorded.

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, यह बात तो क्रेडिट के बारे में थी। दूसरा सवाल यह है कि जेसेवधवा साहब ओर दलाल

साहब ने लैंड डिवेल्पमेंट की बात उठायी। मैं यह मान कर चलता हूं कि जो आदमी असलियत को नहीं समझता वह किसी किस्म कारिफार्म नही कर सकता। जब हम अपनी आंखों से एक बात को देखते है तो उसके बाद निर्णय भी ले सकते है। डाक्टर अगर बीमारी को डायागनोज नहीं करेगा तो दवाई किस बात की देगा? लैंड डिवैल्पमेट बैंक में जो कर्जे दिये जाते थे, वे चाहे डीजल पम्प के लिये हो या मोटरों के लिये हो, उनका बडा दुयपयोग होता था। किसान के साथ बडी लूट होती थी क्योकि लैंड डिवैल्पमेट बैंक सीधे किसानों को पैसा नही`दता था बल्कि डीलर्ज को देता था। डीलर्ज पुरानी चीजें किसानों के जिम्मे थोप देते थे। मैने एक –एक केस को एग्जामिन करवाया है। यह जो डीजर्ल वाला सिस्टम था,उसको हमने टोटली स्टाप कर दिया हैं हमने सोचा कि भायद ये डीलर्ज हमारी इस स्कीम को कामयाब होने में रोड़ा अटकायेंगें लेकिन बावजूद सब बातों के हमने वह प्रैक्टिस खत्म कर दी। हमने अब यह किया है कि जैसे हमारे एग्रो–सैन्टर्ज है, वे डायरैक्ट मैनुफैक्चरर्ज से माल लेकर आयेगें और अपना खर्चा और बयाज वगैरा लगा कर रीजनेबल रिटेल प्राइस पर बेच कर सारा मुनाफा जो पहले डीलर्ज खाते थे वह किसान को देगें जो स्टैंड्डर्ड के मैनुफैक्चरर्ज है, हमने सिर्फ उन्ही के नाम दिये है उनके अलावा किसी से भी म ीनरी नहीं ली जा सकेगी। हमने आई0एस0.आई0 मार्क वाली बात भी खत्म कर दी है। क्योकि उसमें भी गडबड हो सकती है। हमने यह रूल बनाया है कि जो भी कर्जा लेगा मोटर या पम्प के लिये वह उन्ही सैन्टर्ज में फिॅट

करवायेगा। उसकी एक साल तक फ्री सर्विस भी देगें। एक साल के अन्दर–2 अगर किसान के पम्प या मोटर में कोई गडबड पाई जाती है। तो उसके लिये हम जिम्मेदा होगें। इसके अलावा हमने यह भी फैसला किया है कि हम एक ुसल के बाद कर्ज की वसूली करेगें। स्पीकर साहब, जिस वक्त किसानलकर्जा लेने के लिये बैंक मे जाता है तो उस समय किसान को पटवारी से जमाबन्दी, ,खसरा, गिरदावरी की फर्द वगैरह लेनी पडती है। हमने इस बात को महसूस कियाऔर इसके लिये हमने पिछले महीने कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला कर दिा कि जो कर्जा लेने वालाकिसान है, उसे कर्जा लेने के लिये बैंक मैनेजर को एक सिम्पल कागज पर एप्लीके ान लिख्‍ा कर देनी होगी ओर उस किसान का रैवेन्यू रिकार्ड खुद मैनेजर पटवारी से ले लेगा।

श्री जय नारायण वर्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, हाउस मे डिमांड नम्बर 22 पर डिस्क ान हुई है। डिस्क ान के दौरान मैंबर्ज ने कोआप्रे ान महकमे के बारे मे ंकुछ प्वांयटस रेज किये है ओर कुछ सुजै ाजन दी है। उनके बारे मे मंत्री जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है और न ही किसी मैंबर के पवायंट को रैफर किया है। मंत्री जी वैसे ही बात टाल रहे है।

Mr. Speaker: This is no point of order. Please sit down. The Hon.Minister is at full liberty to explain the improvement s in the system of working that he has initiated in the Department.

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं साथ–2 जवाब दे रहा हू। स्पीकर साहब ये मेरे अपोजी ान के भाई किसानो ंऔर मजदूरों के हितैशी बनते है। मैं किसानों की भलाई की बात कर रहा हूं फिर भी ये सुनने के लिये तैयार नही ंहै। स्पीकरसहब, हमने पिछले महीने ही रूल्ज बनाये है कि जब एक किसान बैंक से कर्जा लेने के लिये एक सिम्पल कागज पर एप्लीके ान मैनेजर को दे दे तो मैनेजर की यह डियूटी होगी कि वह खुद उस किसान की फर्द रैवेन्यू आफिसर से हासिल करेगा। फर्द के लिय `जो सरकारी फीस होगी वही वसूल की जायेगी और जयादा पैसा वसूल नहीं किया जायेगा। इसके अलावा स्पीकरसाहब, दलाल साहब ने कहा कि आप फाईल मंगवा कर देख ले ं कि किसी भी बैंके ने किसान को बिना पैसे लिये कर्जा नहीं दिया। स्पीकर साहब, मैं दलाल साहब की बात से सहमत हू। इस करप ान को दूर कनरे के लिये हमने काफी स्टैप उठाये है। जिनमें से एक सटैप यह उठाया है कि लैंड डिवैलपमेंट बैंक को किसानों के कर्ज के केसिज डिस्पोज आफ करने के लिये हमने एक महीने की मियाद दी है। स्पीकर साहब मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब से हमने बैंको को यह हिदायत दी है उस समय से 85 परसैंट केसिज की डिस्पोजल विद इन ए मंथ होती है ओर 80 परसैटं केसिज की डिस्बर्समेंट करदी जाती है। कहने कामतलब यह है कि किसानों द्वारा मांगे गये कर्ज की 80 परसैंट एप्लीके ान्ज पर पेमैंट विद इन ए मन्थ कर दी जाती है। स्पीकर सहब, मैं भी समझता हूं कि जहां डिले होती है वहां

करप् ान होती हैं इस तरह की करप् ान को दूर करने के लिये मैं हर महीने बैकों से फिगर्ज लेता हू। केसिज को डिस्पोज आफ करने के लिये हमन बैंक मैनजर्ज की डियूटी लगाई हुई है। यदि मैनेजर केस को डिस्पोज आफ करने मे एक महीने से ज्यादा समय लगाता है तो उसकी एक्सप्लेने ान काल कर ली जाती हैं कि यह डिले क्यो हुई है? उसके खिलाफ एक् ान भी लिया जाता है।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकरसहब, मंत्री जी ने कहा कि बैंक मैनेजर किसान की जमाबन्दी रैवेन्यू पटवारी से खूद लेगा। यह बात इनहोने कब से लागू की है?

ठाकुर बीर सिंहः बाबू जी यह सिस्टम तो हमने पिदली जनवरी से भाुरू किया हैं

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकरसाहब, मंत्री जी ने बताया कि गेहूं निकालने के लिये हम थ्रै ार हैफड से खरीदते हैं यदि कोई जमीदार उसी कम्पनी का थ्रै ार 1200 रूपये में किसी ओर जगह से ले लेता है और हैफड से वह थ्रै ार 1100 रूपये मे मिलता है फिर तो हम समझेगें कि सरकार ने बिचोलिया खत्म कर दिया है। लेकिन हैफड वही थ्रे ार अबोहर ओर फाजिल्का से एक हजाररूपये में खरीदकर किसानों को 1400 रूपये मे दे तो यह तो ठीक बात नहीं है। आप इसचीज की इन्कवायरी कर लैं।

ठाकूर बीर सिंहः स्पीकर साहब, कोआप्रे ान विभाग मे ंजितने काम मैने कि है यदिउन सारे कामों को मैं यहां हाउस मे

ंएक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाईम लगेगा। इसके अलावा, स्पीकर साहब, भूगर मिलो के बारे में यहां हाउस कें बार–2 जिक आता रहा है आपने भी देखा होगा, जब से यह सरकार बनी है चाहे यह जनता पार्टी की भी सरकार रही है बार–2 इस बात का जिक आया है कि है भूगर मिलों की तरफ से किसानानें को पूरा पैसा नहीं मिलता है और पैसे की रैगूलर पेमैंन्ट नहीं होती हैं स्पीकरसहब, मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहताहूं कि हरियाणा की चारो भूगर मिलें किसानों को कै ा पेमैंन्ट होते है। । जिस समय किसान अपनी गन्ने की गाडी मिल के गेट पर लेकर आता है उसी वक्त उसको पेमेन्ट देदी जाती हैं जो गन्ना सैंअर से आता है उसकी वीकली पेमेन्ट होती है। इस सरकार ने किसानों की भलाई करने में कोई कसर नही छोडी है। इसे अलावा यहां हाउस में यह भी जिक आया कि हरियाणा की भूगर मिलों की तरफ किसानों का लगभग दो तीन करोड रूपया बकासया हैं लेकिन स्पीकरसाहब, मैं यह कहना चहाता हूं कि भूगर मिलों की तरफ भूगर केन ग्रेाअर्ज का कोई पेसा बकाया नही है। भूगर मिलों की तरफ से उनको लगातार पेमैंन्ट होती है। इसके आलवा स्पीकर साहब, जो किसान एक एकड़ या दो एकड जमीन में गन्ना बोता है ा 10 एकड गन्ना बोता है उस गन्ने के लिये किसान बाउंडिड है कि वह भूगर मिल का गन्ना सप्लाई करेगा। उसके लिये हमने किसानों को फैसिलिटीज भी दी है कि किसान गन्ना पैदा करता है उसके लिये भी कोई न कोई फैसिलिटी अव य होनी चाहिये ईीलिये हमने महसूस किया है कि सिकान को उसके

अपने बच्चों की भाादी के लिये भी कोई फैसिलिटी होनी चाहिये हमने उसके लिये महकमें की तरफ से यह कानून बना दिया कि जो किसान 200 क्विंटल गन्ना मिल को सप्लाई करता है उसको एक बोरी चीनी मिल रेट पर दी जाएगी। जो किसान 500 क्विंटल `दगा उसको दो बौरी चीनी दी जायेगी । (ाोर)

आवाजें: हमारी बातों का जवाब आना चाहिये। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप वाईन्ड अप करे। (ाोर)

ठाकुर बीर सिंहः हमने बहुत सारे काम किये हैं जो आदमी गलत काम करता है उसके खिलाफ एक ान लेते हैं मेरे साथियों ने जो सवाल उठाये है...........(ाोर)

Mr. Speaker: Now, the hon'bwl minister of Irrigation andPower may speak. (Noise & interruptions)

ठाकुर बीर सिंहः सर, मैं सिर्फ एक मिनट में ही अपनी बात खत्म करना चहता हूं । अभी 5–6 बैंको के अन्दर ताजा भर्ती हुई है। मैं सारे फैक्टस एंड फिग्र्ज इकट्ठी करके लाया हू। (ाोर) जो इल्जाम ये मुझ पर लगाते ळै वे सरासर गलत ओर बेबूनियाद हैं (ाोर)

आवाजें: हम साबित कर देगें । आपको इस सम्बन्ध में हाउस की एक कमेटी बना देनी चाहिये। हम अच्छी तरह साबित करके दिखा देगें (ाोर)

श्री अध्यक्षः इन्होने अपना जवाब देने के लिये सिर्फ एक मिनट का समय मांगा हैं इसलिये इनको जवाब दे देने लीजिये। (ाोर)

आवाजें: स्पीकरसाहब, इस सम्बनध में हाउस की कमेटी बना देनी चाहिये। (ाोर)

ठाकुर बीर सिंहः यह मुझे सुनना नहीं चाहते । इनको पहले मेरी बात सुन तो लेनी चाहिये। (ाोर)

आवाजें: हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। इनको पहले मेरी बात सुन तो लेनी चाहिये। (ाोर)

आवाजें: हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। यदि ये हमारी बात को गलत बताते है तो हाउस की एककमेटी बना दी जानी चाहिये। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चोधरी भजन लाल): आन ए पवांयट आफ आर्डर सर। मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जब एक मंत्री जी जवाब दे रहे है तो इनको जवाब सुन लेना चाहिये। यदि ये सुनना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते है।(ाोर)

आवाजें: हाउस की कमेटी बना दी जाये।(ाोर)

चौधरी भजन लालः किस बात के लिये हाउस की कमेटी बनाई जाये? (ाोर) अध्यक्षमहोदय, इस सदन के सारे सदस्य बडे ही माननीय औरसम्मान योग्य है। लेकिन मैं एक बात

कहना चहाता हूं कि जब कोई मिनिस्टर जवाब दे रहा हो तो उस कीबात को तो सुन लेना चाहिये। ये किसी दूसरे की भी कोई बात न सुने। तो यह अच्छी बात नहीं है । (ाोर) टाईम तो आपने देखना हे कि किस कोकितना टाईम बोलने के लिये देना है। (ाोर) कम से कम इनको मंत्री जी की बात तो सुन लेनी चाहिये।

ठाकुर बीर सिंहः इनको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिये।

श्री मूलचन्द जेनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि हमनेएवीडैंस एक्ट मेंयह पढा है। ....(ाोर)

ठाकुर बीर सिंहः ठाकूरवाद और पैसावाद की जो ये बातें कह रहे है यह सरासर गलत है। जो आरोप मुझ पर लगाये जा रहे हे, ये सभी गलत हैं। (ाोर)

श्री मूलचन्द जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर सहाब, एवीडैंस एक्ट में हमने यह पढा है कि एक पार्टी यदि किसी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है तो उसको जवाब देना होता है । जो आरोप इन पर लगाये गये है इनको उनका जवाब देना चाहिये। लेकिन ये अपनी तारीफ अपने आप करनेलग रहे है। जो पवायंट हमने रेज किये थे, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। (ाोर) यदि इनहोनें एम्पलाएमेंअ एक्सचेंजिज से भर्ती किये है और अगर कोई गडबउी नहीं की है तो एक कमी ान बना दे।

यदिकमी ान नहीं बनाना तो हाउस की एक कमेटी बना दे। (ाोर)

सिचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर सहाब, आज इरीगें ान की डिमांड पर बोलते हुये पक्ष ओर विपक्ष की ओरसे कई सदस्य बोले है। यह मैं मानता हूं कि हमारा हरियाणा कृशि प्रधान प्रदे ा है। (ाोर)

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर , सर।

श्री अध्यक्ष: प्वायंट आफ आर्डर किस बात पर। उन्होंने तो अभी बोलना ही भाुरू किया है।

श्री कंवल सिंह: मेरा प्वांयट आफ आर्डर कोआप्रे ान डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष: वे तो अपनी बात कह कर बैठ चुके है ओर इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने अभी बोलना ही भाुरू किया हैं इसलिय इस समय कोई पवायंट आफ आर्डर उठाना उचित नहीं हैं (ाोर)

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हरयिाणा एग्रीकल्चरल स्टेट हैं

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अभी मिनिस्टर साहेबन ने बोलना ळे । उसके बाद डिमांडज फार ग्रान्टस पर वोटिंग भी

हेानी है। इसलिये मेरा ख्याल है कि अगर हाउस की सैन्स हो तो एक घंटा समय बढा लिया जाये।

आवाजें: जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं तो अपना काम दस मिनट मे ंकर सकता हूं लेकिन आप सब चूंकि बोलने के मूड में है इसलिये टाईम यदि बढा लिया जाए तो ठीक रहेगा।

आवाजें: जी नहीं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सबेरे 11 बजे से हम लोग बैठे हुये है।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर सहाब, मैं कह रहा था..........
(ोर)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप लोग मेरे से ज्यादा तजूर्बेकार लेजिस्लेटर हैलेकिन जहां तक मेरे सोचने का तरीका है उसके मुताबिक कोई भी मंत्री महेादय अपने डिपार्टमेंट के बारे में , जो भी उसने काम किया है या आगे करने का इरादा रखता है, बोल सकता है। मैंबर्ज साहेबान को मैने बोलने के लिये मैंक्सिमम टाईम दियाहैं आज भी हम लगातार सात घंटे से बैठे हुये हैं तकरीबन सब मांगों पर कट मो न्ज आ रही है फिर भी अगर कोई संतुश्ट न हो तो उन पर वे अपनी आत्मा की आवाज

के मुताबिक वोट कर लेना लेकिन कृपया मंत्री महोदय को डिस्टर्ब न करे।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, में फख्र से कह सकता हूं कि इरीगे ान डिपार्टमेंट की जितनी ब्रांचिज है, उन सबका काम बहुत अच्छा है। काम चाहे लाइनिंग का है, चाहे जे0एल0एन0 का है, एस0वाई0एल0 का है ा एम0आई0टी0सी0 का है प्रत्येक के उपर आधा–2 घंटा बोलने की गुजांइ ा है लेकिन चूंकि टाईम थोडा हे इसलिये इन सब बातें के बारे में मैं फिर जब कभी टाईम मिलेगा कह दूंगा। आज मेरी हाउस से आपके द्वारा यही प्रार्थना है कि इस डिमांड को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Now I put the various demands and the cut motions to the vote of the House.

There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 2. I will pujt it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 84320573 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 2- General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 3. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 279233064 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No.3- Home

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 4. I will put it to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 49055580 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 4- Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 5. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 28152650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No.5- Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 15. I will pujt it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 585787790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year

1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 17. I will pujt it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 388844510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No.17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 22. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 42821300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 22- Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

(17.57 बजे)

तत्प चात सदन मंगलवार दिनांक 30–3–1982 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)